भारतीय रिज़र्व बैंक

बुलेटिन

सितंबर 2022

खंड 76 अंक 9

अध्यक्ष
माइकल देबब्रत पात्र

संपादन समिति
अजित आर. जोशी
देब प्रसाद रथ
मुनिश कपूर
रेखा मिश्र
इन्द्रनील भट्टाचार्य
स्नेहल हेरवाडकर
पंकज कुमार
तुषार बरन दास
वी. धन्या
श्वेता कुमारी
सुजाता कुंडू

संपादक
जी. वी. नथनएल

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादकीय समिति के
निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग द्वारा
मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है।
इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए
बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है।
हस्ताक्षरित आलेखों में व्यक्त विचारों के लिए
लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2022

सर्वाधिकार सुरक्षित।
सामग्री के पुनः प्रयोग की अनुमति है,
बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन के सदस्यता शुल्क के लिए कृपया “भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के महत्त्वपूर्ण प्रकाशन” खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को इंटरनेट के माध्यम से
https://bulletin.rbi.org.in पर भी देखा जा सकता है।

विषय-वस्तु

भाषण

वित्तीय बाजार सुधार: दृष्टिकोण और अपेक्षाएं
शक्तिकांत दास 1

दक्षिण एशिया में मुद्रास्फीति की गतिशीलता
माइकल देबब्रत पात्र 7

समावेशी ऋण : अगला लक्ष्य
एम. राजेश्वर राव 13

भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार - चुनौतियां और संभावनाएं
टी. रबी शंकर 19

आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति 27

इनपुट कीमतों के प्रति आउटपुट कीमतों की संवेदनशीलता:
भारत के लिए एक अनुभवजन्य विश्लेषण 65

भारतीय राज्यों में आर्थिक गतिविधि पर कोविड-19 का प्रभाव 77

वर्तमान सांख्यिकी **89**

हाल के प्रकाशन **142**

भाषण

वित्तीय बाजार सुधार: दृष्टिकोण और अपेक्षाएं
शक्तिकांत दास

दक्षिण एशिया में मुद्रास्फीति की गतिशीलता
माइकल देबब्रत पात्र

समावेशी ऋण : अगला लक्ष्य
एम. राजेश्वर राव

भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार - चुनौतियां और संभावनाएं
टी. रबी शंकर

वित्तीय बाजार सुधार: दृष्टिकोण और अपेक्षाएं*

शक्तिकांत दास

आज एफआईएमएमडीए[1] के कार्यक्रम का हिस्सा बनकर मुझे खुशी हो रही है। मैं इस अवसर पर भारत में वित्तीय बाजारों के विकास में एफआईएमएमडीए द्वारा निभाई गई प्रमुख भूमिका के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से प्रशंसा करना चाहता हूँ।

आज शाम के अपने संबोधन में, मैं हाल के कुछ वित्तीय बाजार के घटनाक्रमों और प्रचलित वैश्विक एवं घरेलू वातावरण में उनसे निपटने के हमारे प्रयासों के संबंध में विचार रखना चाहता हूं। इसके बाद मैं घरेलू वित्तीय बाजारों के विकास के लिए हमारी हाल की कुछ पहलों के बारे में बात करूंगा और फिर आने वाले समय में बाजार सहभागियों और बाजार निकायों से हमारी अपेक्षाओं पर प्रकाश डालते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा।

हाल ही में वित्तीय बाजार में उथलपुथल

अमेरिकी मौद्रिक नीति के भावी पथ पर जैक्सन होल में यूएस फेड की हालिया टिप्पणी ने वैश्विक वित्तीय बाजारों में भारी अस्थिरता पैदा कर दिया है, जिसका प्रभाव-विस्तार और परोक्ष प्रभाव उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) पर हुआ है। यह घटना 23 अगस्त 2022 को मेरे मीडिया साक्षात्कार में दिए गए उस बिंदु का एक और प्रदर्शन है, जहां निभावकारी मौद्रिक नीति के समय में भावी मार्गदर्शन एक उपयोगी नीतिगत साधन हो सकता है, लेकिन सख्ती चक्र में सामंजस्यपूर्ण और सुसंगत मार्गदर्शन प्रदान करना काफी कठिन हो सकता है। उच्च अनिश्चितता के मौजूदा माहौल में कठिनाई और बढ़ती जा रही है। इस तरह के भावी मार्गदर्शन का वित्तीय बाजारों पर अस्थिर प्रभाव भी हो सकता है, खासकर अगर बाद की नीतिगत कार्रवाइयाँ पहले की घोषणाओं से भिन्न हों। वर्तमान संदर्भ में केंद्रीय बैंक का संचार वास्तविक नीतिगत कार्रवाइयों की तुलना में और भी अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। हालांकि, विशेष रूप से, भारत में वित्तीय बाजार जैक्सन होल घटना के तत्काल बाद के निचले स्तर से उबर गए हैं।

इस अशांत वैश्विक माहौल में, भारतीय वित्तीय बाजारों द्वारा प्रदर्शित सुदृढ़ता अर्थव्यवस्था के मजबूत समष्टि-आर्थिक तत्व और कोविड-19 महामारी और यूरोप में युद्ध के तुरंत बाद हुए दो ब्लैक स्वान घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिए सक्रिय और कार्यनीतिक नीतिगत हस्तक्षेप को दर्शाता है।

अनुभव हमें बताता है कि बाजार अक्सर नई जानकारी के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, जो अस्थिरता को भी बढ़ाता है। विशेष रूप से अभी के समय में, जब भू-राजनीतिक तनाव और समकालिक मौद्रिक नीति सख्ती एक साथ आते हैं, तो ओवरशूटिंग अक्सर अंतर्निहित मूल सिद्धांतों के साथ बाद के पुनर्निर्माण से पहले होता है। इसलिए, भारत के समष्टि-आर्थिक मूल तत्व और बफ़र्स का जायजा लेना और मौजूदा एवं विकसित परिस्थितियों में उनका आकलन करना उपयोगी है। सबसे पहले, भारत को व्यापक रूप से 2022 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में माना जाता है[2], जब अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को मंदी या उनकी वृद्धि की गति में काफी कमी का सामना करना पड़ सकता है। भारत का अनुकूल वृद्धि अंतर निवेशकों को विश्वास प्रदान करता है। यह जुलाई 2022 के बाद से भारत में पोर्टफोलियो प्रवाह में तेजी से परिलक्षित होता है। अकेले अगस्त में 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रवाह जुलाई के निवल प्रवाह के 16 गुना से अधिक है। दूसरा, पण्य वस्तुओं की कीमतों में हालिया नरमी और आपूर्ति श्रृंखला के दबावों ने व्यापार के आघात को कम कर दिया है, जिसका भारत को महामारी और युद्ध के बाद सामना करना पड़ा था। आयातित मुद्रास्फीति के दबावों के परिणाम में कमी के साथ, भारत की सीपीआई मुद्रास्फीति अप्रैल 2022 में चरम पर पहुंच गई है। इसके अलावा, अगस्त में औसत भारतीय विविध कच्चे तेल की कीमत 97.4 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से कम हो गई है, जो हमने पूरे वर्ष के लिए मान लिया था - 105 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल - 5 अगस्त के मौद्रिक नीति संकल्प में। वास्तव में, भारत की मुद्रास्फीति उसके व्यापारिक भागीदारों की एक बड़ी संख्या

* 05 सितंबर 2022 को मुंबई में एफआईएमएमडीए के वार्षिक कार्यक्रम में श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक का संबोधन

1 भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ

2 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट, जुलाई 2022, आईएमएफ।

से कम है। तीसरा, पण्य वस्तु कीमत के दृष्टिकोण में बदलाव भी 2022-23 में भारत के चालू खाता घाटे के आकलन को बदल रहा है, जिसके अब संधारणीय स्तरों के भीतर रहने की प्रत्याशा है। चौथा, ऐसे समय में जब दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा की कमी और बढ़ती कीमतों से खतरा है, भारत का खाद्यान्न का बड़ा बफर स्टॉक घरेलू आपूर्ति का पूरक है और घरेलू स्तर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। पांचवां, भारत का 561 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार (26 अगस्त तक) बाहरी आघातों से राहत प्रदान करता है, जैसा कि दिन-प्रतिदिन के आधार पर प्रदर्शित किया जा रहा है। इसके अलावा, वायदा आस्तियों द्वारा आरक्षित निधि को भी मजबूत किया जाता है। छठा, हमारी बैंकिंग प्रणाली की सेहत अच्छी है। बेहतर आस्ति गुणवत्ता के साथ यह अच्छी तरह से पूंजीकृत और अच्छी तरह से प्रावधानित है। यह वित्तीय स्थिरता का एक प्रमुख स्तंभ है और इससे वित्तीय बाजारों के लिए सकारात्मक प्रभाव-विस्तार प्रदान करने की उम्मीद है।

इन मूलभूत कारकों को प्रतिबिंबित करते हुए, भारतीय रुपया चालू वित्त वर्ष में अब तक एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा है। इसने अन्य ईएमई और एई मुद्राओं में तेज मूल्यह्रास की दुनिया में अपना स्थान बनाए रखा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान जहां अमेरिकी डॉलर में अब तक 11.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वहीं भारतीय रुपये में 5.1 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो दुनिया में सबसे कम है। चलनिधि और विश्वास प्रदान करके आरबीआई नियमित आधार पर बाजार में उपस्थित है, ताकि इसके सुचारू और सामान्य कामकाज को सुविधाजनक बनाया जा सके।

विनिमय दर स्थिरता हमारे समग्र समष्टि-आर्थिक और वित्तीय स्थिरता का एक आंतरिक तत्व है। निरंतर आधार पर विश्व स्तर पर सामने आ रही असाधारण घटनाओं के बीच हमारा प्रयास प्रत्याशाओं पर लगाम लगाना और विनिमय दर को ओवरशूट के बजाय मूल सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करने की अनुमति देना रहा है। बाजार द्वारा निर्धारित विनिमय दर व्यवस्था का लाभ उठाते हुए सभी हितधारकों के लिए अनुचित और अत्यधिक अस्थिरता से बचना एक वांछनीय नीतिगत उद्देश्य है।

कीमत स्थिरता मध्यम अवधि में विनिमय दर स्थिरता के लिए अवलंब प्रदान करती है। लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) व्यवस्था वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को स्थिर रखने के लिए आरबीआई की मौद्रिक नीति अधिदेश को विश्वसनीयता प्रदान करता है। जहां आने वाली मासिक मुद्रास्फीति निकट अवधि में उतार-चढ़ाव वाली हो सकती है, वहीं हम उम्मीद करते हैं कि यह वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही में सामान्य हो जाएगी, और फिर चौथी तिमाही में सहिष्णुता बैंड के भीतर और फिर वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में और भी कम हो जाएगी।

महामारी और यूरोप में युद्ध की प्रतिक्रिया

जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, महामारी की प्रतिक्रिया स्वरूप, आरबीआई ने पारंपरिक और अपरंपरागत मौद्रिक नीति साधनों का प्रयोग किया। वित्तपोषण की स्थिति को आसान रखा गया था। वित्तीय बाजार के विभिन्न खंडों का सामान्य कामकाज सुनिश्चित किया गया। हमारे संचार और आगे के मार्गदर्शन ने बाजारों को वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों के लिए बहुत आवश्यक स्पष्टता और विश्वास प्रदान किया।

जैसा कि हमने महामारी के प्रति अनुकूलित कर लिया है, नीतिगत दृष्टिकोण धीरे-धीरे सामान्य हो गया है। यहां तक कि जब भारतीय अर्थव्यवस्था महामारी से उबर रही थी, तब उसे यूरोप में युद्ध से झटका लगा, जिससे ताजा आपूर्ति बाधित हुई और पहले वाले बाधित हो गए। मुद्रास्फीति वैश्वीकृत हो गई। नतीजतन, केंद्रीय बैंकों की प्रतिक्रिया आक्रामक रही है जिससे दुनिया भर में समकालिक मौद्रिक सख्ती हुई है। भारत में, एमपीसी ने मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य के रूप में कीमत स्थिरता को फिर से प्राथमिकता दी और निभाव को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की।

आगे चलकर, कीमत स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हमारी मौद्रिक नीति वृद्धि का समर्थन करते हुए सतर्क, चुस्त-दुरुस्त और सुविचारित रहेगी। आरबीआई संशोधित चलनिधि प्रबंधन फ्रेमवर्क के अनुरूप, वारंट के अनुसार, दोतरफा परिचालन के साथ बाजार का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। आरबीआई स्थिर मुद्रा बाजार स्थितियों, जी-सेक में प्राथमिक नीलामी के सुचारू संचालन और प्रतिफल वक्र के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने का भी प्रयास करेगा।

विनियामकीय फ्रेमवर्क और वित्तीय बाजारों में सुधार

दो ब्लैक स्वान घटनाओं के बावजूद, जो हाल के विमर्श पर हावी हैं, आरबीआई घरेलू वित्तीय बाजारों के विकास के उद्देश्य से विनियामकीय सुधारों के साथ दृढ़ता से कायम है। हमारा दृष्टिकोण आधुनिक वित्तीय बाजार की जरूरतों को अपनाने के सिद्धांत पर आधारित है क्योंकि यह बाकी दुनिया के साथ एकीकृत होता है।

मैं पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए कुछ विनियामकीय परिवर्तनों के बारे में बात करना चाहूंगा। राष्ट्रिक प्रतिफल वक्र के व्यवस्थित विकास के लिए महत्वपूर्ण बेंचमार्क परिपक्वता काल बिंदु पर अच्छी ख़ासी बाजार चलनिधि की जरूरत होती है और बाजार सहभागियों के विभिन्न वर्ग को उनकी निवेश अपेक्षाओं के अनुरूप विभिन्न अवधियों के जी-सेक की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। इसके लिए, बेंचमार्क सुरक्षा जारी करने की रणनीति वर्ष 2020-21 के दौरान पेश की गई थी, जिसके तहत 2, 5, 10, 14, 30 और 40 वर्ष की विशिष्ट बेंचमार्क अवधि की सरकारी प्रतिभूतियां (जी-सेक) जारी की जाती हैं। इस वर्ष बाजार परामर्श के बाद 7 वर्ष की अवधि के जी-सेक भी पेश किए गए हैं।

हरित बांड जारी करना कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था के प्रति देश की प्रतिबद्धता का एक मजबूत संकेत प्रदान करता है। यह हरित परियोजनाओं के लिए पूंजी की लागत को कम करने में भी मदद करता है। वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में घोषणा के बाद, सरकार और आरबीआई वैश्विक मानकों के अनुरूप राष्ट्रिक हरित बॉन्ड जारी करने के लिए एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं।

जी-सेक में खुदरा भागीदारी बढ़ाने के हमारे निरंतर प्रयासों के तहत, व्यक्तिगत निवेशकों को जी-सेक, राज्य विकास ऋण (एसडीएल) और राष्ट्रिक स्वर्ण बॉन्ड में आसानी से निवेश करने की सुविधा के लिए नवंबर 2021 में 'आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना' शुरू की गई थी। इसके अलावा, खुदरा निवेशकों के लिए चलनिधि सुनिश्चित करने हेतु, "रिटेल डायरेक्ट योजना – बाजार निर्माण" को 04 जनवरी 2022 को अधिसूचित किया गया था। इस योजना के लिए प्राथमिक डीलरों को खुदरा निवेशकों से बाजार की अवधि के दौरान खरीदने/बेचने के अनुरोधों का प्रत्युत्तर देना अपेक्षित है।

आरबीआई जी-सेक बाजार में व्यापार, निपटान और सूचना के समय पर प्रसार के लिए अत्याधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुनिश्चित करने में लगातार जुटा हुआ है। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पहल अक्टूबर 2020 में एनडीएस-ओएम पर रिक्वेस्ट फॉर कोट (आरएफक्यू) डीलिंग मोड की शुरुआत है। आरएफक्यू मोड का उद्देश्य बाजार सहभागियों को बेहतर कीमत निर्धारण के लिए एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म पर ही व्यापार के संबंध में सौदा करने में सक्षम बनाना है।

व्युत्पन्नी बाजार संस्थाओं को अपने जोखिमों को कम करने और अंतर्निहित उत्पाद के लिए चलनिधि में सुधार करने की अनुमति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विदेशी मुद्रा, ऋण और ब्याज दर डेरिवेटिव बाजारों के लिए विनियामकीय फ्रेमवर्क को युक्तिसंगत बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। बाजार सहभागियों को अधिक लचीलापन और परिचालन स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए निर्देशात्मक विनियमों के स्थान पर सिद्धांत-आधारित व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। इन बाजारों में अनिवासियों की पहुंच आसान कर दी गई है। बाजारों में संस्थागत उपयोगकर्ताओं की पहुंच को हेजिंग और बाजार की गतिविधियों पर अपने विचार व्यक्त करने, दोनों के लिए सुविधा प्रदान की गई है।

इन सुधार उपायों से उत्पाद की जांच पड़ताल अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यह सुनिश्चित करेगा कि बाजार-निर्माता ऐसे उत्पादों की पेशकश करें जो उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता से मेल खाते हों और अपने ग्राहकों को अत्यधिक जोखिम में डालने से बचें। ओटीसी डेरिवेटिव्स से संबंधित विनियमों में हाल के परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप, ओटीसी डेरिवेटिव्स[3] में बाजार निर्माताओं के लिए एक विनियामकीय फ्रेमवर्क स्थापित किया गया है ताकि बाजार निर्माताओं द्वारा अभिशासन, जोखिम प्रबंधन और आचरण के उच्च मानकों को सुनिश्चित किया जा सके।

हमने घरेलू और अपतटीय आईएनआर बाजारों को एकीकृत करने की दिशा में भी अपने प्रयास जारी रखे हैं। भारत में सक्रिय आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों वाले बैंकों को 2020 में ऑफशोर

[3] मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (ओटीसी व्युत्पन्नी में बाजार निर्माता) निदेश, 2021 दिनांक 16 सितंबर 2021 (https://www.rbi.org.in/scripts/FS_Notification.aspx?Id=12163&fn=6&Mode=0)

नॉन-डिलीवरेबल रुपया डेरिवेटिव मार्केट तक पहुंच की अनुमति दी गई थी। ओवरनाइट इंडेक्स्ड स्वैप (ओआईएस) के लिए अपतटीय और तटीय बाजारों के एकीकरण की सुविधा के लिए - घरेलू बाजार में सबसे सक्रिय रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव - भारत में बैंकों और एकल प्राथमिक व्यापारियों (एसपीडी) को विदेशी मुद्रा में अनिवासियों के साथ ओआईएस लेनदेन का निपटान करने की अनुमति दी गई है।

मोटे तौर पर, हाल के विनियामकीय और संस्थागत सुधारों का उद्देश्य घरेलू वित्तीय बाजारों को अगले दशक की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाना है। सभी बाजार खंडों में, ये सुधार एक सरलीकृत, सिद्धांत-आधारित विनियामकीय फ्रेमवर्क की शुरूआत करना चाहते हैं जो पहुंच को आसान बनाकर, भागीदारी को बढ़ाकर, नवन्मेष की सुविधा, उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और निष्पक्ष आचरण को बढ़ावा देकर बाजारों को व्यापक बनाना चाहता है।

सुधार के भागीदारों के रूप में बाजार सहभागी और बाजार निकाय

यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि वित्तीय बाजार और इसके बुनियादी ढांचे के लिए विनियामकीय फ्रेमवर्क में महत्वपूर्ण बदलावों से वांछित परिणामों की उपलब्धि बाजार सहभागियों के सुधार एजेंडे को आगे बढ़ाने पर निर्भर है। यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि हाल के वर्षों की चुनौतियों का सामना करने के लिए बाजार सहभागी इस अवसर लाग्भ उठा रहे हैं और रिज़र्व बैंक के साथ भागीदारी कर रहे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण पिछले दो वर्षों में बढ़े हुए निर्गमन के बावजूद सरकार के उधार कार्यक्रम का सुचारू रूप से पूर्ण होना था।

इसी तरह, बाजार में चलनिधि की स्थिति को सामान्य बनाने की दिशा में कदम भी बिना किसी व्यवधान के उठाया गया है। विनियमनों में परिवर्तनों के प्रतिक्रियास्वरूप हम देख रहे हैं कि हमारे बैंक सक्रिय हो रहे हैं और वैश्विक बाजारों में दिखाई दे रहे हैं तथा वास्तविक क्षेत्र की हेजिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए उत्पादों के साथ आ रहे हैं। लाइबोर से अलग संक्रमण भी सापेक्ष सहजता के साथ प्राप्त किया गया है। बेशक, पूर्ण परिवर्तन की दिशा में प्रयासों को जारी रखने की जरूरत है क्योंकि हम एक वर्ष से भी कम समय में सभी अमेरिकी डॉलर लाइबोर व्यवस्था को समाप्त करने की समय सीमा के करीब पहुंच गए हैं। इन सभी क्षेत्रों में, एफआईएमडीडीए, पीडीएआई[4], एफईडीएआई[5] और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) जैसे बाजार निकायों ने बाजार सहभागियों और विनियामक के बीच सेतु के रूप में कार्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा है, जो बाजार के विचारों को सक्रिय रूप से व्यक्त करता है और नीति निर्माण के लिए समय पर इनपुट प्रदान करना।

बाजार सहभागियों से अपेक्षाएं

हालांकि, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां बाजार सहभागियों के प्रदर्शन में और सुधार हो सकता है। एक क्षेत्र छोटे/खुदरा ग्राहकों के लिए सेवाएं मुहैया करना रहा है। जहां आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत द्वितीयक बाजार व्यापारों की मात्रा में लगातार वृद्धि हुई है, वहीं एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म पर पूरे बाजार समय के दौरान खुदरा निवेशकों के लिए चलनिधि सुनिश्चित करने में सुधार की काफी गुंजाइश बनी हुई है। हमें विदेशी मुद्रा उत्पादों के उचित कीमत निर्धारण के बारे में ग्राहकों से अभ्यावेदन मिलना जारी है - विशेष रूप से उनसे, जो छोटे आकार वाले विदेशी मुद्रा लेनदेन करते हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक के कुछ अधिकारियों द्वारा किए गए एक अनुसंधान अध्ययन में ओटीसी मुद्रा डेरिवेटिव बाजार में उल्लेखनीय कीमत भेदभाव की मौजूदगी का अनुभवजन्य साक्ष्य मिला। एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म पर बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों का रिस्पांस समय और ऑनबोर्डिंग तेज हो सकता है।

ओटीसी डेरिवेटिव बाजारों में संशोधित उत्पाद नियम अब बाजार-निर्माताओं को अलग-अलग जटिलता के डेरिवेटिव उत्पादों में सौदा करने और इन उत्पादों को केवल गैर-खुदरा/संस्थागत ग्राहकों को पेश करने की अनुमति देते हैं, जिनके पास ऐसे उत्पादों से जुड़े जोखिमों को संभालने की क्षमता है। यह समझने वाली बात है कि बाजार सहभागियों और उपयोगकर्ताओं ने जटिल उत्पादों के उपयोग में विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है। बाजार-निर्माताओं के मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को लगातार अद्यतन करने की जरूरत हो सकती है। ग्राहकों को इन उत्पादों से जुड़े अनूठे जोखिमों से भी अवगत कराने की जरूरत है।

4 भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई)

5 भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई)

हाल के सुधार उपायों ने वैश्विक बाजारों के साथ घरेलू बाजार के अधिक जुड़ाव की सुविधा प्रदान की है। जैसे-जैसे भारत में बैंकों कि उपस्थिती अपतटीय बाजारों में बढ़ रही है, वैसे-वैसे यह उम्मीद की जा रही है कि रुपये उत्पादों के कीमत निर्धारण तटवर्ती बाजार में समेकित होगी। इस क्षमता को हासिल करने के लिए, बैंकों को जोखिम प्रबंधन में विशेषज्ञता द्वारा समर्थित पर्याप्त पूरक बुनियादी ढाँचा स्थापित करने की आवश्यकता है। इसलिए भी, क्योंकि एकीकृत वित्तीय बाजार भी आघातों के तेजी से प्रसार का कारण बन सकते हैं जिसके लिए उचित जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष

अब मैं निष्कर्ष के तौर पर कह सकता हूँ कि बाजार का विकास अंततः विनियामक और बाजार सहभागियों दोनों का एक साझा लक्ष्य है। आरबीआई ने बाजारों को उदार बनाने, बाधाओं को दूर करने और एक सुविधाजनक विनियामकीय फ्रेमवर्क स्थापित करने की दिशा में कदम उठाए हैं। नए उत्पादों को अपनाने के लिए चलनिधि प्रदान करने, कीमत निर्धारण में योगदान देने और परिचालन संबंधी बाधाओं को कम करने के मामले में बाजार सहभागियों की भागीदारी की आवश्यकता होती है। यह बाजार सहभागियों पर है कि वे बाजार को विकसित करने के लिए इस मशाल को आगे ले जाएं और ग्राहकों के व्यापक समूह को नवीन वित्तीय उत्पादों की पेशकश करें। आरबीआई लगातार बाजार निकायों और भागीदारों के साथ जुड़ा रहेगा। साथ-साथ, हमें हर समय भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे दृढ़ विश्वास है कि हम ऐसा कर सकते हैं। मैं एफआईएमएमडीए के भविष्य के प्रयासों में सफलता की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारी निरंतर साझेदारी बनी रहेगी।

धन्यवाद।

*दक्षिण एशिया में मुद्रास्फीति की गतिशीलता**

माइकल देबब्रत पात्र

नमस्कार ! महामारी के बाद सार्कफाइनेंस के तत्वावधान में इस पहली प्रत्यक्ष संगोष्ठी में भाग लेने वाले दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के सहभागी केंद्रीय बैंकों का गर्मजोशी से स्वागत है।

सुश्री डेचन पेलज़ोम, कार्यकारी निदेशक, भूटान रॉयल मॉनेटरि अथॉरिटी, को बधाई।

हमें, अपने साथ वित्त मंत्रालय के सहयोगियों, और हमारे केंद्रीय बैंकों, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अप्रत्यक्ष प्रतिभागियों को साथ पाकर खुशी हो रही है। मैं, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के सहयोगियों, जो विभिन्न विभागों का प्रतिनिधित्व करते हैं, के साथ इसमें शामिल हुआ हूं।

यह संगोष्ठी, मार्च 2021 में सार्कफाइनेंस गवर्नर समूह की 41वीं बैठक में भारत द्वारा की गई प्रतिबद्धता की पूर्ति का प्रतीक है। हमारे देशों में घटनाक्रमों और वैश्विक मुद्रास्फीति संकट को देखते हुए, संगोष्ठी का विषय - मुद्रास्फीति की गतिशीलता और दक्षिण एशिया में इस पर नियंत्रण - से अधिक सामयिक और प्रासंगिक नहीं हो सकता था। व्यापक दृष्टिकोण में, सार्कफाइनेंस के अधिदेश के तहत इस प्रकार के सेमिनार और कार्यशालाएं, ज्ञान और अनुभवों को साझा करने के साथ-साथ व्यक्तिगत बातचीत और हमारे जुड़ाव को बेहतर करने का एक प्रभावी अवसर साबित हुए हैं। हमारा अगला सेमिनार सार्कफाइनेंस डेटाबेस पर होगा, जिसकी मेज़बानी मालदीव मॉनेटरि अथॉरिटी द्वारा की जाएगी।

* 24 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में भारत द्वारा आयोजित सार्कफाइनेंस सेमिनार में डॉ. माइकल देबब्रत पात्र, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, द्वारा दिया गया मुख्य भाषण। स्मिता शर्मा, सोमाश्री तिवारी और अजेश पालयी के बहुमूल्य इनपुट और विनीत कुमार श्रीवास्तव की संपादकीय सहायता के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है।

सार्क: हमारा इतिहास

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अनुसार, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का गठन 1985 में - हमारे क्षेत्र में साझा समझ और सहयोग को बढ़ावा देने की सामूहिक इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में - किया गया था। वर्तमान में, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका, सार्क के सदस्य हैं।

वर्षों से, हमारे देशों ने हमारे मजबूत सांस्कृतिक संबंधों और साझा इतिहास के अलावा, व्यापार, धन-प्रेषण और वित्तीय लेनदेन के रूप में मजबूत संबंध विकसित किए हैं। अब हम इस क्षेत्र की पूरी संवृद्धि क्षमता का उपयोग करके आर्थिक विकास और समृद्धि को गति देने के लक्ष्य के साथ अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने की आशा रखते हैं।

सार्कफाइनेंस: एक अवलोकन

सार्कफाइनेंस की स्थापना 1998 में हमारे केंद्रीय बैंक के गवर्नरों और वित्त सचिवों के संपर्क-तंत्र के रूप में समष्टि आर्थिक नीतियों पर संवाद और आपसी अनुभवों और विचारों के आदान-प्रदान की सुविधा के लिए की गई थी। सार्कफाइनेंस को जनवरी 2002 में काठमांडू, नेपाल में आयोजित 11वें सार्क शिखर सम्मेलन में औपचारिक मान्यता मिली।

पिछले दो दशकों में, हमारे केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग में विस्तार और मजबूती आए हैं। स्वैप सुविधा, जो इस सहयोग की आधारशिला रही है, ने महामारी के दौरान बाह्य-क्षेत्र के दबावों को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने सार्क-सहयोगियों को कई क्रेडिट लाइनों के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान की है।

नीतिगत इंटरफेस, तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण और ज्ञान के आदान-प्रदान ने इस जुड़ाव को गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेष रूप से, अनुसंधान और नीति संचालित सहयोगी अध्ययन, और इस तरह के संगोष्ठियों और सेमिनारों ने

प्रत्येक देश और क्षेत्र द्वारा अनुभव किए गए मुद्दों, चुनौतियों और सफलताओं को सामने लाकर इस पूरे प्रयास को सुगम बनाया है।

सार्कफाइनेंस के तहत कुछ पूर्ण कार्यों का परिचय देने के लिए, गवर्नर समूह बैठक ने समष्टि आर्थिक स्थितियों और नीतियों पर हमारे सहयोग और संवाद को औपचारिक रूप दिया है। सार्कफाइनेंस वेबसाइट को 2011 में विकसित और आरंभ किया गया। सार्कफाइनेंस डेटाबेस 26 मई 2016 को मुंबई में आयोजित गवर्नर सम्मेलन में लाइव हुआ था। अर्धवार्षिक सार्कफाइनेंस ई-न्यूजलेटर का पहला अंक दिसंबर 2006 में प्रकाशित हुआ था। 2020-21 में भारत की अध्यक्षता के दौरान, हमारे केंद्रीय बैंकों के बीच कनेक्टिविटी के नेटवर्क के रूप में 'सार्कफाइनेंस सिंक' नामक पोर्टल बनाया गया था। छात्रवृत्ति योजना का दायरा और कवरेज अधिक विश्वविद्यालयों, अधिक केंद्रीय बैंकिंग से संबंधित पाठ्यक्रमों को शामिल करके और एक वर्ष में दी जाने वाली छात्रवृत्ति राशि और छात्रवृत्ति की संख्या दोनों में वृद्धि करके विस्तारित किया गया था। एक नए डिजाइन और प्रारूप के साथ और सामयिक आलेखों तक विस्तार कर, सार्कफाइनेंस न्यूजलेटर को नया रूप देने का भी प्रयास किया गया है। हमारे आभासी सेमिनारों ने महामारी के दौरान हमारे जुड़ाव को चालू रखा। वित्तीय समावेश प्लेटफॉर्म - वित्तीय समावेश और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए सार्क केंद्रीय बैंकों द्वारा की गई पहलों - का एक केंद्र है जिसने इसे अखिल-क्षेत्रीय दृष्टिकोण से नीति निर्माण को समृद्ध कर इसे बेहतर बनाया है। क्षमता निर्माण पर सहयोग - विशेष रूप से विभिन्न विषयों पर समवेत अध्ययन - बढ़ाने की पहल भी उल्लेखनीय है।

समष्टि आर्थिक घटनाएँ: अवसर और चुनौतियाँ

हमारे देशों ने सभी सदस्यों के अंशदान के साथ एक विशेष सार्क कोविड-19 आपातकालीन कोष की स्थापना करके कोविड-19 से सामूहिक लड़ाई के लिए साथ जुटे हैं। टीकों के एक प्रमुख उत्पादक के रूप में, भारत समान पहुंच के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत ने जनवरी 2021 में अपनी वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत से एक महीने के भीतर कई सार्क देशों को टीके उपलब्ध कराए हैं।

आरबीआई डिजिटल बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके पेमेंट विजन 2025 में, हमारे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी), यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) और रुपे कार्ड्स की वैश्विक पहुंच शामिल है। उदाहरण के लिए, भूटान और भारत ने रुपे कार्ड को लेकर सहयोग बनाया है ताकि भूटानी बैंक अपने नागरिकों को रुपे कार्ड जारी कर सकें।

सार्क देशों के कुल निर्यात में अंत:सार्क व्यापार का हिस्सा 2010 में 6.1 प्रतिशत से बढ़कर 2020 में 7.1 प्रतिशत हो गया है। इसी तरह, सार्क देशों के कुल आयात में अंत:सार्क व्यापार का हिस्सा 2010 में 3.6 प्रतिशत से 2020 में 5.0 प्रतिशत बढ़ गया है। व्यापार के विस्तार की गति धीमी बनी हुई है, हालांकि, आसियान जैसे अन्य क्षेत्रीय समूहों के सापेक्ष भी।

महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित होने के कारण, इस क्षेत्र में 2020 में आर्थिक संकुचन देखा गया। 2021 के दौरान पूरे क्षेत्र में बहुस्तरीय गति और नुकसान के साथ एक कमजोर सुधार हुआ। हमारे क्षेत्र के कई हिस्सों में महामारी के निशान अभी भी गहरे और दर्दनाक हैं।

2022 में, लगातार उच्च मुद्रास्फीति ने जोर पकड़ लिया है, जो 2021 में हुई प्रारंभिक प्रगति के कमजोर होने का खतरा उत्पन्न हो रहा है। कई सदस्य-देश उच्च स्तर में द्विअंकीय मुद्रास्फीति का सामना कर रहे हैं। विनिमय दर में उतार-चढ़ाव, जिंसों की ऊंची कीमतों और आपूर्ति शृंखला दबावों के रूप में वैश्विक प्रसार-प्रभाव ने आयातित मुद्रास्फीति को बढ़ा दिया है। इस साल फरवरी से आवश्यक वस्तुओं की कमी और भोजन और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों ने हमारे लोगों की आजीविका और कल्याण को खतरे में डाल दिया है।

बाहरी मोर्चे पर, व्यापार आघातों और सख्त वैश्विक वित्तीय स्थितियों के कारण व्यापक चालू खाता घाटा, पूंजी बहिर्वाह, घरेलू वित्तीय बाजारों में उच्च अस्थिरता उत्पन्न हुए एवं बाहरी कमजोरियाँ बढ़ीं और आरक्षित निधि को नुकसान पहुँचा। हममें से कुछ कर्ज संकट का भी सामना कर रहे हैं। विभिन्न बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा रेटिंग डाउनग्रेड करने से बाधित अंतरराष्ट्रीय

वित्तीय बाजारों तक पहुंच ने बाहरी तरलता और वित्तपोषण की स्थिति को खराब कर दिया है। हममें से कुछ को इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बहुपक्षीय सहयोग की तत्काल आवश्यकता है।

संगोष्ठी का विषय

इस परिवेश में संगोष्ठी का विषय महत्वपूर्ण है। महामारी के झटके और हाल ही में युद्ध से उत्पन्न मुद्रास्फीति का राष्ट्रीय विस्तार, एक संकट बना हुआ है। जुलाई 2022 के आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार, जिंसों की कीमतों में बढ़ोतरी और कीमतों के दबाव-विस्तार के कारण 2022 में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति 6.6 प्रतिशत और उदीयमान बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 9.5 प्रतिशत तक पहुंच सकती है, जिससे समष्टि आर्थिक स्थिरता को खतरा पैदा हो सकता है।

इसकी प्रतिक्रिया में, दशकों में अब तक देखी गई सबसे समकालिक और अग्रसक्रिय मौद्रिक नीति को सख्त किया जा रहा है। नतीजतन, जैसे-जैसे तरलता और मौद्रिक स्थितियां सख्त हुई हैं, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मंदी या हार्ड लैंडिंग की संभावना उन स्तरों तक बढ़ गई है जो अतीत में वास्तविक मंदी से पहले देखे गए थे। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक आक्रामक रूप से अपनी विश्वसनीयता हासिल करने और मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को नियंत्रित किया जा सके और मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाया जा सके।

देश के आकार, आर्थिक और सामाजिक विकास, भूगोल, जनसंख्या, व्यापार और राजनीतिक व्यवस्था के मामले में दक्षिण एशियाई क्षेत्र की विविधता के बावजूद, मुद्रास्फीति का यह भयावह भूत हम सभी को परेशान करता है। भोजन हमारी औसत खपत बास्केट के साथ-साथ हमारे मूल्य सूचकांकों का एक बड़ा हिस्सा है और पूरे क्षेत्र में उपभोक्ता कीमतों में इसकी हिस्सेदारी 35 से 47 प्रतिशत के बीच है। गरीबी से जूझ रही हमारी आबादी के बड़े हिस्से को देखते हुए, दक्षिण एशिया खाद्य मुद्रास्फीति के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है। इसके अलावा, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें खाद्य कीमतें बढ़ रही हैं जो दूसरे दौर के प्रभावों को ट्रिगर कर सकती हैं, जिससे मुद्रास्फीति के स्थायी और निरंतर बना रह सकता है। इसके अलावा, तेल आयात पर निर्भरता ने हमारे देशों को आमतौर पर व्यापार और आपूर्ति के झटकों के प्रति संवेदनशील बना दिया है। नतीजतन, सामान्य कारकों के कारण इस क्षेत्र में मुद्रास्फीति में तेज बदलाव देखने को मिला। दूसरी ओर, हमारे नीतिगत ढाँचे में विविधता है जो देश-विशिष्ट परिस्थितियों को दर्शाते हैं और यह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के हमारे दृष्टिकोण को आकार देता है। हमारी विनिमय दर व्यवस्थाएं भी इस विविधता को दर्शाती हैं।

मुद्रास्फीति के संकट से निपटना जटिल हो गया है क्योंकि हम निरंतर वैश्विक प्रभाव-प्रसार से जूझ रहे हैं। यह क्षेत्र अब एक जबरदस्त विकासपरक चुनौती का सामना कर रहा है, जिसमें महामारी जैसी अप्रत्याशित घटनाओं के कारण हुए नुकसान की भरपाई सबसे विकट दिखती है। हमारे देशों ने राजकोषीय घाटे में तेज वृद्धि और भुगतान संतुलन का बिगड़ना भी अनुभव किया है। आर्थिक गतिविधियों, रोजगार और निर्यात आय में अभूतपूर्व मंदी की पृष्ठभूमि में भविष्य अनिश्चित और निराशाजनक दिखाई देता है। हमारी संवृद्धि संभावनाओं के सामने जोखिम हैं। आर्थिक-मंदी की काली छाया हम पर और हमारे नजरिये पर मंडरा रही है।

भारतीय अनुभव

भारत में, हमने 2016 से मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे को अपनाया है, जिसमें हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत के लक्ष्य को इसके आसपास +/- 2 प्रतिशत के टॉलरेंस बैंड के भीतर परिभाषित किया गया है। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा नीतिगत निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। लक्ष्य से मुद्रास्फीति परिणामों के विचलन के मामले में विधि और संबंधित नियमों द्वारा ढांचे में निहित सख्त जवाबदेही मानदंड हैं। जहाँ, 2016-20 के दौरान मुद्रास्फीति औसतन 4 प्रतिशत से कम थी, यह 2020-21 में बढ़कर 6.2 प्रतिशत हो गई – जो महामारी की पहली लहर का वर्ष था। यद्यपि यह अगले वर्ष, यानी 2021-22 से 5.5 प्रतिशत तक कम हो गया और 2022-23 में 4.5 प्रतिशत तक और कम होने का अनुमान लगाया गया था, जैसा कि हाल ही में फरवरी

2022 तक, यूक्रेन युद्ध ने नज़रिये को काफी बदल दिया है। हालांकि यह इस साल अप्रैल में अपने चरम 7.8 प्रतिशत से कम होता हुआ प्रतीत होता है, इससे पहले कि हम आश्वस्त हों कि यह एक स्थायी प्रवृत्ति है, हम आने वाले डेटा की प्रतीक्षा करना पसंद करेंगे। जहाँ, वैश्विक और घरेलू स्तर पर अंतरराष्ट्रीय जिंसों की कीमतों और आपूर्ति शृंखला दबावों में कुछ नरमी, सकारात्मक संकेत है, वहीं संभावित दूसरे क्रम के प्रभाव और मुद्रास्फीति के मुख्य घटक पर कच्चे माल की लागत के दबाव के रूप में ऊर्ध्वोन्मुखी जोखिम बने हुए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 (अप्रैल-मार्च) के लिए समग्र रूप से, आरबीआई ने अनुमान लगाया है कि हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति औसतन 6.7 प्रतिशत रहेगी।

तदनुसार, आरबीआई ने अप्रैल में नीतिगत दर के दायरे को कम करने के अलावा अब तक नीतिगत दर में संचयी 140 आधार अंकों की वृद्धि के साथ एक अग्रसक्रिय मौद्रिक नीति कर्रवाई शुरू की है, जिसने मुद्रा बाजार दरों को महामारी के निम्न स्तर से 40 आधार अंक उपर खींच लिया है। अगस्त की शुरुआत में अपनी नवीनतम बैठक में, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने यह सुनिश्चित करने के लिए समायोजनकारी नीति की बहाली पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया कि संवृद्धि में सहायक बन कर मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे। इसके साथ ही, आरबीआई, सुविचारित बहु-वर्षीय समय सीमा में महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था में डाली गई चलनिधि की निकासी में लगा हुआ है।

चूँकि मुद्रास्फीति पूर्वानुमान, मौद्रिक नीति ढांचे में एक मध्यवर्ती लक्ष्य की भूमिका निभाता है, आरबीआई ने मुद्रास्फीति की निगरानी को मजबूत करने और पूर्वानुमान की सटीकता में सुधार करने के लिए कई पहल किए हैं। भविष्योन्मुखी सर्वेक्षणों के दायरे और गहराई को बढ़ाने के अलावा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग (एआई/एमएल) सहित वैकल्पिक पूर्वानुमान तकनीकों और मॉडलों का पता लगाने के लिए एक डेटा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भोजन के बड़े हिस्से को देखते हुए और इस तथ्य को देखते हुए कि भारतीय अर्थव्यवस्था को आपूर्ति-जनित आघात लग सकते हैं, मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान की सहायता के लिए डेटा साइंस लैब में रिमोट सेंसिंग के माध्यम से फसल की स्थिति का आकलन करने का काम भी शुरू किया गया है। इसके अलावा, विश्वास विश्लेषण के माध्यम से जनता की प्रत्याशाओं के आकलन के लिए नई पहल की जा रही है जिससे पूर्वानुमान प्रक्रिया और सटीकता में सुधार हो सके। हमने व्यापार निकायों, व्यापारियों, डोमेन विशेषज्ञों और क्षेत्रीय इकाइयों से बाजार आधारित आसूचना एकत्र करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। हमारा इरादा जितना संभव हो उतती उपयोगी जानकारी आत्मसात करना और मुद्रास्फीति की गतिशीलता की हमारी समझ को समृद्ध बनाना है। हालांकि, अल्पावधि में, मुद्रास्फीति का वृद्धि-पथ भू-राजनीतिक घटनाक्रम, अंतरराष्ट्रीय जिंस-बाजार की गतिशीलता और वैश्विक वित्त बाजार के घटनाक्रमों पर निर्भर है।

समापन टिप्पणी

केंद्रीय बैंकों और सार्वजनिक संस्थानों के रूप में, हमें समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने एवं बनाए रखने और अपनी विकासपरक आकांक्षाओं की पूर्णता के लिए हमारी अर्थव्यवस्थाओं की प्रगति सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। हम अपने दिन-प्रतिदिन के कामकाज और गहन सार्वजनिक-संवीक्षा में संतुलन बनाने की चुनौती का सामना करते हैं। हाल के वर्षों में हमारी भूमिका में बदलाव आया है। अंतिम ऋणदाता से हम पहला बचावकर्ता बन गए हैं। इसलिए, मुद्रास्फीति आघातों के प्रति हमारी कार्रवाई, जैसा कि हम आज सामना कर रहे हैं, प्रत्याशाओं के प्रबंधन और विश्वसनीयता को मजबूत करने पर आधारित होना चाहिए। यदि विश्वसनीयता अधिक है और झटका अस्थायी है, तो मुद्रास्फीति बिना किसी मौद्रिक नीति कार्रवाई की आवश्यकता के संतुलन में लौट आती है। दूसरी ओर, बार-बार आपूर्ति के झटके - जिनका हम अभी सामना कर रहे हैं - लागत में वृद्धि, प्रत्याशाओं, विनिमय दर और मांग चैनलों के माध्यम से दूसरे दौर के प्रभाव को ट्रिगर करते हैं और इससे अग्रसक्रिय मौद्रिक नीति कार्रवाई की जरूरत पैदा होती है। पूर्ण विश्वसनीयता के साथ भी, मौद्रिक नीति बार-बार होने वाले आपूर्ति झटकों के दूसरे दौर के प्रभावों को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। यदि लंबे समय तक मुद्रास्फीति लक्ष्य पार करता है, तो यह प्रत्याशाओं को अस्थिर कर सकता है और अंततः उच्च मुद्रास्फीति में परिलक्षित हो सकता है। उच्च विश्वसनीयता, बार-बार होने वाले आपूर्ति

झटकों के दूसरे दौर के प्रभावों के लिए मौद्रिक नीति की प्रतिक्रिया को कम कर सकती है परंतु इसका स्थानापन्न नहीं हो सकती। वर्तमान समय में, हमारा अनुभव यह है कि मौद्रिक नीति कार्रवाइयों को सामने लाकर और मुद्रास्फीति लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता दिखाकर विश्वसनीयता प्रदर्शित की जा सकती है। मौद्रिक नीति की विश्वसनीयता का एक अन्य आयाम इसकी प्रतिक्रिया का समय है। मौद्रिक नीति की प्रतिक्रिया में देरी से विश्वसनीयता में और कमी आती है और मुद्रास्फीति प्रत्याशाएँ बढ़ती हैं और अंततः उच्च मुद्रास्फीति से संवृद्धि प्रभावित होती है।

प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों, मानव पूंजी और बाजार पहुंच के साथ सार्क में आर्थिक विस्तार की काफी संभावनाएं हैं। दक्षिण एशिया में, व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक विकास की काफी संभावनाएं हैं। हमें इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और अवसर का लाभ उठाना चाहिए, भले ही हम महामारी और भू-राजनीतिक घटनाओं के दुर्बल प्रभावों से उबर जाएं। इस तरह के संगोष्ठियों में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान और जुड़ाव से हमें क्षमता और तकनीकी कौशल निर्माण में प्रगति में मदद मिलेगी। वर्ष 2016 में तैयार किए गए क्षेत्रीय सहयोग के रोडमैप को सार्कफाइनेंस के अधिदेश के तहत, लक्ष्य और समयसीमा के साथ वर्तमान वास्तविकताओं और फोकस क्षेत्रों को शामिल करने हेतु संशोधित करने की आवश्यकता है।

मैं इस संगोष्ठी की सफलता की कामना करता हूँ।

धन्यवाद !

*समावेशी ऋण : अगला लक्ष्य**

एम. राजेश्वर राव

देवियो और सज्जनो,

मैं एसोचैम को धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे आज यहां इस वक्तव्य के लिए आमंत्रित किया। इस शिखर सम्मेलन का विषय - "वित्तीय समावेश और भारत में वित्तीय सेवाओं का भविष्य - विजन 2030" - वास्तव में इस समय हमारे सामने आने वाली चुनौतियों को देखते हुए, सामयिक और प्रासंगिक है। इस शिखर सम्मेलन में इस मुद्दे पर होने वाली चर्चाओं से स्फूर्तिदायक विमर्श और नये निष्कर्ष बाहर आने चाहिए।

आर्थिक विकास और जनता के सामाजिक कल्याण में इसके महत्व को समझते हुए वित्तीय समावेश हमेशा महत्वपूर्ण नीतिगत अनिवार्यता रही है। हम वित्तीय समावेश के अपने प्रयास में एक लंबा सफर तय कर चुके हैं, जो सहकारी समितियों को बढ़ावा देने, बैंकों के राष्ट्रीयकरण, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और अग्रणी बैंक योजना के संस्थानीकरण, बीसी मॉडल के कार्यान्वयन और हाल ही में प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के साथ शुरू हुआ।

इस यात्रा में, हमने बदलती जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति और सामाजिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीतियों और नीति संकेंद्रण को समायोजित किया है। व्यापक भौगोलिक प्रसार और बड़ी संख्या में बैंक से कटी हुई आबादी को शामिल करने की आवश्यकता को देखते हुए, लंबे समय से नीतिगत बल बुनियादी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने पर रहा है। यह काफी हद तक सही माना जाता है कि बैंक और बैंक खाते तक पहुंच व्यापक वित्तीय समावेश की दिशा में पहला कदम है क्योंकि यह लोगों को अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंच के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करने के अलावा धन-प्रेषण जैसे बुनियादी बैंकिंग कार्य करने में सक्षम बनाता है। इस प्रयास में, आरबीआई ने बैंकों को अंडरबैंक पॉकेट्स में शाखाएं खोलने के लिए बाध्य किया, जिसके कारण 1990 के दशक से 2000 के दशक की शुरुआत में बैंक शाखाओं और बाद में ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) में काफी वृद्धि हुई। 2000 से अधिक (2009 में) और 2000 से कम (2012 में) की आबादी वाले गांवों में बैंकिंग आउटलेट खोलने का रोडमैप भी तैयार किया गया था। इसके बाद, बैंकों को 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों में भौतिक शाखाएं खोलने की सलाह दी गई। वित्तीय समावेश को मजबूत करने के लिए, शाखा प्राधिकार (ऑथराइजेशन) दिशानिर्देशों में ढील दी गई और प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण सहायता के लिए ₹2000 करोड़ की आरंभिक निधि के साथ वित्तीय समावेश फंड (एफआईएफ) स्थापित किया गया।

वर्ष 2015 में लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) और भुगतान बैंकों (पीबी) के लिए अलग-अलग बैंकिंग लाइसेंस जारी करने के पीछे वित्तीय समावेश भी एक सोच था। एसएफबी को अनुकूलित जमा उत्पादों के माध्यम से वित्तीय समावेश बढ़ाने और लघु व्यवसाय इकाइयों, छोटे और सीमांत किसान, सूक्ष्म और लघु उद्योग, और अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को, प्रौद्योगिकी की बदौलत कम परिचालन-लागत के माध्यम से ऋण प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। । प्रवासी श्रमिकों, अल्प आय वाले परिवारों, छोटे व्यवसायों और अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं / अन्य उपयोगकर्ताओं को छोटे बचत खाते और भुगतान / धन-प्रेषण सेवाएं प्रदान करने के लिए भुगतान बैंक भी स्थापित किए गए थे।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) और वित्तीय समावेश के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफआई) 2019-2024 ने इन प्रयासों को और बढ़ावा दिया है। एनएसएफआई, वित्तीय क्षेत्र में सभी हितधारकों को शामिल करते हुए व्यापक प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय समावेश प्रक्रिया को विस्तारित करने और बनाए रखने में मदद करने के लिए भारत में वित्तीय समावेश नीतियों के दृष्टिकोण और प्रमुख उद्देश्यों को परिभाषित करता है। इस रणनीति का उद्देश्य औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक किफायती तरीके से पहुंच प्रदान करना, वित्तीय समावेश को व्यापक और गहरा करना और वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता

* श्री एम. राजेश्वर राव, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया भाषण - 08 सितंबर 2022, मुंबई - एसोचैम का 17वाँ वार्षिक शिखर सम्मेलन और बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के ऋण संबंधी अवॉर्ड। श्री चंदन कुमार, श्री प्रदीप कुमार और श्री प्रमांशु राजपूत द्वारा प्रदत्त सूचनाओं के लिए आभार।

संरक्षण को बढ़ावा देना है, जबकि पीएमजेडीवाई के माध्यम से कम सेवा वाले क्षत्रों में बैंकों की पहुंच को बढ़ावा मिला है।

कुछ डेटा, परिप्रेक्ष्य समझने में हमारी मदद करेंगे। पीएमजेडीवाई के तहत अब तक 46.40 करोड़ लाभार्थी खाते खोले जा चुके हैं और इन खातों[1] में ₹1.73 लाख करोड़ जमा-शेष है। जून 2022 तक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा परिचालित 1.59 लाख शाखाएं हैं, जिनकी कुल जमा राशि 170 लाख करोड़ रुपये[2] से अधिक है, जो प्रति 1 लाख जनसंख्या पर लगभग 15 शाखाओं के बराबर है। यह आगे 2.17 लाख एटीएम[3] के नेटवर्क द्वारा पूरित है, जिनमें से 47 प्रतिशत एटीएम ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं और बैंकों द्वारा करीब 32 लाख व्यवसाय प्रतिनिधियों को नियुक्त किया गया है[4]। विश्व बैंक के ग्लोबल फिनडेक्स डेटाबेस के आंकड़ों के अनुसार, 2021 तक, 78 प्रतिशत भारतीय वयस्कों (15 वर्ष या उससे अधिक आयु की आबादी) के पास बैंक खाता था, जबकि 2014 में यह 53 प्रतिशत था। 25 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में 5 किमी के दायरे में लगभग हर गांव तक हम बैंकिंग सेवा प्रदान करने में सक्षम हैं, जिसमें 99.94 प्रतिशत चिन्हित गांव शामिल हैं।

लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं रह सकते हैं, और वित्तीय सेवाओं और उत्पादों तक सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं। साथ ही नीतिगत फोकस को केवल 'वित्तीय सेवाओं तक पहुंच' से हटाकर वित्तीय सेवाओं के 'उपयोग' और 'गुणवत्ता' पर भी केंद्रित किया जा रहा है। आरबीआई द्वारा निर्मित एफआई-इंडेक्स, जो इस दिशा में हमारे प्रयासों का संकेतक है, उपर्युक्त तीन आयामों, 'पहुंच', 'उपयोग' और 'गुणवत्ता' पर आधारित है। वित्तीय समावेश ('उपयोग' और 'गुणवत्ता') की गहनता के पक्ष को प्रदत्त उच्च भार के साथ सूचकांक के भार भविष्योन्मुखी हैं।

जिम्मेदार और निरंतर वित्तीय समावेश के लिए आपूर्ति और मांग दोनों पक्षों पर संतुलन अवसर और नवाचार की आवश्यकता होती है। आपूर्ति पक्ष में, इसमें बचत खाते और उचित वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक सस्ती और आसान पहुंच प्रदान करने के कदम शामिल हैं। मांग पक्ष में, यह वित्तीय साक्षरता और जागरूकता में सुधार करना चाहता है जो वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की मांग बढ़ाने में मदद करता है। मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष के उपाय आदर्श रूप से एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। भारत जैसी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में आम तौर पर मांग और आपूर्ति पक्ष के कारकों के बीच एक असमानता होती है।

जहाँ, पारंपरिक भौतिक संरचनाओं ने बुनियादी बैंकिंग सेवाओं को हमारे देश के कोने-कोने तक ले जाने में मदद की है, वहीं वित्तीय सेवाओं के विस्तार में डिजिटल नवाचारों के आगमन से, वित्तीय समावेश के अगले स्तर तक जाने की क्षमता है जिसमें वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता के मुकाबले समावेश की गुणवत्ता को वरीयता दी जाती है। भारत को एक महाद्वीपीय अर्थव्यवस्था के रूप में कई भाषाओं और संस्कृतियों, विविध और कभी-कभी कठिन इलाकों, बड़ी आबादी और कम आय वाले स्तरों के साथ समावेशी संवृद्धि सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इस प्रकार हमारा ध्यान न केवल बैंक खाते खोलने पर है बल्कि वित्तीय सेवाओं का एक पैकेज- लेनदेन, भुगतान, बचत, बीमा, और ग्राहकों के लिए आसानी से सुलभ और सस्ती क्रेडिट – की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी है। समावेशी ऋण ही समावेशी वित्तीय समावेश प्रक्रिया का आधार बनेगा।

वित्तीय समावेश पर समिति (अध्यक्ष: डॉ. सी. रंगराजन , आरबीआई, 2008) ने वित्तीय समावेश की परिभाषा में कमजोर समूहों के लिए 'सस्ती लागत और समय पर पर्याप्त ऋण' को स्पष्ट रूप से शामिल किया। वित्तीय समावेश के मध्यावधिक पथ संबंधी समिति (अध्यक्ष: श्री दीपक मोहंती, आरबीआई, 2015) ने औपचारिक वित्त तक छोटे और सीमांत उद्यमों की पहुंच बढ़ाने पर भी जोर दिया। इस प्रकार, क्रेडिट तक पहुंच, हमेशा वित्तीय समावेश को आगे बढ़ाने की दिशा में आरबीआई के प्रयासों का एक अभिन्न अंग रही है। अब मुझे समावेशी ऋण के प्रावधानों की थोड़ी चर्चा करनी चाहिए।

[1] https://www.pmjdy.gov.in 24 अगस्त 2022 तक

[2] dbie.rbi.org.in

[3] https://www.rbi.org.in/Scripts/ATMView.aspx?atmid=136

[4] आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22

समावेशी ऋण का महत्व

क्रेडिट तक पहुंच एक बल गुणक के रूप में कार्य करती है, यदि व्यक्तियों के साथ-साथ फर्मों द्वारा इष्टतम रूप से इसका उपयोग किया जाता है। व्यक्तियों के लिए, यह उनकी वित्तीय और उद्यमी जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है और जहां आवश्यक हो, आर्थिक झटकों के प्रति उनकी भेद्यता को कम करता है, जबकि फर्मों के लिए, यह उन्हें नई और अधिक उत्पादक प्रौद्योगिकियों में निवेश की योजना बनाने की अनुमति देने के अलावा सामान्य व्यवसाय संचालन को सक्षम बनाता है। व्यापार विविधीकरण और विस्तार उन्हें बढ़ने में मदद करता है जिससे नौकरी के अवसरों में वृद्धि होती है और आम तौर पर आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। औपचारिक ऋण के लिए पर्याप्त, समय पर और सस्ती पहुंच के बिना, ग्राहक या तो अपनी इक्विटी या ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर होते हैं, जो न केवल महंगे हैं बल्कि दीर्घकालिक आधार पर शायद अस्थिर हैं।

हालांकि, हमारी वित्तीय समावेश यात्रा में एक चुनौती बैंक खाता खोलने के बाद विविध वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की गतिविधि और उपयोग के स्तर को बढ़ाना है। इस पृष्ठभूमि में, डिजिटल तरीका अपनाना सभी बाधाओं का समाधान प्रतीत होता है। हालाँकि, ऐसा करने से कहना आसान है।

आरबीआई और समावेशी ऋण

इस प्रयास में, आरबीआई ने त्रि-आयामी रणनीति अपनाई है जिसमें शामिल हैं:

- डिजिटल ऋण देने या डिजिटल ऋण की सुविधा के लिए वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं की स्थापना,
- सुरक्षित और निर्बाध ऋण वितरण सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी अवसंरचना का पोषण करना और
- ग्राहक-प्रथम विनियामक दृष्टिकोण अपनाना

मैं तीन फोकस क्षेत्रों में से प्रत्येक पर एक दृष्टिकोण साझा करना चाहता हूँ।

ऋण देने के लिए वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं की स्थापना

वित्तीय समावेश में आपूर्ति पक्ष की समस्याओं से निपटने हेतु पहले कदम के रूप में, नई वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं को क्रेडिट प्रदान करने के प्रावधान के साथ सामने लाया गया है ताकि यह सुनिश्चित की जा सके कि ग्राहक को वित्तीय सेवाएं 'कब और कहां आधार' पर उपलब्ध हैं और इस प्रकार सही मायने में 'कहीं भी, कभी भी बैंकिंग' की सुविधा स्थापित हो सके। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं -

पी2पी लेंडिंग प्लेटफॉर्म: इस तरह की प्रथम पहल में, आरबीआई पी2पी नियमों के साथ उस समय सामने आया जब यह उद्योग स्वयं विकास के शुरुआती चरण में था। एक 'पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म' उधारकर्ताओं को ऋण प्राप्त करने और निवेशक को ज्यादातर छोटे टिकट ऋणों का विस्तार करने के लिए एक ऑनलाइन ऑन-टैप स्थान प्रदान करता है। नियमों को इस तरह से तैयार किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फ्रेमवर्क नवोन्मेषी ऋण सेवाओं सीमित को नहीं करता है, साथ ही ग्राहक के हितों की रक्षा करने और प्रणालीगत चिंताओं को कम करने की मांग करता है।

सिर्फ डिजिटल एनबीएफसी: दूसरा, आरबीआई, सिर्फ डिजिटल एनबीएफसी के लिए पंजीकरण दिशानिर्देशों के साथ सामने आया, जो एक एनबीएफसी है और किसी भौतिक उपस्थिति (प्रशासनिक उद्देश्य को छोड़कर) के बिना पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। आरबीआई ने 2018 में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक एनबीएफसी की स्थापना की अनुमति देकर क्रेडिट मध्यस्थता में स्वस्थ नवाचार को संभव किया। हालांकि यह एनबीएफसी की एक नई श्रेणी नहीं है, लेकिन उनकी लाइसेंसिंग शर्तें उन्हें केवल डिजिटल मोड में अपने उत्पाद प्रदान करने के लिए बाध्य करती हैं। यहां भी, उपभोक्ताओं की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा गया है और संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे अनधिकृत पहुंच, डेटा परिवर्तन और विनष्टीकरण, यदि कोई हो, पर पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ आवश्यक आईटी अवसंरचना स्थापित करके ऑडिट ट्रेल्स को बनाए रखे। डेटा साझा करने के लिए स्पष्ट सहमति, सर्वरों का स्थानीयकरण, ऑडिट ट्रेल्स को बनाए रखना, सूचना सुरक्षा ऑडिट आदि जैसी विनियामक विशेषताएं एक साथ प्रगामी और अग्रसक्रिय हैं।

डिजिटल बैंकिंग यूनिट: 'ब्रिक एंड मोर्टार' बैंकिंग आउटलेट्स के साथ-साथ डिलीवरी के पसंदीदा मोड के रूप में

डिजिटल बैंकिंग के उभरने के साथ, केंद्रीय बजट 2022-23 में डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की अवधारणा की घोषणा की गई थी और इन इकाइयों के संचालन के लिए दिशानिर्देश इस साल की शुरुआत में आरबीआई द्वारा जारी किए गए थे। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ स्थापित करने के लिए अधिकृत किया गया है, जो कि डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं को वितरित करने के साथ-साथ स्वयं-सेवा और सहायक दोनों मोड में - डिजिटल रूप से मौजूदा वित्तीय उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए विशिष्ट निश्चित बिंदु व्यापार इकाइयों के के रूप में होंगे। यह उम्मीद की जाती है कि ऐसी इकाइयाँ ग्राहकों को इन उत्पादों और सेवाओं के कुशल, कागज रहित, सुरक्षित और उन्नत वातावरण में सस्ता, सुविधाजनक और उन्नत डिजिटल अनुभव प्रदान करने में सक्षम बनाती हैं, जिसमें अधिकांश सेवाएँ किसी भी समय स्व-सेवा मोड में उपलब्ध होती हैं।

समावेशी ऋण के लिए बाजार का बुनियादी ढांचा तैयार करना

भारत ने वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में एक सक्षम डिजिटल अवसंरचना बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यूपीआई, जीएसटीएन, टीआरईडीएस, जेएएम ट्रिनिटी और अकाउंट एग्रीगेटर्स (एए) कुछ का उदाहरण हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का यह मजबूत समूह स्थापित हो गया है और जैसे-जैसे यह परिपक्व होता है, यह एक सहज और समयबद्ध तरीके से क्रेडिट के विस्तार का मार्ग प्रशस्त करेगा जिसे लगभग कागज रहित वातावरण में डिजिटल रूप से उपलब्ध कराया जा सकता है। विभिन्न वित्तीय सेवा प्रदाताओं में फैले वित्तीय डेटा को एकत्र करने की ए ए की क्षमता और उपभोक्ताओं को उनकी वित्तीय योजना में मदद करने के लिए एनालिटिक्स और अंतर्दृष्टि बनाने हेतु इस डेटा का लाभ उठाने के लिए वित्तीय सेवा प्रदाताओं को अपने ग्राहकों को अनुकूलित उत्पादों की पेशकश करने की अनुमति मिलेगी। एए ढांचे में 'इलेक्ट्रॉनिक सहमति संरचना' का एक महत्वपूर्ण तत्व भी है जो कई विकसित देशों के खुले बैंकिंग व्यवस्थाओं में सुधार करके बनाया गया है।

जैसा कि यूपीआई ने लोगों के भुगतान करने के तरीके को बदल दिया है, अकाउंट एग्रीगेटर के पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करने वाले सभी के लिए इसे और अधिक सहज और सुलभ बनाकर क्रेडिट को बदलने की क्षमता है। जे ए एम की तिकड़ी ने एफ आई के लिए चमत्कार किया है। यूपीआई, ई-केवाईसी और ए ए की अगली तिकड़ी से कस्टमाइज्ड और समावेशी क्रेडिट सेवाओं के प्रावधान में बैंकिंग में अगली क्रांति को सक्षम करने की उम्मीद है।

ग्राहक-प्रथम विनियामक दृष्टिकोण

महामारी के दौरान डिजिटल ऋण देने में एक आदर्श बदलाव देखा गया। कोविड-19 के प्रकोप के बाद ऑनलाइन ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म/ मोबाइल ऋण देने वाले ऐप में तेजी आई थी, जिसमें एक अध्ययन[5] का अनुमान है कि कोविड महामारी के दौरान उधार देने वाले ऐप के डाउनलोड में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

उद्योग में सरलीकृत और गैर-प्रतिस्पर्धी स्थितियों के परिणामस्वरूप 1950 से 1970 के दशक तक बैंकिंग प्रथाओं की ओर इशारा करते हुए बैंकिंग में 3-6-3 नियम की बात करते थे। नियम था कि 3 फीसदी पर डिपॉजिट लिया जाए, 6 फीसदी पर कर्ज दिया जाए और दोपहर 3 बजे के बाद गोल्फ खेला जाए। हालाँकि, फिनटेक क्रांति ने इसे 2-1-0 के फॉर्मूले में बदल दिया है - निर्णय लेने के लिए 2 मिनट, मानव से मानव शून्य संपर्क के साथ धन हस्तांतरित करने के लिए 1 मिनट। सहायक तकनीकी परिवर्तनों के कारण हुए बैंकिंग व्यवसाय मॉडल में इस बदलाव ने हर संभव के दायरे का विस्तार किया है।

आरबीआई द्वारा पिछले साल स्थापित डिजिटल लेंडिंग पर वर्किंग ग्रुप ने नोट किया था कि बैंकों के मामले में भौतिक मोड की तुलना में डिजिटल मोड में उधार देना, अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है (डिजिटल मोड [6] के माध्यम से ₹1.12 लाख करोड़ रुपये की तुलना में भौतिक मोड के माध्यम से ₹53.08 लाख करोड़) जबकि, एनबीएफसी के लिए, उधार का उच्च अनुपात (डिजिटल मोड के माध्यम से ₹0.23 लाख करोड़ भौतिक मोड के माध्यम से ₹1.93 लाख करोड़) डिजिटल मोड[7] के माध्यम से

[5] फू, जोनाथन और मिश्रा, मृणाल, फिनटेक इन द टाइम ऑफ कोविड-19: टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन ड्यूरिंग क्राइसिस (28 नवंबर, 2021)। स्विस फाइनेंस इंस्टीट्यूट रिसर्च पेपर नंबर 20-38, फाइनेंशियल इंटरमीडियेशन जर्नल, आगामी, एसआरएन पर उपलब्ध: https://ssrn.com/abstract=3588453 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3588453

[6] ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप्स के जरिए कर्ज देना शामिल है

[7] https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=52589 पर उपलब्ध है।

दिया जा रहा है। हालांकि, अगर हम डिजिटल मोड के माध्यम से संवितरण की कुल मात्रा में वृद्धि देखते हैं, तो इसमें 2017 और 2020 के बीच बारह गुना की भारी वृद्धि देखी गई है। डिजिटल ऋण देने के परिदृश्य में उत्पाद वितरण के लिए अभिनव मॉडलों में तेजी से वृद्धि देखी गई है, जिसमें प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) लेनदेन-आधारित उधार, बैंक-फिनटेक साझेदारी मॉडल, बाजार ऋण और बैंक-आधारित डिजिटल मॉडल शामिल हैं। हालाँकि, अधिकांश डिजिटल ऋण, बैंक / एनबीएफसी - फिनटेक साझेदारी द्वारा दिए जा रहे हैं, जहाँ फिनटेक बैंकों / एनबीएफसी के लिए ऋण सेवा प्रदाता (एलएसपी) के रूप में कार्य कर रहे हैं।

हालाँकि, डिजिटल ऋण के विस्तार के साथ, विभिन्न चिंताएँ भी सामने आई हैं। ये मुख्य रूप से तीसरे पक्ष के बेलगाम जुड़ाव, गलत बिक्री, डेटा गोपनीयता का उल्लंघन, अनुचित व्यापार आचरण, अत्यधिक ब्याज दरों और अनैतिक वसूली प्रथाओं से संबंधित हैं। अग्रसक्रिय उपाय के रूप में, आरबीआई ने 24 जून 2020 को डिजिटल ऋण पर एक परिपत्र जारी किया, जिसमें यह सलाह दी गई थी कि डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफ़ॉर्म बैंक / एनबीएफसी के नाम का खुलासा करेंगे, जिनकी ओर से वे ऋण प्रदान कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृति पत्र संबंधित बैंक / एनबीएफसी के लेटरहेड पर है। दूसरी ओर में बैंक / एनबीएफसी उनके द्वारा नियोजित डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म की पर्याप्त निगरानी सुनिश्चित करेंगे।

डिजिटल लेंडिंग पर वर्किंग ग्रुप ने डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम से उत्पन्न होने वाली चिंताओं पर गहराई से विचार किया। डिजिटल ऋण देने के लिए हाल ही में घोषित विनियामक ढांचा आरबीआई के ग्राहक-प्रथम विनियमों के दृष्टिकोण को समाहित करता है। ढांचे को नवोन्मेषी और समावेशी प्रणाली की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, साथ ही यह सुनिश्चित किया गया है कि ग्राहक के हितों को दुष्प्रभावित करने के लिए विनियामक हस्तक्षेप का दुरुपयोग न किया जाए। इस विनियामक ढांचे का एक अन्य अंतर्निहित विषय यह है कि विनियामक दिशानिर्देशों का पालन करने का दायित्व विनियमित संस्थाओं के पास है और उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऋण सेवा प्रदाता और डिजिटल ऋण देने वाले ऐप जिनके साथ उन्होंने टाई-अप किया है, कार्य और सिद्धांत दोनो रूप में, विनियामक परितंत्र के भीतर कार्य करे।

आगे का दृष्टिकोण

वित्तीय समावेश की व्यापकता से भारत में बचत के वित्तीयकरण में वृद्धि होगी। डिजिटल मोड, जीएसटीएन, ऑनलाइन शॉपिंग, पी2पी भुगतान, क्यूआर कोड परिनियोजन और अन्य सभी चीजों को एक साथ अपनाने से ग्राहक डेटा की मात्रा उत्पन्न होगी। इस डेटा का, संभावित रूप से, ग्राहकों की जरूरतों, व्यवहार और पुनर्भुगतान क्षमता को चार्ट करने और डिजिटल समावेश में मदद करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। एक विशिष्ट क्षेत्र जहां डिजिटल लेंडिंग में आर्थिक संवृद्धि के लिए उत्प्रेरक बनने की क्षमता है, वह एमएसएमई को कैश-फ्लो आधारित लेंडिंग है। एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संवृद्धि का एक महत्वपूर्ण इंजन है क्योंकि निर्यात में वह लगभग 45 प्रतिशत योगदान करता है और 11.1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। निर्बाध और डिजिटल कैश-फ्लो आधारित उधार द्वारा एमएसएमई के लिए उचित ऋण का प्रावधान उन्हें बहुत जरूरी प्रोत्साहन प्रदान करेगा। यह उधारदाताओं को एंड-टू-एंड उधार प्रक्रिया और उत्पादों के “शैचेकरण” को पुन: तैयार करने के लिए तत्काल नकदी-प्रवाह डेटा का लाभ उठाने में मदद करेगा।

दूसरी ओर, डिजिटल लेंडिंग पर वर्किंग ग्रुप द्वारा सुझाए गए अतिरिक्त उपाय, जैसे, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी (डिजिटा)- एक स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) की स्थापना और जैसे केवल प्राधिकृत संस्थाओं को डिजिटल मोड के माध्यम से बैलेंस शीट ऋण देने की सीमा तय करने के लिए, अविनियमित जमाराशि योजना पर प्रतिबंध (बीयूडीएस) अधिनियम, 2019 की तर्ज पर अविनियमित उधार गतिविधियों पर प्रतिबंध (बीयूएलए) अधिनियम के रूप में अनुशंसित/ प्रस्तावित विधायी हस्तक्षेप, डिजिटल ऋण परितंत्र को काफी हद तक सुरक्षित और स्वस्थ बनाएगा।

निष्कर्ष

भारत जैसी तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था में विनियामक के लिए चुनौती, बाजार के नवाचारों के साथ तालमेल बनाए रखना है और बेरोक नवाचार और सुरक्षा सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करना है – जोकि एक कठिक कार्य

है। जिम्मेदार वित्तीय नवाचार के लिए वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और ग्राहक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ नये उत्पादों को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। इसलिए, डिजिटल क्रेडिट से निकलने वाले लाभों की पहचान करते हुए, हमें डेटा गोपनीयता, विघटनकारी व्यापार मॉडल, आक्रामक वसूली के तरीकों और अत्यधिक ब्याज दरों जैसे आसन्न जोखिमों का संज्ञान लेने की आवश्यकता है। एक विनियामक के रूप में, हम उद्योग/ बाजार के विकास के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण का पालन कर रहे हैं और यह डिजिटल ऋण देने के लिए एक उपयुक्त विनियामक ढांचा लाने में परिलक्षित होता है।

व्यक्तियों और फर्मों को आर्थिक अवसर उत्पन्न करने के लिए सशक्त बनाकर, डिजिटल क्रेडिट एक सतत और समावेशी संवृद्धि के लिए एक शक्तिशाली कारक हो सकता है। हमें याद रखना चाहिए कि वित्तीय समावेश केवल एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि सतत आर्थिक संवृद्धि, असमानता को कम करने और गरीबी को खत्म करने का साधन भी है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वित्तीय समावेश की पहचान 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 7 के लिए एक संबल के रूप में की गई है। सबसे पहले, डिजिटल क्रेडिट को जिम्मेदार, समावेशी और व्यवहार्य होना चाहिए और इसके लिए हर वित्तीय संस्थान को प्रयास करना चाहिए। हमेशा की तरह, आरबीआई, वित्तीय नवाचार, ग्राहकों के हितों की सुरक्षा और वित्तीय अवसंरचना को मजबूत करने के लिए एक सक्षम विनियामक परितंत्र बनाने के अपने प्रयासों को जारी रखेगा।

धन्यवाद !

*भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार - चुनौतियां और संभावनाएं**

टी. रबी शंकर

भूमिका

एक सक्रिय कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार कई कार्य करता है। उधारकर्ताओं को बैंक वित्त का विकल्प प्रदान करने के अलावा, कॉरपोरेट बॉन्ड दीर्घ अवधि के वित्त पोषण की लागत को कम कर सकते हैं। बैंक आमतौर पर दीर्घ अवधि के ऋण देने में विवश होते हैं क्योंकि उनकी देयताएं अपेक्षाकृत कम अवधि की होती हैं। कम लागत और शीघ्र निर्गमन समय वाले प्रभावशाली कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार कॉरपोरेट्स के लिए दीर्घावधि निधियों का कार्यक्षम और लागत प्रभावी स्रोत प्रदान कर सकता है। साथ ही, यह संस्थागत निवेशकों जैसे बीमा कंपनियों और भविष्य और पेंशन निधियों को दीर्घावधि वित्तीय आस्तियां ("पसंदीदा वास") प्रदान कर सकता है, जिससे उन्हें अपनी आस्ति और देयताओं की अवधि से मेल कराने में मदद मिलती है।

समष्टि-वित्तीय या वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से, एक अच्छी तरह से विकसित कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार जोखिम को बैंकिंग प्रणाली से दूर हटाने का काम करता है। वित्तीय स्थिरता के लिए बैंक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे अर्थव्यवस्था को चलनिधि सेवाएं, ऋण और भुगतान प्रणाली प्रदान करते हैं, और उनकी जोखिम लेने वाली गतिविधियों को विनियमित करना महत्वपूर्ण है। वित्त का बाजार आधारित स्रोत, जैसे कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार, निवेशकों की एक बहुत व्यापक श्रेणी में जोखिम को दूर करने में अधिक प्रभावी है, जिससे समग्र वित्तीय स्थिरता में योगदान मिलता है। यथोचित रूप से विकसित कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार वित्तीय आघातों को कम करके और वित्तीय स्थिरता को संरक्षित करके "स्पेयर टायर[1]" की भूमिका निभा सकता है।

इस पृष्ठभूमि के आलोक में सरकार, सेबी और रिज़र्व बैंक भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए ठोस प्रयास कर रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं इस अवसर का उपयोग इस बाजार के विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं, अब तक की यात्रा, जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है उन पर ध्यान केन्द्रित करने और आगे के संभावित तरीकों पर कुछ विचार साझा करने के लिए करूंगा।

विनियामकीय प्रयास

पिछले डेढ़ दशक में मोटे तौर पर कॉरपोरेट बॉन्ड बाजारों को विकसित करने के लिए किए गए प्रयास व्यापक रहे हैं। कॉरपोरेट बॉन्ड सूक्ष्म संरचना में प्रगति से लेकर एक सुविधाजनक विनियामकीय फ्रेमवर्क के विकास तक सुधार और विकास हुए हैं, जिसे संबंधित जोखिम और डेरिवेटिव बाजारों को विकसित करने के प्रयासों और द्वितीयक बाजार चलनिधि को बढ़ाने के उपायों से पूरक बनाया गया है।

कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार के प्राथमिक विनियामक सेबी ने कॉरपोरेट बॉन्ड के लिए बाजार सूक्ष्म संरचना में सुधार के लिए पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जैसे कि सुपुर्दगी बनाम भुगतान (डीवीपी) मोड के माध्यम से निपटान जो निपटान जोखिम को दूर करता है; पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक व्यापार रिपोर्टिंग मंच का परिचालन; प्राथमिक निर्गम के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्लेटफॉर्म (ईबीपी) की शुरूआत; पुनर्निर्गम के माध्यम से स्टॉक का समेकन; रिक्वेस्ट फॉर कोट (आरएफक्यू) प्लेटफॉर्म और कई अन्य। भारतीय रिज़र्व बैंक कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को विकसित करने के लिए भी उपाय कर रहा है, मसलन बैंकों को एक बड़े निवेशक आधार को प्रोत्साहित करने के लिए आंशिक ऋण वृद्धि (पीसीईई) प्रदान करने की अनुमति देना; बड़े कर्जदारों को अपनी वृद्धिशील उधारी का एक हिस्सा (लगभग 50 प्रतिशत) बाजार लिखतों के माध्यम से जुटाने की आवश्यकता; निवेश सीमा बढ़ाकर एफपीआई निवेश को प्रोत्साहित करना, स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग की शुरूआत; आदि। संस्था विनियामक के रूप में, आरबीआई, आईआरडीएआई और पीएफ़आरडीए ने

* 24 अगस्त 2022 को बॉम्बे चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मुंबई में श्री टी रबी शंकर, उप गवर्नर द्वारा दिया गया मुख्य भाषण। आरबीआई के वित्तीय बाजार विनियमन विभाग के डिंपल भांडिया, मुख्य महाप्रबंधक, जी जगन मोहन, महाप्रबंधक और ऋतुराज, सहायक महाप्रबंधक के इनपुट के लिए आभार व्यक्त किया जाता है।

[1] शब्द "स्पेयर टायर" मूल रूप से 1999 में एलन ग्रीनस्पैन, अध्यक्ष, फेडरल रिज़र्व (1999) के एक भाषण से आया था और बैंक वित्त की तुलना में संसाधन जुटाने के वैकल्पिक स्रोतों से संबंधित है।

अपने विनियमित संस्थाओं को कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

वर्तमान स्थिति

कॉरपोरेट बॉन्ड बाजारों के विकास के लिए किए गए विभिन्न उपायों और प्रयासों पर नज़र डालने के बाद, अब मैं थोड़ा समय इस दिशा में हुई प्रगति का आत्मविश्लेषण पर देना चाहूँगा।

ए. संसाधन जुटाना - प्राथमिक बाजार

कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार का बढ़ता आकार और हर वर्ष जारी होने वाली संख्या सरकार और विनियामकों के विकासात्मक प्रयासों की सफलता के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। पिछले कुछ वर्षों में, कॉरपोरेट बॉन्ड रूट के माध्यम से संसाधन जुटाने में लगातार वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2012 के अंत में कॉरपोरेट बॉन्ड का बकाया स्टॉक ₹10.51 लाख करोड़ से चार गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2022 के अंत में ₹40.20 लाख करोड़ हो गया (चार्ट 1)। इस अवधि के दौरान वार्षिक निर्गमन ₹3.80 लाख करोड़ से बढ़कर ₹6.0 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया (चार्ट 2)।

भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र में संसाधनों के प्रवाह में कॉरपोरेट बॉन्ड की हिस्सेदारी का दीर्घकालिक रुझान आश्वस्त करने वाला है। आरबीआई के भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सांख्यिकी पुस्तिका के आंकड़ों से पता चलता है कि “गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा सकल निजी स्थानन” का अनुपात - गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा कॉरपोरेट बॉन्ड जारी करने के लिए एक व्यापक परोक्षी – खाद्येतर ऋण से 2010-11 में 0.09 से बढ़कर 2020-21 में 0.50 हो गया है। (चार्ट 3)।

चार्ट 2: कॉरपोरेट बॉन्ड – निर्गमन

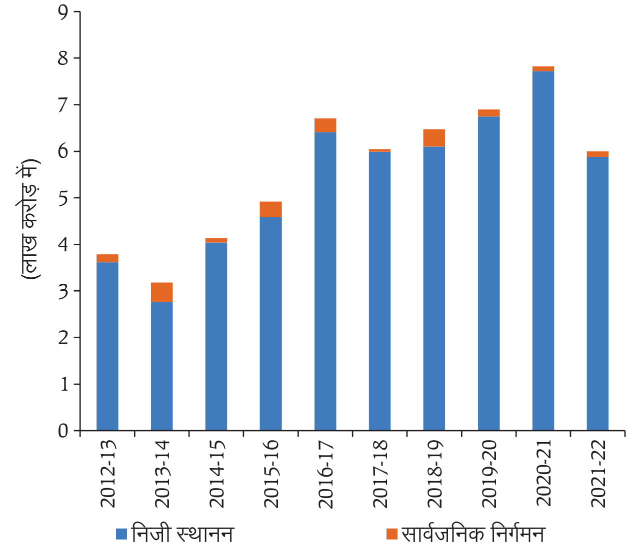

स्रोत: https://www.sebi.gov.in/statistics/corporate-bonds/publicissuedata.html

चार्ट 1: कॉरपोरेट बॉन्ड – बकाया

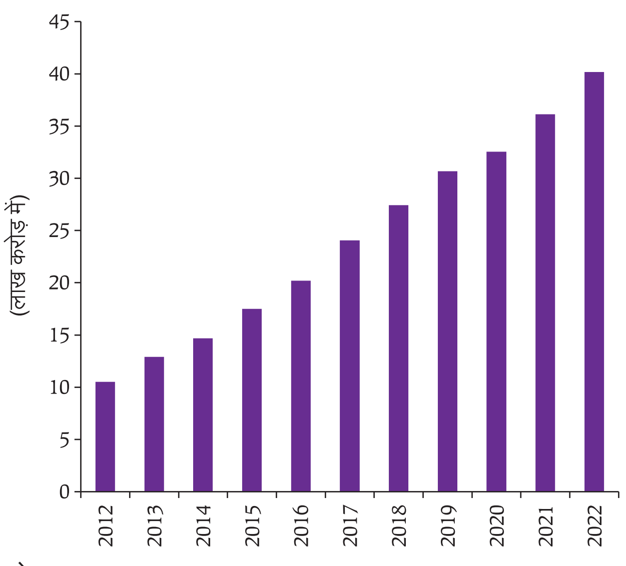

स्रोत: https://www.sebi.gov.in/statistics/corporate-bonds/outstandingcropbond.html

चार्ट 3: भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र में संसाधनों का प्रवाह

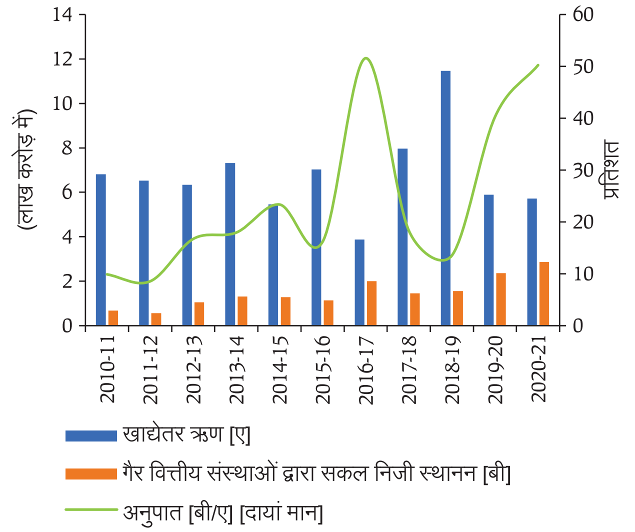

स्रोत: आरबीआई

चार्ट 4: प्रमुख एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में कॉरपोरेट बॉन्ड बकाया (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

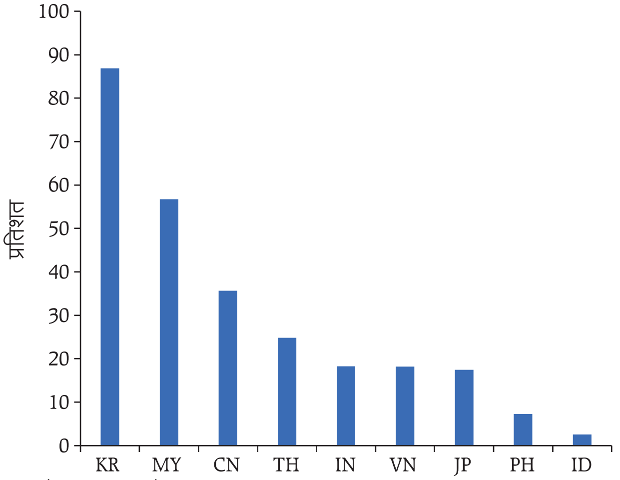

आंकड़े मार्च 2022 के अनुसार

स्रोत: https://asianbondsonline.adb.org/data-portal/ & https://www.sebi.gov.in/statistics/corporate-bonds/outstandingcropbond.html

चार्ट 5: जीडीपी की हिस्सेदारी के रूप में कॉरपोरेट बॉन्ड बकाया

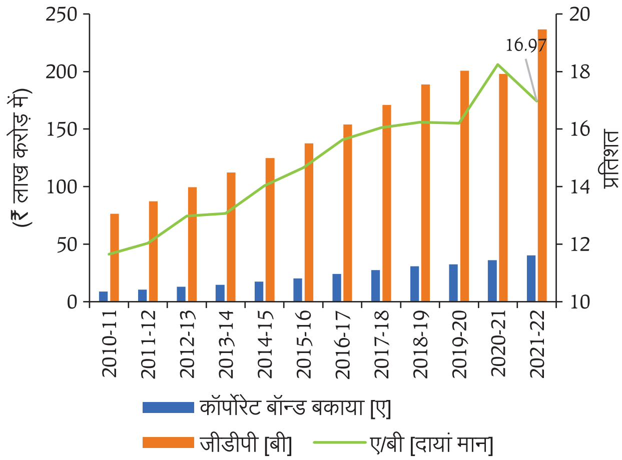

स्रोत: आरबीआई एवं सेबी

https://www.sebi.gov.in/statistics/corporate-bonds/outstandingcorpdata.html & https://www.sebi.gov.in/statistics/corporate-bonds/outstandingcropbond.html

माना जाता है कि भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार का आकार, जिसे जीडीपी द्वारा मापा गया है, अन्य प्रमुख एशियाई उभरते बाजारों जैसे मलेशिया, कोरिया और चीन की तुलना में छोटा है (चार्ट 4)। लेकिन बाजार लगातार बढ़ रहा है (चार्ट 5) और यथोचित रूप से पारंपरिक बैंक का प्रभुत्व देखने को मिला।

कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार का बढ़ता आकार निर्गमकर्ताओं और बाजारों की बढ़ती विविधता के साथ बढ़ रहा है। अब हमारे पास नए प्रकार की संस्थाओं के निर्गमन हैं, उदाहरण के लिए केंद्रीय बजट में सेबी अधिनियम, 1992, प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम, 1956 और सरफेसी अधिनियम, 2002 सहित कई अधिनियमों में बदलावों की घोषणा के अनुरूप आरईआईटी और इन्विट्स कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों के निर्गमन हेतु इन संस्थाओं के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं। नगरपालिका ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम और सूचीबद्धता संबंधी सेबी निर्गमन विनियमावली ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए बाजार आधारित वित्तपोषण की सुविधा प्रदान की है। बेशक, इस क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों को स्थापित करने के लिए और अधिक काम करने की जरूरत होगी, उदाहरण के लिए, शहर के बजट में अधिक पारदर्शिता, विश्वसनीय लेखांकन और वित्तीय विवरण, स्वतंत्र लेखापरीक्षा और निगरानी योग्य कार्य-निष्पादन मानदंड। कॉरपोरेट दिवाला प्रक्रियाओं के हिस्से के रूप में निर्गत ऋण प्रतिभूतियों सहित संकटग्रस्त कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों के लिए एक बाजार के विकास के शुरुआती संकेत भी आश्वस्त करने वाले हैं।

ऐसे अन्य कारक हैं जो देश में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार के विकास और इसकी बढ़ती सुदृढ़ता की गवाही देते हैं। एक अच्छी तरह से विकसित सरकारी प्रतिभूति बाजार कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार जैसे अन्य दर बाजारों के विकास के लिए आधार प्रदान करता है। कॉरपोरेट बॉन्ड की कीमत आमतौर पर राष्ट्रिक प्रतिफल वक्र से दूर होती है और सुदृढ़ बाजारों को सरकारी प्रतिभूतियों के बेंचमार्क प्रतिफल पर स्थिर क्रेडिट स्प्रेड की विशेषता होती है। देश में 5-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों और 5-वर्ष की अवधि के एएए रेटेड बॉन्डों की प्रतिफल की तुलना से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि सरकारी प्रतिभूतियों की प्रतिफल वक्र ने देश में कॉरपोरेट बॉन्डों के कीमत निर्धारण के लिए एक स्थिर आधार प्रदान किया है (चार्ट 6)। क्रेडिट स्प्रेड की विविधताओं में रुझान भी आश्वस्त कर रहे हैं - कीमत निर्धारण में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार की परिपक्वता की परिसाक्ष्य में, घरेलू या वैश्विक तनाव और अस्थिरता के समय में प्रसार बढ़ गया है।

चार्ट 6: 5 वर्षीय जी-सेक और 5 वर्षीय एएए बॉन्ड प्रतिफल में उतार-चढ़ाव

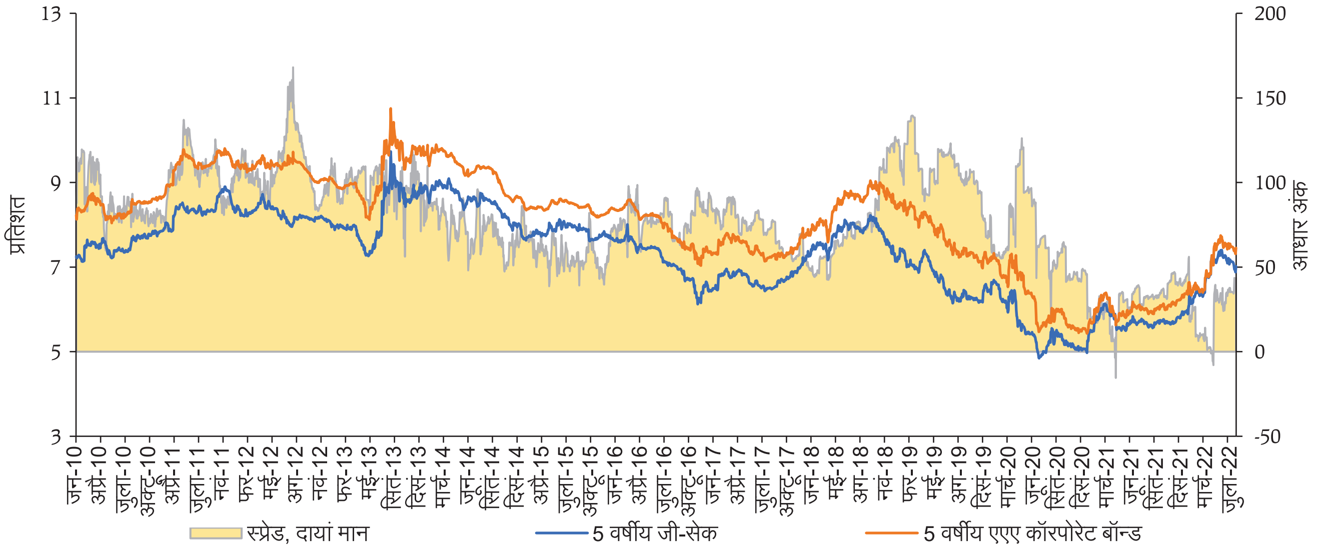

स्रोत: ब्लूमबर्ग

कॉरपोरेट बॉन्ड बाजारों के विकास और परिपक्वता के बारे में एक और आश्वस्त करने वाली प्रवृत्ति इसकी नवीनता और अनुकूलन की क्षमता रही है। इस प्रकार, जब कारोबारी फर्मों की क्रेडिट गुणवत्ता और लॉकडाउन के व्यवधानों का सामना करने की उनकी क्षमता के बारे में चिंताएं महामारी के शुरुआती दिनों में प्रभुत्वकारी विमर्श थे, तब कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार ने उन निर्गमकर्ताओं के हितों के सामंजस्य के लिए सशर्त ऋण जोखिम प्रीमियम वाले बॉन्ड को आवश्यक बना दिया जो ऋण गुणवत्ता के बारे में निवेशकों की चिंताओं के साथ प्रचलित कम ब्याज दरों को लॉक करना पसंद करते हैं। इसी तरह, जहां भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड मुख्य रूप से फिक्स्ड कूपन बॉन्ड के रूप में जारी किए जाते हैं, वहीं कैलेंडर वर्ष 2021 के दौरान, मुद्रा बाजार और सरकारी प्रतिभूतियों के बेंचमार्क से जुड़े कूपन के साथ फ्लोटिंग रेट बॉन्ड के जारी होने में वृद्धि देखी गई, जो निवेशकों द्वारा घरेलू ब्याज दरों में किसी भी वृद्धि के मुकाबले हेजिंग के प्रयासों को दर्शाता है। ये महत्वपूर्ण मेट्रिक्स हैं जो बाजार की सुदृढ़ता की गवाही देते हैं, विशेष रूप से दबाव के समय में अच्छी तरह से काम करने की क्षमता का।

बी. चलनिधि मेट्रिक्स - द्वितीयक बाजार का विकास करना

कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट के विकास का आकलन करने के लिए दूसरा महत्वपूर्ण मीट्रिक द्वितीयक बॉन्ड बाजार का विकास है। क्या द्वितीयक बाजार में व्यापार की मात्रा पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है? निस्संदेह, ये बढ़ी हैं (चार्ट 7)। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान द्वितीयक बाजार व्यापार का कुल व्यवस्थित मूल्य ₹4.50 लाख करोड़ था जो वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बढ़कर ₹14.37 लाख करोड़ हो गया। स्पष्ट रूप से, बाजार के आकार के अनुरूप द्वितीयक व्यापार नहीं बढ़ा है।

चार्ट 7: कॉरपोरेट बॉन्ड में द्वितीयक बाजार व्यापार

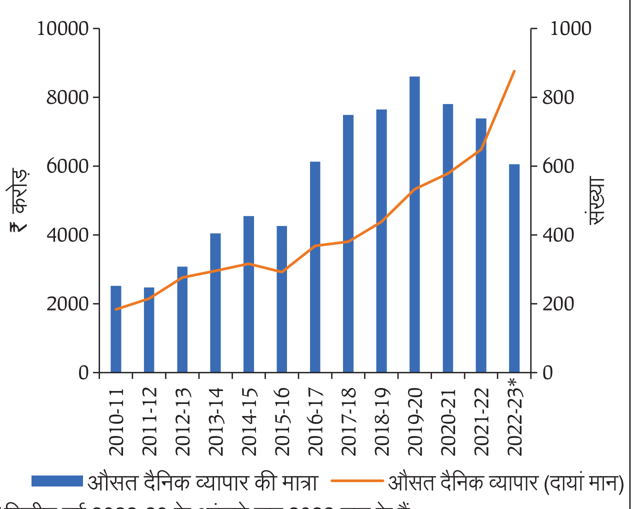

*वित्तीय वर्ष 2022-23 के आंकड़े जून 2022 तक के हैं

स्रोत: https://www.sebi.gov.in/statistics/corporate-bonds/corpbondsarchivesnew.html

लेकिन इस मामले में किसी निर्णय पर पहुँचने से पहले थोड़ा ठहरते हैं वैश्विक वित्तीय प्रणाली की बीआईएस समिति द्वारा "व्यावहारिक पूंजी बाजार की स्थापना" विषय पर 2019 की रिपोर्ट, क्षेत्राधिकारों के एक नमूना सेट के सर्वेक्षण के आधार पर, निष्कर्ष निकाला गया कि सर्वेक्षण किए गए उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (यूएस को छोड़कर) के कॉरपोरेट बॉन्ड बाजारों में चलनिधि की चिंताओं की डिग्री और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं औसतन समान थीं। इस प्रकार बॉन्ड बाजारों में चलनिधि के विकास की चुनौतियाँ स्पष्ट रूप से भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजारों के लिए अलग नहीं हैं। विभिन्न क्षेत्राधिकारों के कॉरपोरेट बॉन्ड बाजारों के टर्नओवर अनुपात पर तुलनात्मक आंकड़े आसानी से उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन अनुमानित मूल्यांकन से पता नहीं चलता है कि भारतीय कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार द्वितीयक बाजार की चलनिधि के मामले में अपने समकक्षों से पीछे है।

अंतर्निहित मुद्दों पर गौर करने करने के लिए भी मैं थोड़ा समय चाहूँगा। 30 जून 2022 तक कॉरपोरेट बॉन्ड का बकाया स्टॉक ₹39.58 लाख करोड़[2] था। बकाया लिखतों की संख्या 29,745 थी। अत: एक उत्कृष्ट कॉरपोरेट बॉन्ड लिखत का औसत आकार ₹133 करोड़ था - एक छोटी राशि जो द्वितीयक बाजार में चलनिधि के विकास के लिए अनुकूल नहीं थी। इसकी तुलना 100 लिखतों[3] में ₹84.71 लाख करोड़ के सरकारी प्रतिभूतियों के मौजूदा बकाया स्टॉक से करें। दोनों बाजारों की तुलना नहीं की जा सकती और मेरा इरादा उनकी तुलना करने का नहीं है। कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में 30 जून 2022 तक 5,394 निर्गमकर्ताओं की तुलना में सरकारी प्रतिभूति बाजार में केवल एक निर्गमकर्ता है – वह है सरकार। कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में सरकारी बॉन्ड बाजार के अनुभव को दोहराना एक यथार्थवादी उद्देश्य नहीं है। सेबी कॉरपोरेट बॉन्ड बाजारों में विखंडन को कम करने और चलनिधि में सुधार करने के लिए बाजार को फिर से निर्गम करने की दिशा में उत्तरोत्तर प्रयास कर रहा है - किसी भी वित्तीय वर्ष में परिपक्व होने वाले कॉरपोरेट बॉन्ड की संख्या को सीमित करके। बाधा यह है कि पुनर्निगम के माध्यम से समेकन के परिणामस्वरूप पुनर्भुगतान दायित्वों में शामिल रोलओवर जोखिम से निपटने के लिए जो साधन सरकार के पास है वो कॉरपोरेट को उपलब्ध नहीं हैं। द्वितीयक बाजार में सीमित गतिविधि में योगदान करने वाले अन्य कारक निवेशकों का "खरीद और धारण" स्वभाव और निजी स्थानन की प्रबलता है।

सी. पूरक बाजारों का विकास

यह विश्व स्तर पर अच्छी तरह से स्थापित है कि अच्छी तरह से काम करने वाले संबंधित बाज़ार - डेरिवेटिव और रीपो बाज़ार - निवेशकों और बाज़ार-निर्माताओं को जोखिम और निधि की स्थिति को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम बनाकर नगदी बाज़ार में चलनिधि के विकास को पूरक और संपूरक बनाते हैं।

कॉरपोरेट बॉन्ड रखने से जुड़े प्राथमिक जोखिम ब्याज दर जोखिम और क्रेडिट जोखिम हैं। ब्याज दर व्युत्पन्नी बाजार यथोचित रूप से अर्थसुलभ है, विशेष रूप से एकदिवसीय सूचकांकित स्वैप बाजार। स्वैप्शन जैसे अन्य ब्याज दर व्युत्पन्नी उत्पादों के लिए बाजार विकसित हो रहे हैं। हाल के विनियामकीय प्रयास एक ओर, अनिवासियों को घरेलू बाजार में पहुंच की अनुमति देकर, और दूसरी ओर, घरेलू बाजार निर्माताओं को अपतटीय बाजार तक पहुंच की अनुमति देकर, तटीय और अपतटीय बाजारों में सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं। ब्याज दर व्युत्पन्नी भी एक्सचेंजों पर कारोबार कर रहे हैं, हालांकि मात्रा कम है।

एक दशक से भी अधिक समय से विनियामक पहलों के बावजूद क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए बाजार का अभाव चिंता का विषय है। एक हद तक यहां मुर्गी और अंडे वाली समस्या है। टॉप रेटेड निर्गमों का प्रभुत्व क्रेडिट जोखिम को प्रबंधित करने की जरूरत को कम करता है, जबकि कम रेटिंग वाले बॉन्ड जारी करने के लिए ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) बाजार का विकास आवश्यक है। हाल के दो घटनाक्रम सीडीएस बाजार के भविष्य के विकास के लिए आशा प्रदान करते अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग अधिनियम, 2020 अधिनियम का पारित होना, जिसके अनुसार रिज़र्व बैंक ने अन्य ओटीसी डेरिवेटिव्स के साथ सीडीएस को नेटिंग के लिए अर्हित वित्तीय संविदाओं के रूप में अधिसूचित किया है। इस वर्ष फरवरी में, आरबीआई ने सीडीएस के लिए

[2] स्रोत: https://www.sebi.gov.in

[3] स्रोत: आरबीआई

निर्गमकर्ता (संरक्षण विक्रेता) और प्रतिभागी आधार का विस्तार किया, जिसमें सभी प्रमुख गैर-बैंक विनियमित संस्थाएं शामिल थी, जिनमें बैंक और विदेशी निवेशकों के अतिरिक्त प्राथमिक व्यापारी, एनबीएफसी, बीमा कंपनियां, पेंशन निधि, वैकल्पिक निवेश निधि और म्यूचुअल फंड शामिल थे।

सरकारी प्रतिभूतियों में रीपो बाजार देश के सबसे अर्थसुलभ बाजारों में से एक है। लेकिन कॉरपोरेट बॉन्ड में रीपो ने रफ्तार नहीं पकड़ी है। बाजार प्रतिक्रिया से पता चलता है कि सरकारी प्रतिभूतियों में रीपो के लिए उपलब्ध ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की कमी, केंद्रीय प्रतिपक्षकार की कमी, उच्च मार्जिन अपेक्षाओं आदि से संबंधित मुद्दों ने कॉरपोरेट बॉन्ड में रीपो के लिए बाजार के विकास को बाधित किया है। सेबी एक रीपो क्लियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना की सुविधा देने की कोशिश कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर हम देखेंगे कि यह बाजार भी विकसित होना शुरू हो जाएगा।

समस्याएं, चिंताएं और चुनौतियां

अब मैं देश में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार के कुछ सूक्ष्म-संरचना संबंधी समस्याओं की ओर आता हूं, जो चिंता पैदा करते हैं अथवा जिनसे निपटने की जरूरत है यदि बाजार को विकास के अगले स्तर तक ले जाना है और देश में संसाधन जुटाने के लिए प्रमुख अवसर के रूप में अपनी क्षमता को पूरा करना है तो।

ए. रेटिंग प्रोफ़ाइल

सबसे पहले, जैसा कि सर्वविदित है कि बाजार में उच्च रेटिंग वाले निर्गमकर्ताओं का वर्चस्व है। लेकिन आइए समस्या के आयाम पर नज़र डालते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में, ₹22.55 लाख करोड़[4] की राशि के 1,235 कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों को रेटिंग दी गई थी। इनमें से 278 या 22.5 फीसदी को एएए और 358 या 29 फीसदी को एए रेटिंग मिली थी। 66 निर्गम या 5.3 प्रतिशत निर्गम गैर-निवेश श्रेणी के थे। जहां ये संख्याएँ स्वयं उच्च रेटिंग वाले निर्गमों के पक्ष में विषम हैं, वहीं जब मूल्य के संदर्भ में देखा जाता है तो विषमता अधिक स्पष्ट होती है - मूल्य के संदर्भ में 80 प्रतिशत निर्गमों को एएए रेट किया गया था और अन्य 15 प्रतिशत को एए रेटिंग दी गई थी। जहां हम इस प्रवृत्ति के कारणों पर चर्चा कर सकते हैं, वहीं यह स्पष्ट है कि कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार काफी हद तक उच्च श्रेणी के कॉर्पोरेट्स की जरूरतों को पूरा करता है।

बी. निर्गमन का तरीका

दूसरी समस्या निर्गम के तरीके से संबंधित है। हर वर्ष कॉरपोरेट बॉन्ड जारी करने का बड़ा हिस्सा सार्वजनिक निर्गम के बजाय निजी स्थानन मार्ग के माध्यम से होता है। वित्त वर्ष 2021-22 में, कॉरपोरेट बॉन्ड के सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जुटाई गई राशि ₹11,589 करोड़ थी - निजी स्थानन के माध्यम से जुटाई गई राशि का लगभग 2 प्रतिशत ₹5.88 लाख करोड़[5] थी। कीमत निर्धारण की पारदर्शिता और दक्षता के संदर्भ में सार्वजनिक निर्गम के लाभों को अच्छी तरह से समझा जाता है। सेबी निजी स्थानन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के प्रयास कर रहा है, उदाहरण के लिए, स्टॉक एक्सचेंजों पर इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्रक्रिया की शुरुआत करके। फिर भी, निजी स्थानन के लिए भारी अधिमान है। निर्गमकर्ताओं द्वारा सार्वजनिक निर्गम प्रक्रिया से बचना पसंद करने के कारणों सहित अंतर्निहित समस्याओं पर एक कड़ी नज़र रखना शायद आवश्यक है।

सी. निवेशक प्रोफ़ाइल

तीसरा, आइए हम निवेशक आधार पर नज़र डालें। कॉरपोरेट बॉन्ड के लिए निवेशक आधार, जैसा कि उम्मीद की जा सकती है, बाजार की सूक्ष्म संरचना को देखते हुए, बड़े पैमाने पर घरेलू संस्थाओं - बीमा कंपनियों, बैंकों और म्यूचुअल फंड का प्रभुत्व है (चार्ट 8)। कॉरपोरेट बॉन्ड में खुदरा भागीदारी कम बनी हुई है - यह वास्तव में एक वैश्विक प्रवृत्ति है। भारत में जो कुछ अनोखा है वह यह है कि ऋण उन्मुख म्युचुअल फंड में निवेशक - जो कि ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से वैश्विक स्तर पर खुदरा निवेशक ऋण बाजारों में भाग लेते हैं - भी काफी हद तक संस्थागत हैं। कॉरपोरेट ऋण में विदेशी भागीदारी भी द्वितीयक बाजार गतिविधि के अनुकूल नहीं रही है।

4 स्रोत: https://www.sebi.gov.in

5 स्रोत: https://www.sebi.gov.in

चार्ट 8: बकाया कॉरपोरेट बॉन्ड में हिस्सेदारी (प्रतिशत) – वित्तीय वर्ष 2022 के अंत तक

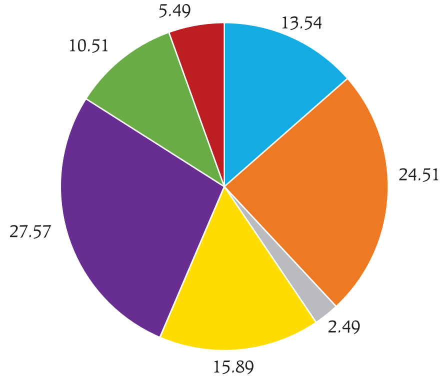

स्रोत: सेबी

कॉरपोरेट बॉन्ड बाजारों के लिए निवेशक आधार के प्रोफाइल में कुछ ऐसी समस्याओं और चिंताओं के निहितार्थ हैं, जिन्हें मैंने पहले बताया था। मैंने संसाधन जुटाने के लिए कम रेटिंग वाले निर्गमकर्ताओं की कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार तक सीमित पहुंच की बात की है। उत्तर का एक अंश उस बाजार में निवेशक आधार में निहित है जो कड़ाई से विनियमित है और शायद उचित रूप से, वहां उच्च श्रेणी के निर्गमों के लिए अधिमान है। इन संस्थाओं का आर्थिक प्रोफाइल, अधिदेश और/या विनियामकीय परिवेश अक्सर कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में "खरीद और धारण" प्रकार की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। इस प्रोफ़ाइल के साथ एक बड़े निवेशक आधार के साथ, द्वितीयक बाजार में चलनिधि विकसित करने या अर्थसुलभ रीपो और व्युत्पन्नी बाजारों को विकसित करने की चुनौतियां जटिल हैं। उदाहरण के लिए, बीमा और पेंशन निधि वैश्विक स्तर पर क्रेडिट डेरिवेटिव बाजारों के सबसे सक्रिय प्रतिभागियों में से एक हैं - संरक्षण के खरीदार और विक्रेता दोनों के रूप में। इन संस्थाओं की भागीदारी के बिना, देश में क्रेडिट डेरिवेटिव बाजार का विकास करना मुश्किल हो सकता है।

सवाल यह उठता है कि कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में कम रेटिंग वाले निर्गमकर्ताओं और चलनिधि की पहुंच बढ़ाने के लिए निवेशक आधार को बढ़ाने के लिए किन उपायों पर विचार किया जा सकता है। घरेलू इक्विटी बाजार में खुदरा निवेश में वृद्धि को देखते हुए, क्या यह श्रेणी, जो कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में अपनी अनुपस्थिति के कारण विशिष्ट है, को बाजार में निवेशक आधार को व्यापक बनाने के लिए प्रोत्साहन की पेशकश की जा सकती है? हमारे बाजारों में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या किया जा सकता है? विवेकपूर्ण सोच से समझौता किए बिना, जोखिम वाले बाजारों में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने हेतु विनियमित संस्थाओं के लिए प्रोत्साहन के माध्यम से क्या किया जा सकता है? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर सभी हितधारकों - सरकार, विनियामकों और स्वयं कॉरपोरेट बॉन्ड बाजारों के प्रतिभागियों द्वारा विचार-विमर्श की जरूरत है।

डी. विशिष्ट बॉन्ड

पिछले कुछ वर्षों में, घरेलू कॉरपोरेट्स द्वारा धन जुटाने के लिए वैश्विक बाजारों का दोहन करने के मामले बढ़ रहे हैं। काफी हद तक चलनिधि के बड़े पूल और सौम्य ब्याज दर के माहौल को देखते हुए इसकी उम्मीद की जा सकती है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित था। यह शेष विश्व के साथ घरेलू अर्थव्यवस्था के अधिक एकीकरण का एक अनिवार्य परिणाम भी है। लेकिन कुछ प्रवृत्तियां ऐसी भी हैं जिनकी गहन जांच की आवश्यकता है।

हमारे कई कॉरपोरेट्स पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) फंडिंग बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों का दोहन कर रहे हैं, जबकि घरेलू स्तर पर इस तरह के निर्गमन कम रहे हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं लेकिन शायद हमें इस बात पर बारीकी से गौर करने की जरूरत है कि ईएसजी बॉन्ड के लिए घरेलू बाजार के विकास में बाधा डालने वाले कारक क्या हैं और ईएसजी फंड के बढ़ते वैश्विक पूल को देश में आकर्षित करने के लिए क्या करने की जरूरत है। विनियामकीय उपायों से परे अंतरराष्ट्रीय अनुभव पर गौर करें तो ईएसजी बॉन्डों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने की आवश्यकता है - अधिक पारदर्शिता, ग्रीनवॉशिंग के खिलाफ विश्वसनीय जांच जिसमें स्वतंत्र लेखापरीक्षा की व्यवस्था और बाजार और बॉन्ड के लिए एक मजबूत वर्गीकरण शामिल है। इस वर्ष के केंद्रीय बजट में 'ग्रीन बॉन्ड' के माध्यम से संसाधन जुटाने की घोषणा से भी उम्मीद है कि आने वाले समय में ईएसजी बॉन्ड के लिए कीमत स्थिरक सक्षम होगा।

भारत में बैंकों द्वारा जारी पूंजी बॉन्ड के लिए सीमित निवेशक आधार है। इसके परिणामस्वरूप भारतीय बैंक पूंजी जुटाने के लिए वैश्विक बाजारों तक पहुंच बना रहे हैं। जहां कोई भी निर्गमकर्ता, बैंकों सहित, स्वाभाविक रूप से उस बाजार की तलाश करेगा जहां वे सबसे अधिक कुशलता से धन जुटा सकते हैं, वहीं ऐसे कारकों को देखने की जरूरत है जो ऐसे बॉन्डों के लिए घरेलू वहन-क्षमता को बाधित कर रहे हैं और क्या कारक अंतरराष्ट्रीय मानदंडों / मानकों के अनुरूप हैं।

ई. कीमत में पारदर्शिता

वित्तीय बाज़ारों पर उच्च-गुणवत्ता और समय पर जानकारी का महत्व बाज़ार के विकास के लिए बुनियादी है। आप में से अधिकांश इस बात से अवगत होंगे कि घरेलू सरकारी प्रतिभूति बाजार में पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को लागू करते हुए लगभग वास्तविक समय में प्रत्येक व्यापार के बारे में जानकारी प्रसारित की जाती है। कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में प्राथमिक और द्वितीयक बाजार लेनदेन संबंधी आंकड़ों की समयबद्धता और अखंडता में सुधार की आवश्यकता के बारे में बाजार सहभागियों से प्रतिक्रिया मिली है। यकीनन यह हमारे पहुंच में है जिसकी हम आकांक्षा कर सकते हैं। यह भी रेखांकित किया गया है कि सभी निवेशकों के लिए समान मूल्यांकन पद्धति अपनाने की आवश्यकता है। एक स्वतंत्र बेंचमार्क व्यवस्थापक द्वारा मूल्यांकन आदर्श होगा।

निष्कर्ष

अब मैं निष्कर्ष पर आता हूं। हमने कॉरपोरेट बॉन्ड बाजारों के विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है - बाजार बड़ा है और बढ़ रहा है; निर्गमकर्ता आधार का विस्तार हो रहा है; उत्पाद विविधता और परिष्कार में प्रगति हो रही है; द्वितीयक मात्रा कम है लेकिन बढ़ रही है; और बाजार का बुनियादी ढांचा दुनिया में सबसे अच्छा है। पूरक-रीपो और डेरिवेटिव-बाजारों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने, घरेलू और वैश्विक दोनों तरह के निवेशक आधार में विविधता लाने और क्रेडिट स्पेक्ट्रम के निचले छोर पर उधारकर्ताओं की पहुंच में सुधार करने के प्रयासों पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा, बाजार का विकास और सुधार एक सतत कार्य रहेगा। जितना हमें इन कदमों को उठाने की आवश्यकता है, उतना ही यह द्वितीयक कॉरपोरेट बॉन्ड बाजारों में चलनिधि के स्तर के संबंध में हमारी अपेक्षाओं को कम करने में हमारी मदद करेगा। यदि अंतरराष्ट्रीय अनुभव कुछ भी हो जाए, तो भी हम जो सबसे अच्छा हासिल कर सकते हैं, भले ही वह उस चलनिधि से काफी कम हो जिसका उपयोग हम सरकारी बॉन्ड बाजारों या इक्विटी बाजारों में करते हैं।

धन्यवाद।

आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति

इनपुट कीमतों के प्रति आउटपुट कीमतों की संवेदनशीलता:
भारत के लिए एक अनुभवजन्य विश्लेषण

भारतीय राज्यों में आर्थिक गतिविधि पर कोविड-19 का प्रभाव

*अर्थव्यवस्था की स्थिति**

वैश्विक आर्थिक गतिविधि में गति की हानि मुद्रास्फीति को कम कर सकती है, जो कि वर्तमान में उच्च स्तर पर बनी हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था, 2022-23 की पहली तिमाही में विकास की गति में मामूली कमी को दूर करने के लिए तैयार है। कुल मांग मजबूत है और त्योहारी सीजन के शुरू होने के साथ इसमें और बढ़ोतरी होगी। घरेलू वित्तीय स्थितियां विकास के आवेगों का समर्थन करती हैं। मुद्रास्फीति ऊपर बनी हुई है और आघात सहनीयता के स्तर से ऊपर है, जो दूसरे क्रम के प्रभावों को नियंत्रित रखने के लिए मौद्रिक नीति की आवश्यकता को क्षीण करती है और मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं को मजबूती से स्थिर रखती है।

भूमिका

हम परस्पर विरोधात्मक संभावनाओं के समय में जी रहे हैं - उच्च मुद्रास्फीति और बढ़ती मंदी के जोखिम; आर्थिक गतिहीनता और बढ़ता कर्ज; अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना और अन्य देशों की मुद्राओं को कमजोर होना; आपूर्ति शृंखला के दबाव का कम होना और रिशोरिंग होना; नीतिगत कार्रवाइयों और विवैश्वीकरण में तुल्यकालन; तुलन पत्र सामान्यीकरण और चलनिधि दबाव का होना। नतीजतन, दुनिया भर में नीति निर्माताओं को सबसे कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यह संज्ञानात्मक असंगति "एक प्रथम श्रेणी की बुद्धि की परीक्षा है, जब एक ही समय में दो विरोधी विचारों को दिमाग में रखने की क्षमता और फिर भी उन्हें कार्य करने की क्षमता बनाए रखना है।" [1]

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने अपनी नवीनतम सांख्यिकी समाचार विज्ञप्ति में कहा है कि जी 20[2] के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में पहली तिमाही में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि के बाद 2022 की दूसरी तिमाही में तिमाही-दर-तिमाही (क्यूओक्यू) गिरावट आई है। समकालिक मंदी के बजाय, हालांकि, गति में यह गिरावट देश-विशिष्ट कारकों को दर्शाता है। इस संबंध में भारत के लिए, ओईसीडी "सरकारी खर्च और निवल व्यापार में कमी"[3] को उत्तरदायी मानता है।

जैसा कि अभी हो रहा है, गतिविधि में मंदी मुद्रास्फीति को कम कर रही है - यह अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक मुद्रास्फीति जुलाई 2022 में मासिक आधार पर 0.3 प्रतिशत तक कम हो गई, जो कि पहली छमाही[4] में औसतन 0.7 प्रतिशत प्रति माह थी और अब तक जारी आंकड़ों के अनुसार, मुद्रास्फीति की गति में यह कमी अगस्त में भी विस्तारित होगी। घटती क्रय शक्ति के कारण वैश्विक मांग कमजोर होने से दो मुख्य चैनलों के माध्यम से अवस्फीति हो रही है – पण्य की कीमतों पर दबाव और वैश्विक आपूर्ति शृंखला बाधाओं में कमी। दुनिया भर में अनाज, मोटे अनाज और तेल, आहार के स्टेपल की कीमतें वापस बहुत निचले स्तर तक गिर रही हैं; जो कि युद्ध शुरू होने से पहले के देखे गए स्तर की है। वैश्विक स्तर पर आपूर्तिकर्ताओं के वितरण समय में सुधार हो रहा है और परिवहन लागत में कमी आ रही है। आपूर्ति शृंखला के दबाव को ध्यान में रखते हुए जिन खुदरा विक्रेताओं ने इनवेंटरी का स्टॉक किया था, वे स्टॉक को स्थानांतरित करने के लिए कीमतों में कटौती कर रहे हैं। भारत में भी, घरेलू आपूर्ति वितरण समय में सुधार, बैकलॉग और ट्रक भाड़े में गिरावट के कारण आपूर्ति शृंखला दबाव कम हो रहा है (चार्ट 1)।

आपूर्ति शृंखला जैसे ही सामान्य हो जाती है और मांग का झुकाव माल से सेवाओं में वापस आ जाती है तथा संतुलन समाप्त हो जाता है, तैयार माल के बड़े स्टॉक को रखना महंगा और अनावश्यक हो सकता है। आपूर्ति शृंखला दबाव में कमी के उपरांत आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन में सुधार के कारण आर्थिक गतिविधि में स्थिरता आ सकती है। यह भू-राजनीतिक शत्रुता के

* इस आलेख को डॉ. जी. वी. नथनएल, मधुरेश कुमार, कुणाल प्रियदर्शी, राजीव जैन, गरिमा वाही, रमेश कुमार गुप्ता, कौस्तुभ, पंकज कुमार, अर्जित शिवहरे, प्रशांत कुमार, इप्सिता पाढ़ी, आयुषी खंडेलवाल, लव कुमार शांडिल्य, आशीष थॉमस जॉर्ज, शैलजा भाटिया, आकाश कोवुरी, प्रियंका सचदेवा, सुप्रियो मंडल, प्रतिभा केडिया, अवनीश कुमार, युवराज कश्यप, पलक गोदारा, जॉन विजय गुरिया, साक्षी अवस्थी, राजेंद्र रघुमंदा, श्रेया भान, अरविंद कुमार श्रीवास्तव, हरेंद्र बेहरा, विनीत कुमार श्रीवास्तव, समीर रंजन बेहरा, डॉ. देब प्रसाद रथ और माइकल देबब्रत पात्र द्वारा तैयार किया गया है। इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

[1] 1936 में निबंध दि क्रैक-अप, एस्क्वायर में एफ. फिजराल्ड स्कॉट।

[2] अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, जी20 का वैश्विक जीडीपी में 80 प्रतिशत से अधिक का योगदान है।

[3] ओईसीडी स्टैटिस्टिक्स न्यूज़ रिलीज़ जी20 जीडीपी ग्रोथ, 13 सितंबर 2022, पेरिस।

[4] जेंटिवैनी, एन., (4 सितंबर 2022)। 'ए स्लोइंग चाइना हेल्प्स रेन इन इन्फ़्लटीओन अराउंड दि वर्ल्ड', डब्ल्यूएसजे: https://www.wsj.com/articles/a-slowing-china-helps-rein-in-inflation-around-the-world-11662296400

चार्ट 1: भारत के लिए आपूर्ति शृंखला दबाव सूचकांक (आईएसपीआई)

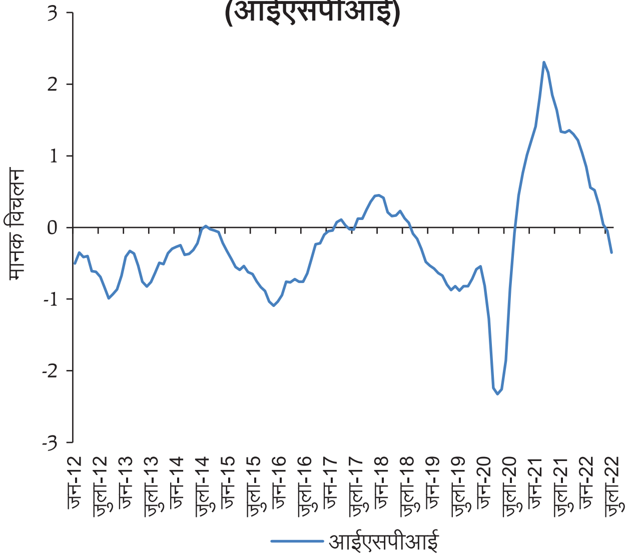

स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान

प्रकोप से पहले चल रही रिकवरी को और भी अधिक पुनर्जीवित कर सकता है। हालाँकि, यह सकारात्मक दृष्टिकोण युद्ध और महामारी पर बहुत अधिक आकस्मिक है। आयातित मुद्रास्फीति पर राहत आने वाली तिमाहियों में उपभोक्ता कीमतों के माध्यम से प्रवाहित हो सकती है, इसके बावजूद श्रम बाजार की तंगी और युद्ध से प्रेरित प्राकृतिक गैस की कीमतें विपरीत दिशा में धकेलती हैं। यह उम्मीद की जाती है कि वैश्विक मुद्रास्फीति 2022 की दूसरी छमाही में दूसरी तिमाही में 9.7 प्रतिशत से कम होकर 5 प्रतिशत की वार्षिक दर पर आ सकती है।

हालांकि ऐसे संकेत हैं कि कम मुद्रास्फीति अभिशासन की अवधि छोटी होगी। सबसे बड़े क्रेटर वे हैं जो वित्तीय बाजारों और वित्तीय स्थितियों पर वैश्विक स्पिलओवर विस्फोट सामान्य रूप से तैयार कर रहे हैं। भले ही ब्रेंट स्पॉट 90 के दशक (12 सितंबर, 2022 को यूएस $ 93 प्रति बैरल) में कम हो गया हो, ऊर्जा संकट हर गुजरते दिन और एक हल्की सर्दी के समीप आने के साथ बड़ा हो जाता है। विनिमय दरों में बड़े बदलाव से वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। जैसा कि अमेरिकी डॉलर 20 साल के उच्च स्तर को पार करता है, यह अन्य आरक्षित मुद्राओं के मूल्य को कम करता है और उभरती बाजार अर्थव्यवस्था (ईएमई) की मुद्राओं को अव्यवस्था की ओर धकेल देता है। मुद्रा मूल्यह्रास, आयातित मुद्रास्फीति, व्यापक चालू खाता असंतुलन, पूंजी बहिर्वाह, आरक्षित हानि और वित्तीय अस्थिरता के संबंध में प्रत्येक देश अपने आप पर निर्भर हैं। 50 साल पहले अमेरिकी कोशागार सचिव जॉन कोनली के शब्द गूंजने लगते हैं: "डॉलर हमारी मुद्रा है लेकिन यह आपकी समस्या है"।[5] इस बीच, जैसे ही इस महीने से फेड के खजाना धारिता अपवाह की गति दोगुनी हो जाती है, अमेरिकी डॉलर की चलनिधि हर जगह बाजारों से बाहर हो जाती है, जबकि इक्विटी और बांड एक बंधन में जकड़ लिए जाते हैं। फेडस्पीक द्वारा प्रसारित स्पिलओवर शायद वैश्विक अर्थव्यवस्था की बाधित रिकवरी के साथ तालमेल के लिए सबसे बड़ा जोखिम है।

भारत की ओर मुड़ते हुए, अर्थव्यवस्था उड़ान भरने के लिए तैयार है और यह आईएनएस विक्रांत के रूप में सबसे अच्छा उदाहरण है, जो 2 सितंबर को समुद्र में उतरने वाला भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है और जो भारत को दुनिया की महान समुद्री शक्तियों के एक चुनिंदा क्लब में शामिल कर रहा है। महीने के दौरान, भारत ने सेमी-कंडक्टर और डिस्प्ले फैब के लिए विनिर्माण हब बनने की दिशा में अनेक कदम उठाए। इन रणनीतिक मध्यवर्ती क्षेत्रों में भविष्य में आपूर्ति शृंखला व्यवधानों के लिए आत्मनिर्भरता और प्रतिरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा, यह नौकरी के अवसर और निवेश के लिए नए अवसर प्रदान करेगा। बंदरगाहों पर माल आना शुरू हो गया है।

इन घटनाक्रमों के अंतर्गत, ऐसे संकेत हैं कि अर्थव्यवस्था सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की गति में मामूली कमी को दूर कर रही है जो कि वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही की विशेषता है। यह सकल आपूर्ति स्थितियों में सबसे अधिक स्पष्ट है। मानसून के देर से पुनः आगमन और कम क्षेत्रों में प्रसार तथा देरी से वापसी की भविष्यवाणी के कारण, खरीफ की बुवाई पिछले साल के रकबे से अधिक होना तय है। यहां तक कि धान और दलहन भी तेजी से रफ्तार पकड़ रहे हैं। जलाशय का स्तर रबी की संभावनाओं को बफर प्रदान करेगा। इसलिए, 2022-23 के लिए पिछले वर्ष के उत्पादन से केवल 4 प्रतिशत अधिक 328 मिलियन टन का खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य महत्वपूर्ण सीमा में प्रतीत होता है। जुलाई 2022 में औद्योगिक उत्पादन की गति ऋणात्मक हो गई, लेकिन यह 7 महीने की निरंतर वृद्धि के बाद हुई थी। अगस्त के लिए, विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) बेहतर स्थिति में बना हुआ है, जैसा कि घरेलू विकास के क्षेत्र में इसका प्रभाव

[5] जी10 बैठक, रोम, 1971।

पड़ेगा। सेवाएँ आगे की ओर अग्रसर हैं और सेवाओं के लिए व्यावसायिक अपेक्षा सूचकांक 51 महीने के उच्च स्तर पर था। यात्री वाहनों की बिक्री, तेजी से बढ़ रही उपभोक्ता वस्तुओं और संपत्ति, तथा वस्तुओं और लोगों की आवाजाही से पता चलता है कि सकल मांग मजबूत है और त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ ही इसमें और विस्तार होने की उम्मीद है।

घरेलू वित्तीय स्थितियाँ एक ऐसा वातावरण उत्पन्न कर रही हैं जिसमें विकास के आवेगों को पोषित और मजबूत किया जा सकता है। विदेशी पोर्टफोलियो प्रवाह वापस आने से इक्विटी बाजारों को अपनी स्थिति वापस मिल रही है, जुलाई में हल्की वृद्धि वाली धारा अगस्त और सितंबर में बाढ़ में बदल गई है। वैश्विक रुझान को तोड़ते हुए बॉण्ड प्रतिफल में नरमी आई है और यह चारों ओर अनुकूल उधार लागत की स्थिति पैदा कर रहा है। भारत में वित्त के प्रमुख स्रोत के रूप में अपना स्थान फिर से हासिल करने के लिए बैंक ऋण हर पखवाड़े तेज हो रहा है, यहां तक कि आधार प्रभावों के लिए समायोजन भी कर रहा है। इसकी प्रतिक्रिया में, बैंक एकमुश्त जमा जुटा रहे हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के पास शेष राशि और गैर-एसएलआर लिखतों में अपने निवेश को कम कर रहे हैं। बैंकिंग प्रणाली में जमा दरों में वृद्धि के साथ खुदरा जमाराशियों को गति मिल रही है। डॉलर की चलनिधि की पर्याप्त आपूर्ति के साथ भारतीय रुपया (आईएनआर) मुद्रा बाजारों में अपना स्थान बनाए हुए है; वास्तव में, भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार को इस क्षेत्र में सबसे अधिक चल माना जाता है और विदेशी निवेशकों द्वारा सक्रिय रूप से पड़ोसी देशों में धारित आस्तियों का उपयोग किया जाता है।

विनिमय दरों पर, यह ध्यान देने योग्य है कि वित्त वर्ष 2022 में यूएस $ 3.5 ट्रिलियन के सकल घरेलू उत्पाद के साथ भारत के पास पांचवां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है और 6वें स्थान से ऊपर उठकर यह अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसलिए, प्रबंध निदेशक, आईएमएफ के बयान से कोई असहमत नहीं हो सकता है कि वैश्विक अनिश्चितता और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक उज्ज्वल स्थान बना हुआ है।

इस पृष्ठभूमि के साथ, लेख के शेष भाग को चार खंडों में संरचित किया गया है। खंड II वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से विकसित हो रहे विकास को दर्शाता है। खंड III में घरेलू व्यापक आर्थिक स्थितियों का आकलन प्रस्तुत किया गया है। खंड IV भारत में वित्तीय स्थितियों की समीक्षा करता है, जबकि अंतिम खंड लेख का निष्कर्ष प्रस्तुत करता है।

II. वैश्विक स्थिति

वैश्विक आर्थिक गतिविधि ने 2022 की दूसरी तिमाही में गति में कमी का अनुभव किया, क्योंकि दृष्टिकोण में नकारात्मक स्थिति के कारण अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं ने संकुचन या मंदी का प्रदर्शन किया। यह अगस्त 2022 तक लगातार 13 महीनों के लिए ओईसीडी देशों के लिए संयुक्त प्रमुख संकेतक (सीएलआई) में क्रमिक गिरावट में परिलक्षित हुआ (चार्ट 2)। समकालिक और आक्रामक मौद्रिक सख्ती, भू-राजनीतिक दबावों से बनी अनिश्चितता, निरंतर आपूर्ति शृंखला व्यवधान और बहु-दशकीय उच्च मुद्रास्फीति विकास के लिए प्रमुख बाधाएँ थीं। बाद में गिरावट अधिक स्पष्ट होने के साथ व्यावसायिक स्थिति और उपभोक्ता विश्वास दोनों बिगड़ गए।

हमारे मॉडल आधारित तात्कालिक अनुमान से पता चलता है कि 2022 की दूसरी तिमाही में वैश्विक जीडीपी में कमी आई है, और इसे 2022 की तीसरी तिमाही (चार्ट 3) में भी जारी रहने की संभावना है।[6]

चार्ट 2: ओईसीडी देशों में आर्थिक गतिविधियों के अग्रणी संसूचक

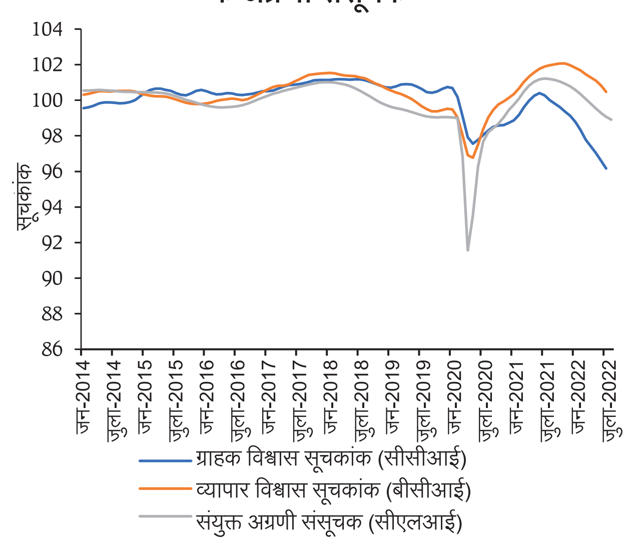

स्रोत: ओईसीडी (12 सितंबर 2022 के अनुसार)

[6] 2022 की पहली तिमाही तक 45 देशों के मुकाबले, 2022 की दूसरी तिमाही के लिए अब तक ओईसीडी द्वारा संकलित जीडीपी शृंखला 35 देशों के लिए उपलब्ध है।

चार्ट 3: वैश्विक जीडीपी तात्कालिक अनुमान

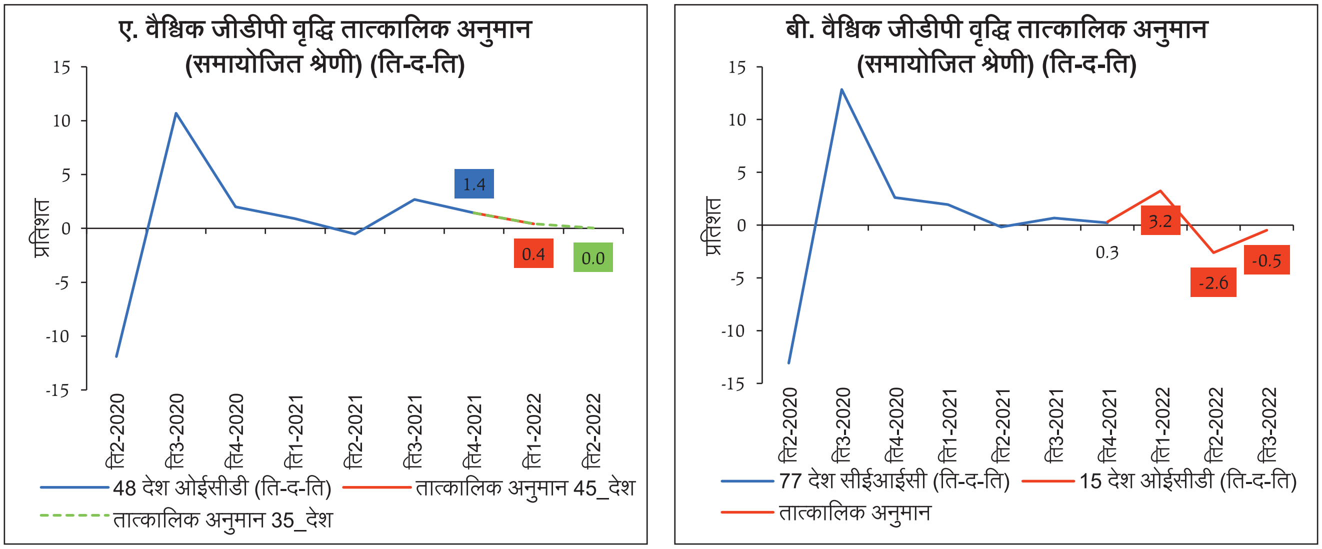

स्रोत: आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

उच्च आवृत्ति संकेतकों के बीच, वैश्विक विनिर्माण पीएमआई जुलाई में 51.1 से अगस्त में 50.3 के 26 महीने के निचले स्तर पर गिर गया, क्योंकि नए क्रयादेश और वैश्विक विनिर्माण उत्पादन कम हो गए, जबकि तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि हुई। यूएस, यूरो क्षेत्र, जापान और यूके सहित उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में आउटपुट में कमी आई, जबकि चीन, ब्राजील, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में धीमी वृद्धि देखी गई। जून 2020 के बाद पहली बार वैश्विक संयुक्त क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) जुलाई में 50.8 से घटकर अगस्त में 49.3 हो गया, साथ ही सेवाएं सूचकांक (चार्ट 4) में भी कमी आई। क्षेत्रवार, पीएमआई उपभोक्ता, मध्यवर्ती और निवेश वस्तुओं में गिरावट आई है।

अगस्त में जारी, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) द्वारा संकलित माल व्यापार बैरोमीटर में लेकिन वर्ष के शेष अवधि के लिए कमजोर दृष्टिकोण के विपरीत ऑन-ट्रेंड व्यापार विस्तार का संकेत दिया गया है । प्रतिकूल आधार प्रभाव और कमजोर गति (चार्ट 5ए) के संयोजन के कारण विश्व पण्य व्यापार मात्रा वृद्धि मई में 5.8 प्रतिशत से घटकर जून 2022 में 5.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई। संयोग से, जहाजों की घटती मांग के कारण बाल्टिक ड्राई इंडेक्स - सूखी थोक वस्तुओं के लिए शिपिंग शुल्क का एक माप - अगस्त में 49.1 प्रतिशत तक गिरकर 2 वर्षों में अपने न्यूनतम स्तर पर आ गया (चार्ट 5बी)। पीएमआई उप-सूचकांक लगातार छठे महीने नए निर्यात कारोबार की मात्रा में गिरावट और अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रवाह में कमी का संकेत देते हैं। केवल भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अगस्त में विदेशी मांग में सुधार देखा।

जून में ऐतिहासिक ऊंचाई से गिरने के बाद वैश्विक पण्य कीमतें अस्थिर रहीं। जुलाई के अंत में - अगस्त की शुरुआत में कीमतों में वृद्धि हुई, महीने के अंत में कम होने से पहले, मुख्य रूप से मांग में कमी (चार्ट 6ए) की चिंताओं से प्रेरित थी। वैश्विक मांग

चार्ट 4: वैश्विक पीएमआई

स्रोत: आईएचएस मार्किट।

चार्ट 5: विश्व व्यापार और शिपिंग लागत

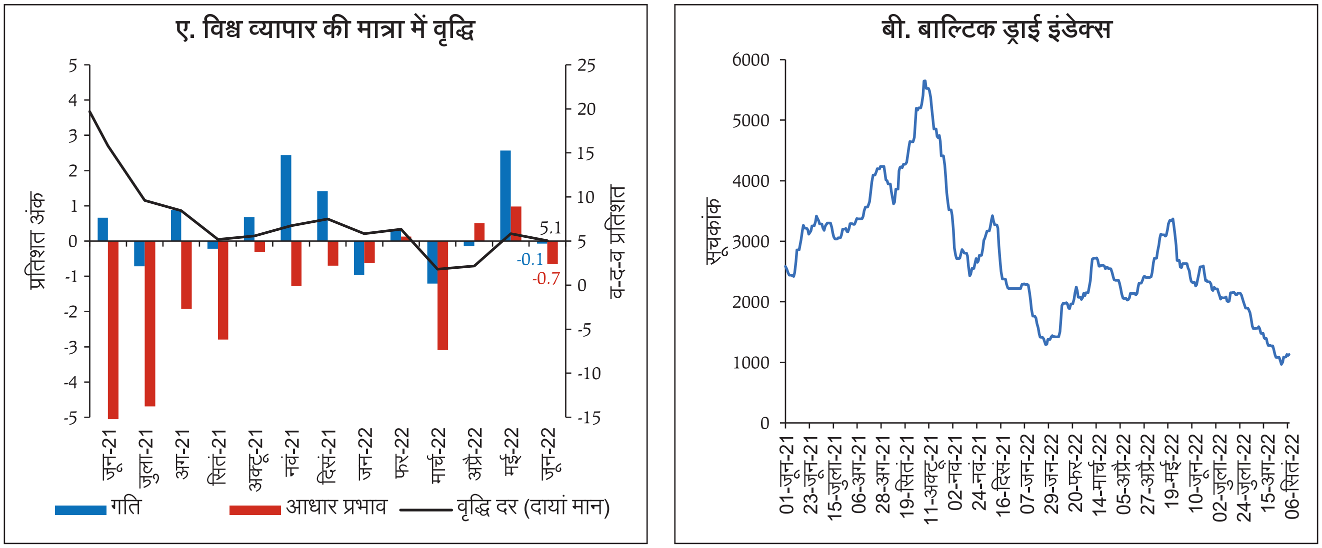

स्रोत: सीपीबी नीदरलैंड; और ब्लूमबर्ग।

में आसन्न मंदी की आशंकाओं के कारण कच्चे तेल की कीमतें 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से नीचे कारोबार कर रही हैं। फरवरी के बाद पहली बार 7 सितंबर को ब्रेंट क्रूड की कीमतें 90 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के प्रमुख समर्थन स्तर से नीचे तक आ

चार्ट 6: पण्य वस्तु और खाद्यान्न कीमतें

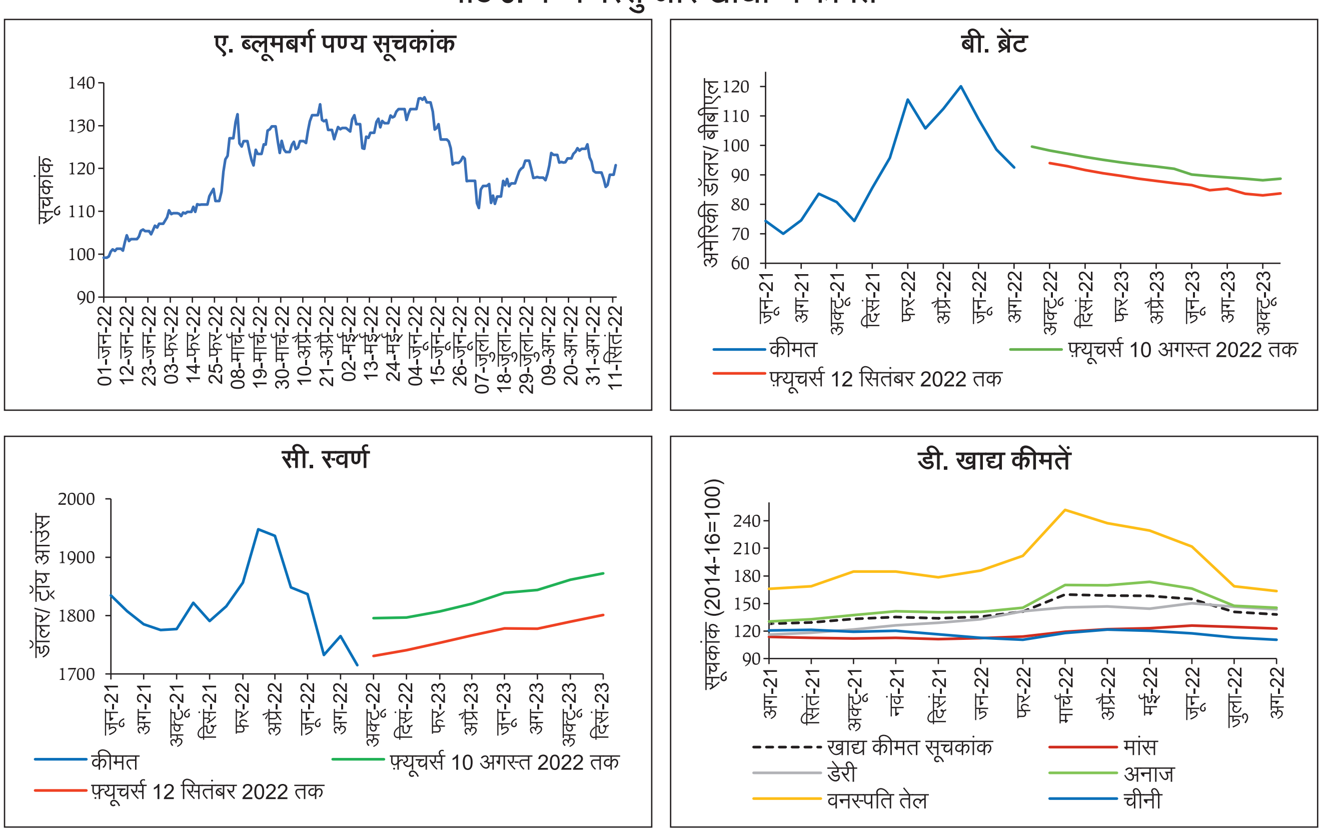

स्रोत: ब्लूमबर्ग; विश्व बैंक पिंक शीट; और एफएओ।

गईं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) के उत्पादन में प्रति दिन 1,00,000 बैरल प्रति दिन की कटौती के निर्णय ने आपूर्ति संबंधी चिंताओं को फिर से जन्म दिया। कच्चे तेल की कीमतों में वर्ष दर वर्ष (14 सितंबर, 2022 तक) 21.5 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई है (चार्ट 6बी)।

सोने की कीमतों में अगस्त की शुरुआत में बढ़ी गति में गिरावट हुई और अगस्त की दूसरी छमाही में अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने तथा यूएस 10-वर्षीय जी-सेक प्रतिफल (चार्ट 6 सी) में वृद्धि के कारण यह 4 प्रतिशत तक कम हो गई। एफएओ खाद्य मूल्य सूचकांक में लगातार पांचवीं मासिक गिरावट दर्ज की गई क्योंकि यह अगस्त 2022 में 1.9 प्रतिशत गिर गया, जो इसके सभी पांच उप-सूचकांकों[7] (चार्ट 6 डी) में गिरावट के रूप में देखा गया।

मुद्रास्फीति एई और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) दोनों में लक्ष्य/आघात सहनीयता स्तर से काफी ऊपर रही, जो ऊर्जा और खाद्य कीमतों से प्रेरित थी (चार्ट 7)। यूएस हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति (वर्ष दर वर्ष) जुलाई में 8.5 प्रतिशत से घटकर अगस्त 2022 में 8.3 प्रतिशत हो गई, जबकि कोर सीपीआई अगस्त में 6.3 प्रतिशत पर पहुंच गई। व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) मूल्य सूचकांक के रूप में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन के आधार पर मापी गई अमेरिका में मुद्रास्फीति जून में -0.1 प्रतिशत की मासिक गति के साथ जुलाई 2022 में 6.3 प्रतिशत पर आ गई, क्योंकि ऊर्जा की कीमतों में 4.8 प्रतिशत की कमी आई (माह-दर माह), जबकि खाद्य कीमतों में 1.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जुलाई 2022 में कोर पीसीई मुद्रास्फीति भी घटकर 4.6 प्रतिशत हो गई, जो एक महीने पहले 4.8 प्रतिशत थी, क्योंकि 0.1 प्रतिशत की मासिक गति अनुकूल आधार प्रभाव के कारण छिपी हुई थी।

चार्ट 7: मुद्रास्फीति

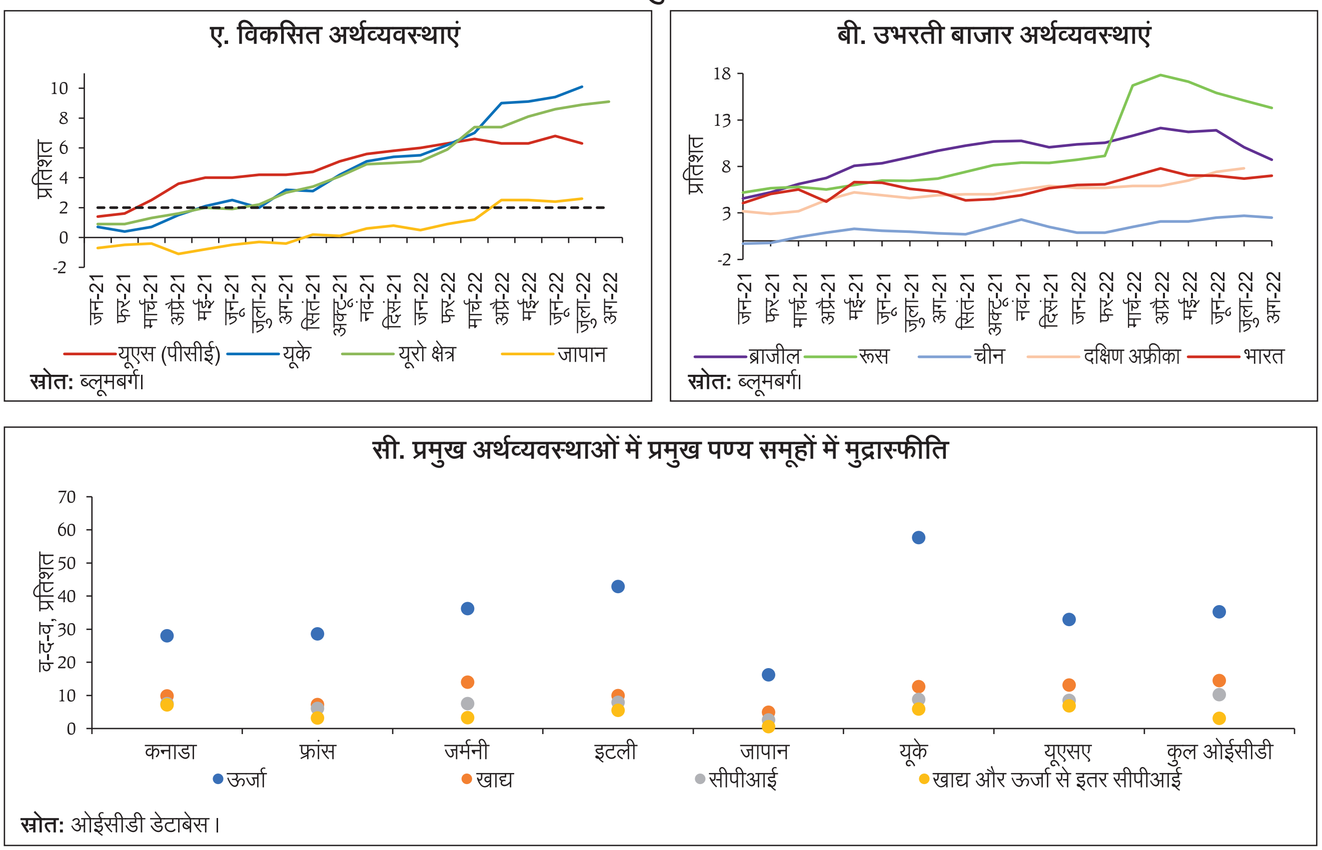

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

स्रोत: ओईसीडी डेटाबेस।

7 मांस, डेयरी, अनाज, वनस्पति तेल और चीनी के लिए उप-सूचकांकों से एफएओ खाद्य मूल्य सूचकांक बना है।

दूसरी ओर, यूरो क्षेत्र की वार्षिक मुद्रास्फीति अगस्त में 9.1 प्रतिशत के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो मुख्य रूप से भोजन, शराब और तंबाकू के बाद उच्च ऊर्जा कीमतों से प्रेरित थी। ब्रिटेन में सीपीआई मुद्रास्फीति अगस्त 2022 में घटकर 9.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई, जो जुलाई में अपने दो अंकों के उच्चतम स्तर से मोटर ईंधन की कीमतों में कमी के कारण थी।

ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं में, ब्राजील में मुद्रास्फीति जुलाई में 10.1 प्रतिशत से घटकर अगस्त में 8.7 प्रतिशत हो गई, जबकि चीन में यह घटकर 2.5 प्रतिशत हो गई (चार्ट 7बी)। रूस में, जुलाई में मुद्रास्फीति 15.1 प्रतिशत से अगस्त में और घटकर 14.3 प्रतिशत हो गई।

वैश्विक इक्विटी बाजार, जो मध्य जून से अगस्त की शुरुआत तक ऊपर की ओर थे, अगस्त के दूसरे पखवाड़े में नीचे की ओर बढ़ने लगे। एमएससीआई विश्व इक्विटी सूचकांक ने अपने लाभ को वापस हासिल कर लिया, जो जुलाई की तुलना में 3.9 प्रतिशत कम था। यह गिरावट मुख्य रूप से एई उप-सूचकांक द्वारा संचालित थी, जबकि उभरते बाजार के इक्विटी पिछले महीने (चार्ट 8ए) के स्तर पर बने रहने में सफल रहे।

बांड बाजार में, प्रमुख एई में 10-वर्षीय जी-सेक प्रतिफल सख्त हुआ है, जो केंद्रीय बैंकों के आक्रामक रुख को दर्शाता है क्योंकि मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है। अगस्त में 10-वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल में 54 आधार अंकों की वृद्धि हुई, जबकि 2-वर्षीय जी-सेक प्रतिफल में 61 बीपीएस की वृद्धि हुई, इस प्रकार इन दोनों के बीच के अंतर को बढ़ाया और एक तेज उल्टे प्रतिफल वक्र (चार्ट 8बी) की ओर अग्रसर हुआ। अमेरिकी डॉलर ने फेडरल रिज़र्व के हाकिश टोन और सेफ हेवन मांग के कारण अगस्त और सितंबर की शुरुआत में अपनी गति जारी रखी। समवर्ती रूप से, ईएमई के लिए एमएससीआई मुद्रा सूचकांक अगस्त और सितंबर की शुरुआत में ईएमई से इक्विटी और ऋण बहिर्प्रवाह के कारण नीचे गिरा है (चार्ट 8सी और 8डी)।

अधिकांश एई और ईएमई के केंद्रीय बैंकों ने मुद्रास्फीति को कम करने के लिए आक्रामक रूप से मौद्रिक सख्ती की है। यूरोपीय

चार्ट 8: वित्तीय बाजार

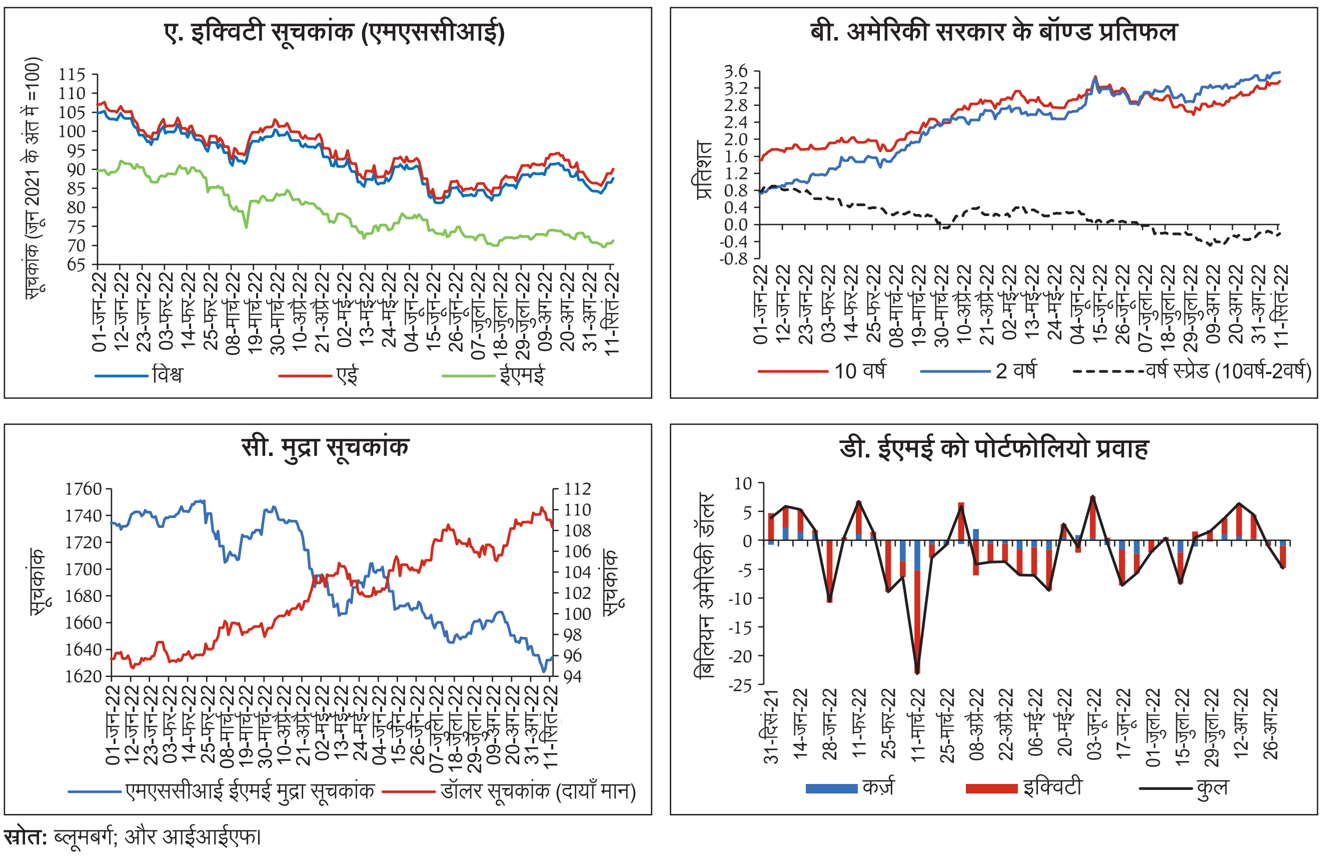

स्रोत: ब्लूमबर्ग; और आईआईएफ।

चार्ट 9: समकालिक नीतिगत सख्ती

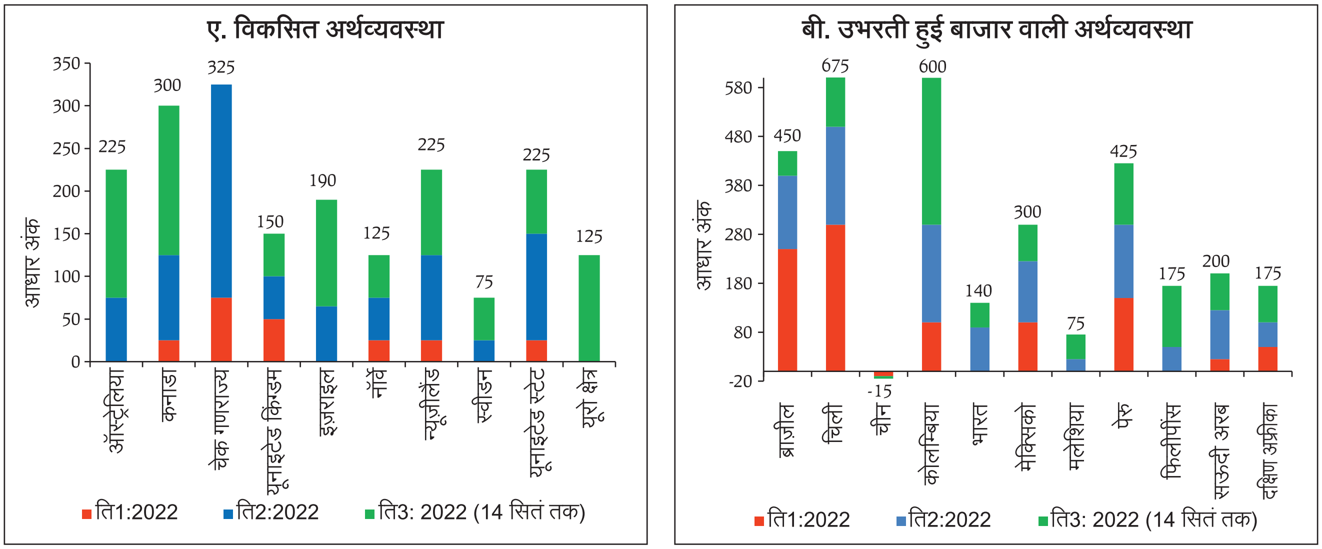

स्रोत: बीआईएस।

केंद्रीय बैंक (ईसीबी) ने अपनी नीतिगत दर में रिकॉर्ड 75 बीपीएस की बढ़ोतरी की है, जो एकबारगी उपाय के रूप में है और मांग को कम करने और मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं में लगातार ऊपर की ओर बदलाव के जोखिम से बचाव के लिए आगे भी दर में वृद्धि का संकेत दिया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अगस्त में अपनी नीति दर में 50 बीपीएस की वृद्धि की और सितंबर की बैठक के बाद गिल्ट की बिक्री शुरू होने का संकेत दिया। लगातार मुद्रास्फीति, विशेष रूप से मुख्य मुद्रास्फीति पर सितंबर में बैंक ऑफ कनाडा ने भी 75 बीपीएस की बढ़ोतरी की। बढ़ती मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया ने सितंबर में अपनी नकद दर में 50 बीपीएस की वृद्धि की। इज़राइल और आइसलैंड ने अपनी नीति दर में 75 बीपीएस की वृद्धि की जबकि न्यूज़ीलैंड और नॉर्वे ने अगस्त में 50 बीपीएस की वृद्धि की। हालाँकि, जापान ने उदार रुख बनाए रखते हुए प्रवृत्ति को कम करना जारी रखा।

अधिकांश ईएमई केंद्रीय बैंकों ने भी नीति को सख्त करना जारी रखा है (चार्ट 9)। इंडोनेशिया ने 25 बीपीएस की वृद्धि के साथ नीति को सख्त करने का मार्ग शुरू किया, जो कि 2018 के बाद पहली वृद्धि हुई। तुर्की ने अपनी दर में 100 बीपीएस की कटौती करके खुद को इससे बाहर ही रखा । चीन ने अगस्त में 1 साल के लोन प्राइम रेट (एलपीआर) को 5 बीपीएस और बंधक के मूल्य निर्धारण के लिए 5 साल के एलपीआर बेंचमार्क को 15 बीपीएस घटाकर अपनी मौद्रिक नीति सहजता चक्र को जारी रखा।

III. घरेलू विकास

वैश्विक विपरीत परिस्थितियों के कारण गति में कुछ कमी के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2022-23 में सुधार के पथ पर चलना जारी रखा। हमारा आर्थिक गतिविधि सूचकांक जो 15 उच्च आवृत्ति संकेतकों के साथ एक गतिशील कारक मॉडल (डीएफ़एम) का प्रयोग करता है, मई से जुलाई (चार्ट 10) के दौरान सीमाबद्ध प्रदर्शन को दर्शाता है। वैकल्पिक मॉडल विशिष्टताओं के अनुसार, 2022-23 की दूसरी तिमाही के लिए सकल घरेलू

चार्ट 10: गतिविधि सूचकांक (डीएफ-15)

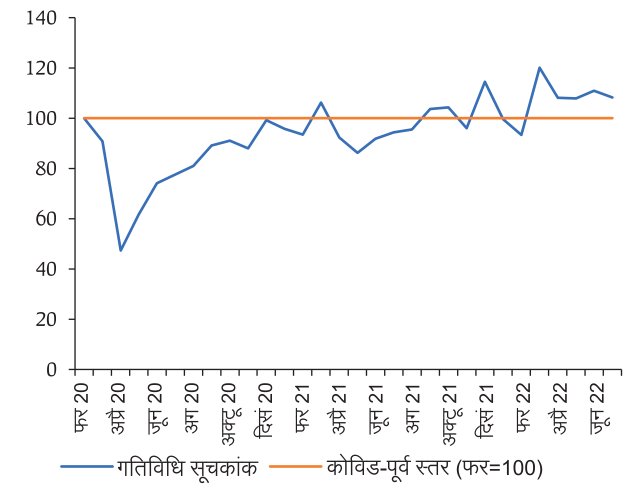

टिप्पणी: गतिविधि सूचकांक (एक्टिविटी इंडेक्स) का निर्माण डायनेमिक फैक्टर मॉडल (डीएफएम) का उपयोग करके आर्थिक गतिविधि के सावधानी से चयनित उच्च आवृत्ति संकेतकों के समूह में अंतर्निहित सामान्य प्रवृत्ति को निकालकर किया गया है।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

चार्ट 11: जीडीपी - वास्तविक और तात्कालिक अनुमान

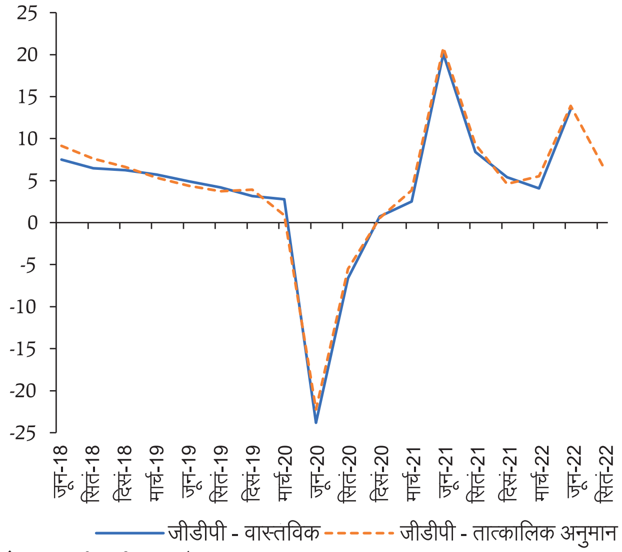

स्रोत: आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

उत्पाद की वृद्धि का तात्कालिक अनुमान 6.8 प्रतिशत है (चार्ट 11)। 30 सितंबर, 2022 के एमपीसी संकल्प में सूचनाओं और संकेतकों के व्यापक सेट के साथ दूसरी तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद का पूर्ण मूल्यांकन प्रस्तुत किया जाएगा।

सकल मांग

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी तिमाही अनुमानों से पता चला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने अनुकूल आधार प्रभाव (चार्ट 12) की सहायता से 2022-23 की पहली तिमाही में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। जून 2022 तक, जीडीपी अपने महामारी-पूर्व स्तर (2019-20 की पहली तिमाही) से 3.8 प्रतिशत अधिक था। 2022-23 की पहली तिमाही में 25.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज वाला निजी उपभोग इसके लिए प्रमुख संवाहक था। अवसंरचना पर सरकार के जोर से उत्साहित, सकल निश्चित पूंजी निर्माण (जीएफ़सीएफ़) ने 2022-23 की पहली तिमाही में 20.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। यह आसन्न समकालीन संकेतकों - स्टील की खपत; सीमेंट उत्पादन; और पूंजीगत वस्तुओं के आयात में तेजी के रूप में भी परिलक्षित हुआ था। निर्यात की तुलना में आयात में वृद्धि के कारण निवल निर्यात ने 2022-23 की पहली तिमाही में ऋणात्मक योगदान दिया।

भारतीय कंपनियों, सूचीबद्ध गैर-वित्तीय निजी और सरकारी कंपनियों की बिक्री वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) 2022-23 की पहली तिमाही में क्रमशः 41.0 प्रतिशत और 73.6 प्रतिशत बढ़ी। यहां तक कि मुद्रास्फीति के लिए समायोजित, बिक्री वृद्धि उच्च दोहरे अंकों में रही। कच्चे माल सहित उत्पादन की परिवर्तनीय लागत में चौतरफा वृद्धि के कारण सरकारी और निजी दोनों कंपनियों के परिचालन लाभ मार्जिन में कुछ दबाव आया है (चार्ट 13)। वैश्विक

चार्ट 12: जीडीपी वृद्धि में भारित योगदान

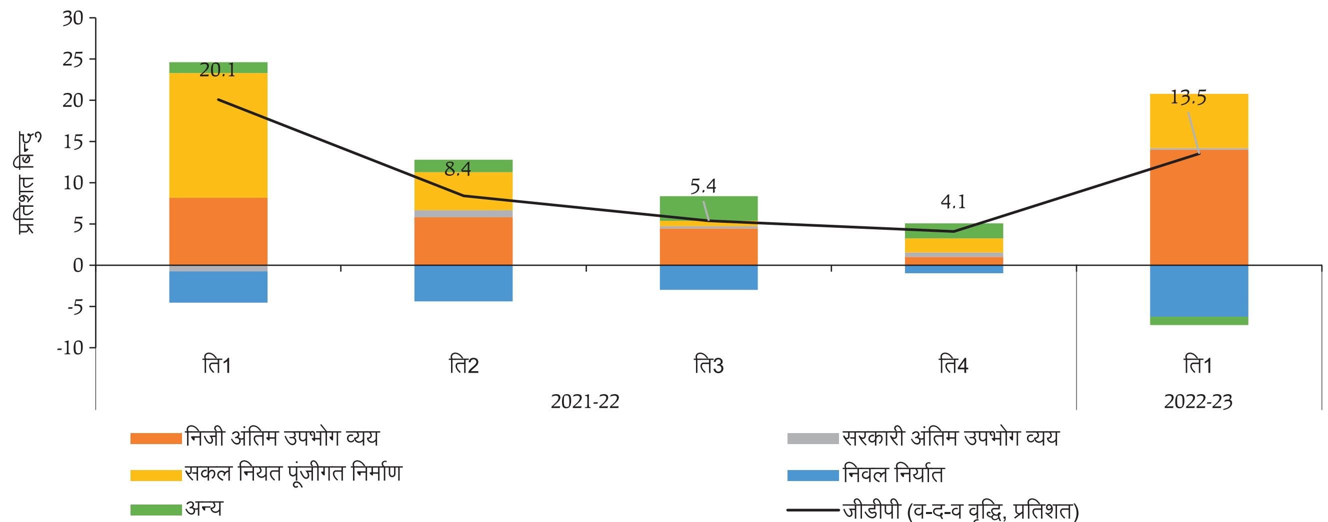

टिप्पणी: अन्य में स्टॉक, कीमती सामान और सांख्यिकीय विसंगतियों में परिवर्तन शामिल हैं।
स्रोत: एनएसओ।

चार्ट 13: सूचीबद्ध गैर-वित्तीय कंपनियाँ – परिचालन लाभ मार्जिन

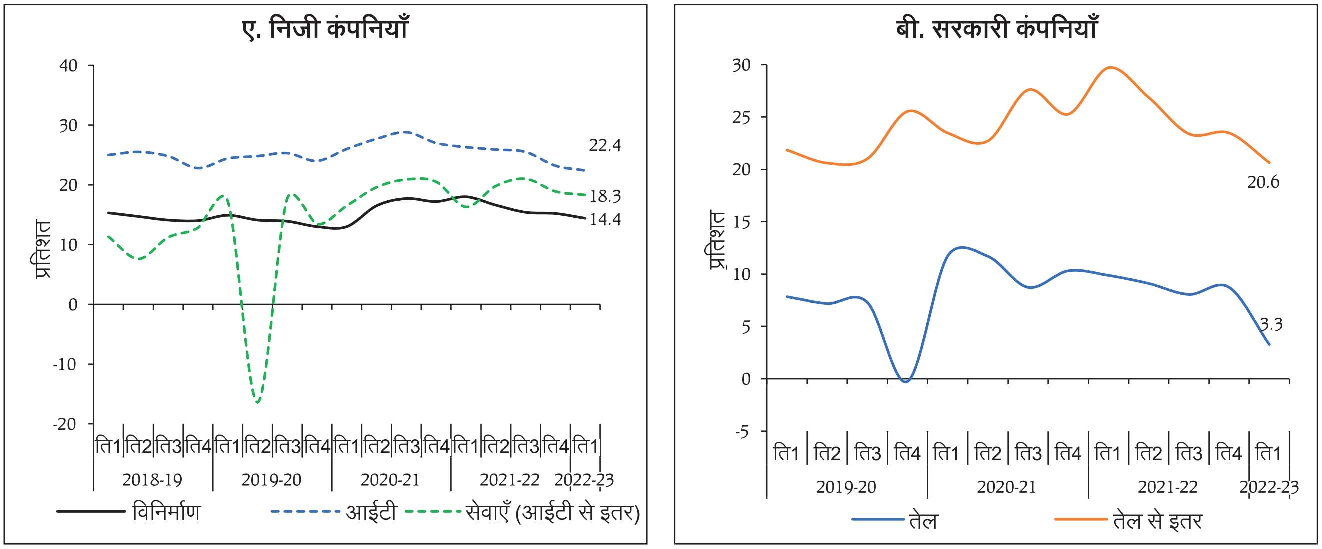

स्रोत: कैपिटलाइन डेटाबेस और आरबीआई स्टाफ का अनुमान

पण्य की कीमतों में नरमी और घरेलू मुद्रास्फीति के दबाव में कमी के साथ, परिचालन मार्जिन में वृद्धि की संभावना है।

आर्थिक गतिविधि के उच्च आवृत्ति संकेतकों में 2022-23 की दूसरी तिमाही में धीमी गति से सुधार जारी रहने का संकेत मिलते हैं। अगस्त 2022 (चार्ट 14ए) में अंतर और अंतरा-राज्य दोनों ई-वे बिल उत्पादन क्रमिक रूप से बढ़ी है। टोल संग्रह पिछले महीने की तुलना में मात्रा और मूल्य दोनों के आधार पर बढ़ा है (चार्ट 14बी)।

अगस्त में ईंधन की खपत में वृद्धि हुई, पेट्रोल और विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की खपत में वृद्धि से मदद मिली, यहां तक कि परिवहन वाहनों में उपयोग किए जाने वाले उच्च-गति डीजल में मामूली गिरावट दर्ज की गई (चार्ट 15ए)। अगस्त में

चार्ट 14: ई-वे बिल और टोल संग्रह

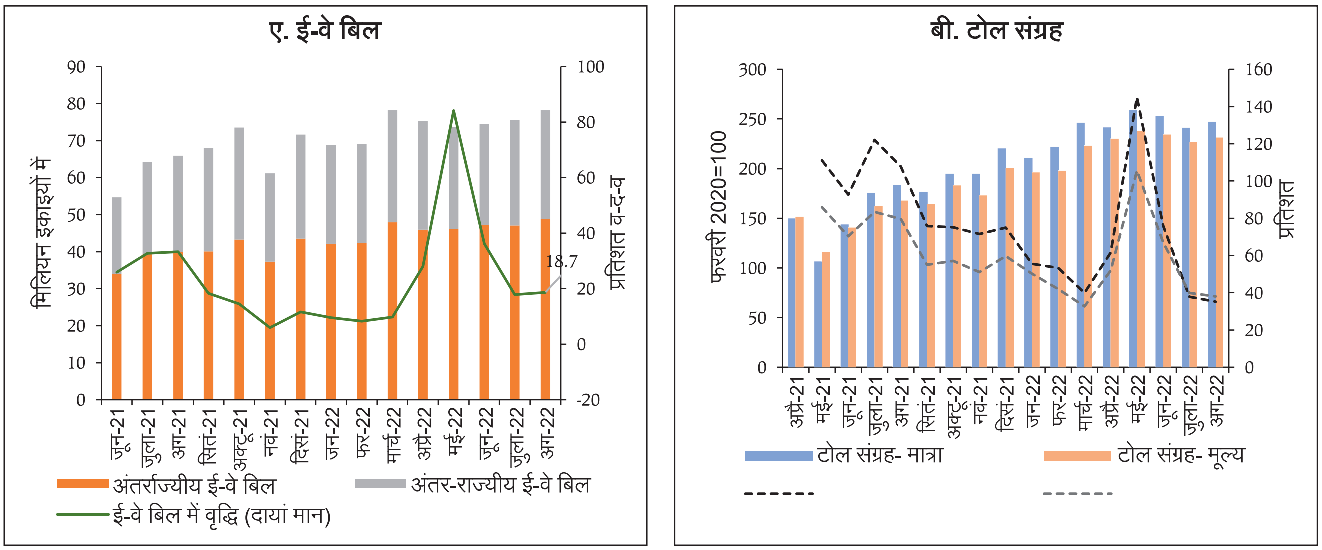

स्रोत: जीएसटीएन; भारतीय रिज़र्व बैंक; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

ऑटोमोबाइल क्षेत्र में तेजी जारी रही और आपूर्ति संबंधी बाधाएं समाप्त होने के कगार पर पहुंच गईं। यात्री वाहनों के भीतर, एंट्री लेवल सेगमेंट (3600 मिमी से कम की सीमा में) अगस्त में बढ़ा, जो घरेलू स्तर पर महामारी-पूर्व बिक्री के लगभग 75 प्रतिशत तक पहुंच गया (चार्ट 15बी)। त्योहारों के मौसम की शुरुआत, नए उत्पाद लॉन्च होने और आपूर्ति की बाधाओं में कमी (चार्ट 15सी) के कारण परिवहन और गैर-परिवहन दोनों वाहनों के पंजीकरण में अगस्त में वृद्धि दर्ज की गई, जिससे ऑटोमोबाइल की खुदरा बिक्री में तेजी आई। ग्रामीण क्षेत्र ने भी मजबूत मांग प्रदर्शित की, दोपहिया और तिपहिया वाहनों की बिक्री क्रमिक रूप से बढ़ी, जिसमें तिपहिया वाहनों ने 30 महीनों में सबसे अधिक बिक्री दर्ज की। अन्य संकेतक, जैसे, दोपहिया वाहनों की घरेलू बिक्री महामारी-पूर्व के स्तर को पार करना जारी रखती है, भले ही मॉनसून के असमान प्रसार के कारण ट्रैक्टर की बिक्री कम रही (चार्ट 15डी)।

त्योहारी सीज़न की बंपर मांग के साथ, अगस्त 2022 में एफएमसीजी की बिक्री में सुधार हुआ। अच्छे मॉनसून और नकद आमदनी से मदद मिलने से ग्रामीण खपत में तेजी दर्ज की जा रही है। अगस्त में कुल एफएमसीजी बिक्री में माह-दर-माह आधार पर 6.3 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि दर्ज की गई[8]। त्योहारी सीजन, सामान्य मॉनसून और प्रशीतलन पण्य की कीमतों से एफएमसीजी की बिक्री को बढ़ावा मिलने की उम्मीद के साथ आने वाले महीनों में मांग के बने रहने की उम्मीद है।

जीएसटी संग्रह (केंद्र और राज्य) अगस्त 2022 में 1.44 लाख करोड़ रुपये था, जो लगातार छठे महीने 1.4 लाख करोड़

चार्ट 15 : परिवहन क्षेत्र संकेतक

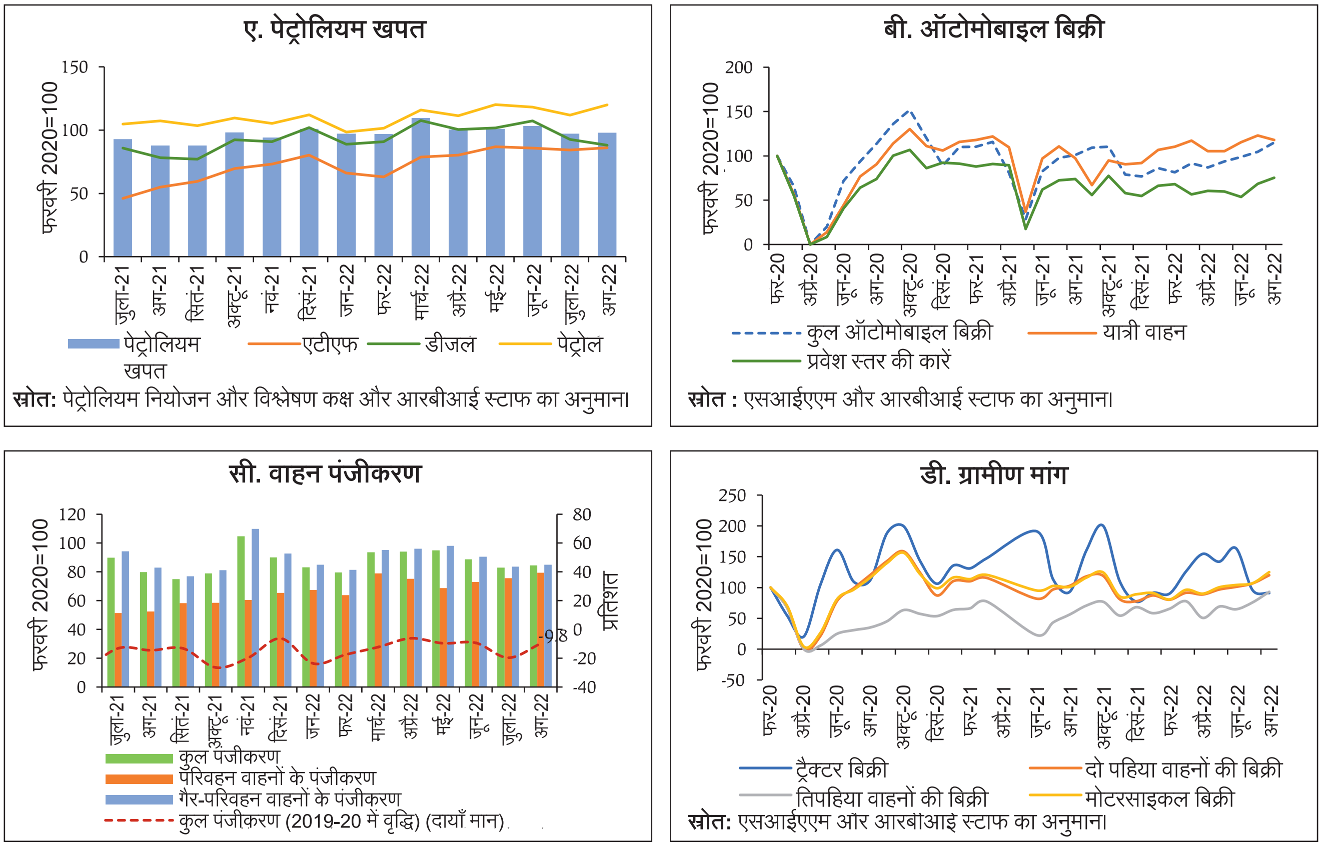

---

[8] बिजनेस स्टैंडर्ड, 02 सितंबर 2022।

चार्ट 16 : मासिक जीएसटी राजस्व

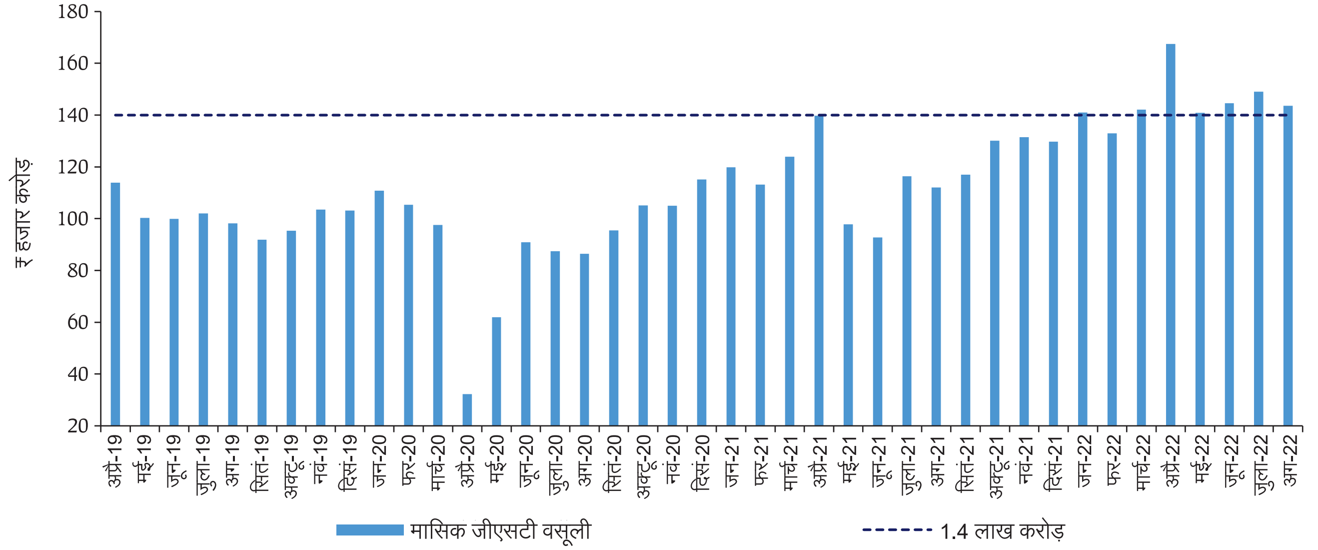

स्रोत : प्रेस सूचना कार्यालय (पीआईबी)

रुपये से अधिक था, जिसमें 28.2 प्रतिशत की सालाना वृद्धि थी (चार्ट 16)।

भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र (सीएमआईई) के घरेलू सर्वेक्षण के अनुसार, अगस्त 2022 में श्रम भागीदारी दर एक महीने पहले के 39.0 प्रतिशत से बढ़कर 39.2 प्रतिशत हो गई, जबकि रोजगार दर में 0.3 प्रतिशत की गिरावट आई। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, बेरोजगारी दर जुलाई में 6.8 प्रतिशत से बढ़कर 8.3 प्रतिशत हो गई (चार्ट 17)। जबकि अगस्त में बेरोजगारी में वृद्धि का एक मजबूत मौसमी घटक है, यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान रूप से फैली हुई है (अनुलग्नक)।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत काम की मांग अगस्त में लगातार 36.4 प्रतिशत

चार्ट 17: रोज़गार, बेरोज़गारी, श्रम भागीदारी दरें

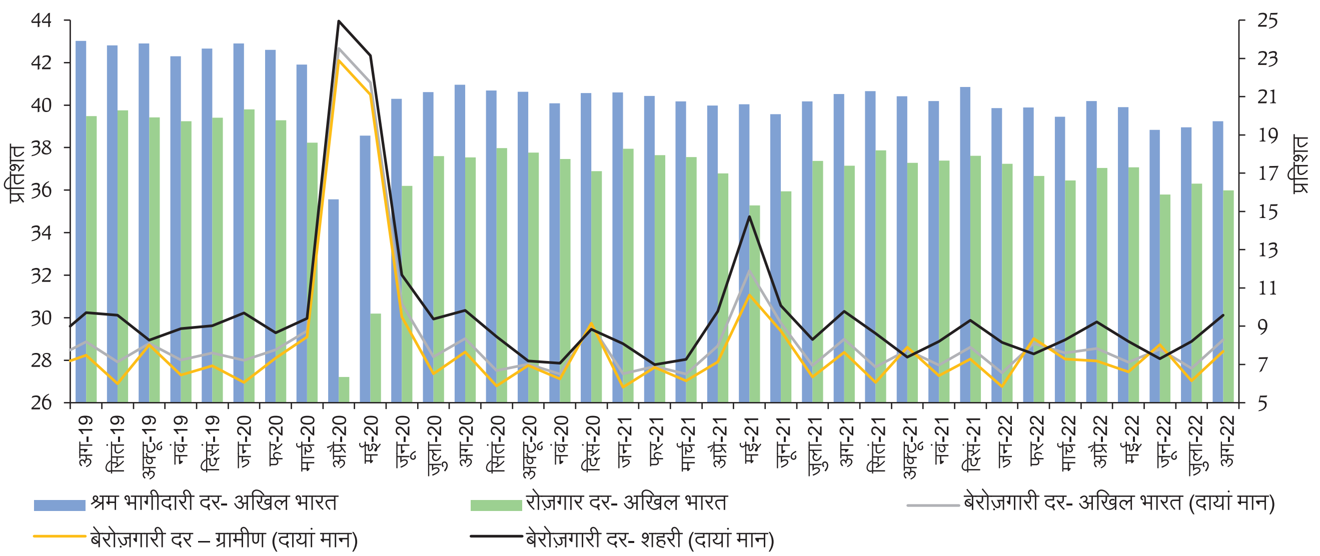

स्रोत: सीएमआईई।

चार्ट 18: मनरेगा के अंतर्गत काम की मांग

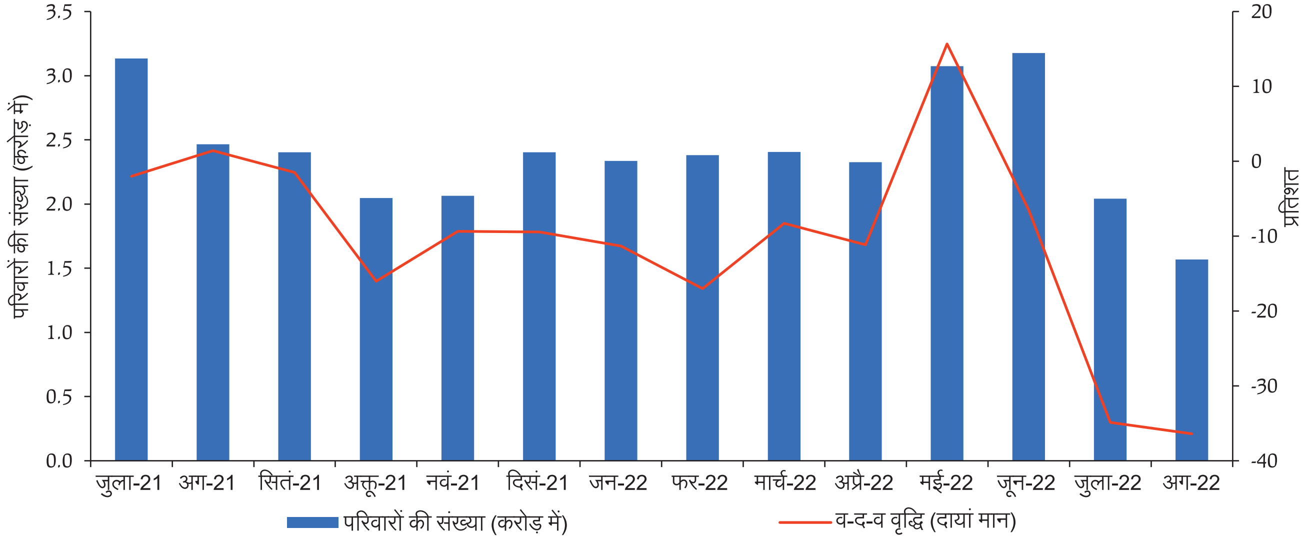

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

की कमी के साथ गिरावट दिखाती रही, जो कृषि और कृषि क्षेत्रों में लाभकारी रोजगार के अवसरों की उपलब्धता को दर्शाता है (चार्ट 18)।

संगठित क्षेत्र के रोजगार दृष्टिकोण के संदर्भ में, विनिर्माण के लिए क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) रोजगार उप-सूचकांक में सुधार हुआ, जबकि सेवा क्षेत्र के रोजगार पीएमआई ने उपभोक्ता सेवाओं के लिए दृष्टिकोण में सुधार के कारण 14 साल का उच्च स्तर दर्ज किया (चार्ट 19)। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के आधार पर आकलित संगठित नौकरी बाजार,

चार्ट 19: पीएमआई रोज़गार सूचकांक

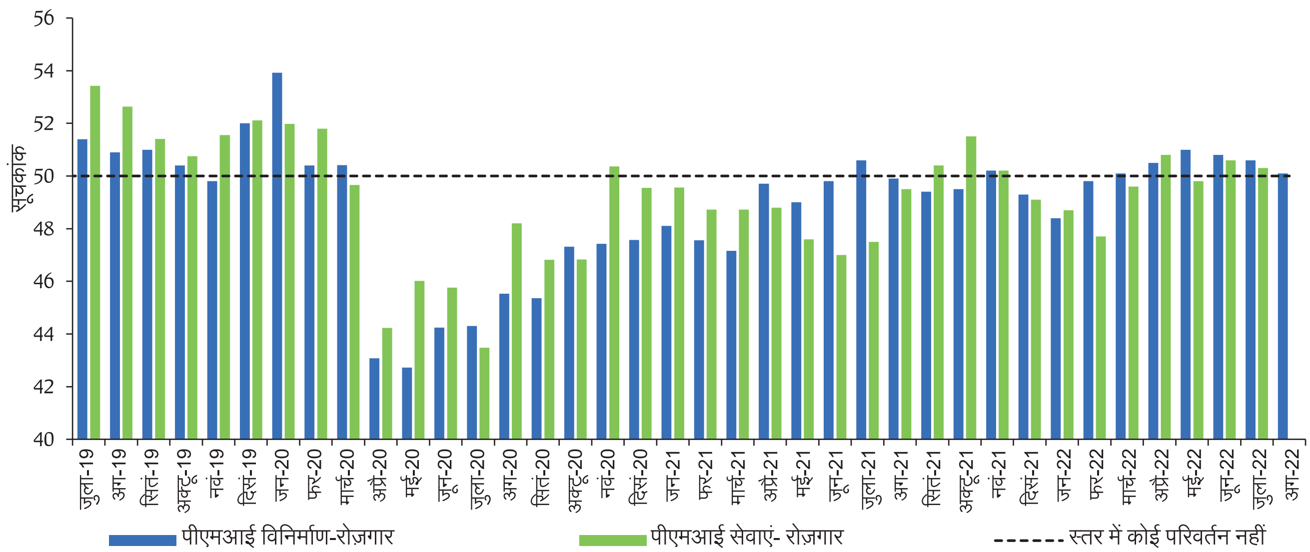

स्रोत: एसएंडपी ग्लोबल।

चार्ट 20: संगठित क्षेत्र में रोज़गार

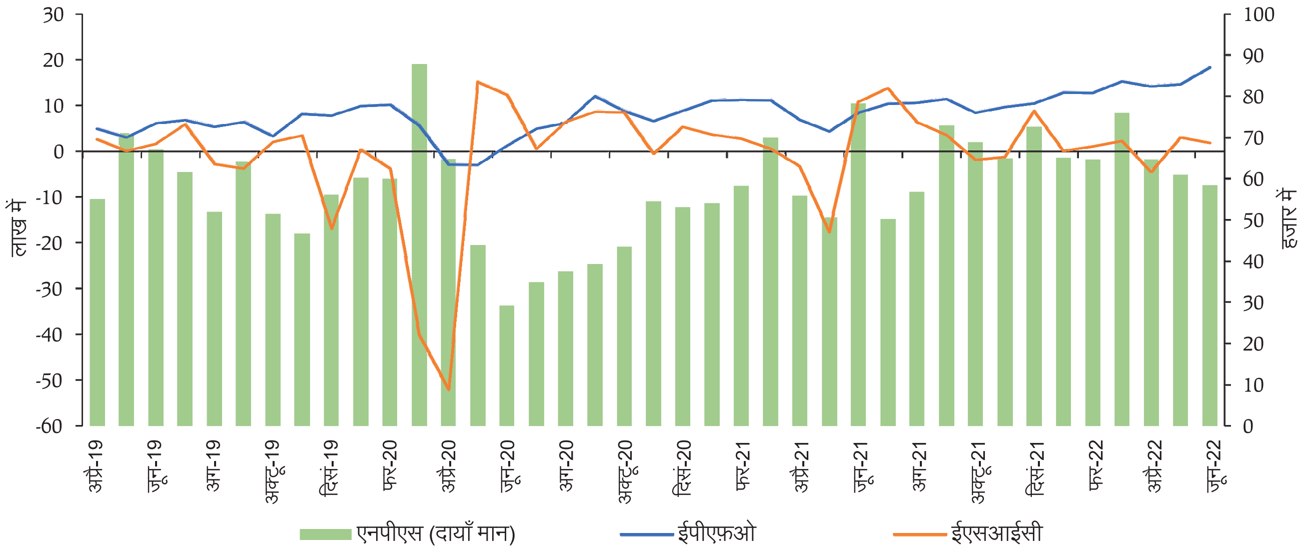

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय।

हालांकि, 2022-23 की पहली तिमाही में एक मिश्रित तस्वीर दिखाता है (चार्ट 20)।

वैश्विक व्यापार मंदी का लहर प्रभाव भारत के व्यापारिक निर्यात पर भी महसूस किया गया। निर्यात में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 1.6 प्रतिशत की धीमी वृद्धि देखी गई, हालांकि, इसमें क्रमिक रूप से (11.8 प्रतिशत) गिरावट आई और अगस्त 2022 (चार्ट 21) में 33.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

अलग-अलग पण्य-वार आंकड़ों से पता चलता है कि इंजीनियरिंग सामान, कपड़ा, कपास और प्लास्टिक का निर्यात, जो कुल निर्यात बास्केट का एक-तिहाई हिस्सा है, दोनों अनुक्रमिक और वर्ष-दर-वर्ष आधारों (सारणी-1) पर कम हुआ है। अगस्त 2022 में 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पेट्रोलियम निर्यात में क्रमिक रूप से एक-चौथाई से अधिक की गिरावट आई। गैर-तेल निर्यात (28.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर) में लगातार विस्तार के

चार्ट 21: भारत का पण्य वस्तु निर्यात – अगस्त 2022

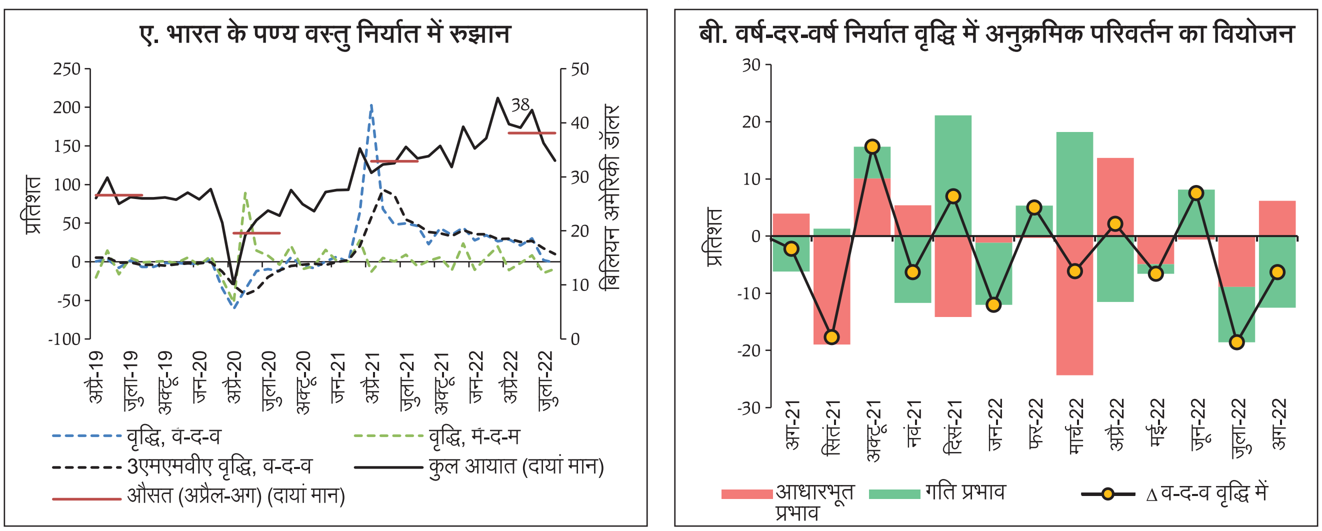

*3एमएमवीए तीन महीने का चर मान औसत है।

स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआईएंडएस; और आरबीआई के स्टाफ द्वारा अनुमान।

सारणी 1: शीर्ष 10 निर्यातित और आयातित वस्तुएं

निर्यात					आयात				
शीर्ष 10 पण्य समूह	अग 22 (हिस्सा)	अग 22 (बिलियन यूएस डॉलर)	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	माह-दर-माह वृद्धि	शीर्ष 10 पण्य समूह	अग 22 (हिस्सा)	अग 22 (बिलियन यूएस डॉलर)	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	माह-दर-माह वृद्धि
इंजीनियरिंग माल	25%	8.3	-14.6	-11.7	पेट्रोलियम, कच्चा तेल और उत्पाद	29%	17.6	86.4	-16.7
पेट्रोलियम उत्पाद	18%	4.9	5.4	-23.0	इलेक्ट्रानिक सामान	12%	7.3	22.9	7.0
रत्न एवं आभूषण	10%	3.3	-4.1	0.4	कोयला, कोक और ब्रिकेट्स इत्यादि	7%	4.5	133.6	-12.5
रसायन	8%	2.5	13.4	-3.5	मशीनरी	6%	3.9	33.3	2.0
दवा एवं औषधि	6%	2.1	6.6	0.9	स्वर्ण	6%	3.5	-47.5	48.4
इलेक्ट्रानिक सामान	5%	1.7	50.7	-5.0	रसायन	5%	3.0	42.7	-6.0
सभी तरह के कपड़ों के रेडीमेड वस्त्र	4%	1.2	-0.4	-10.7	मोती, बहुमूल्य और अर्ध-बहुमूल्य रत्न	4%	2.4	7.5	-24.9
चावल	3%	1.0	42.3	11.0	कृत्रिम रेसिन और प्लास्टिक वस्तुएं	3%	2.0	47.0	-8.0
सूती धागे/ कपड़े/ मेड-अप्स	3%	0.9	-32.3	-6.7	वनस्पति तेल	3%	1.9	41.6	-6.2
प्लास्टिक और लिनोलियम	2%	0.7	-1.5	-7.3	लौह और इस्पात	3%	1.8	32.0	2.0
10 प्रमुख पण्य समूहों का कुल योग	81%	26.7	-1.5	-9.7	10 प्रमुख पण्य समूहों का कुल योग	78%	47.9	35.6	-7.2
कुल निर्यात	**100.0**	**33.0**	-1.2	-9.0	**कुल आयात**	**100.0**	**61.7**	36.8	-6.9

स्रोत: एमओसीआई।

23 महीनों के बाद वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 1.8 प्रतिशत का संकुचन देखा गया।

गंतव्य-वार, यूएई को भारत के निर्यात में अप्रैल-जुलाई 2022 के दौरान वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 28.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है।

भारत का व्यापारिक आयात लगातार छठे महीने 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया, हालांकि अगस्त 2022 में इसकी गति में कमी आई (चार्ट 22)।

चार्ट 22: भारत का पण्य वस्तु आयात- अगस्त 2022

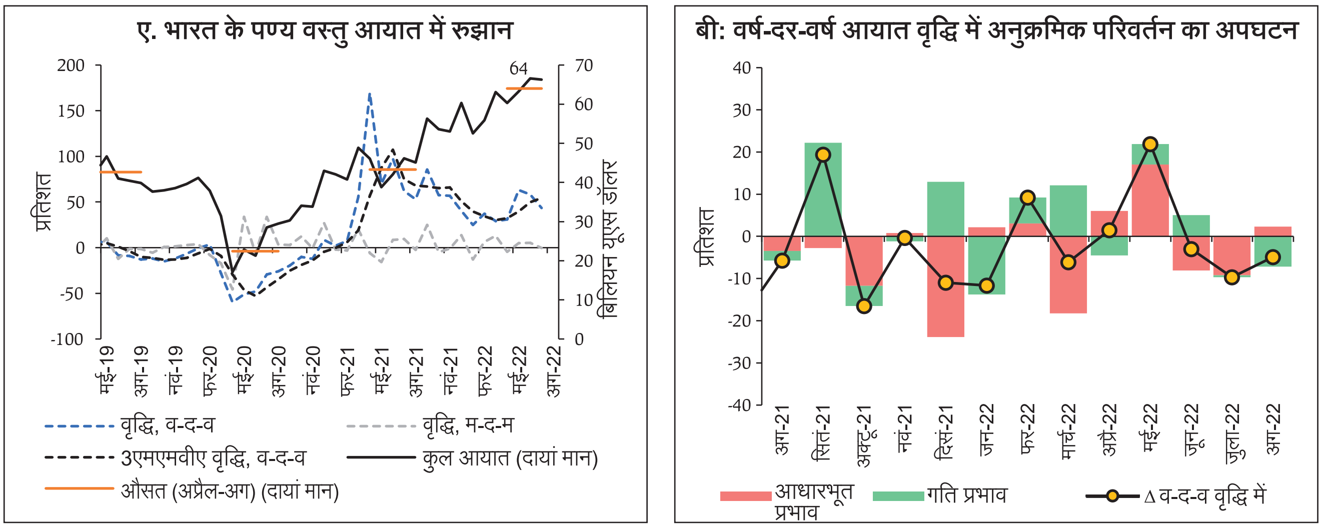

*3एमएमवीए तीन महीने का चार मान औसत है।
स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआईएस; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

चार्ट 23: मुख्य पण्य वस्तुओं में आयात वृद्धि

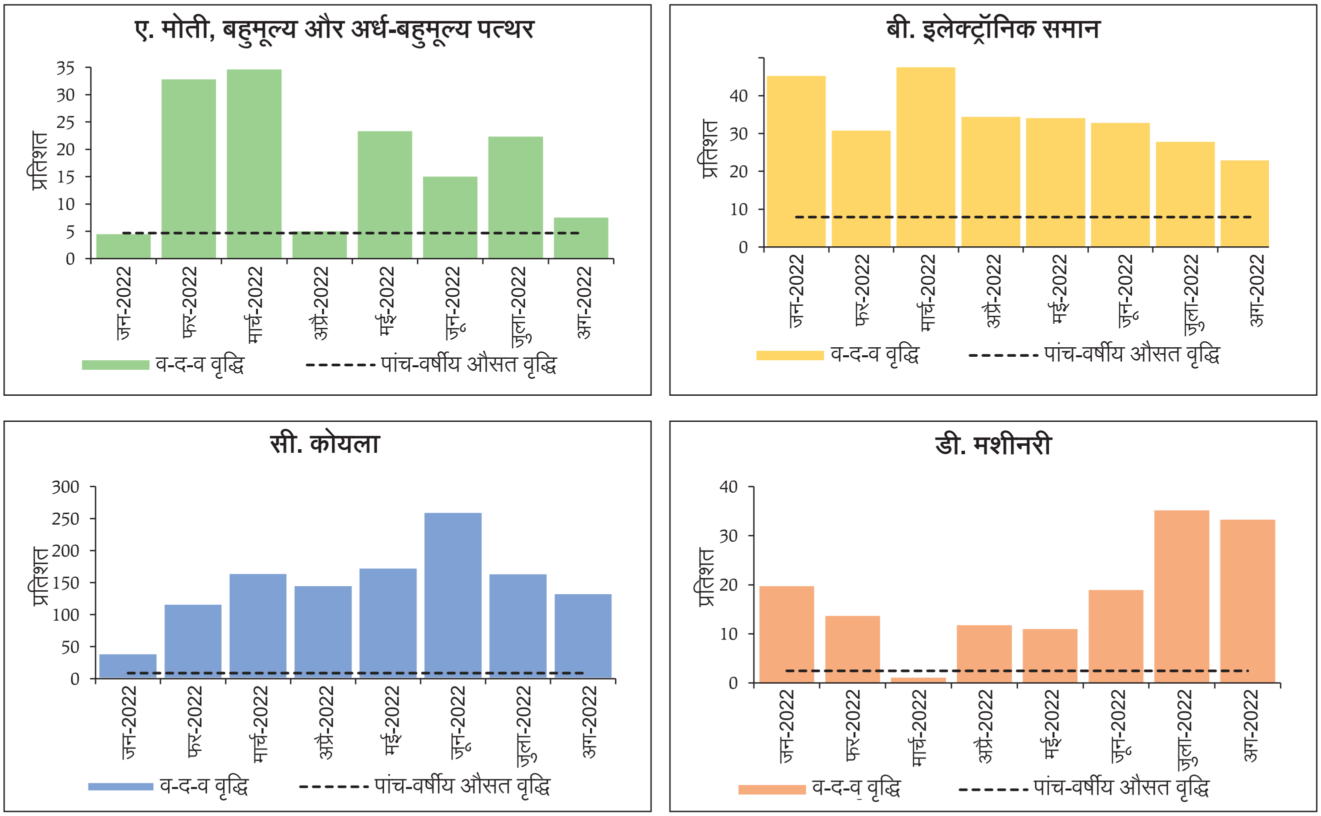

स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआईएस; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

अलग-अलग विश्लेषण से पता चलता है कि सोने को छोड़कर, सभी पण्य समूहों के आयात में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर वृद्धि हुई (सारणी-1)। इसके अलावा, प्रमुख आयातित वस्तुएं जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान, कोयला और मशीनरी, जो भारत के कुल आयात का लगभग पांचवां हिस्सा है, अपनी पांच वर्ष की औसत वृद्धि (चार्ट 23) से ऊपर चल रही है।

अप्रैल-अगस्त 2022 के दौरान तेल का आयात अधिक रहा। अगस्त 2022 में, भारत का तेल आयात मूल्य के दृष्टिकोण से वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 87.4 प्रतिशत बढ़ा। मजबूत इलेक्ट्रॉनिक्स आयात वृद्धि त्योहारी सीजन में बढ़ती आगामी मांग को पूरा करने के लिए स्टॉक प्रबंधन को संरेखित करती है। आंशिक रूप से अनिवार्य सम्मिश्रण आवश्यकताओं को निरस्त करने के सरकार के फैसले के कारण आंशिक रूप से यूएस $ 4.5 बिलियन के कोयले के आयात में क्रमिक आधार पर गिरावट आई है। इससे पहले अप्रैल 2022 में, बिजली मंत्रालय ने घरेलू कमी को देखते हुए बिजली संयंत्रों को सम्मिश्रण के उद्देश्य से 10 प्रतिशत कोयले का आयात करने का आदेश दिया था। जुलाई-अगस्त 2022 के दौरान सोने का आयात लगभग आधा घटकर 5.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो आयात शुल्क में बढ़ोतरी को दर्शाता है।

अगस्त 2022 में भारत का व्यापार घाटा एक साल पहले इसी अवधि के 11.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से दोगुना से अधिक बढ़कर 28.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इसके अलावा, 2022-23 के पहले पांच महीनों के दौरान व्यापार घाटा पिछली इसी अवधि के 54 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 124.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (चार्ट 24)।

अप्रैल-जुलाई 2022-23 के दौरान, केंद्र का सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) एक साल पहले के 21.3 प्रतिशत के मुकाबले बीई के 20.5 प्रतिशत पर बना रहा, जो मजबूत कर संग्रह और कम राजस्व खर्च की वजह से था। पूंजीगत परिव्यय में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 59.4 प्रतिशत (चार्ट 25) के साथ जोर पूंजीगत व्यय की ओर केंद्रित रहा।

चार्ट 24: भारत का पण्य वस्तु व्यापारिक घाटा

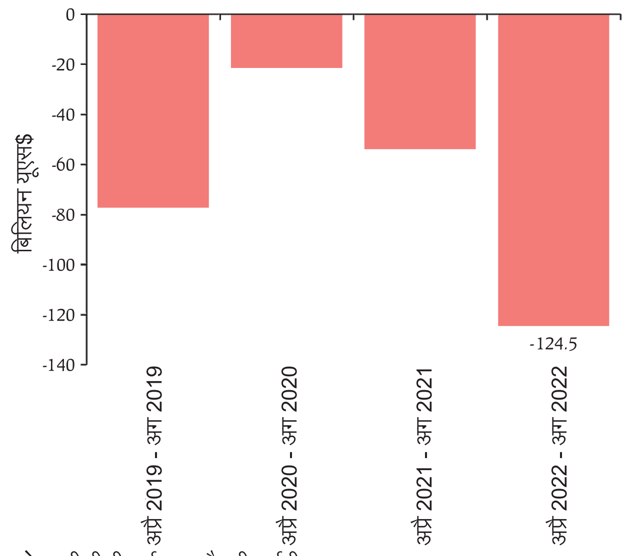

स्रोत: डीजीसीआईएस; और पीआईबी।

चार्ट 25: अप्रैल-जुलाई के दौरान व्यय की प्रवृति

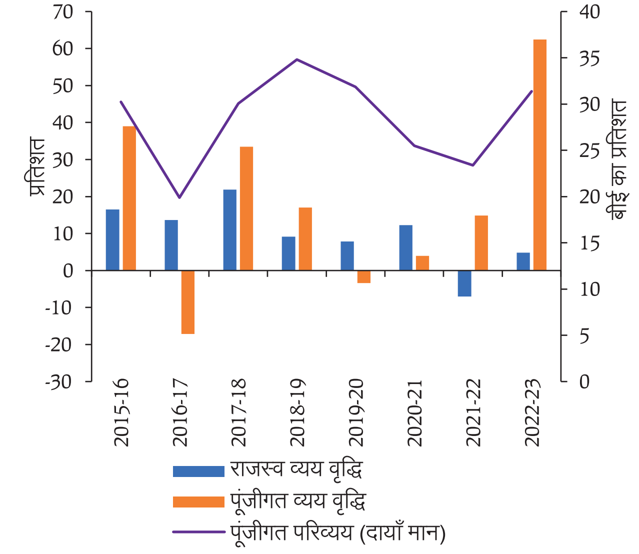

स्रोत : भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) तथा केंद्रीय बजट दस्तावेज़

प्राप्तियों के पक्ष में, सकल कर राजस्व में दोहरे अंकों की वृद्धि देखी गई, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों ने सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में संकुचन के बावजूद क्रमशः 41.9 प्रतिशत और 11.0 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की (चार्ट 26)। प्रत्यक्ष कर संग्रह के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, 08 सितंबर, 2022 तक बजट अनुमानों का 37.2 प्रतिशत एकत्र किया गया है।

चार्ट 26: अप्रैल-जुलाई 2022-23 के दौरान कर राजस्व

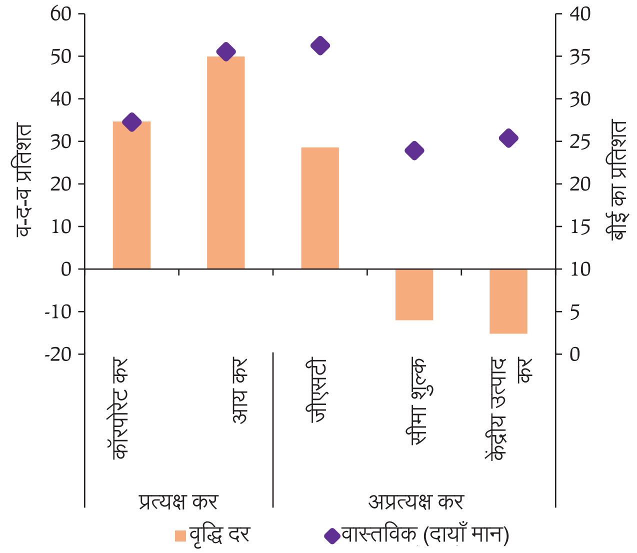

स्रोत : (सीएजी) तथा केंद्रीय बजट दस्तावेज़

अप्रैल-जुलाई[9] के दौरान राज्यों के प्रमुख बजटीय घाटे में गिरावट जारी रही। इसके अलावा, राज्यों के समेकित बजटीय सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) का अनुपात पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कम था, जिससे उनके 2022- 23 के लिए जीएसडीपी [10] के 3.3 प्रतिशत के समेकित बजट जीएफडी लक्ष्य के भीतर रहने की संभावना में सुधार हुआ (चार्ट 27ए)।

यह सुधार मुख्य रूप से सभी उप-घटकों - कर राजस्व और गैर-कर राजस्व के साथ-साथ केंद्र से अनुदान में अप्रैल-जुलाई में राजस्व प्राप्तियों में 29.6 प्रतिशत की निरंतर और मजबूत वृद्धि के कारण हुआ। अप्रैल-जुलाई 2022-23 में राजस्व व्यय में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि थोड़ी अधिक थी। हालांकि, राज्यों द्वारा पूंजी परिव्यय में गिरावट का सामना करना पड़ा और यह ऋणात्मक क्षेत्र में चला गया (चार्ट 27बी)। अगस्त 2022 में, केंद्र ने राज्यों को ₹1.16 लाख करोड़ की राशि के कर अंतरण की दो किस्तें जारी कीं, जिससे राज्यों को अपने पूंजी परिव्यय में तेजी लाने में मदद मिलने की संभावना है।

[9] डेटा 21 राज्यों से संबंधित है।

[10] वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान (ब.अ.) का डेटा 29 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है।

चार्ट 27: अप्रैल-जुलाई अवधि में राज्यों के प्रमुख संकेतकों में रुझान

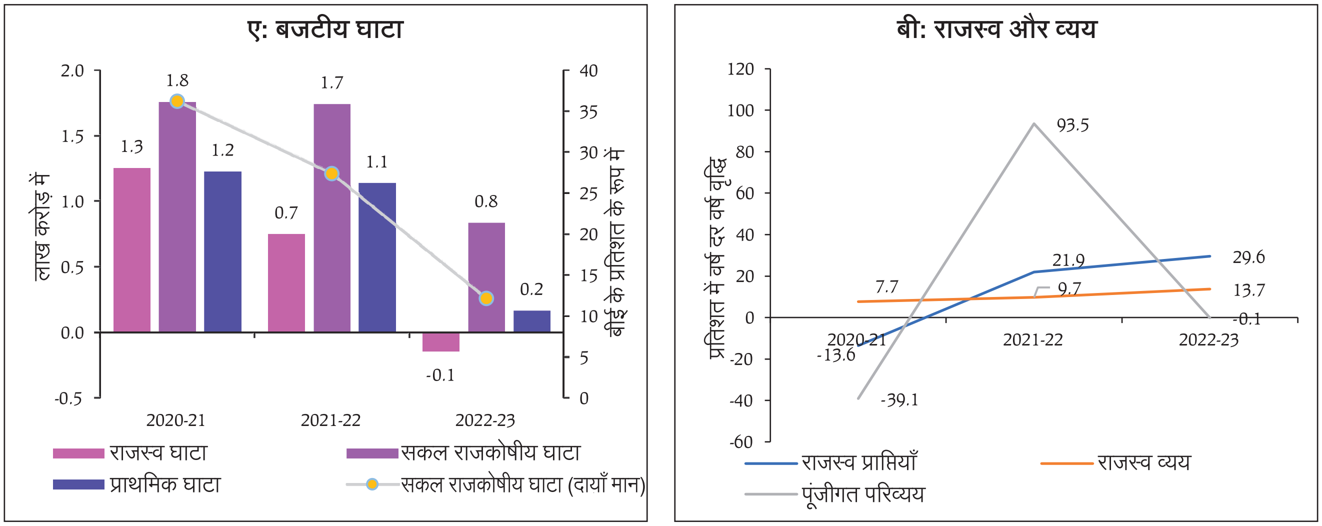

टिप्पणी: आंकड़े 21 राज्यों से संबंधित है।
स्रोत: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग)

समग्र आपूर्ति

मूल कीमतों पर योजित सकल मूल्य (जीवीए) द्वारा मापी गई सकल आपूर्ति, 2022-23 की पहली तिमाही में 12.7 प्रतिशत बढ़ी (चार्ट 28)। जबकि कृषि और सेवा क्षेत्र मजबूत बने रहे, इनपुट लागत के दबाव में वृद्धि और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण औद्योगिक विकास में कमी आई।

वर्षा वितरण के आसपास मंडराती अनिश्चितता के खिलाफ कृषि की आघात-सहनीयता जारी है (चार्ट 29)।

दक्षिण-पश्चिम मानसून, जो जून में अपने दीर्घावधि औसत (एलपीए)[11] से 8.0 प्रतिशत पीछे था, बाद में 9 सितंबर 2022 को एलपीए से 5.0 प्रतिशत अधिक हो गया। हालांकि, वर्षा का स्थानिक वितरण इस वर्ष में अब तक असमान रहा है और

चार्ट 28: जीवीए विकास में भारित योगदान

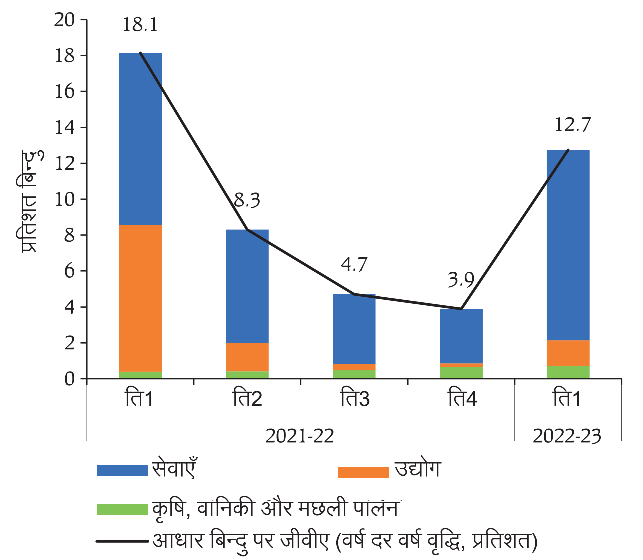

स्रोत : एनएसओ

चार्ट 29: कृषि फसलों का उत्पादन (चौथा उन्नत अनुमान, 2021-22)

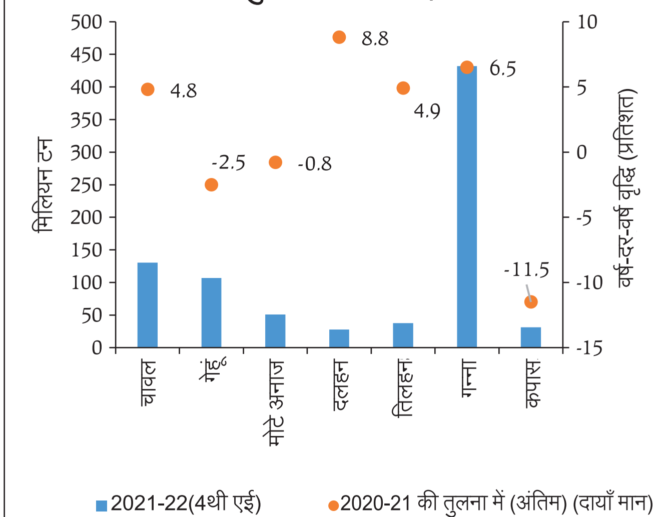

स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।

[11] एलपीए से तात्पर्य है: दीर्घावधि औसत वर्षा, जिसकी गणना 50 वर्षों की औसत (1971-2020) वर्षा के रूप में की जाती है।

चार्ट 30: दक्षिण-पश्चिम मानसून वर्षा की प्रगति

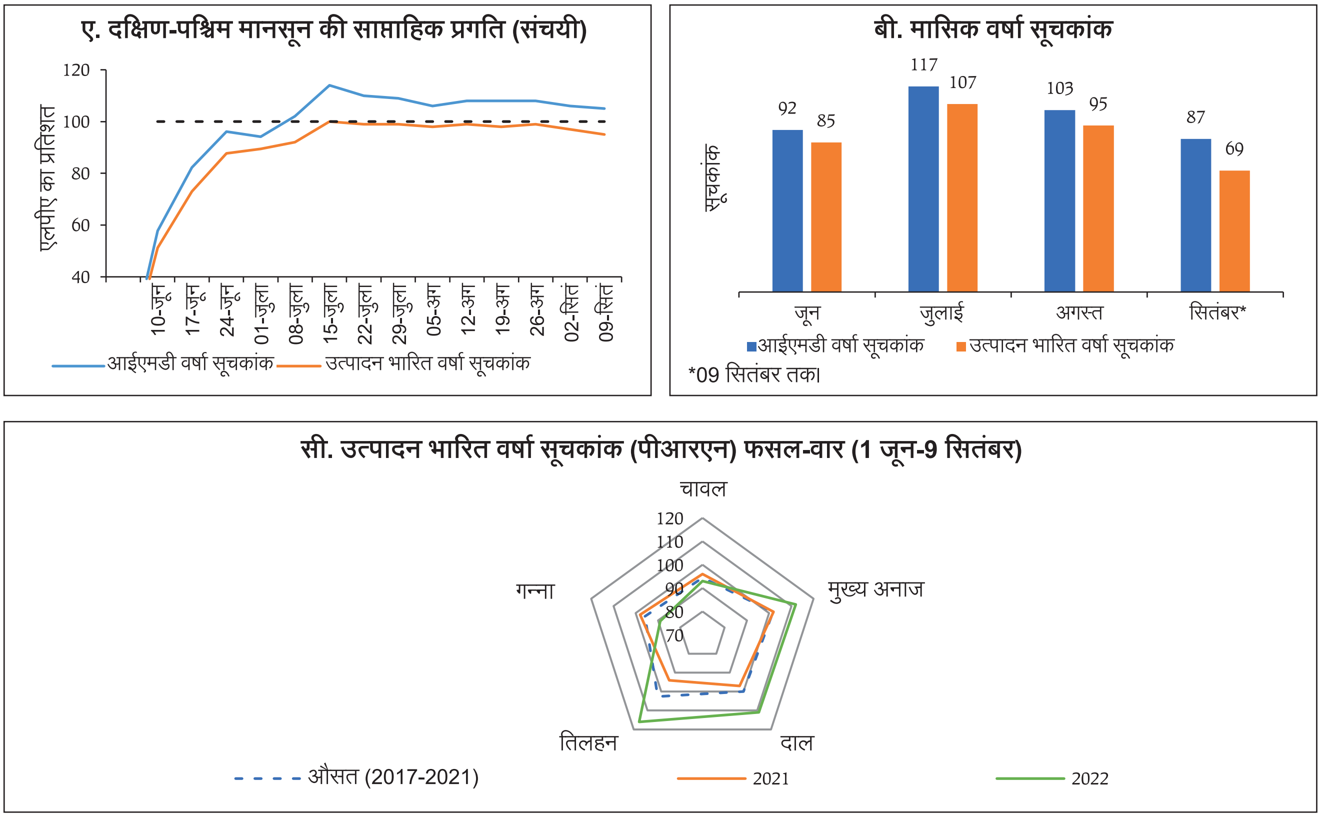

स्रोत: आईएमडी और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के कुल वर्षा सूचकांक से उत्पादन भारित वर्षा सूचकांक (पीआरएन)[12] नीचे रहा है (चार्ट 30ए और बी)। विशेष रूप से, चावल और गन्ने जैसी जल सघन फसलों की खेती करने वाले प्रमुख राज्यों में वर्षा, उनके संबंधित दीर्घावधि औसत से कम रही (चार्ट 30सी)।

देश के कुल खाद्यान्न के लगभग एक तिहाई हिस्से का उत्पादन करने वाले चार प्रमुख राज्यों यथा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल ने इस वर्ष अब तक काफी कम वर्षा दर्ज की है (सामान्य से 18-46 प्रतिशत कम)। इन राज्यों में जलाशय का मौजूदा स्तर भी उनके 10 वर्षों के औसत स्तर *की तुलना में* कम रहा है, जो आगे चलकर *रबी* फसलों को प्रभावित कर सकता है। राज्य सरकारें जोखिम कम करने वाली कार्यनीतियों को लागू करने में सक्रिय रही हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल द्वारा निष्क्रिय सिंचाई प्रतिष्ठानों को बहाल करने की घोषणा और सिंचाई प्रयासों को बढ़ाने के लिए बिहार द्वारा डीजल सब्सिडी का प्रावधान। फिर भी, कुल मिलाकर *खरीफ* का क्षेत्रफल पिछले वर्ष की तुलना में कुछ कम रहा (09 सितंबर 2022 की स्थिति में)। जबकि मोटे अनाज, कपास और गन्ने के तहत बोए गए क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई, चावल, दलहन और तिलहन के मामले में इसमें गिरावट आई (चार्ट 31)।

चालू *रबी* विपणन सत्र (2022-23) के लिए गेहूं की खरीद 18.8 मिलियन टन पर समाप्त हुई, जो पिछले वर्ष की खरीद राशि का 43.4 प्रतिशत है। 59.2 मिलियन टन चावल की संचयी खरीद पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी अधिक है। 31 अगस्त 2022 तक, केंद्रीय पूल में चावल का स्टॉक तिमाही (जुलाई-सितंबर) बफर मानदंड का 2.6 गुना है, जबकि गेहूं के मामले में यह बफर मानदंड से नीचे गिर गया है (चार्ट 32)। घरेलू उत्पादन में संभावित गिरावट के मद्देनजर, सरकार ने चावल की अधिकांश किस्मों के निर्यात

[12] पीआरएन की गणना प्रत्येक राज्य द्वारा खाद्यान्न उत्पादन के योगदान का उपयोग करके की जाती है।

चार्ट 31: खरीफ फसल बुवाई में प्रगति (9 सितंबर 2022 तक)

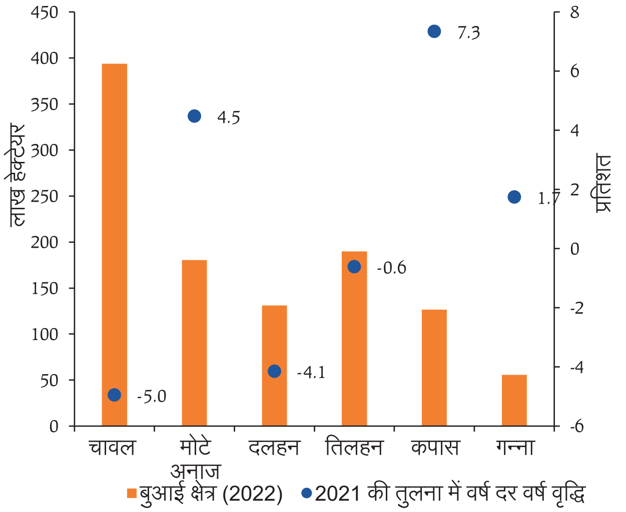

स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।

चार्ट 32: केंद्रीय भंडार में चावल और गेहूं का स्टॉक (31 अगस्त तक)

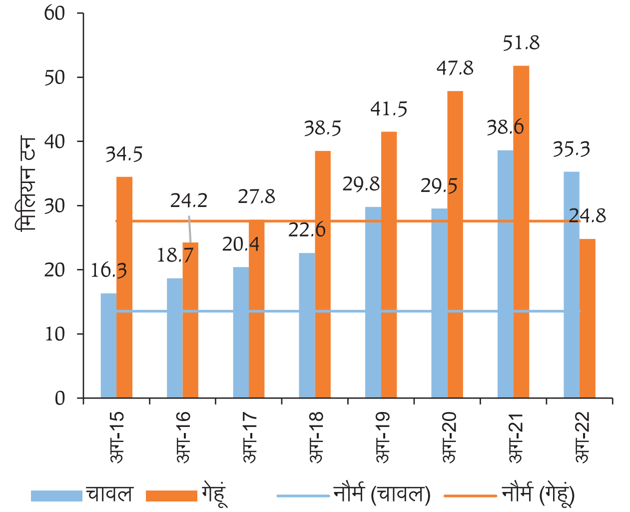

स्रोत: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।

पर 20 प्रतिशत का शुल्क लगाया और 9 सितंबर 2022 से टूटे हुए चावल के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया।

औद्योगिक क्षेत्र में, अगस्त में 56.2 पर हेडलाइन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई विस्तार क्षेत्र में रहा, *हालांकि* पिछले महीने की तुलना में इसमें गिरावट आई। इनपुट कीमतों में कमी के साथ मांग के समेकन ने रुख को बढ़ावा दिया, अगस्त 2022 में भविष्य के आउटपुट उप-सूचकांक को छह साल के उच्च स्तर 64.8 पर धकेल दिया (चार्ट 33ए)। दूसरी ओर, पीएमआई सेवाओं ने जुलाई में चार महीने के निचले स्तर 55.5 से अगस्त 2022 में 57.2 पर मजबूत विस्तार दर्ज किया। इस तेजी का श्रेय मजबूत

चार्ट 33: क्रय प्रबंधक सूचकांक

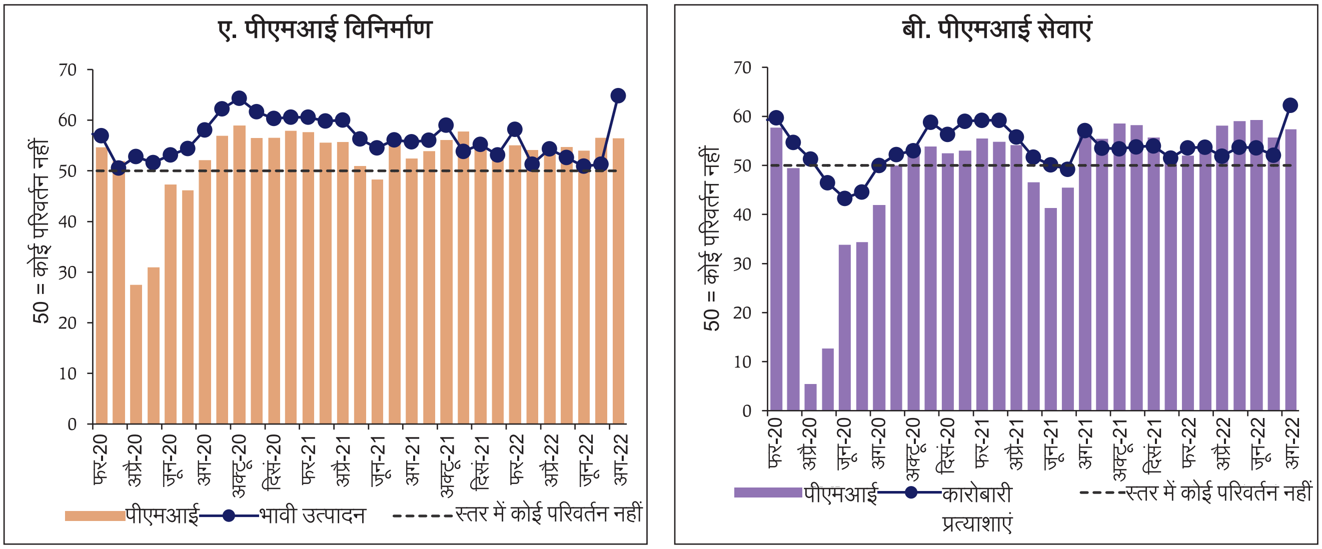

स्रोत: एसएंडपी ग्लोबल।

चार्ट 34: रेलवे और कार्गो ट्रैफिक

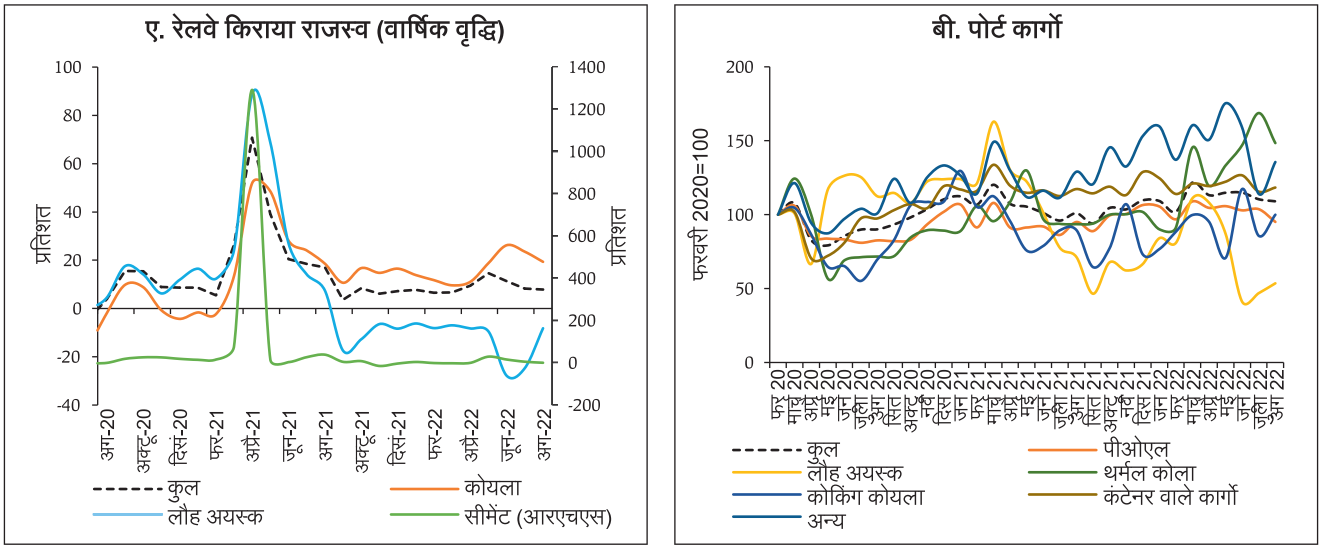

स्रोत: भारतीय पोर्ट संघ।

मांग, नए व्यवसायों में मजबूत लाभ और रोजगार सृजन को दिया गया (चार्ट 33बी)।

सेवा क्षेत्र में, परिवहन संकेतक विस्तार क्षेत्र में रहे क्योंकि अगस्त 2022 में रेलवे माल यातायात अर्जन में 7.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई (चार्ट 34ए)। जबकि कोयले और उर्वरकों में तीव्र विस्तार दर्ज किया गया, लौह अयस्क और खाद्यान्नों में संकुचन जारी रहा। लौह अयस्क और कच्चे उर्वरकों में कमी के कारण अगस्त में प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो यातायात में मामूली कमी दर्ज की गई, जो कुल कार्गो का लगभग 21 प्रतिशत हिस्सा हैं (चार्ट 34बी)।

जुलाई-अगस्त 2022 के दौरान निर्माण क्षेत्र की गतिविधि में विस्तार बना रहा, सीमेंट उत्पादन और इस्पात की खपत में लगातार क्रमशः आठ और ग्यारह महीनों के लिए महामारी-पूर्व के स्तर पर वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट 35)। जुलाई में सीमेंट उत्पादन में कमी दर्ज की गई क्योंकि मानसून की बारिश के कारण निर्माण गतिविधि धीमी हो गई थी।

जुलाई में संकुचन के बाद, विमानन क्षेत्र में घरेलू यात्रियों की संख्या में अगस्त में 0.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अन्य सभी खंडों, *जैसे* अंतरराष्ट्रीय यात्री यातायात, और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कार्गो में जुलाई की तुलना में अगस्त में संकुचन दिखा।

निरंतर मांग के कारण आवास क्षेत्र सुदृढ़ बना रहा। दस प्रमुख शहरों में आवासीय संपत्ति पंजीकरण की संख्या 2022-23 की पहली तिमाही के दौरान एक नए उच्च स्तर पर पहुंच गई और महामारी-पूर्व के उच्चतम स्तर से 50 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गई (चार्ट 36)।

चार्ट 35: स्टील खपत और सीमेंट निर्माण

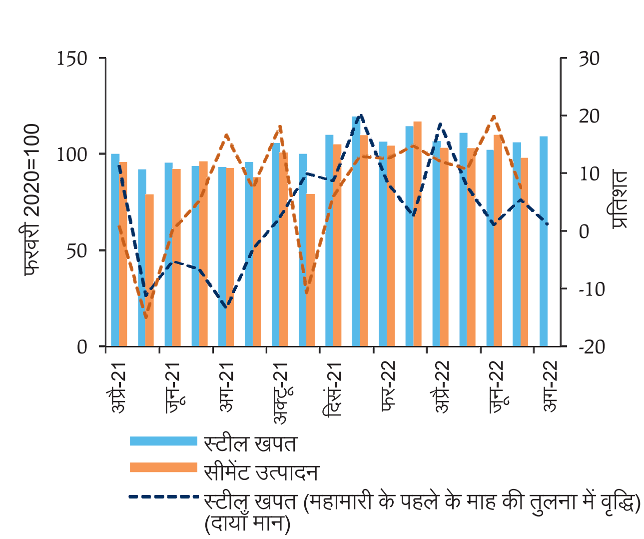

स्रोत: संयुक्त प्लांट समिति और आर्थिक परामर्शदाता, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का कार्यालय।

चार्ट 36: दस प्रमुख शहरों में कुल संपत्ति पंजीकरण *

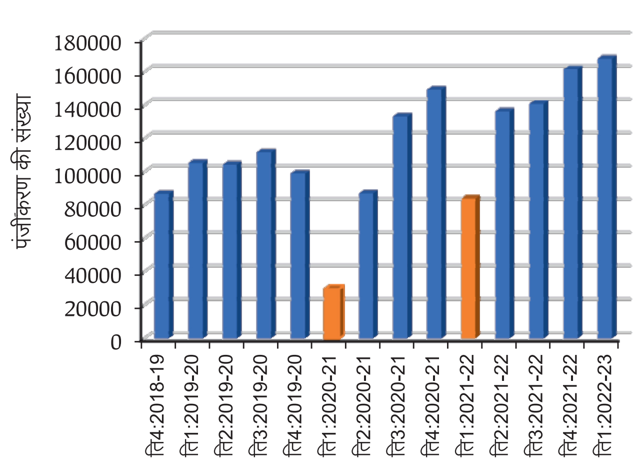

*: दस प्रमुख शहरों में मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, कानपुर और कोच्चि शामिल हैं।
स्रोत: राज्य सरकारों के पंजीकरण प्राधिकरणों से घर की कीमतों के आंकड़े; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट 37: आवास मूल्य सूचकांक में परिवर्तन

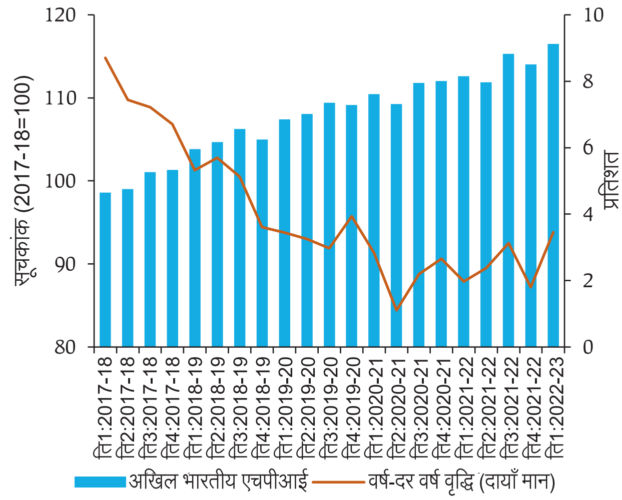

टिप्पणी: 2022-23 की पहली तिमाही के आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: राज्य सरकारों के पंजीकरण प्राधिकरणों से घर की कीमतों के आंकड़े।

अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई)[13] ने 2022-23 की पहली तिमाही में 3.5 प्रतिशत वार्षिक (वर्ष-दर-वर्ष) वृद्धि और 2.2 प्रतिशत अनुक्रमिक (क्यू-ओ-क्यू) वृद्धि दर्ज की (चार्ट 37)।

धीमी वैश्विक अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति के दबावों के बीच जुलाई में उच्च आवृत्ति संकेतकों ने आर्थिक गतिविधियों में सामान्यता देखी (सारणी 2)। सेवा क्षेत्र में समग्र

सारणी 2: उच्च आवृत्ति संकेतक – सेवाएं

क्षेत्र	संकेतक	उच्च आवृत्ति संकेतक – सेवाओं की वृद्धि (वर्षानुवर्ष प्रतिशत)				2019 की तुलना में वृद्धि			
		मई-22	जून-22	जुला-22	अग-22	मई-22/ मई-19	जून-22/ जून-19	जुला-22/ जुला-19	अग-22/ अग-19
शहरी मांग	यात्री वाहन बिक्री	185.1	19.1	11.1	21.1	10.6	31.6	54.6	48.7
ग्रामीण मांग	दुपहिया वाहन बिक्री	253.2	23.4	9.6	17.0	-27.4	-20.7	-8.6	2.9
	तीन पहिया वाहन बिक्री	2161.6	183.9	72.8	65.3	-44.7	-48.5	-43.8	-34.8
	ट्रैक्टर बिक्री	47.4	-14.4	-15.3	-1.9	41.1	24.5	21.2	42.2
व्यापार, होटल, यातायात, संचार	वाणिज्यिक वाहन बिक्री	100.3				11			
	रेलवे माल ढुलाई यातायात	14.6	11.3	8.3	7.8	25.5	23.7	22.5	31
	पोर्ट कार्गो यातायात	10.2	12.2	15.1	8.6	11.4	14.6	6.9	8.6
	घरेलू हवाई कार्गो यातायात	54.7	40.4	18.8		1.9	4.4	-1.6	
	अंतरराष्ट्रीय हवाई कार्गो यातायात	-4.6	0.5	-1.5		-13.6	-5.1	-9.4	
	घरेलू हवाई यात्री यातायात	474.7	247.9	97.9		-2.0	-10.5	-17.1	
	अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात	722.8	753.6	487.7		-28.0	-21.5	-18.1	
	जीएसटी ई-वे बिल्स (कुल)	84.1	36.2	17.8	18.7	35.6	49.7	44.9	52.7
	जीएसटी ई-वे बिल्स (आंतर राज्य)	83.3	38.6	19.8	22.5	45.5	58.7	51.5	62.6
	जीएसटी ई-वे बिल्स (अंतर राज्य)	85.5	32.2	14.7	12.9	21.8	36.4	35.2	38.7
	यात्री आगमन	2043.7	1349.2	783.9		-31.1	-28	-21.7	
विनिर्माण	इस्पात उपभोग	21.3	6.4	12.5	13.1	7.7	0.7	5.5	1.3
	सीमेंट उत्पादन	26.2	19.7	2.1		10.8	19.9	7.5	
पीएमआई संकेतक	विनिर्माण	54.6	53.9	56.4	56.2				
	सेवाएं	58.9	59.2	55.5	57.2				

स्रोत:

[13] आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई) (आधार: 2010-11=100) 10 प्रमुख शहरों की राज्य सरकारों के पंजीकरण प्राधिकरणों से एकत्रित संपत्ति मूल्य लेनदेन पर आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर संकलित किया गया है।

चार्ट 38: सीपीआई मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति और वाहक

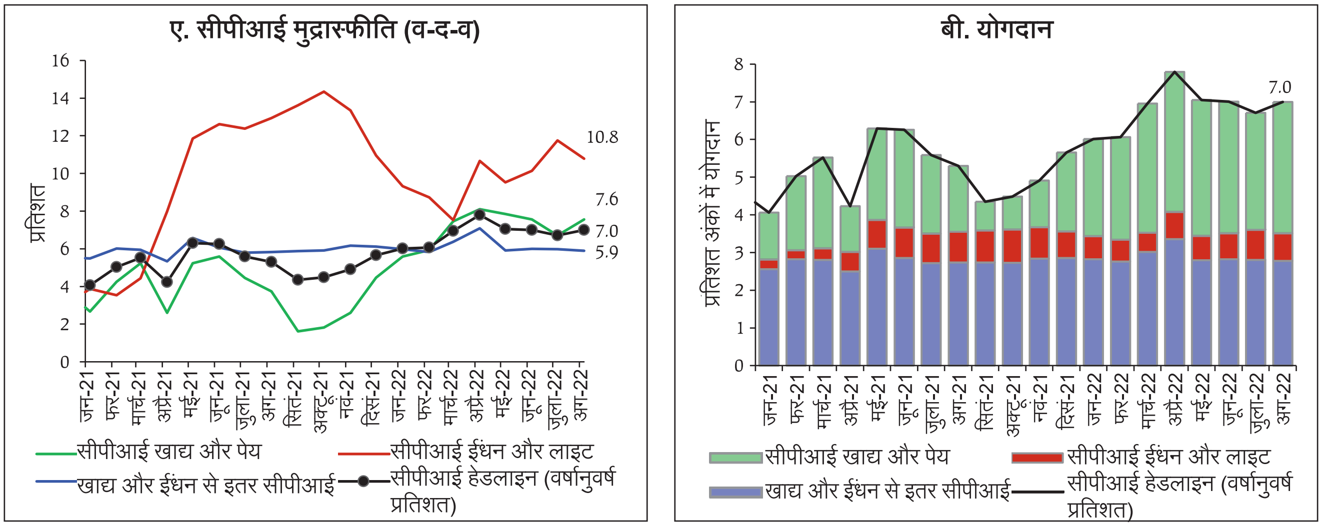

टिप्पणी: अप्रैल- मई 2021 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति की गणना अप्रैल- मई 2020 के लिए इम्प्यूटेड सीपीआई सूचकांकों के आधार पर की गई थी।
स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ); और आरबीआई स्टाफ के आकलन

रूप से निरंतर सुधार, विनिर्माण क्षेत्र में कमी को पाट सकता है।

मुद्रास्फीति

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 12 सितंबर 2022 को जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, मुद्रास्फीति पिछले महीने के 6.7 प्रतिशत से बढ़कर अगस्त में 7.0 प्रतिशत हो गई (चार्ट 38ए)। लगभग 50 आधार अंकों की गति (सूचकांक में माह-दर-माह परिवर्तन) को लगभग 20 आधार अंकों के अनुकूल आधार प्रभाव (एक वर्ष पहले कीमतों में महीने-दर-महीने बदलाव) द्वारा आंशिक रूप से ऑफसेट किया गया था, जिससे जुलाई और अगस्त के बीच हेडलाइन मुद्रास्फीति में लगभग 30 आधार अंकों की वृद्धि हुई।

प्रमुख समूहों में, खाद्य और पेय पदार्थों के लिए माह-दर-माह की कीमतों में वृद्धि (0.7 प्रतिशत) उच्चतम थी, जिसका अनुकरण मूल सीपीआई (0.4 प्रतिशत) ने किया। दूसरी ओर, ईंधन और प्रकाश श्रेणी में 0.4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई (चार्ट 38बी)। अलग-अलग स्तर पर अनाज, दालों, मसालों और सब्जियों ने महीने के दौरान महत्वपूर्ण कीमत दबाव प्रदर्शित किये जबकि फल, खाद्य तेल, अंडे, मांस और मछली की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई (चार्ट 39)।

अनाज, दूध, फल, दालें, सब्जियां, मसाले और तैयार भोजन (चार्ट 40) में उच्च मुद्रास्फीति के कारण सीपीआई खाद्य

चार्ट 39 : उप-समूहों में मुद्रास्फीति व-द-व और परिवर्तन (मा-द-मा)

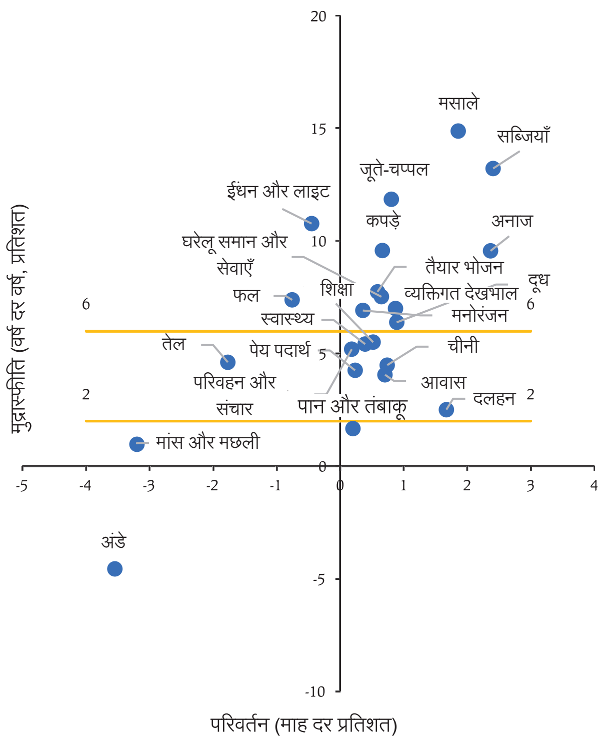

स्रोत : एनएसओ और आरबीआई स्टाफ के आकलन

चार्ट 40: उप-समूहों में वार्षिक मुद्रास्फीति (अगस्त *बनाम* जुलाई 2022)

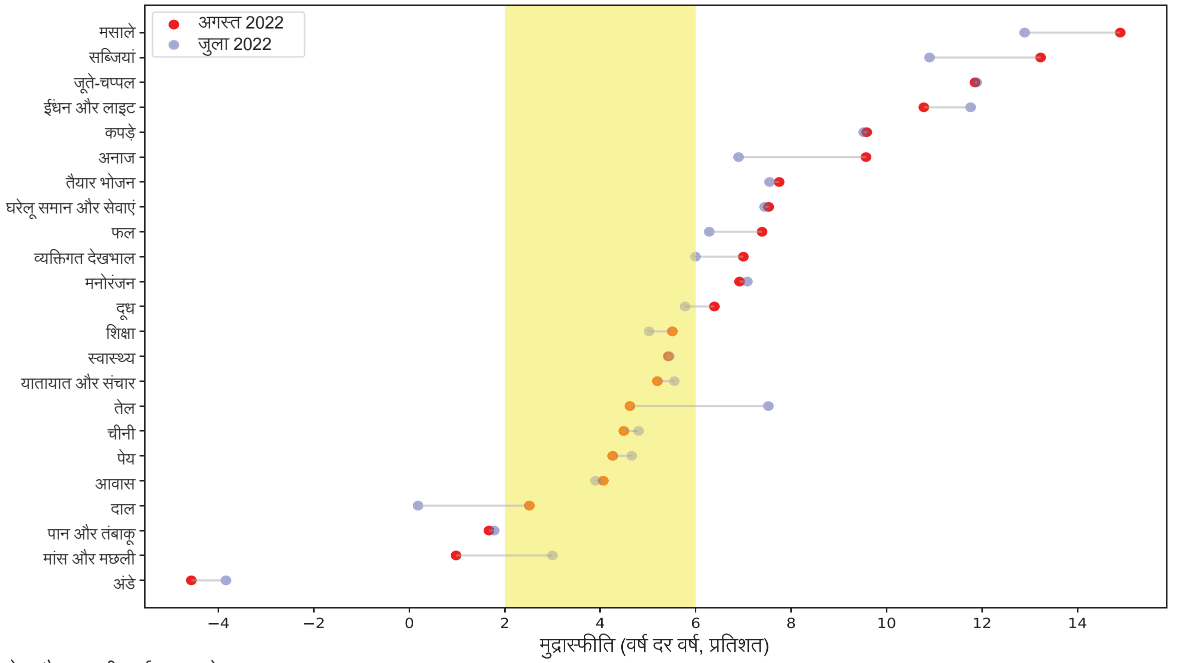

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) पिछले महीने के 6.7 प्रतिशत से बढ़कर अगस्त में 7.6 प्रतिशत हो गई। दूसरी ओर, मांस और मछली, खाद्य तेल, चीनी और गैर-मादक पेय पदार्थों में मुद्रास्फीति में कमी आई। जुलाई की तुलना में अगस्त में अंडों में अवस्फीति और गहरी हो गई।

ईंधन और लाइट श्रेणी में मुद्रास्फीति के लगातार तीन महीनों तक बढ़ने के बाद, जुलाई के 11.8 प्रतिशत से कम होकर यह अगस्त में 10.8 प्रतिशत हो गई। इसका कारण मिट्टी के तेल (पीडीएस) की मुद्रास्फीति में तेज गिरावट थी, यहां तक कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) मुद्रास्फीति भी अधिक बनी रही। बिजली की कीमतें अपस्फीति में रहीं। मुद्रास्फीति में सामान्यता के बावजूद ईंधन समूह ने अगस्त में हेडलाइन मुद्रास्फीति में 10.4 प्रतिशत का योगदान दिया क्योंकि सीपीआई समूह में इसका भारांक 6.8 प्रतिशत था।

मूल मुद्रास्फीति पिछले दो महीनों के दौरान 6.0 प्रतिशत से मामूली रूप से घटकर 5.9 प्रतिशत हो गई। जबकि आवास, घरेलू सामान और सेवाएं, शिक्षा, और व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव जैसे उप-समूहों ने मुद्रास्फीति में वृद्धि दर्ज की, पान, तंबाकू और नशीले पदार्थ, परिवहन और संचार, और मनोरंजन और क्रीड़ा में कमी देखी गई। कपड़े और जूते-चप्पल और स्वास्थ्य उप-समूहों में मुद्रास्फीति सीमाबद्ध रही। मूल मुद्रास्फीति श्रेणी के भीतर, वस्तुओं में मुद्रास्फीति सेवाओं की तुलना में अधिक बनी रही (चार्ट 41)।

चार्ट 41: सीपीआई मूल मुद्रास्फीति: वस्तु *बनाम* सेवाएं

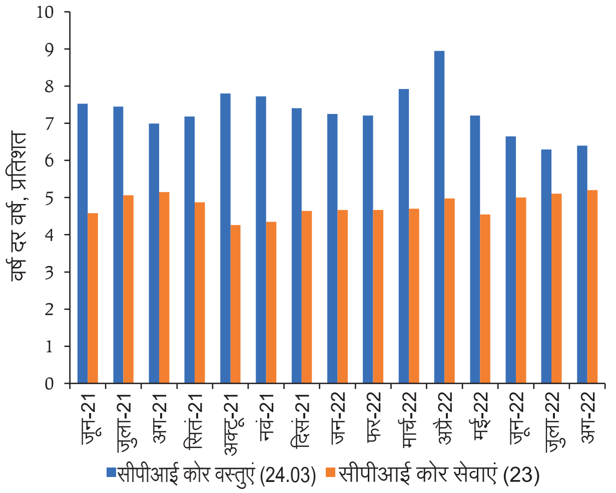

टिप्पणी: कोष्ठक में दिये गए आंकड़े समग्र भार को दर्शाते हैं।
स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

भौगोलिक वितरण के संदर्भ में, ग्रामीण मुद्रास्फीति (7.2 प्रतिशत) अगस्त में शहरी मुद्रास्फीति (6.7 प्रतिशत) से अधिक थी। राज्यों में, गोवा और मणिपुर में 4 प्रतिशत से कम मुद्रास्फीति के साथ मुद्रास्फीति की दरों में व्यापक भिन्नता रही है, जबकि गुजरात, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ने 8 प्रतिशत से अधिक की मुद्रास्फीति प्रदर्शित की (चार्ट 42)।

उपभोक्ता मामले विभाग (डीसीए) से सितंबर के लिए अब तक (सितंबर 1-12) हाई फ्रीक्वेंसी फूड प्राइस डेटा मुख्य रूप से गेहूं की कीमतों में उछाल के कारण अनाज की कीमतों में वृद्धि की ओर इंगित करता है। दालों की कीमत में व्यापक आधार पर वृद्धि दर्ज की गई जबकि अंतरराष्ट्रीय खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट होने से खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। प्रमुख सब्जियों में आलू और प्याज की कीमतों में तेजी जारी है। प्रमुख टमाटर उत्पादक क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण जुलाई-अगस्त के दौरान गिरावट के बाद टमाटर की कीमतों में तेजी से उलटफेर हुआ (चार्ट 43)।

चार्ट 42: मुद्रास्फीति का स्थानिक वितरण (सीपीआई-संयुक्त, वर्ष-दर-वर्ष)

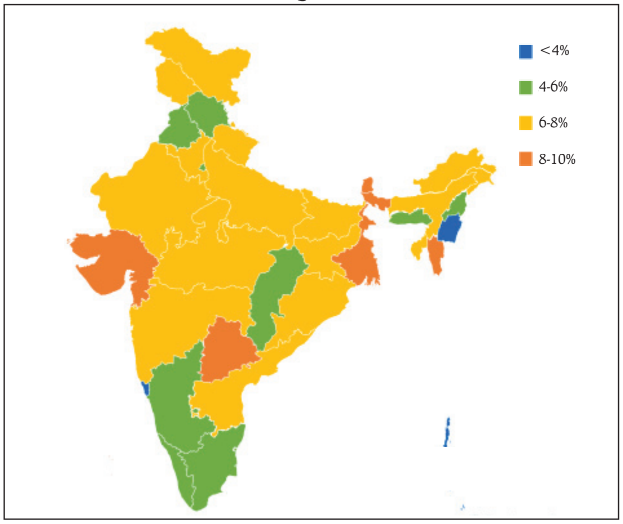

स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

सितंबर में चार बड़े महानगरों में पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री कीमतें अब तक समान रही हैं। जबकि अगस्त की

चार्ट 43: डीसीए आवश्यक पण्य कीमतें

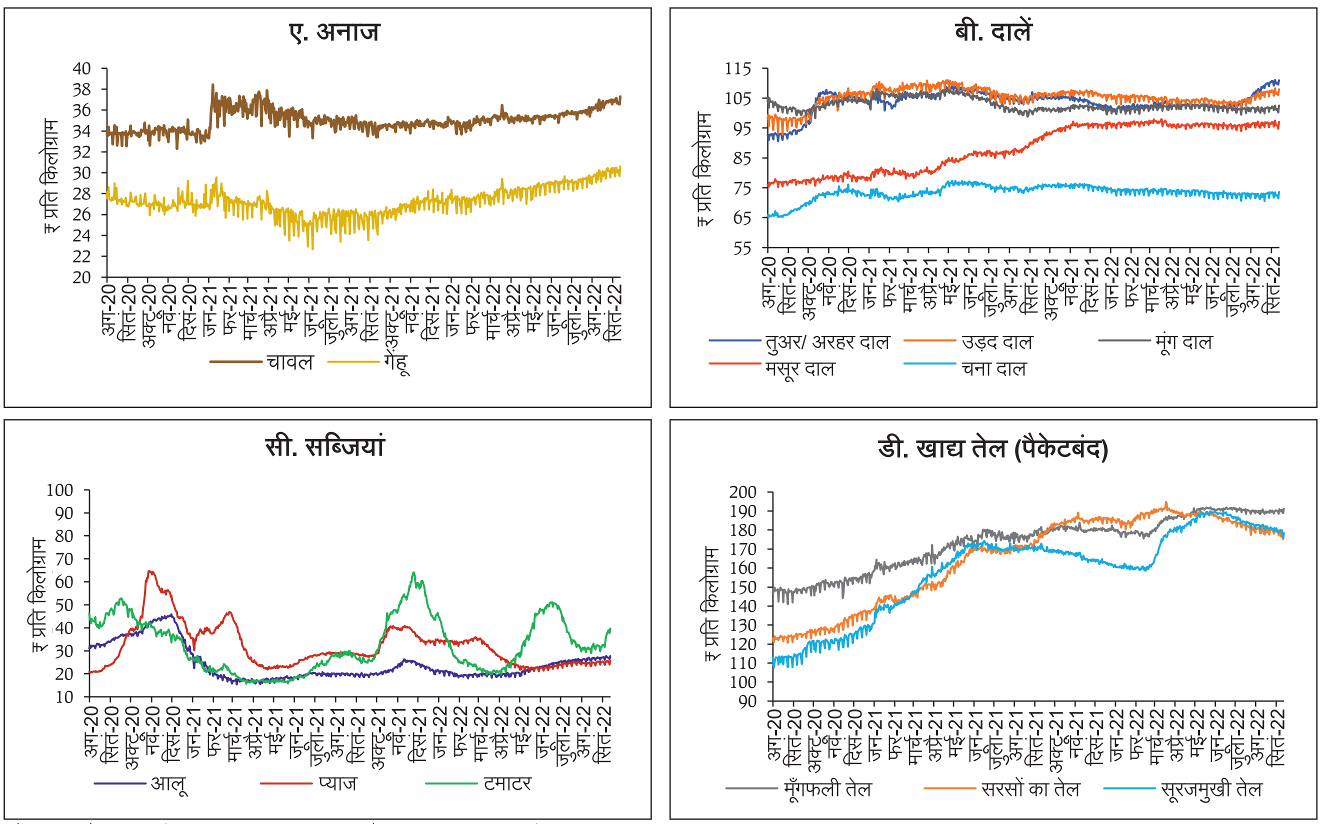

स्रोत: उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

सारणी 3: पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतें

वस्तु	इकाई	घरेलू कीमतें			माह-दर-माह (प्रतिशत)	
		सितं-21	अग-22	सितं-22^	अग-22	सितं-22
पेट्रोल	₹/लीटर	102.30	102.92	102.92	-0.5	0.0
डीज़ल	₹/लीटर	92.62	92.72	92.72	-0.4	0.0
मिट्टी का तेल (सब्सिडी)	₹/लीटर	33.18	62.73	60.13	-12.2	-4.2
एलपीजी (गैर-सब्सिडी)	₹/सिलेंडर	895.13	1063.25	1063.25	0.8	0.0

^: 1-12 सितंबर 2022 की अवधि के लिए।

टिप्पणी: मिट्टी के तेल के अलावा, कीमतें चार प्रमुख महानगरों (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई) में औसत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की कीमतों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मिट्टी के तेल के लिए कीमतें, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में रियायती कीमतों के औसत को दर्शाती हैं।

स्रोत: इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल); पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी); तथा आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

तुलना में मिट्टी के तेल की कीमतों में कमी आई, सितंबर के पहले पखवाड़े में एलपीजी की कीमतें स्थिर रहीं (सारणी 3)।

अगस्त 2022 में विनिर्माण और सेवाओं में इनपुट लागत का दबाव बढ़ा, *यद्यपि* धीमी गति से, जैसा कि पीएमआई में परिलक्षित होता है। बिक्री कीमतों में विनिर्माण और सेवाओं में भी वृद्धि हुई (चार्ट 44)।

IV. वित्तीय स्थितियाँ

चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत अवशोषण 16 जुलाई से 15 अगस्त 2022 के दौरान ₹2.7 लाख करोड़ था, जो 16 अगस्त से 14 सितंबर 2022 के दौरान घटकर ₹2.6 लाख करोड़ हो गया (चार्ट 45)। इस अवधि के दौरान दैनिक औसत अधिशेष चलनिधि में से लगभग ₹1.6 लाख करोड़ एकदिवसीय

चार्ट 44: इनपुट और आउटपुट कीमतें

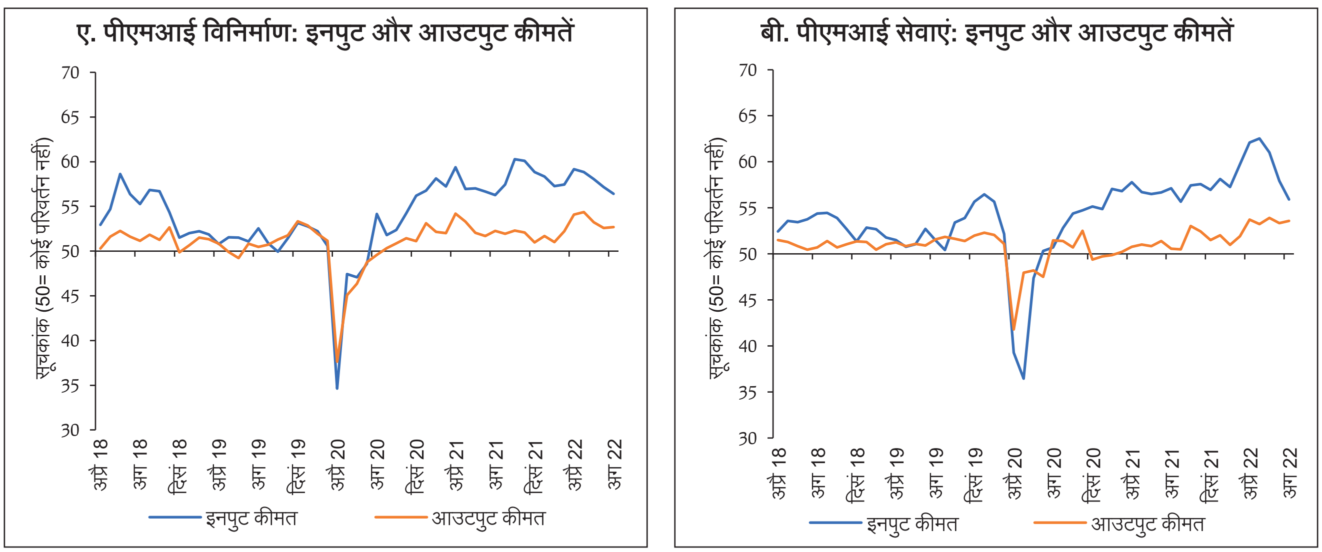

स्रोत: एसएंडपी ग्लोबल; एमओएसपीआई; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

चार्ट 45: चलनिधि की स्थिति

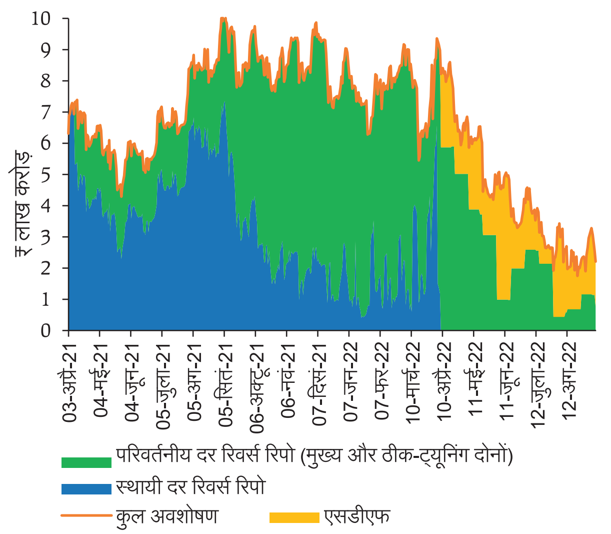

स्रोत: आरबीआई।

स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के माध्यम से अवशोषित किए गए, जबकि शेष भाग लंबी अवधि की परिवर्तनीय दर रिवर्स रिपो (वीआरआरआर) नीलामियों (मुख्य और फाइन-ट्यूनिंग दोनों) के माध्यम से 5.24 प्रतिशत की औसत प्रभावी अवशोषण दर[14] पर जुटाए गए। चलनिधि की प्रत्याशित तंगी को देखते हुए, पाक्षिक नीलामियों के तहत निधियों को नियोजित करने की बैंकों की प्रवृत्ति में कमी, निम्न बोली-कवर अनुपात में स्पष्ट है। 26 अगस्त और 9 सितंबर को आयोजित 14-दिवसीय वीआरआरआर पारिचालन में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखी गई: प्रत्येक को ₹2.0 लाख करोड़ की अधिसूचित राशि के मुकाबले प्रत्येक को 5.39 प्रतिशत की भारित औसत दर पर, दोनों नीलामियों में क्रमशः ₹70,331 करोड़ और ₹33,392 करोड़ प्राप्त किए गए।

अगस्त के दूसरे पखवाड़े से लेकर 14 सितंबर 2022 के दौरान भारित औसत मांग दर (डब्ल्यूएसीआर) का कारोबार, नीति रिपो दर से औसतन 28 आधार अंक नीचे और एसडीएफ दर से 3 आधार अंक नीचे रहा, जबकि पिछले पखवाड़े में यह नीति रिपो दर से 13 आधार अंक नीचे और एसडीएफ से 12 आधार अंक ऊपर था (चार्ट 46ए)। संपार्श्विक खंड में इसी अवधि के दौरान, एलएएफ कॉरिडोर के भीतर ट्रेड की गई त्रि-पक्षीय दर और बाजार रिपो दर - औसतन, नीति रिपो दर से क्रमशः 22 और 19 आधार अंक नीचे रहे (चार्ट 46बी)। 3-महीने के खजाना बिल (टी-बिल) की दर सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर के आस-पास ट्रेड करती है, जबकि 3-महीने के जमा प्रमाणपत्र (सीडी) और 3-महीने के वाणिज्यिक पत्र (सीपी) पर प्रतिफल एमएसएफ दर से ऊपर क्रमशः औसतन 29 आधार अंकों और 62 आधार अंकों पर ट्रेड हुआ (चार्ट 39बी)। प्राथमिक बाजार में,

चार्ट 46: पॉलिसी कॉरिडोर और और मुद्रा बाजार दरें

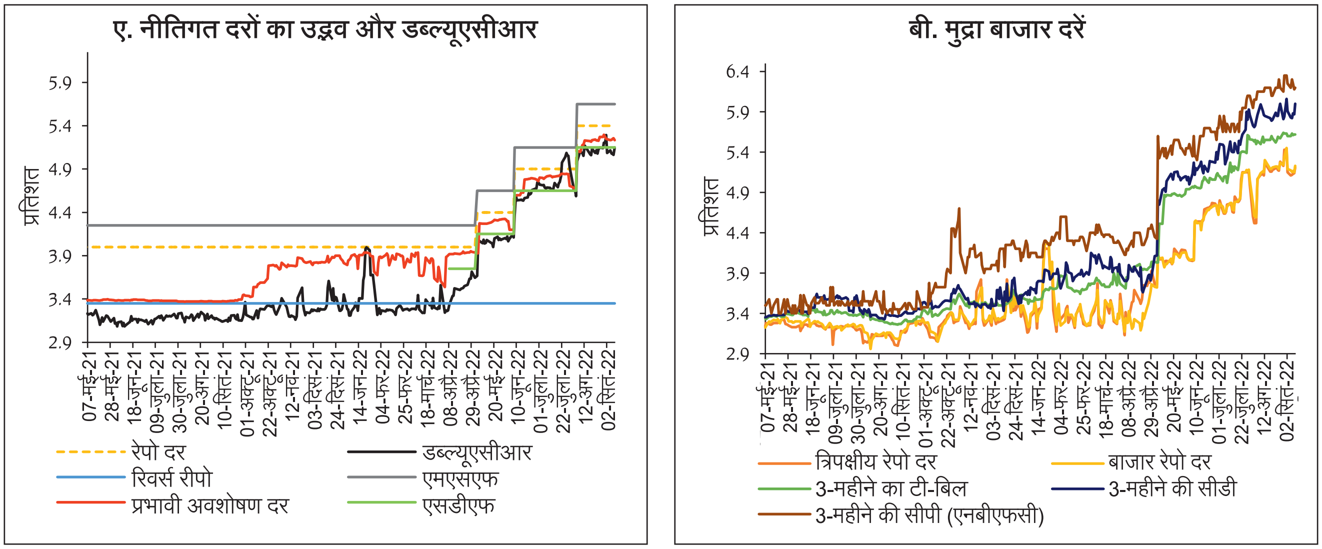

स्रोत: आरबीआई; ब्लूमबर्ग; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

[14] अलग-अलग परिपक्वता की एसडीएफ दर और वीआरआरआर नीलामियों का भारित औसत क्रमशः एसडीएफ और वीआरआरआर विंडो के तहत अवशोषित राशि के भार के साथ।

चार्ट 47: सरकारी प्रतिभूति बाजार में विकास

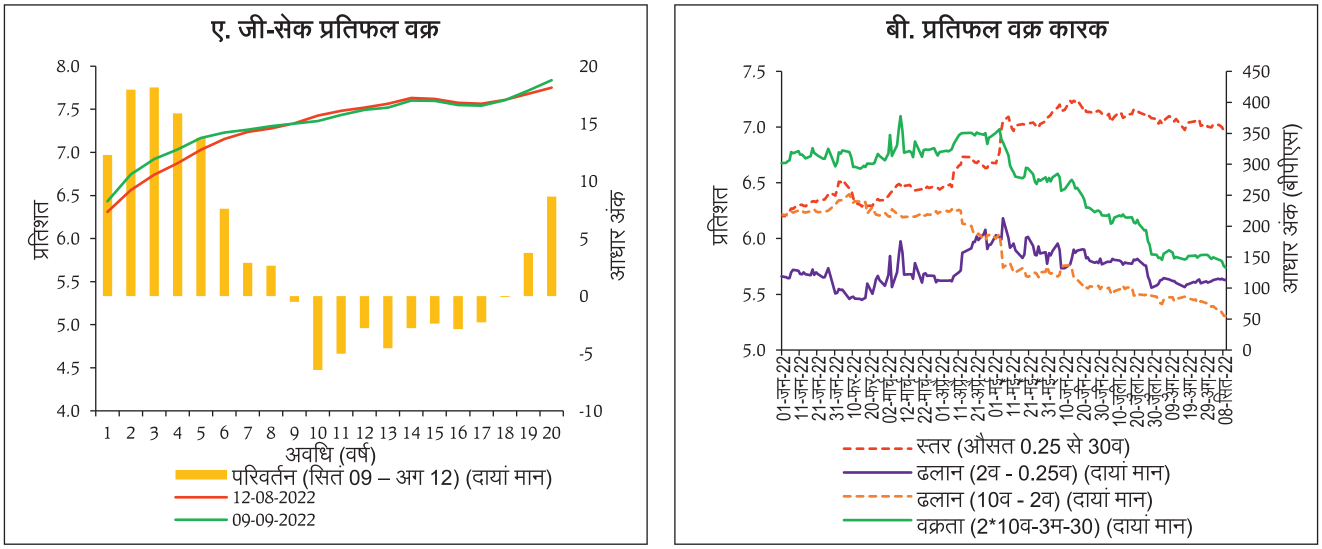

स्रोत: ब्लूमबर्ग; सीसीआईएल; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

सीपी जारी करने के माध्यम से अगस्त 2022 के दौरान धन संग्रहण पिछले महीने के ₹94,599 करोड़ की तुलना में बढ़कर ₹1.51 लाख करोड़ हो गया, हालांकि यह एक वर्ष पहले इसी अवधि (₹2.21 लाख करोड़) की तुलना में कम रहा। प्राथमिक निर्गमन का बड़ा हिस्सा 31-90 दिनों के परिपक्वता खंड में था।

नियत आय बाजार में, वक्र के लॉन्ग एंड पर बॉन्ड प्रतिफल में आम तौर पर कमी आई, नए 10 साल के बेंचमार्क जी-सेक (7.26 जीएस 2032) पर प्रतिफल 14 सितंबर 2022 को 7.12 फीसदी पर बंद हुए। 16 अगस्त से 9 सितंबर 2022 की अवधि के दौरान तक, अमेरिकी मौद्रिक नीति पर फेडरल रिजर्व के अधिकारियों द्वारा आक्रामक टिप्पणी के कारण प्रतिफल में रुक-रुक कर वृद्धि हुई। हालांकि, अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि के दबाव को कच्चे तेल की कीमतों में कमी से पाट दिया था। वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों में भारत के बॉन्ड को शामिल किए जाने की संभावना पर बढ़ती प्रत्याशा ने भी रुख को जीवंत रखा। इसी समय, वक्र के शॉर्ट एंड में ढलान आई, और 8 वर्ष तक की अवधि के लिए दरों में वृद्धि देखी गई (चार्ट 47ए)। परिणामस्वरूप, ढलान - जैसा कि 10-वर्ष और 2-वर्ष जी-सेक प्रतिफल के बीच के स्प्रेड द्वारा मापा जाता है – में आगे तेजी से कमी आई, जो मौद्रिक नियंत्रण के प्रभाव को दर्शाता है (चार्ट 47बी)। हालांकि अप्रैल से प्रतिफल वक्र के स्तर में ऊपर की ओर बदलाव एक घटते ढलान के अनुरूप है (जैसा कि 10-वर्ष माइनस 2-वर्ष के विस्तार द्वारा मापा जाता है), वक्रता[15] में एक स्पष्ट गिरावट मई में हुई नीति बैठक के बाद से स्पष्ट है, जो मौद्रिक नीति के और अधिक नियंत्रण की धूमिल प्रत्याशा का संकेत देता है। समग्र रूप से, प्रतिफल वक्र दीर्घावधि की विकास संभावनाओं में सुधार और मुद्रास्फीति की *प्रत्याशित* अपेक्षाओं में कमी का सुझाव देता है।[16]

सभी अवधियों और रेटिंग स्पेक्ट्रम में जी-सेक प्रतिफल के साथ कॉर्पोरेट बॉन्ड प्रतिफल में आम तौर पर कमी आई या वे मामूली रूप से परिवर्तित हुए (सारणी 4)। इसी अवधि के दौरान क्रेडिट जोखिम प्रीमियम में भी मामूली कमी आई। जुलाई 2022 के दौरान ₹69,166 करोड़ (2022-23 में अब तक का उच्चतम) के कॉरपोरेट बॉन्ड जारी किए गए, जो एक वर्ष पहले के ₹31,889 करोड़ से दोगुना था। पिछले कुछ महीनों में कॉरपोरेट बॉन्ड प्रतिफल में गिरावट स्थिर जोखिम प्रीमियम का संकेत देती है, जिसने बड़े कॉर्पोरेट्स को बॉन्ड मार्केट से धन जुटाने के लिए आकर्षित किया है।

[15] प्रतिफल वक्र की वक्रता लघु, मध्यम और लंबी परिपक्वताओं पर प्रतिफल के बीच संबंध का वर्णन करती है। उच्च वक्रता का अर्थ है, वक्र की उच्च अवतलता *अर्थात* प्रतिफल वक्र, मध्यम से लंबी अवधि के प्रतिफल की तुलना में लघु से मध्यम कार्यकाल में ढालू है और इसलिए प्रतिफल वक्र में एक उभार दिखाता है। वक्रता की गणना 10-वर्ष के प्रतिफल के दोगुने से 30-वर्ष और 3-महीने के प्रतिफल के योग को घटाकर की जाती है।

[16] पात्र, एम.डी., जॉइस, जे., कुशवाहा, के.एम., और आई. भट्टाचार्य (2022)। 'प्रतिफल वक्र हमें अर्थव्यवस्था के बारे में क्या बता रहा है?' *आरबीआई बुलेटिन*, जून।

सारणी 4: वित्तीय बाजार - दर और स्प्रेड

लिखत	ब्याज दरें (प्रतिशत)			स्प्रेड (बीपीएस) (संबंधित जोखिम मुक्त दर के आधार पर)		
	जुला 16 - अग 15 2022	अग 16 - सितं 09 2022	परिवर्तन (बीपीएस में)	जुला 16 - अग 15 2022	अग 16 - सितं 09 2022	परिवर्तन (बीपीएस में)
1	2	3	(4 = 3-2)	5	6	(7 = 6-5)
कॉरपोरेट बॉन्ड						
(i) एएए (1-वर्ष)	6.63	6.90	27	28	46	18
(ii) एएए (3-वर्ष)	7.32	7.32	0	41	41	0
(iii) एएए (5-वर्ष)	7.51	7.43	-8	30	29	-1
(iv) एए (3-वर्ष)	8.04	8.06	2	113	115	2
(v) (v) बीबीबी-(3-वर्ष)	11.72	11.73	1	481	482	1
10-वर्ष जी-सेक	7.33	7.22	-11			

टिप्पणी: प्रतिफल और स्प्रेड की गणना मासिक औसत के रूप में की जाती है।
स्रोत: एफआईएमएमडीए; और ब्लूमबर्ग।

नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में परिवर्तन के पहले दौर के प्रभाव को छोड़कर आरक्षित मुद्रा (आरएम) 2 सितंबर 2022 (एक वर्ष पहले 9.3 प्रतिशत) तक वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 8.4 प्रतिशत बढ़ा [चार्ट 48]। आरएम का सबसे बड़ा घटक, संचलन में मुद्रा (सीआईसी) 8.3 प्रतिशत (एक वर्ष पहले 9.4 प्रतिशत) की दर से बढ़ा। मुद्रा आपूर्ति (एम3) - बैंकिंग क्षेत्र की देयताओं - ने 26 अगस्त 2022 को 8.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की (एक वर्ष पहले 9.5 प्रतिशत)।

चार्ट 48: मौद्रिक और ऋण कुल राशियां

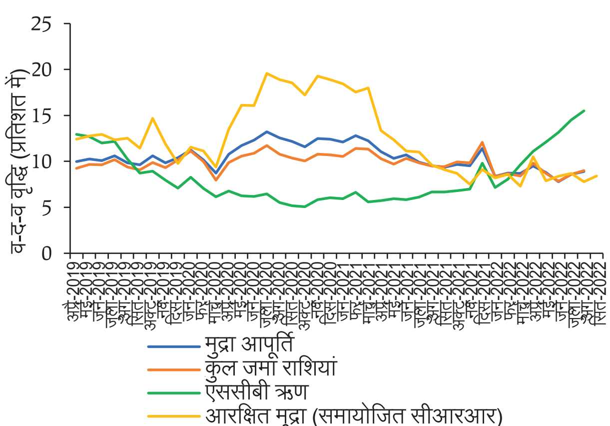

टिप्पणियां: 1. ये आंकड़े मुद्रा आपूर्ति, कुल जमा राशियों और बैंकों के क्रेडिट के लिए प्रत्येक महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं; और आरक्षित मुद्रा के लिए प्रत्येक महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं।
2. तथापि, आरक्षित मुद्रा के लिए अद्यतन आंकड़े 02 सितंबर 2022 की स्थिति के अनुसार हैं, जबकि मुद्रा आपूर्ति के लिए 26 अगस्त 2022 की स्थिति के अनुसार हैं।
स्रोत: आरबीआई।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की क्रेडिट वृद्धि 26 अगस्त 2022 को 15.5 प्रतिशत (एक वर्ष पहले 6.7 प्रतिशत) तक बढ़ गई। बैंकों की महानगरीय शाखाएं, जिनकी बैंक क्रेडिट में 60 प्रतिशत से अधिक और बैंक जमा राशि में आधे से अधिक हिस्सेदारी है, बैंकिंग व्यवसाय के विकास के प्रमुख चालक रही हैं।

अप्रैल से जुलाई 2022 के दौरान, जब नीतिगत रिपो दर में 90 आधार अंकों की वृद्धि की गई थी, एससीबी के नए और बकाया रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दरों (डब्ल्यूएएलआर) में क्रमशः 55 आधार अंकों और 27 आधार अंकों की वृद्धि हुई थी (सारणी 5)। इसके अलावा प्रमुख बैंकों ने अगस्त के अंत में अपनी बाह्य बेंचमार्क-आधारित उधार दरों (ईबीएलआर) को कुल 140 आधार अंकों तक पूरी तरह से समायोजित किया है। अप्रैल से अगस्त 2022 के दौरान, एससीबी की निधि-आधारित उधार दर (एमसीएलआर) की 1-वर्षीय औसत सीमांत लागत में 55 आधार अंकों की वृद्धि हुई।

सारणी 5: रेपो दर से बैंकों की जमा और उधार दरों में अंतरण

(आधार अंकों में परिवर्तन)

अवधि	रेपो दर	जमा दरें		उधार दरें		
		मीडियन टीडीआर (नया जमा)	डब्ल्यूएडी-टीडीआर (बकाया जमा)	1-वर्ष एम-सीएलआर (मिडियन)	डब्ल्यू-एए-लआर (नया रुपए ऋण)	डब्ल्यूएए-लआर (बकाया रुपए ऋण)
अप्रैल-अगस्त 2022*	**140**	**24**	**19**	**55**	**55**	**27**
मेमो						
अप्रैल 2022	0	0	0	0	-12	-2
मई से अगस्त 2022*	140	24	19	55	67	29

* डब्ल्यूएएलआर और डब्ल्यूएडीटीडीआर पर अद्यतन डेटा जुलाई 2022 से संबंधित हैं और इसलिए अगस्त में रिपो दर में 50 आधार अंकों की वृद्धि डब्ल्यूएएलआर और डब्ल्यूएडीटीडीआर के लिए प्रभाव-अंतरण में नहीं दिखाई दी है।
डब्ल्यूएएलआर: भारित औसत उधार दर; डब्ल्यूएडीटीडीआर: भारित औसत घरेलू मीयादी जमा दर।
एमसीएलआर: निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत; टीडीआर: सावधि जमा दर।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

प्रणालीगत चलनिधि में कमी के साथ-साथ क्रेडिट मांग में वृद्धि ने, बैंकों को स्थिर निधीयन के लिए अपनी जमा दरों में वृद्धि करने के लिए प्रेरित किया है। मीडियन टर्म जमाराशि दरें- नई खुदरा जमाराशि पर कार्ड की दरों में अप्रैल से अगस्त 2022 के दौरान 24 आधार अंकों की वृद्धि हुई है। थोक जमाराशियों पर ब्याज दरों में वृद्धि और भी अधिक है। उपलब्ध जानकारी इंगित करती है कि प्रमुख बैंकों ने अप्रैल 2022 से अपनी थोक जमा दरों (1 से 2 वर्ष की अवधि) में 200 आधार अंकों तक की वृद्धि की है।

बैंक समूह स्तर पर, विदेशी बैंकों के मामले में उधार और जमा दरों में संचरण अधिकतम था, जो उनकी कुल देयताओं में कम लागत और कम अवधि के थोक जमा के उच्च हिस्से को दर्शाता है (चार्ट 49)। निजी बैंकों की तुलना में घरेलू बैंकों में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने नए उधारकर्ताओं के लिए रिपो दर में बढ़ोतरी को उधार दरों में तेजी से पास किया।

भारतीय इक्विटी बाजार ने अगस्त 2022 में लगातार दूसरे महीने धनात्मक प्रतिफल प्राप्त किए, जिसमें बीएसई सेंसेक्स में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मजबूत जीएसटी संग्रह और जुलाई के लिए प्रत्याशा से अधिक घरेलू विनिर्माण पीएमआई डेटा के उत्तर में बाजारों ने महीने की शुरुआत तेजी के साथ की। यूएस-चीन तनाव के बाद कमजोर वैश्विक संकेतों को दरकिनार करते हुए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की खरीदारी, घरेलू मुद्रास्फीति में गिरावट और खुदरा बिक्री में तेजी के बीच घरेलू इक्विटी ने ग्रीन में कारोबार करना जारी रखा। यूएस फेड और यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) की ओर से भविष्य में दरों में बढ़ोतरी पर आक्रामक बयानों के बाद एशियाई साथियों के साथ लॉकस्टेप में महीने के अंत में बाजार में आशंका महसूस हुई। खराब शुरुआत के बाद, सितंबर में घरेलू इक्विटी में उछाल आया, पण्य कीमतों में गिरावट के बीच बीएसई सेंसेक्स 9 सितंबर 2022 को 0.4 प्रतिशत की बढ़त के साथ 59,793 पर बंद हुआ। 2022-23 में अब तक, भारतीय इक्विटी ने अधिकांश उन्नत और ईएमई समकक्षों की तुलना में आघात-सहनीयता दिखाई है (चार्ट 50ए)। परिणामस्वरूप, मूल्यन अधिक बना रहा, सेंसेक्स के 12 महीने का वायदा कीमत अर्जन अनुपात 21.6 गुना तक बढ़ गया, जिससे बॉन्ड प्रतिफल-अर्जन प्रतिफल अंतर[17] 2.5 फीसदी हो गया, जो कि इसके दीर्घावधि औसत 1.7 प्रतिशत से 75 आधार अंक अधिक है (चार्ट 50बी)।

चार्ट 49: उधार और जमा दरों में बैंक समूह-वार संचरण (अप्रैल से जुलाई 2022)

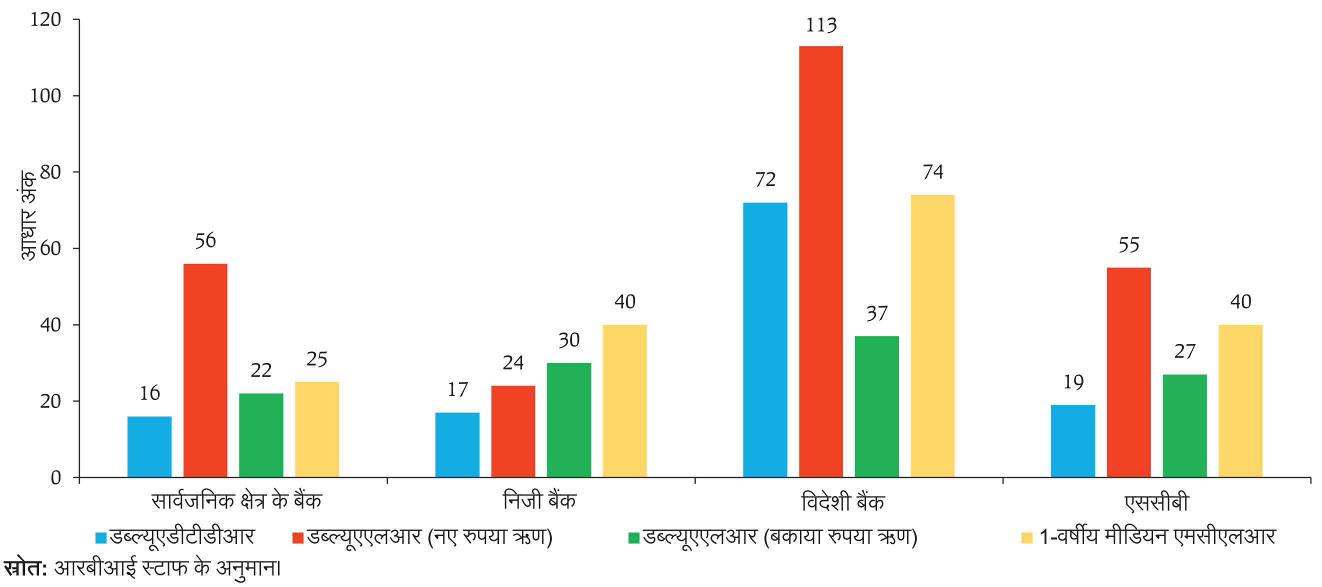

स्रोत: आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

[17] अर्जन पर प्रतिफल एक मूल्यन मेट्रिक है, जो प्रति शेयर आय को प्रति शेयर मौजूदा कीमत से विभाजित करता है (कीमत अर्जन अनुपात का व्युत्क्रम)। जैसे-जैसे मूल्यन का विस्तार होता है, अर्जन पर प्रतिफल घटता जाता है और इसके *विलोमतः* होता है। इक्विटी निवेश के सापेक्ष आकर्षण का पता लगाने के लिए सेंसेक्स अर्जन और दीर्घावधि जी-सेक के बीच प्रतिफल में अंतर को ट्रैक किया जाता है।

चार्ट 50: इक्विटी बाजार और मूल्यांकन

ए. वैश्विक इक्विटी बाजार रिटर्न (प्रतिशत)

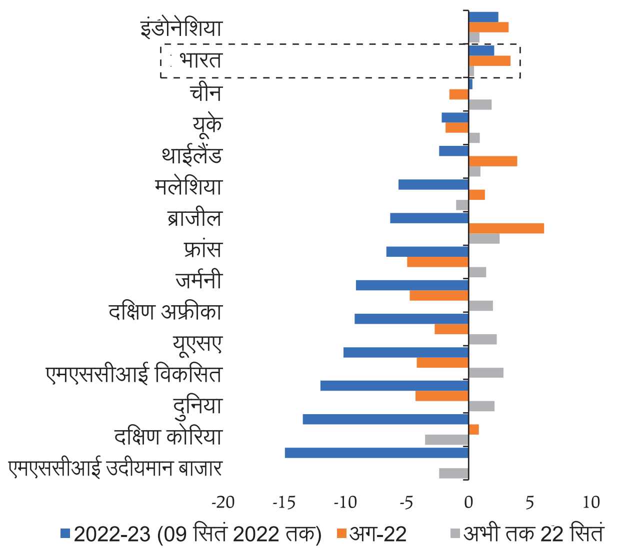

बी. सेंसेक्स के 12 महीने की फॉरवर्ड अर्निंग यील्ड और 10 साल की जी-सेक यील्ड के मध्य स्प्रेड

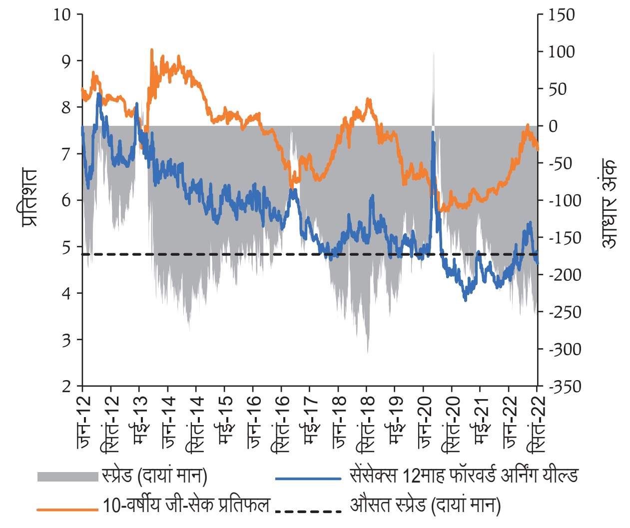

स्रोत: ब्लूमबर्ग और आरबीआई स्टाफ द्वारा की गई गणना।

एफपीआई, भारतीय इक्विटी के आक्रामक खरीदार बने रहे और अगस्त में ₹53,994 करोड़ डाले। दूसरी ओर, घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) लगातार 17 महीनों तक इक्विटी बाजार में भारी खरीदारी करने के बाद अगस्त 2022 में ₹7,069 करोड़ के निवल विक्रेता बन गए, जिसने बड़े पैमाने पर एफपीआई द्वारा बिक्री के दबाव को अवशोषित किया (चार्ट 51ए)। इसके अलावा, पार्टिसिपेटरी नोट्स के माध्यम से भारतीय पूंजी बाजार में एफआईआई निवेश जुलाई 2022 के अंत में घटकर ₹75,725 करोड़ हो गया, जो लगातार तीसरे महीने गिरावट के बाद 2 वर्षों में (अक्टूबर 2020 के बाद से) सबसे निम्न स्तर है (चार्ट 51बी)। हालांकि, अगस्त 2022 में खुदरा निवेशकों ने डीमैट खातों की संख्या 100 मिलियन के मील के

चार्ट 51: संस्थागत निवेश

ए. संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय इक्विटी में निवल निवेश

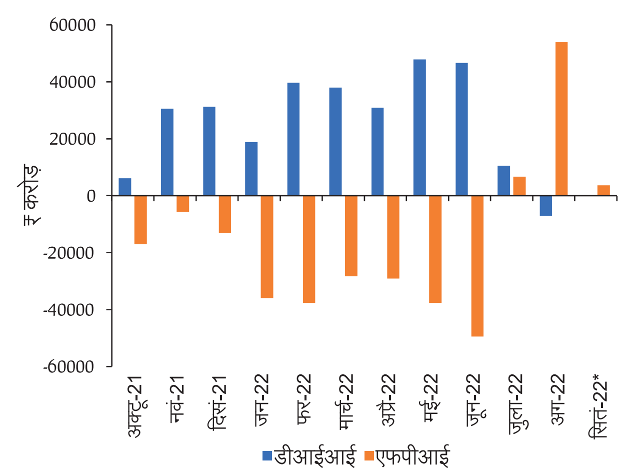

बी. पार्टिसिपेटरी नोट्स के माध्यम से निवेश

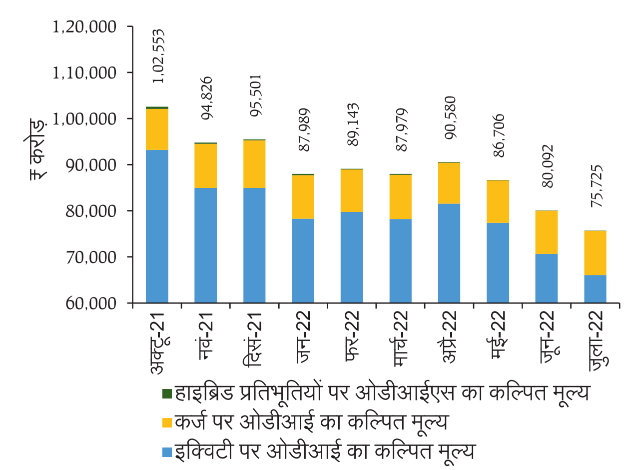

टिप्पणी: ओडीआई: अपतटीय डेरिवेटिव लिखतें। *: डेटा 9 सितंबर 2022 तक का है।
स्रोत: एनएसडीएल; कैपिटलाइन; और सेबी।

पत्थर तक पहुंचने के साथ घरेलू इक्विटी बाजार में प्रवेश करना जारी रखा।

अप्रैल-जुलाई 2022 के दौरान 29.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सकल आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) एक वर्ष पहले के स्तर से अधिक था (चार्ट 52)। इसी तरह, निवल एफडीआई इस अवधि के दौरान एक साल पहले के 13.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 18.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसका मुख्य कारण नए इक्विटी अंतर्वाह में वृद्धि और भारत से बाह्य एफडीआई में गिरावट है। अप्रैल-जुलाई 2022 के दौरान विनिर्माण, सेवाओं और खुदरा और थोक व्यापार क्षेत्रों को एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह का प्रमुख हिस्सा प्राप्त हुआ।

अगस्त 2022 में एफपीआई द्वारा इक्विटी में 6.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निवल खरीदारी दिसंबर 2020 के बाद से सबसे अधिक थी, जो उदीयमान बाजार के सहभागियों से अधिक है (चार्ट 53)। भारतीय इक्विटी में नए सिरे से पोर्टफोलियो की रुचि मजबूत कॉरपोरेट आय और मैक्रो फंडामेंटल में सुधार के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। वित्तीय सेवाओं, बिजली, और तेल, गैस और उपभोज्य ईंधन क्षेत्र एफपीआई इक्विटी अंतर्वाह के सबसे बड़े प्राप्तकर्ता थे। अगस्त में एफपीआई भी भारतीय कर्ज बाजार में निवल खरीदार बने।

चार्ट 52: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)

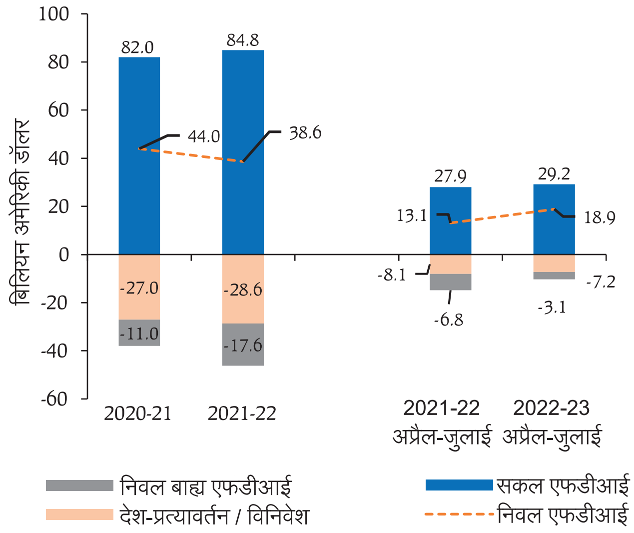

स्रोत: आरबीआई।

अप्रैल-जुलाई 2022 के दौरान भारत में सकल बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) एक वर्ष पहले के 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। अंतर-कंपनी उधारों को छोड़कर, ईसीबी ने इस अवधि के दौरान 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल पुनर्भुगतान दर्ज किया, जबकि एक साल पहले 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल

चार्ट 53: निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई)

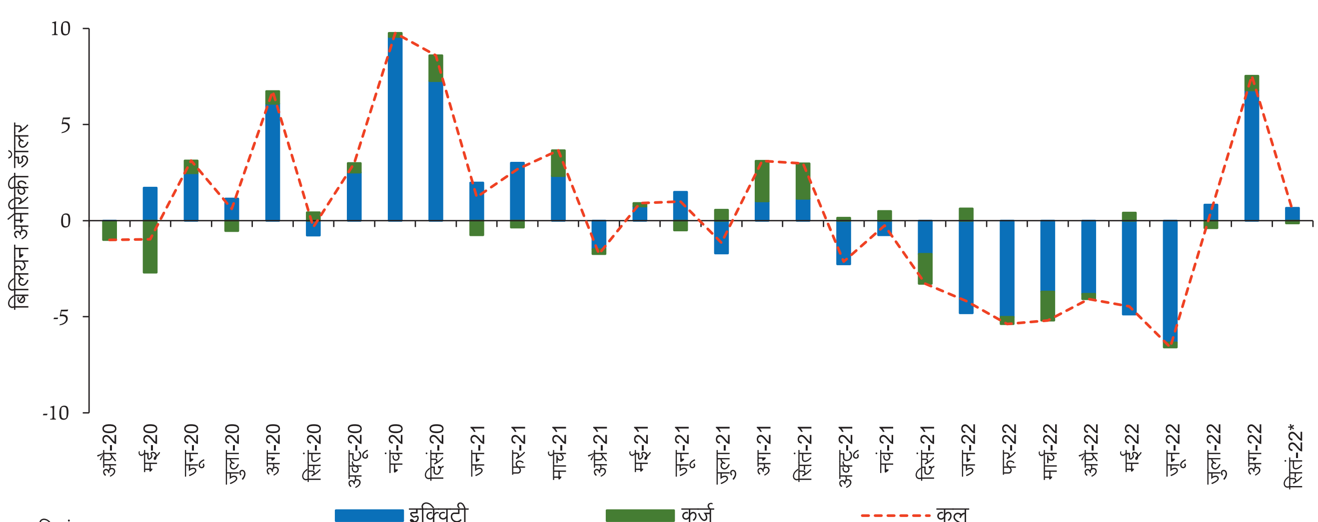

*12 सितंबर 2022 तक

स्रोत: राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)।

चार्ट 54: ईसीबीएस की समग्र लागत

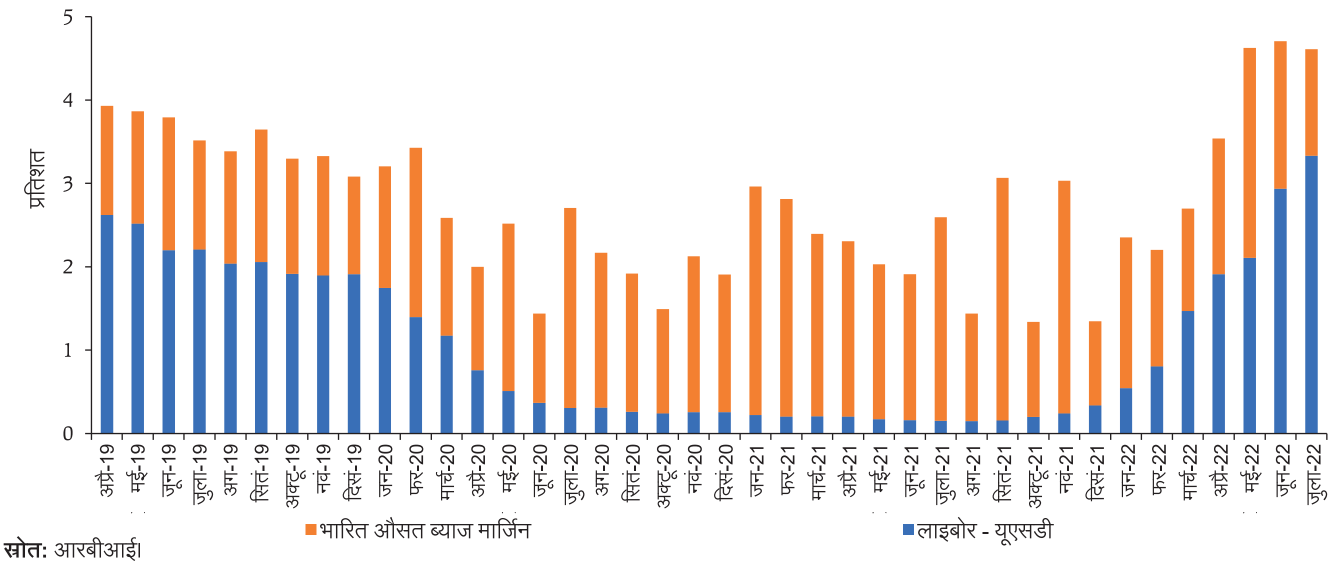

स्रोत: आरबीआई।

भुगतान किया गया था। जुलाई 2022 में ईसीबी का बड़ा हिस्सा, आगे उधार देने (ऑन-लेंडिंग)/ सब-लेंडिंग, पहले के ईसीबी के पुनर्वित्त और कार्यशील पूंजी के उद्देश्य से जुटाया गया था। जनवरी 2022 से जुलाई 2022 के बीच लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (लाइबोर) और सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट (एसओएफआर) में क्रमशः 280 आधार अंकों और 220 आधार अंकों की वृद्धि के साथ बेंचमार्क वैश्विक दरें हाल की अवधि में बढ़ रही हैं। तथापि, ईसीबी ऋणों की समग्र लागत अपेक्षाकृत कम रही है क्योंकि ईसीबी की भारित औसत ब्याज दर स्प्रेड (बेंचमार्क ब्याज दर से अधिक) घट रही है (चार्ट 54)।

2 सितंबर 2022 को 553.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार, 2022-23 के लिए अनुमानित आयात के 9 महीनों के समतुल्य था (चार्ट 55)।

चार्ट 55: विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां

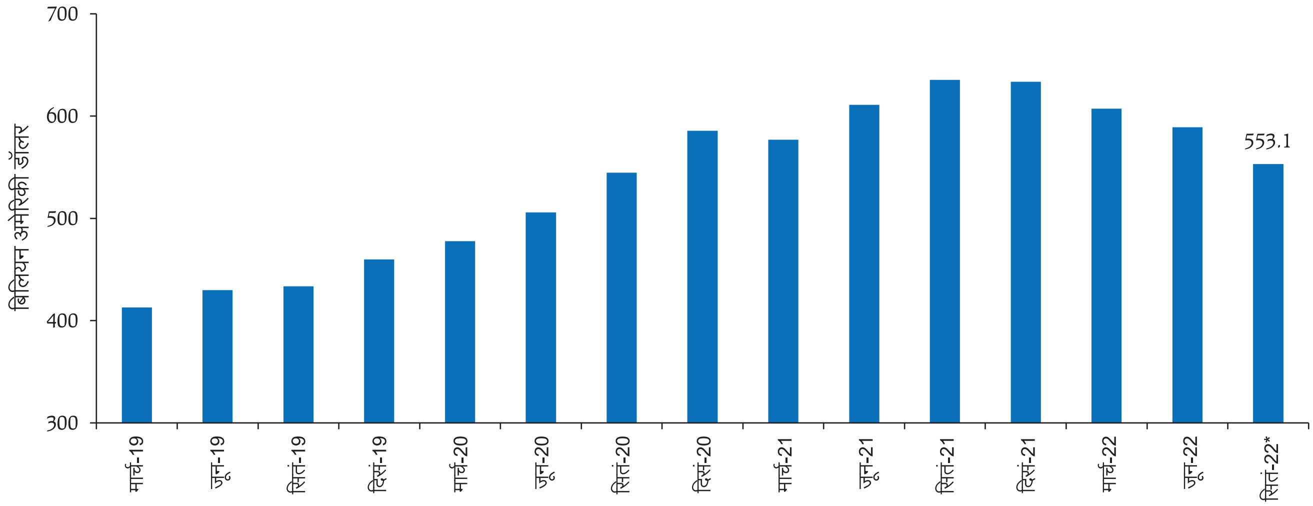

*2 सितंबर 2022 की स्थिति के अनुसार।

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट 56: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये और ईएमई मुद्राओं का उतार-चढ़ाव (अगस्त 2022, माह-दर-माह)

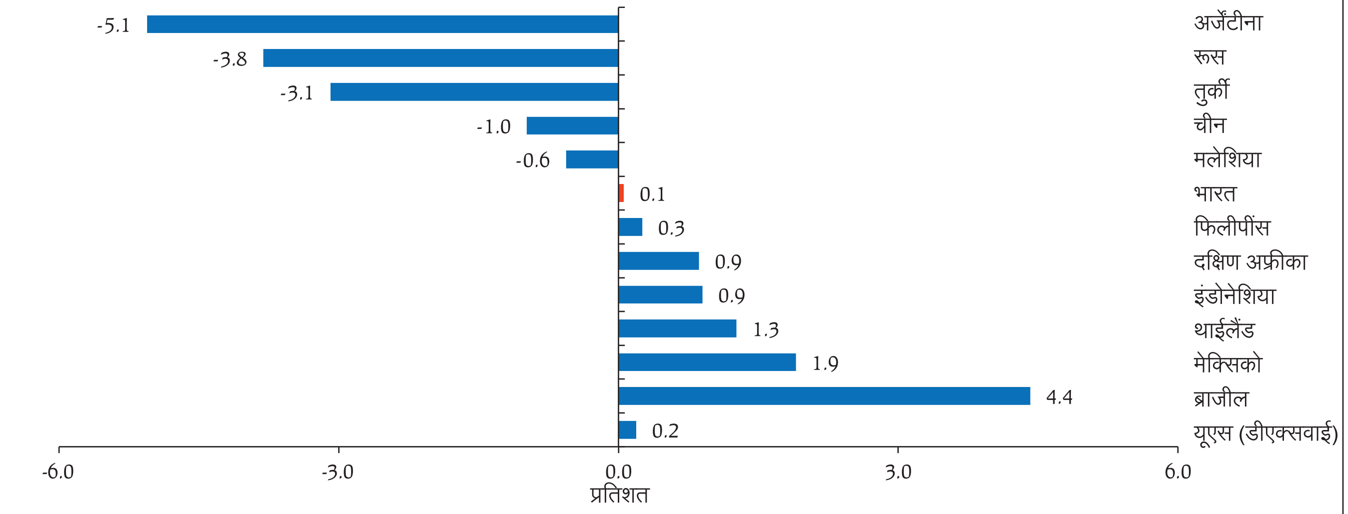

स्रोत: एफबीआईएल; थॉमसन रॉयटर्स; और आरबीआई स्टाफ द्वारा की गई गणना।

विदेशी मुद्रा बाजार में, अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने के बावजूद, अगस्त 2022 में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये (आईएनआर) में 0.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट 56)।

महीने में आईएनआर की 40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) के संदर्भ में सराहना हुई क्योंकि यह सांकेतिक प्रभावी शर्तों में बढ़ी (चार्ट 57)।

भुगतान प्रणाली

अगस्त 2022 में, बड़े मूल्य और खुदरा क्षेत्रों में फैले डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र ने मात्रा और मूल्य के आधार पर प्रगति करना जारी रखा (वर्ष-दर-वर्ष, सारणी 6)। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने ₹10.73 लाख करोड़ मूल्य के 658 करोड़ लेनदेन के साथ अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर को बनाए रखा। भारतीय सीमाओं से परे यूपीआई के एकीकरण का विस्तार करने के प्रयासों

चार्ट 57: 40 मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) में मासिक उतार-चढ़ाव

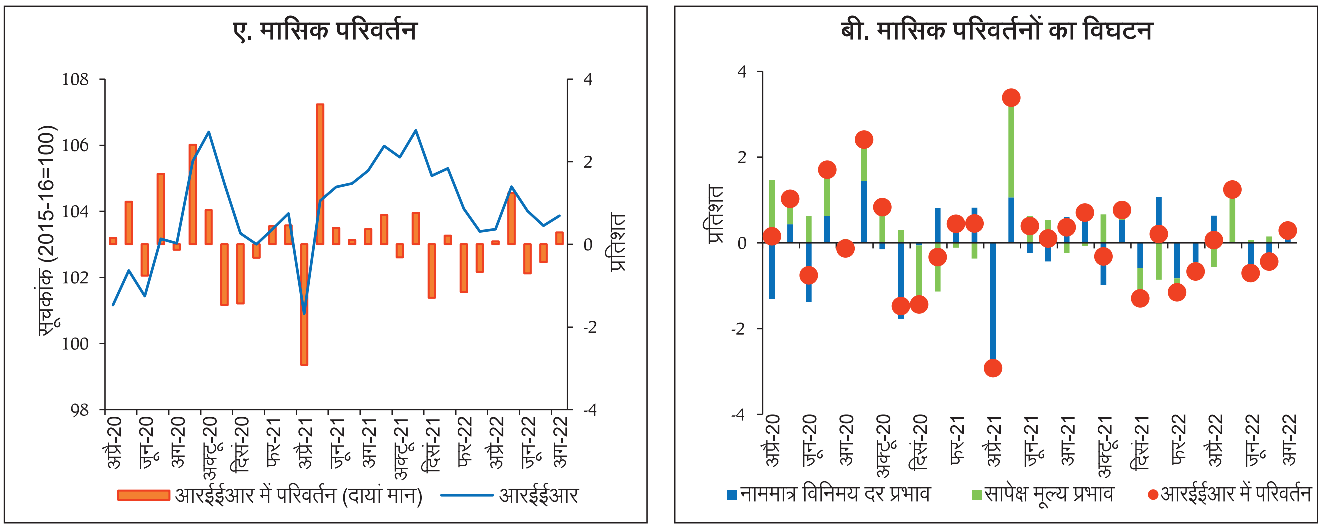

टिप्पणी: अगस्त 2022 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: आरबीआई।

सारणी 6: चुनिंदा भुगतान प्रणालियों में वृद्धि दर

(प्रतिशत)

भुगतान दर संसूचक	लेनदेन मात्रा वृद्धि (वर्ष दर वर्ष)				लेनदेन मूल्य वृद्धि (वर्ष दर वर्ष)			
	जुला-21	जुला-22	अग-21	अग-22	जुला-21	जुला-22	अग-21	अग-22
आरटीजीएस	34.4	12.9	42.6	12.9	28.9	7.5	39.4	14.8
एनईएफटी	32.0	26.8	37.2	29.5	12.3	19.2	14.5	19.1
यूपीआई	116.7	93.8	119.6	85.1	108.5	75.5	114.2	67.9
आईएमपीएस	58.7	30.7	54.3	23.0	37.9	42.8	36.2	39.3
एनएसीएच	1.9	36.4	-2.3	14.3	1.8	29.4	21.0	24.3
एनईटीसी	122.0	37.9	107.8	35.2	83.4	39.8	79.6	38.0
बीबीपीएस	153.7	67.9	177.6	48.5	159.3	68.7	172.5	56.1

स्रोत: आरबीआई।

से विकास की इस गति को टर्बोचार्ज करने की उम्मीद है।[18] यूपीआई और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई-मोबाइल वॉलेट) के औसत मासिक लेनदेन मूल्यों में कमी छोटे मूल्य के लेनदेन की जरूरतों को पूरा करने के लिए खुदरा डिजिटल मोड की ओर बढ़ते बदलाव का संकेत देती है।[19] दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रीय वित्तीय स्विच (एनएफएस) के माध्यम से नकद निकासी का टिकट आकार भी कम हो गया है, जो महामारी-प्रेरित एहतियाती जमाशेष के कम होने का संकेत देता है। अन्य खुदरा भुगतान मोड जैसे तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी), और भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) ने एक साल पहले उच्च आधार के बावजूद मजबूत वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) प्रदर्शित की है।

मजबूत नीति समर्थन, व्यापक रूप से प्रौद्योगिकी के प्रयोग और बढ़ती वित्तीय जागरूकता से प्रेरित, भारतीय फिनटेक बाजार 2030 तक प्रबंधन के तहत आस्ति (एयूएम) यूएस $ 1 ट्रिलियन और राजस्व के तहत यूएस $ 200 बिलियन तक अर्थात 2021 की तुलना में लगभग 10- गुना वृद्धि (क्रमशः 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर) तक पहुंचने के लिए तैयार है।20 एक प्रमुख फिनटेक घटक - डिजिटल ऋण - 2030 तक 515 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।"21

अगस्त में, रिज़र्व बैंक ने एक सहयोगी और अंशांकित दृष्टिकोण के माध्यम से भुगतान उद्योग की रूपरेखा बदलने के उद्देश्य से तीन प्रमुख पहलें की है। पहला, 'भुगतान प्रणालियों में प्रभारों पर चर्चा पत्र' के माध्यम से भुगतान सेवाओं के लिए विभिन्न शुल्कों पर प्रतिपुष्टि की समीक्षा का अनुरोध किया गया है। तत्पश्चात रिज़र्व बैंक ने ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली को बदलने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण के एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की। अंत में, रिज़र्व बैंक ने एक कार्यकारी समूह (अध्यक्ष: श्री जेके दाश) की सिफारिशों के आधार पर डिजिटल ऋण देने संबंधी विनियामकीय ढांचा जारी किया है।22 इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, विनियमित संस्थाओं से ग्राहकों को ऋण का सीधा संवितरण; ऋण व्यवस्था की शर्तों का पर्याप्त प्रकटीकरण; स्पष्ट सहमति के बिना ऋण सीमा में स्वत: वृद्धि पर रोक; और स्पष्ट लेखा-परीक्षा के पश्चात आवश्यकता-अनुसार आंकड़ा संग्रह शामिल है।

निष्कर्ष

इस आलेख के अगस्त संस्करण में, हमने परिकल्पना की थी कि अप्रैल 2022 में मुद्रास्फीति चरम पर होगी और उसके बाद मूल्य परिवर्तन की गति में एक गंभीर और असमान सहजता होगी।

[18] एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) ने यूके में यूपीआई की स्वीकार्यता को अंतरराष्ट्रीय बनाने के लिए भुगतान समाधान प्रदाता पेएक्सपर्ट के साथ साझेदारी की है।

[19] 2021-22 में यूपीआई भुगतान के लिए औसत टिकट का आकार ₹1,841 और पीपीआई-मोबाइल वॉलेट के लिए ₹416 था। ये मूल्य क्रमशः ₹1,630 (अगस्त 2022) और ₹386 (जुलाई 2022) तक कम हो गए हैं।

[20] चिराटे वेंचर्स और ईवाई, अगस्त 2022 । 1 ट्रिलियन $ *इंडिया फिनटेक ऑपर्चुनिटी।*

[21] आईबीआईडी ।

[22] ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से उधार देने सहित डिजिटल उधारी पर कार्य समूह की 22वीं रिपोर्ट, आरबीआई (13 जनवरी 2021 को गठित)।

अगस्त 2022 का आकलन काफी हद तक इस भविष्यवाणी के अनुरूप था - वास्तव में, हेडलाइन मुद्रास्फीति की गति जून/जुलाई के 0.5 प्रतिशत के स्तर से अपरिवर्तित थी, लेकिन आधार प्रभावों के समाप्त होने से जुलाई की तुलना में हेडलाइन में 30 आधार अंकों की वृद्धि हुई। हालांकि, खाद्य कीमतों के दबाव में फिर से उछाल आया है, जो मुख्य रूप से अनाज से प्रभावित है, यहां तक कि ईंधन और मुख्य घटकों ने राहत का एक मामूली उपाय प्रदान किया है। सितंबर में वर्षा में स्थानिक असमानता के कारण प्रमुख सब्जियों, विशेष रूप से टमाटर की कीमतों में उछाल आया है। इसके अलावा, खाद्य मोर्चे पर, हमें मानसून की देरी से वापसी के पूर्वानुमान के प्रभाव के लिए भी तैयार रहने की जरूरत है। इन दबाव बिंदुओं और हाल की नरमी के बावजूद ऊर्जा की कीमतों के आसपास भारी अनिश्चितता को छोड़कर, हम अपने विचार को बनाए रखते हैं कि मुद्रास्फीति की गति तीसरी तिमाही में कम होनी चाहिए और चौथी तिमाही में थोड़ा ऋणात्मक हो जाना चाहिए। 2022-23 की दूसरी छमाही में आधार प्रभाव के अनुकूल होने के साथ, मुद्रास्फीति में कमी आनी चाहिए, हालांकि अपसाइड जोखिम बना हुआ हैं। आयातित मुद्रास्फीति के दबाव कम हो रहे हैं, विनिमय दर में स्थिरता से मदद मिली है, और इनपुट लागत कम हो गई है, जिससे अधोगामी पक्ष में, इसका विक्रय मूल्यों तक प्रसारण कम हो सकता है।

कम सख्त मुद्रास्फीति दृष्टिकोण भी भारत के व्यापार की निवल आधार पर सुधार के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका बाह्य चालू खाता शेष के लिए अनुकूल प्रभाव होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगले कुछ महीनों में कच्चे तेल के अनुबंधों की भविष्य की कीमतों में नरमी आई है। वनस्पति तेलों और उर्वरकों की अंतरराष्ट्रीय कीमतें भी पहले की तुलना में कम दिख रही हैं। कुछ अन्य संभावनाएं भी हैं। अगस्त में पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई है। मुक्त व्यापार समझौतों के साथ नए बाजार खुल रहे हैं। कुल मिलाकर, 2022-23 के लिए वस्तुओं और सेवाओं के लिए 750 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात लक्ष्य पहुंच के भीतर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा, पिछले साल 90 अरब अमेरिकी डॉलर के अंतर्वाह के साथ भारत दुनिया में शीर्ष धनप्रेषण प्राप्तकर्ता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है और एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर, चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 3.0 प्रतिशत के भीतर रहने की उम्मीद है। पोर्टफोलियो प्रवाह की रिकवरी और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के मजबूत रहने के साथ, घाटे का यह क्रम प्रमुख रूप से वित्तपोषित है।

इस महत्वपूर्ण मोड़ पर, मौद्रिक नीति को अर्थव्यवस्था के लिए नाममात्र के सहारादाता की भूमिका निभानी है क्योंकि यह एक नए विकास प्रक्षेपवक्र की ओर अग्रसर है। लक्ष्य के साथ मुद्रास्फीति को संरेखित करने के लिए लगातार समय पर ध्यान देना चाहिए। इस संदर्भ में, मौद्रिक नीति की एकबारगी कार्रवाई मुद्रास्फीति की उम्मीदों को मजबूती से बनाए रख सकता है और मध्यम अवधि के विकास हानि को कम कर सकता है।

अनुबंध

श्रमिक बाजार के आंकड़े: विपथनकारी प्रवृत्ति?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसएंडपीआई) ने 31 अगस्त, 2022 को अप्रैल-जून 2022 से संबंधित शहरी क्षेत्रों के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफ़एस) 23 का त्रैमासिक बुलेटिन जारी किया। रिपोर्ट सभी प्रमुख श्रम बाजार संकेतकों, जैसे - श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर), श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) और बेरोजगारी दर (यूआर) में जून 2022 को समाप्त तिमाही में क्रमिक रूप से और पिछले वर्ष की तुलना में; दोनों संकेतकों में सुधार दिखाती है। जनवरी-मार्च 2022 में श्रम बल की भागीदारी दर 47.3 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल-जून 2022 में 47.5 प्रतिशत हो गई, जबकि इसी अवधि में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 43.4 प्रतिशत से बढ़कर 43.9 प्रतिशत हो गया। दूसरी ओर, बेरोजगारी दर जनवरी-मार्च 2022 में 8.2 प्रतिशत से घटकर अप्रैल-जून 2022 में 7.6 प्रतिशत हो गई। यह एक वर्ष पहले दर्ज 12.6 प्रतिशत के स्तर से भी काफी नीचे गिर गई।

चूंकि भारत में श्रम बाजार के आधिकारिक अनुमान आम तौर पर एक अंतराल के बाद उपलब्ध होते हैं, इसलिए विभिन्न निजी स्रोतों से रोजगार के आंकड़े संबंधी जानकारी का उपयोग श्रम बाजार में रुझान को मापने के लिए किया जाता है। त्रैमासिक आवृत्ति पर शहरी क्षेत्रों के लिए पीएफएलएस और सीपीएचएस में श्रम बाजार के आंकड़ों की तुलना करने पर, यह पाया गया है कि दोनों डेटासेट में श्रम भागीदारी दर अपने महामारी-पूर्व स्तर (जनवरी-मार्च 2020) को प्राप्त नहीं कर पाई है, श्रमिक जनसंख्या अनुपात केवल पीएलएफएस के तहत ही महामारी से पहले के स्तर को पार किया है। यद्यपि, पीएलएफएस के तहत अप्रैल-जून 2022 के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात महामारी-पूर्व स्तर से 0.2 प्रतिशत अंक ऊपर है, यह अभी भी सीपीएचएस (चार्ट ए1ए) के तहत 2.6 प्रतिशत अंक से पीछे है।

बेरोजगारी दर पर कोविड-19 महामारी का प्रतिकूल प्रभाव दोनों सर्वेक्षण डेटासेट में समान है। दूसरी ओर, पीएलएफएस के डेटा अप्रैल-जून 2021 से शहरी क्षेत्रों में तिमाही बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट दिखाते हैं, जबकि सीपीएचएस डेटा से पता चलता है कि जुलाई-सितंबर 2021 की तिमाही में बेरोजगारी दर महामारी की दूसरी लहर के उच्च स्तर से गिरने के बाद, लगभग 7.5 प्रतिशत पर स्थिर बनी रही (चार्ट ए1बी)।

चार्ट ए1: श्रम बाजार की स्थिति (शहरी, त्रैमासिक)

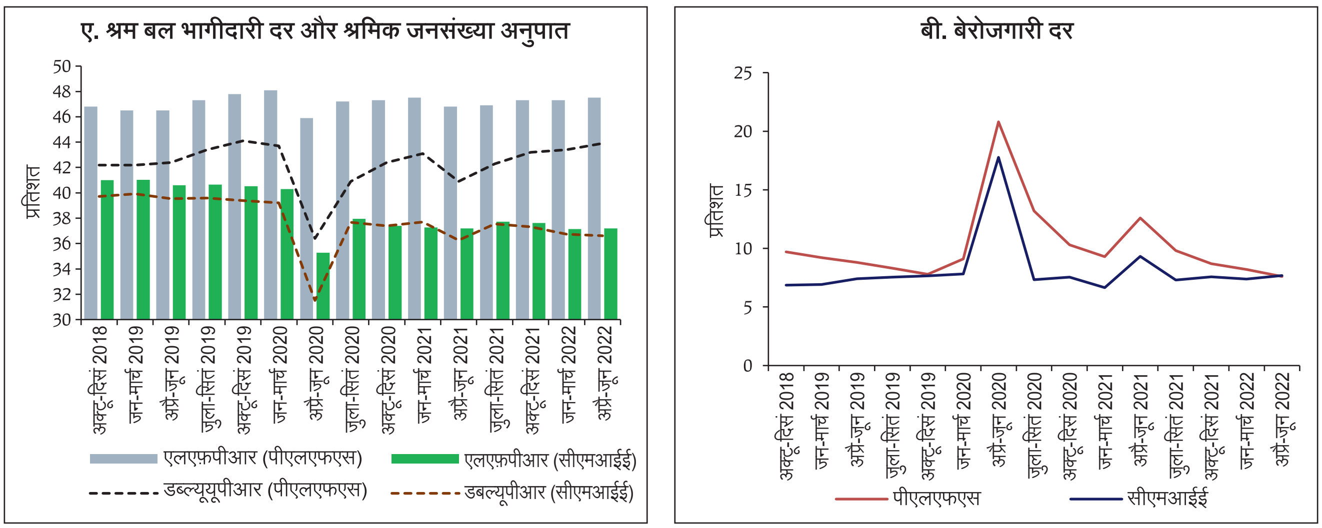

टिप्पणी: सभी तुलनाएं 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए हैं।
स्रोत: पीएलएफएस; सीपीएचएस।

(जारी)

[23] आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) पर प्रेस नोट, तिमाही बुलेटिन (अप्रैल-जून 2022), राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार। *(https://mospi.gov.in/documents/213904/416359//3.Press_note_QB151661945262123.pdf/8642cf-aae6-41a0-69f2-7c2060352708)*

ये विसंगतियां विभिन्न निजी स्रोतों से रोजगार के आंकड़ों की सटीकता पर सवाल उठाती हैं। पीएलएफएस सर्वेक्षण प्रतिभागियों को रोजगार की स्थिति प्रदान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत पद्धति24 को अपनाता है। शहरी क्षेत्रों के लिए त्रैमासिक रिपोर्ट में, पीएलएफएस वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) पद्धति का अनुसरण करता है। इस पद्धति के तहत, एक व्यक्ति को नियोजित माना जाता है यदि व्यक्ति पिछले सप्ताह के कम से कम एक घंटे के लिए आय-सृजन गतिविधि में जुड़ा होता है। दूसरी ओर, सीपीएचएस, एक नियोजित व्यक्ति को केवल तभी मानता है जब व्यक्ति सर्वेक्षण के दिन या सर्वेक्षण से पहले वाले दिन किसी आर्थिक गतिविधि में शामिल हो या आम तौर पर नियमित रूप से आर्थिक गतिविधि में शामिल हो लेकिन इन दिनों केवल अस्थायी रूप से काम नहीं किया हो।25 यह श्रम बाजार के संकेतकों में अंतर लाता है। श्रम बाजार के रुझान को समझने और नीतियां बनाने के लिए इन डेटासेट का उपयोग करते समय इन समस्याओं को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है।

[24] *https://mospi.gov.in/documents/213904/301563//Quarterly%20Bulletin%20PLFS%20April%20June%202022 1661945175911.pdf/c904e4b1-c5c8-2421-53f9-8e064e0db20a*
[25] *consumerpyramiddx.cmie.com*

इनपुट कीमतों के प्रति आउटपुट कीमतों की संवेदनशीलता: भारत के लिए एक अनुभवजन्य विश्लेषण*

आस्था ^, शैलजा भाटिया ^
और संगीता मिश्रा द्वारा ^

उच्च वैश्विक ऊर्जा कीमतों, कमोडिटी कीमतों और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के परिणामस्वरूप बढ़े हुए इनपुट मूल्य दबाव व्यापार चक्र के चरण और फर्मों की मूल्य निर्धारण शक्ति के आधार पर आउटपुट कीमतों को बढ़ा सकते हैं। उपयुक्त मौद्रिक नीति प्रतिक्रिया के लिए अलग-अलग बाजार स्थितियों में खुदरा कीमतों के लिए इनपुट कीमतों के पास-थ्रू की गतिशीलता को समझना महत्वपूर्ण है। लेख में अनुभवजन्य विश्लेषण भारत में इनपुट कीमतों से आउटपुट कीमतों तक मामूली पास-थ्रू का सुझाव देते हैं, आउटपुट कीमतों की संवेदनशीलता के साथ इनपुट कीमतों को गैर-रैखिक पाया जाता है, जब इनपुट कीमतों की घटना अधिक होती है।

I. प्रस्तावना

2021 के बाद से वैश्विक मुद्रास्फीति में वृद्धि, मुख्य रूप से महामारी से उत्पन्न आपूर्ति-पक्ष के कारकों के कारण, यूरोप में युद्ध से विपरीत परिस्थितियों के कारण और अधिक उलझ गई। लगातार वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं और सेवाओं के सापेक्ष वस्तुओं की मांग में मजबूत पलटाव के बीच उच्च वैश्विक ऊर्जा और वस्तुओं की कीमतों के कारण बढ़े हुए इनपुट मूल्य दबावों ने दुनिया भर में त्वरित लागत-धक्का मुद्रास्फीति के लिए प्रजनन आधार तैयार किया। आम तौर पर, ऐसे पण्य मूल्य आघातों का समग्र मुद्रास्फीति पर केवल अस्थायी प्रभाव होगा। हालांकि, यह निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है कि क्या उच्च इनपुट लागत उच्च हेडलाइन मुद्रास्फीति में परिवर्तित हो रही है, जो अस्थायी होने के बजाय लगातार बनी रहती है, इन उच्च इनपुट कीमतों के आउटपुट कीमतों के पास-थ्रू की सीमा है, जिसे आम तौर पर मूल्य निर्धारण शक्ति कहा जाता है, जिससे समय के साथ मूल्य दबावों का विस्तार। फर्म की मूल्य निर्धारण शक्ति की राज्य-आकस्मिक प्रकृति का समर्थन करने के लिए पर्याप्त साहित्य है जिससे पास-थ्रू मजबूत होता है जब मांग की स्थिति अनुकूल होती है और इसके विपरीत [1] (श्राबेल, 2022)। केंद्रीय बैंकों को एक सक्रिय मौद्रिक नीति का पालन करने की अनुमति देने में अच्छी तरह से स्थिर मुद्रास्फीति की उम्मीदें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अध्ययनों ने मुद्रास्फीति पास-थ्रू (लघु अवधि से लंबी अवधि के मुद्रास्फीति पूर्वानुमान) में समग्र गिरावट दिखाई है, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (येटमैन, 2020) के कारण समय के साथ बढ़ती मुद्रास्फीति की उम्मीदों का सामना करने वाले देशों की कुल हिस्सेदारी के साथ। महामारी के बाद की दुनिया में, जबकि आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के कारण इनपुट लागत लगभग हर जगह बढ़ी है, आउटपुट कीमतों के लिए इसके संचरण का पैटर्न और सीमा व्यापार चक्रों के चरण और फर्मों की मूल्य निर्धारण शक्ति के आधार पर भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में, फर्मों की मूल्य निर्धारण शक्ति 2021 (विजिल्डर, 2022) के बाद से बढ़ी हुई इनपुट कीमतों और मजबूत मांग के तीव्र दबाव के मुकाबले काफी बढ़ गई है, अन्य एई और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं (ईएमई) या तो हैं अमेरिका में शामिल होना या 2022 की शुरुआत में ऐसे दबावों का अनुभव करना शुरू कर दिया है, जिसमें उच्च इनपुट मूल्य दबावों (दास, 2022) की विस्तारित अवधि के साथ सेक्टोरल स्पिल ओवर के बढ़ते संकेत हैं।

भारत को देखते हुए, 2021-22 के बाद से कई सूचकांकों से देखी गई इनपुट लागत कीमतें बढ़ रही हैं, हालांकि मांग में निरंतर कमी (आरबीआई, 2022) को देखते हुए आउटपुट कीमतों में उनका पास-थ्रू मौन रहा है। परिणामस्वरूप, 2020-21 के मध्य से इनपुट और आउटपुट कीमतों के बीच अंतर [2] बढ़ता रहा (चार्ट 1)। चालू वर्ष वित्त वर्ष 2022-23 में, हालांकि, बढ़ती इनपुट कीमतों के कारण आउटपुट कीमतों पर दबाव के कुछ शुरुआती

^ लेखक मौद्रिक नीति विभाग से हैं।

* लेखक श्री मुनीश कपूर के मूल्यवान सुझावों और प्रतिक्रिया के लिए आभारी हैं। इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

[1] संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) में, मूल्य निर्धारण शक्ति में कमी 1990 के दशक के अंत में देश में मुद्रास्फीति में वृद्धि की अनुपस्थिति के स्पष्टीकरणों में से एक के रूप में प्रकट हुई।

[2] एस एंड पी ग्लोबल द्वारा जारी इनपुट और आउटपुट प्राइस इंडेक्स के बीच अंतर का उपयोग करके मूल्य अंतर की गणना की जाती है।

चार्ट 1: इनपुट-आउटपुट प्राइस इंडेक्स गैप और कोर इन्फ्लेशन

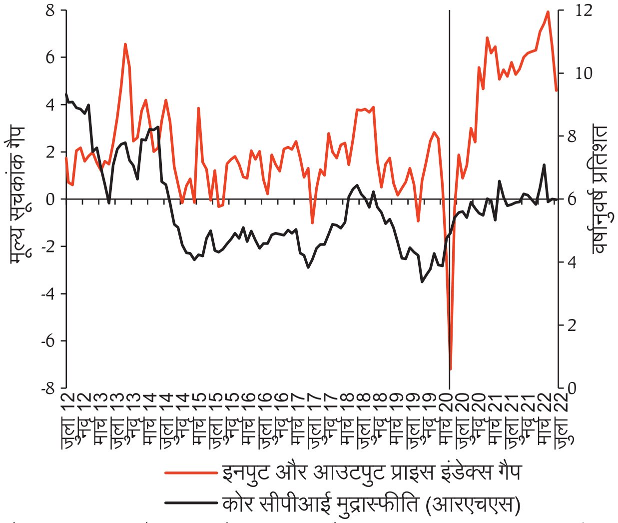

स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल: एमओएसपीआई; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान है।

संकेत रिज़र्व बैंक के सर्वेक्षणों से स्पष्ट हैं। 2022 के दौरान लगभग छह महीनों के लिए कच्चे तेल की कीमतों के 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर रहने के साथ यूरोप में युद्ध के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के साथ प्रमुख औद्योगिक आदानों की कीमतों में व्यापक उछाल ने अभूतपूर्व इनपुट के पास-थ्रू जोखिमों को और बढ़ा दिया है- प्रसंस्कृत खाद्य, गैर-खाद्य विनिर्मित उत्पादों और सेवाओं की श्रेणियों के बीच लागत दबाव। जबकि इनपुट लागत पुश दबाव निकट अवधि में राहत के कुछ संकेत प्रदर्शित कर रहे हैं, वे अनिवार्य रूप से भू-राजनीतिक कारकों के कारण अनिश्चितताओं से भरे उच्च स्तर पर बने हुए हैं। यह इस पृष्ठभूमि के खिलाफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के रूप में इनपुट लागतों के खुदरा कीमतों के पास-थ्रू की गतिशीलता की निगरानी करना अनिवार्य हो जाता है। प्रारंभिक क्षणभंगुर मुद्रास्फीति आघात बनाम दूसरे दौर के प्रभावों के बीच प्रभावी रूप से अंतर करने के लिए आपूर्ति पक्ष मुद्रास्फीति की गतिशीलता को समझना महत्वपूर्ण है।

इस प्रकार, इस लेख का प्राथमिक उद्देश्य इनपुट लागत मूल्य निर्धारण व्यवहार का विश्लेषण और डिकोड करना है और इनपुट लागत दबावों के लिए भारत में मुद्रास्फीति की संवेदनशीलता पर मौजूदा अध्ययनों को पूरक बनाना है। शेष लेख निम्नानुसार आयोजित किया गया है: खंड II भारत और अन्य प्रमुख एई और ईएमई दोनों के लिए क्रय प्रबंधक सूचकांकों (पीएमआई) के आधार पर हाल के इनपुट और आउटपुट कीमतों पर शैलीगत तथ्यों की संक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत करता है। खंड III विषय पर एक संक्षिप्त साहित्य समीक्षा की पृष्ठभूमि के खिलाफ अनुभवजन्य रूपरेखा प्रस्तुत करता है, डेटा का विवरण और अध्ययन में उपयोग की जाने वाली अनुभवजन्य पद्धति। खंड IV परिणामों पर चर्चा करता है, और अंतिम खंड टिप्पणियों के समापन की रिपोर्ट करता है।

II. इनपुट और आउटपुट मूल्य व्यवहार

मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के उभरने के बाद से पीएमआई मूल्य सूचकांक [3] से देखा गया इनपुट-आउटपुट मूल्य अंतर अर्थव्यवस्थाओं में भिन्न है। बड़े पैमाने पर आपूर्ति व्यवधान और विभिन्न कच्चे माल की लागत में वृद्धि के बीच दुनिया भर में इनपुट लागत दबाव तेज हो गया। हालाँकि, विविध पोस्ट-कोविड विकास प्रक्षेपवक्र वाले देशों के साथ, इनपुट और आउटपुट मूल्य अंतराल ने अर्थव्यवस्थाओं में अलग-अलग निशान का पालन किया है। अधिकांश देशों में इनपुट कीमतों का आउटपुट कीमतों से अंतिम पास-थ्रू घरेलू रूप से संचालित संकेतकों पर निर्भर करता है जो उनके प्रक्षेपवक्र को फिर से आकार देते हैं।

सामान्य तौर पर, एई अपने व्यवसाय की लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए अपने मार्जिन की रक्षा करने वाली फर्मों के साथ इनपुट लागत में बड़ी वृद्धि को स्थानांतरित करने में सक्षम हैं, हालांकि पास-थ्रू की सीमा के संबंध में विचलन मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देश और यूरोजोन में से कुछ देश अपने नवीनतम सर्वेक्षणों में इनपुट-आउटपुट मूल्य अंतर में बढ़ते रुझान को प्रदर्शित करते हैं, जो तीव्र इनपुट लागत दबावों को दर्शाते हैं, जो आउटपुट मूल्य वृद्धि (चार्ट 2ए) के माध्यम से आनुपातिक रूप से मुआवजा नहीं दिया जाता है। इसके विपरीत, यूएस, यूनाइटेड किंगडम (यूके), फ्रांस और स्पेन जैसे देशों में, 2020 के दौरान इनपुट-आउटपुट प्राइस गैप में बढ़ती प्रवृत्ति या तो स्थिर हो गई है या पिछले वर्ष के आसपास कुछ समय के लिए इनपुट के पास-थ्रू को दर्शाती है। उपभोक्ताओं के लिए लागत (चार्ट 2बी)।

[3] पेपर में पीएमआई मूल्य सूचकांकों का उपयोग किया गया है क्योंकि वे इनपुट और आउटपुट मूल्य दबावों को मापने के लिए दुनिया भर में एक सामान्य संकेतक का प्रतिनिधित्व करते हैं।

चार्ट 2: एई और ईएमई के बीच इनपुट -आउटपुट मूल्य सूचकांक अंतर

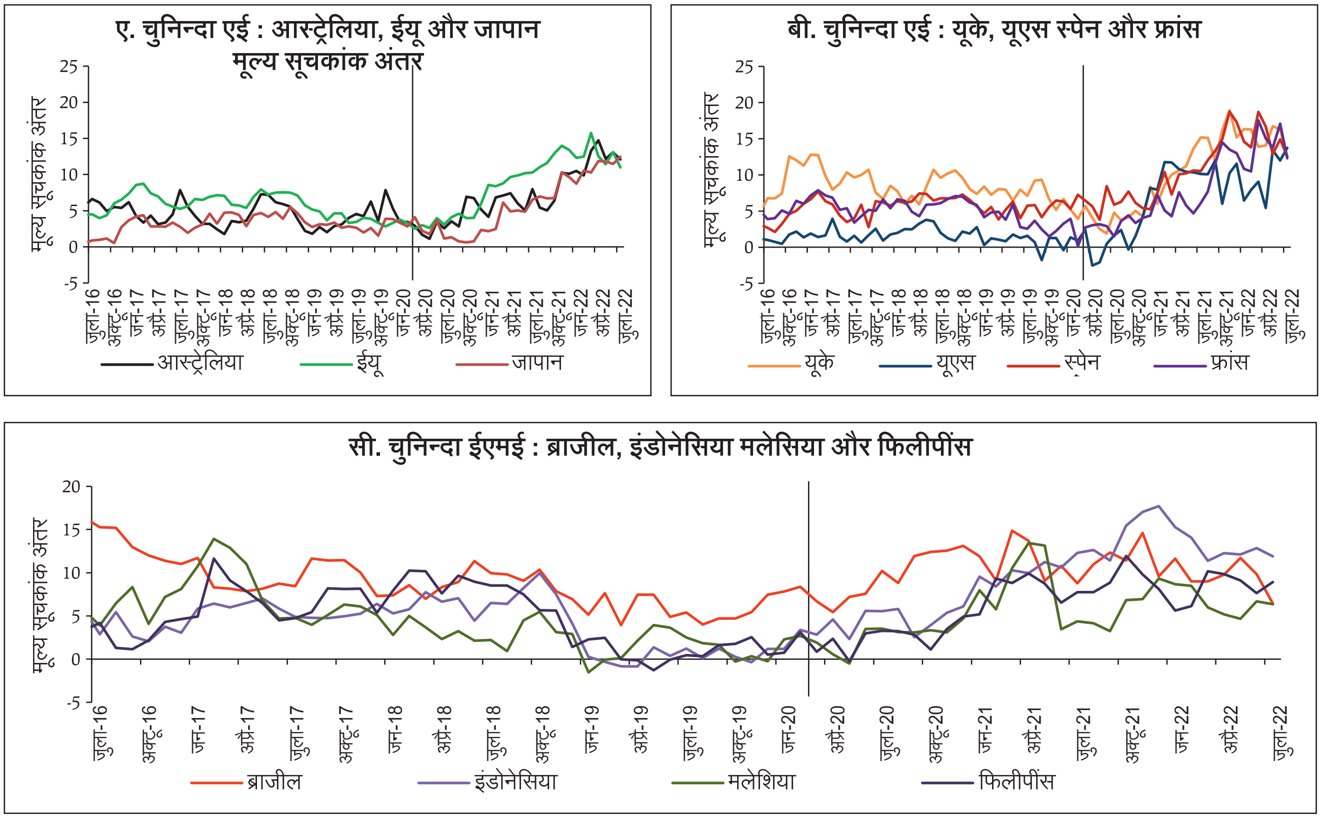

स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल : और आरबीआई स्टाफ के आंकलन

तथापि, ईएमई के लिए 2020 तक बढ़ने के बाद इनपुट और आउटपुट कीमतों के बीच का अंतर 2021 और 2022 के दौरान उच्च स्तर पर काफी अस्थिर बना रहा है, जो उच्च ओवरहेड्स और ईंधन की कीमतों को दर्शाता है, जिसमें कंपनियां रुक-रुक कर दबाव के आगे झुकती हैं (चार्ट 2सी)। हालांकि महामारी के बाद भारत का इनपुट-आउटपुट प्राइस गैप काफी बढ़ गया है, लेकिन एई और ईएमई (पहले चार्ट 1) की तुलना में परिमाण और अस्थिरता में मध्यम बना हुआ है।

पीएमआई इनपुट और आउटपुट मूल्य: भारत

मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी की शुरुआत के साथ, अप्रैल 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव विनिर्माण उत्पादन और सेवाओं में एक अभूतपूर्व संकुचन के रूप में देखा गया। सामाजिक दूरी के मानदंडों को बनाए रखने और उपभोक्ताओं की संख्या में कमी के कारण सेवा क्षेत्र में संकुचन अपेक्षाकृत अधिक मजबूत था। पीएमआई संकेतकों (चार्ट 3ए) से स्पष्ट है कि सेवा क्षेत्र की तुलना में विनिर्माण क्षेत्र के लिए अवस्फीति की दर मजबूत होने के साथ तेज संकुचन के कारण इनपुट और आउटपुट कीमतों में काफी गिरावट आई है। बाद के महीनों में, निर्माण फर्मों ने अपने ग्राहकों को कम लागत वाली लागत दी। इसी तरह, सेवा प्रदाताओं ने आउटपुट मूल्य की दर में एक उल्लेखनीय सहजता दर्ज की जो परिचालन लागत में गिरावट से अधिक थी। आगामी अगस्त और सितंबर के महीनों में कोविड-मानदंडों में छूट के साथ, पीएमआई ने अक्टूबर 2020 में व्यापक-आधारित स्थिरीकरण दर्ज किया। विनिर्माण क्षेत्र ने प्रतिबंधों में छूट और दबी हुई मांग के साथ आशावाद प्राप्त किया, जिससे निर्माताओं को महामारी-पूर्व उत्पादन स्तर हासिल करने की अनुमति मिली, जबकि , सेवा प्रदाताओं ने अपनी गतिविधियों में कमजोर वृद्धि देखी, जिसमें संपर्क-गहन सेवाएं सबसे अधिक खामियाजा भुगत रही हैं।

चार्ट 3: इनपुट और आउटपुट कीमतें

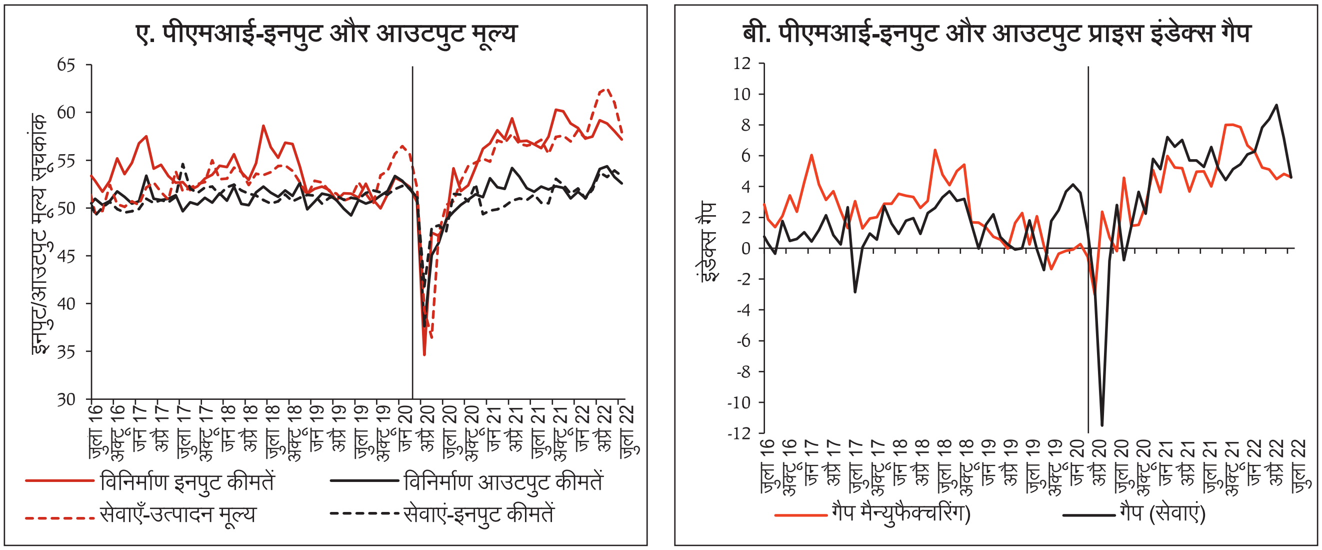

स्रोतः एसएंडपी ग्लोबलः एमओएसपीआईः और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

वर्ष 2021 की शुरुआत जनवरी के महीने में विस्तार क्षेत्र में शेष विनिर्माण पीएमआई के साथ हुई, जो व्यावसायिक स्थितियों में लगातार छठे महीने सुधार का संकेत दे रहा है और इस प्रकार कोविड-19 संबंधित संकुचन से और दूर चला गया, जो 2020 के मध्य (अप्रैल- जुलाई, 2020)। मांग में सुधार के माहौल ने मूल्य वृद्धि और तेज गति से शुल्क बढ़ने के लिए एक अनुकूल स्थान प्रदान किया। सेवा क्षेत्र में, ईंधन की कीमतों में तेजी के कारण लागत में सबसे तेज वृद्धि देखी गई। हालांकि, सेवा प्रदाताओं द्वारा ली जाने वाली कीमतें कम हो गईं क्योंकि अधिकांश कंपनियों ने प्रतिस्पर्धा को मात देने और मांग की स्थिति को प्रोत्साहित करने के लिए छूट की पेशकश की। इसलिए, समग्र उत्पादन शुल्क मोटे तौर पर अपरिवर्तित थे क्योंकि सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाली छूट माल उत्पादकों के बीच कीमतों में वृद्धि से ऑफसेट थी। भारत में कोविड -19 की दूसरी लहर के लगातार उभरने के साथ, वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र पर तनाव फिर से तेज हो गया। कच्चे माल की कमी के कारण कीमतों में बढ़ोतरी के कारण इनपुट लागत और बढ़ गई। इस बीच, सेवा क्षेत्र में लागत प्रेरित मुद्रास्फ़ीतीय दबाव कम हुए, लेकिन अपने ऐतिहासिक मानकों की तुलना में उच्च बने रहे। हालांकि, बिक्री कीमतों में थोड़ी वृद्धि हुई क्योंकि कई कंपनियों ने उच्च इनपुट कीमतों और परिचालन व्यय के बावजूद कमजोर मांग की स्थिति का समर्थन करने के लिए अपनी फीस/प्रभारों को अपरिवर्तित छोड़ दिया। इसलिए, माल क्षेत्रों में पास-थ्रू सेवा क्षेत्रों की तुलना में अधिक था (चार्ट 3बी)। 2021 के अंतिम महीनों में, पीएमआई डेटा ने सेवाओं और विनिर्माण क्षेत्र के लिए मजबूत वृद्धि का संकेत दिया। हालांकि, परिवहन के मुद्दों और प्रमुख कच्चे माल के स्रोत के लिए कठिनाइयों के बीच मुद्रास्फीति लागत दबाव उच्च स्तर पर ऊंचा और तीव्र बना रहा। इसलिए, ग्राहक पर लागत का बोझ डालने से मुद्रास्फीति में नरमी आई। चूंकि नवंबर में उत्पादन में काफी वृद्धि हुई, इसलिए जनवरी 2021 के बाद से निजी क्षेत्र का उत्पादन सबसे तेज गति से बढ़ा। इसलिए, न केवल फर्मों ने नवंबर 2021 से अपने खर्चों में और वृद्धि देखी, बल्कि इनपुट के साथ एक दशक में सबसे बड़ी सीमा तक कीमतें एक वर्ष से अधिक [फरवरी 2021-जून 2022] (चार्ट 4ए) के लिए उच्चतम डेसाइल पर चल रही हैं। भविष्य का उत्पादन, अपेक्षित मांग स्थितियों और पास-थ्रू भावनाओं का एक संकेतक, हालांकि, मामूली बना रहा (चार्ट 4बी)। इसे दर्शाते हुए, कुछ संकेत हैं कि लागत का बोझ आंशिक रूप से ग्राहकों के साथ बिक्री कीमतों में ऊपर की ओर संशोधन के माध्यम से साझा किया जा रहा है, हालांकि इनपुट-आउटपुट मूल्य अंतर अभी भी बना हुआ है।

चार्ट 4: पीएमआई इनपुट कीमतों और भविष्य के आउटपुट की रेंज

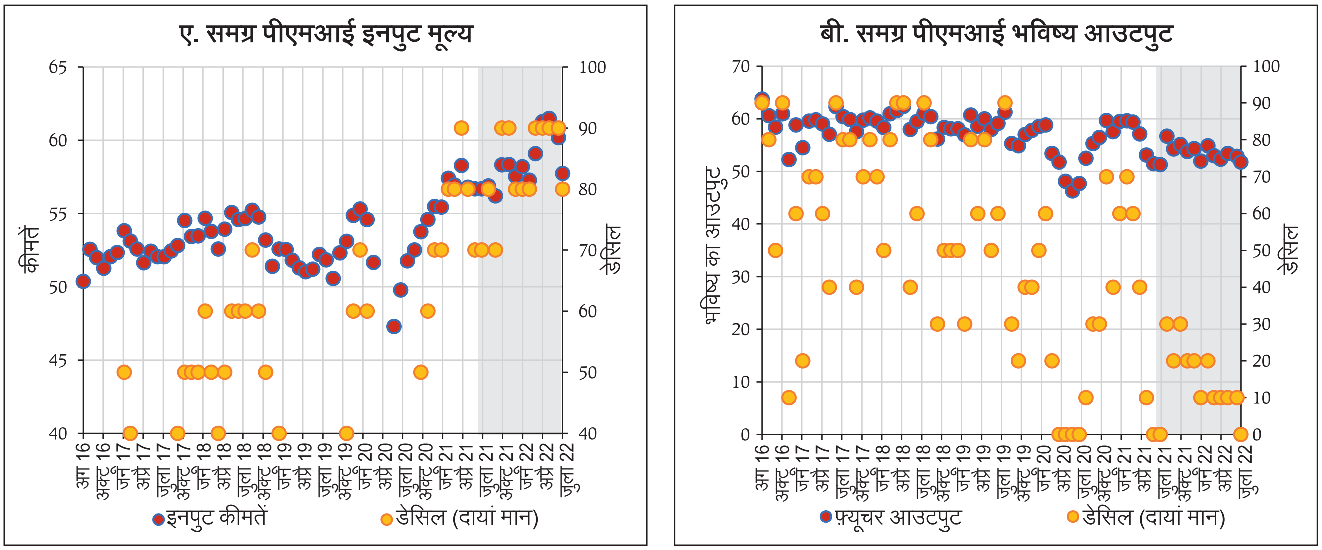

स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान है।

हालांकि, इनपुट कीमतों के आउटपुट कीमतों के पास-थ्रू की सीमा और बदले में हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति, चक्रीय और संरचनात्मक कारकों के एक मेजबान द्वारा वातानुकूलित है जो दूसरे दौर के प्रभावों की प्रकृति को निर्धारित करते हैं। आम तौर पर यह देखा गया है कि इनपुट मूल्य दबाव थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) [4] के मुख्य घटक में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं , हालांकि कोर सीपीआई मुद्रास्फीति (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) के साथ इसका संबंध अपेक्षाकृत कमजोर है (चार्ट 5ए)। इनपुट कीमतों में परिवर्तन कोर सीपीआई पर अप्रत्यक्ष रूप से कोर डब्ल्यूपीआई में परिवर्तन के माध्यम से प्रभाव डालता है, इस प्रकार, इनपुट मूल्य परिवर्तनों के साथ कोर सीपीआई पर प्रभाव अपेक्षाकृत कम हो जाता है (चार्ट 5बी)।

चार्ट 5: मैन्युफैक्चरिंग इनपुट मूल्य और कोर मुद्रास्फीति आधारित उपाय

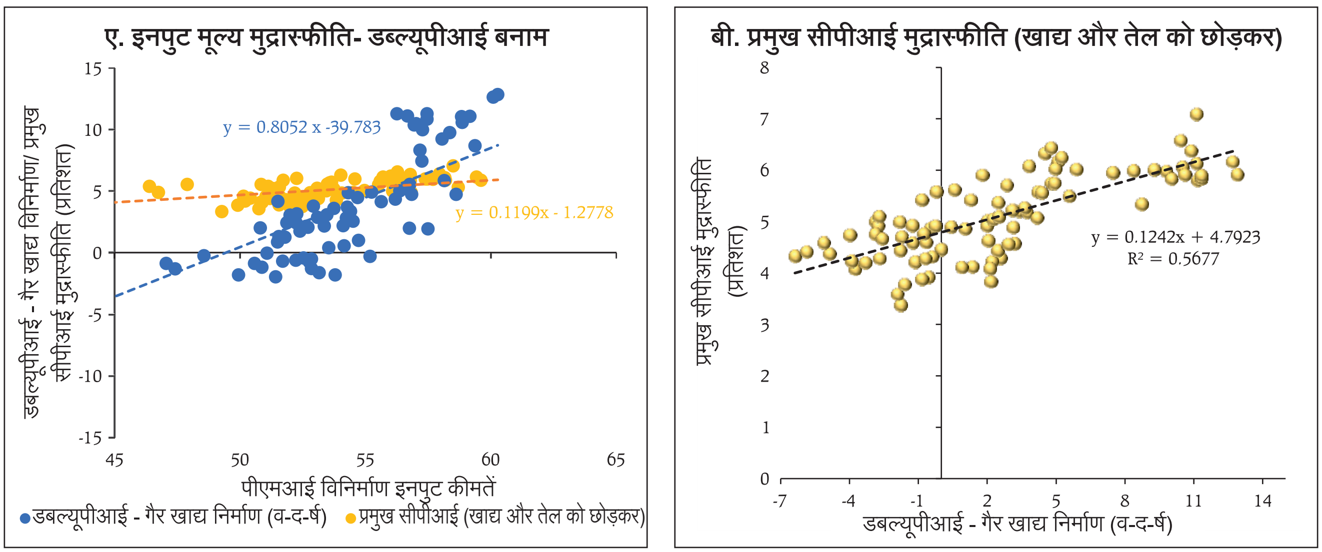

स्रोत: एमओएसपीआई, एसएंडपी ग्लोबल और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

[4] गैर-खाद्य विनिर्माण डब्ल्यूपीआई का उपयोग पिछले अध्ययनों (राज और मिश्रा, 2011) के आधार पर कोर मुद्रास्फीति के माप के रूप में किया जाता है।

III. आनुभविक विश्लेषण

साहित्य की समीक्षा

इनपुट लागतों का आउटपुट लागतों से पास-थ्रू, जिसे आमतौर पर मूल्य निर्धारण शक्ति कहा जाता है, को पारंपरिक रूप से मौद्रिक नीति निर्माण में एक महत्वपूर्ण इनपुट माना जाता है (बॉल, 1999)। पास-थ्रू की डिग्री मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान के लिए महत्वपूर्ण है और उच्च मुद्रास्फीति के जवाब में मौद्रिक नीति तैयार करते समय मौद्रिक सख्ती की सीमा तय करने के लिए केंद्रीय बैंकों के लिए महत्वपूर्ण है। फर्मों के मूल्य निर्धारण कार्यों के मुद्रास्फीतिकारी वातावरण की साहित्य में दो प्रमुख प्रतिमानों के माध्यम से जांच की जाती है - मौद्रिक सिद्धांत और अपूर्ण प्रतिस्पर्धा के साथ मूल्य निर्धारण का सिद्धांत। ब्लैंचर्ड और कियोटाकी (1987) और स्वेनसन (1986) ने मूल्य समायोजन सिद्धांतों में अपूर्ण प्रतिस्पर्धी मॉडल के महत्व को दिखाया है जहां फर्मों के पास बाजार की शक्ति है, जबकि सिद्धांतों के दूसरे सेट में कंपित सूक्ष्म आर्थिक नींव के माध्यम से मूल्य निर्धारण शक्ति के बदलते पैटर्न का महत्व शामिल है। मूल्य निर्धारण। बॉल और सेचेटी (1988) द्वारा विकसित कंपित मूल्य निर्धारण मॉडल के तहत, फर्मों के मूल्य निर्धारण व्यवहार में बदलाव मुद्रास्फीति की निरंतरता की अपेक्षा या इनपुट लागतों में उतार-चढ़ाव के माध्यम से प्रभावित हो सकते हैं। यूएस और यूरोज़ोन क्षेत्र जैसे प्रमुख एई के क्रॉस-कंट्री अनुभव से पता चलता है कि 2021-22 के दौरान इनपुट कीमतों के तीव्र दबाव और मजबूत मांग (विजल्डर , 2022) की पृष्ठभूमि के मुकाबले फर्मों की मूल्य निर्धारण शक्ति में काफी वृद्धि हुई है।

भारतीय संदर्भ में, कई अध्ययनों ने इनपुट/आउटपुट कीमतों और मुद्रास्फीति और मांग की स्थिति के बीच संबंधों के अनुभवजन्य रूप से विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करने की कोशिश की है। सबसे पहले, फर्म स्तर के आंकड़ों का उपयोग करते हुए, 2009-10 के बाद से कॉर्पोरेट मूल्य निर्धारण शक्ति में गिरावट देखी गई है, मुद्रास्फीति पर मूल्य निर्धारण शक्ति के शुद्ध प्रभाव को कम किया जा रहा है, हालांकि यह सकारात्मक है (हैट एवं अन्य, 2013)। दूसरा, पीएमआई मूल्य सूचकांकों को अच्छे संकेतक के रूप में दिखाया गया है और डब्ल्यूपीआई में परिवर्तनों की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी शक्ति है, जो पूर्व-फिट (लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण) अवधि (खुंद्रकपम और जॉर्ज, 2013) 5 में शीर्षक के रूप में कार्य करता है। तीसरा, भारतीय संदर्भ में मजदूरी-कीमत सर्पिल संबंध की भी अनुभवजन्य रूप से जांच की गई है। भारतीय कृषि क्षेत्र में, 2007 से लागत-पुश चैनल के माध्यम से मजदूरी के मूल्य प्रभाव का समर्थन करने वाले साक्ष्य प्रचलित हैं, जिसमें श्रम लागत परिचालन लागत का प्रमुख हिस्सा है (नधनैल, 2012)। इसके अलावा, नाममात्र कृषि और गैर-कृषि मजदूरी दोनों को लंबे समय में कीमतों से सकारात्मक रूप से संबंधित देखा गया है, हालांकि मुद्रास्फीति के लिए मजदूरी-पुश जोखिम मुद्रास्फीति प्रेरित मजदूरी दबावों (कुंडू, 2019) के सापेक्ष कमजोर पाए गए हैं। अंत में, एक और हालिया अभ्यास से पता चला है कि वैश्विक वस्तु कीमतों के प्रत्यक्ष पास-थ्रू का सीपीआई पर अपेक्षाकृत मामूली प्रभाव पड़ता है, जैसा कि हेडलाइन डब्ल्यूपीआई (आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट, 2022) [6] की तुलना में है। कुल मिलाकर, इस क्षेत्र में अध्ययनों ने इनपुट से आउटपुट कीमतों तक के पारित होने के मुद्दे को या तो स्पर्शरेखीय रूप से देखा है या मुख्य रूप से महामारी से पहले के आंकड़ों पर आधारित था, इस प्रकार महामारी के बाद की लागत-पुश व्यवस्था में वर्तमान व्यवहार की जांच करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, इनपुट कीमतों में मौजूदा वृद्धि के संभावित पास-थ्रू को मापने के लिए इनपुट कीमतों में बदलाव के लिए आउटपुट कीमतों की संवेदनशीलता की अनुभवजन्य रूप से जांच करने का प्रयास किया जाता है, विशेष रूप से मांग वसूली भाप इकट्ठा करती है।

आंकड़े

अध्ययन में अनुभवजन्य आकलन 2011 से 2022[7] तक मासिक समय श्रृंखला डेटा का उपयोग करके किया जाता है। हमारे अध्ययन में उपयोग किए गए चर इस प्रकार हैं: समग्र पीएमआई इनपुट मूल्य एक व्याख्यात्मक चर के रूप में और पीएमआई आउटपुट मूल्य आश्रित चर के रूप में। पीएमआई इनपुट कीमतों के साथ इसके संबंध की जांच करने के लिए कोर सीपीआई (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) का उपयोग एक अन्य

5 अध्ययनों ने मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान के लिए, अन्य चरों के साथ, पीएमआई मूल्य सूचकांकों का सफलतापूर्वक उपयोग किया है (बनर्जी और मार्सेलिनो , 2006; और राइट, 2008)।

6 समग्र वैश्विक कमोडिटी कीमतों में एक प्रतिशत परिवर्तन से समग्र सीपीआई मुद्रास्फीति में 0.02 प्रतिशत परिवर्तन होता है, और समग्र डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में लगभग 0.11 प्रतिशत परिवर्तन होता है (वार्षिक रिपोर्ट, भारतीय रिज़र्व बैंक 2021-22)।

7 चूंकि पीएमआई फ्यूचर आउटपुट इंडेक्स केवल 2012 के बाद उपलब्ध है, सारणी 2, 3 और 4 में रिपोर्ट किए गए अनुभवजन्य परिणामों का अनुमान 2012 से 2022 तक की मासिक श्रृंखला का उपयोग करके लगाया जा रहा है।

सारणी 1: ग्रेंजर कार्य-कारण परीक्षण

परिकल्पना	प्रेक्षणों की संख्या	च-आंकड़ा
कंपोजिट इनपुट कीमतें गंभीर नहीं होती हैं, जिससे कंपोजिट आउटपुट कीमतें प्रभावित होती हैं	197	9.17***
कंपोजिट आउटपुट कीमतें ज्यादा गंभीर नहीं होती हैं, जिससे कंपोजिट इनपुट कीमतें प्रभावित होती हैं	197	0.374
समग्र इनपुट कीमतें कोर सीपीआई का कारण नहीं बनती हैं	135	14.67***
कोर सीपीआई समग्र इनपुट कीमतों का कारण नहीं बनता है	135	1.76

टिप्पणियाँ: 1. *** महत्व के 1 प्रतिशत स्तर पर महत्व को दर्शाता है।
2. परिणाम इनपुट कीमतों के अंतराल 1 के लिए रिपोर्ट किए गए हैं; हालांकि, परिणाम आउटपुट कीमतों के समग्र इनपुट के लिए उच्च अंतराल के लिए भी हैं, हालांकि कोर सीपीआई (मौसमी रूप से समायोजित, माँ) के लिए समग्र इनपुट के लिए उच्च अंतराल के लिए महत्व कम हो जाता है।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान है।

आश्रित चर के रूप में भी किया जाता है। मॉडल में कोविड -19 अवधि के लिए उपयुक्त डमी के साथ-साथ साहित्य के अनुरूप अपेक्षित मांग स्थितियों के लिए एक नियंत्रण चर के रूप में भविष्य के आउटपुट (अपेक्षित) भी शामिल हैं। मॉडल के वर्णनात्मक आंकड़े अनुबंध ए में सारणी 1 में दिए गए हैं । स्थिरता के लिए यूनिट रूट परीक्षण इंगित करता है कि एक प्रतिशत विश्वास स्तर पर पीएमआई इनपुट और आउटपुट मूल्य स्थिर हैं, जबकि स्तरों में कोर सीपीआई सूचकांक गैर-स्थिर है; मौसमी रूप से समायोजित माह-दर-माह कोर सीपीआई मुद्रास्फीति स्थिर पाई गई है (सारणी 2 अनुबंध ए)।

अगले कदम के रूप में, पीएमआई समग्र इनपुट कीमतों द्वारा दर्शाए गए इनपुट कीमतों के कारण संबंध की जांच पीएमआई समग्र आउटपुट कीमतों और कोर सीपीआई की तुलना में की जाती है। ग्रेंजर करणीय परीक्षण इस बात की पुष्टि करते हैं कि इनपुट कीमतें आउटपुट कीमतों और कोर सीपीआई को प्रभावित करती हैं, जिसमें विपरीत कारणता का कोई सबूत नहीं है (सारणी 1)।

IV. अनुभवजन्य परिणाम

इनपुट कीमतों के लिए आउटपुट कीमतों की संवेदनशीलता की सीमा की जांच मानक साधारण न्यूनतम वर्गों (ओएलएस) और मात्रात्मक प्रतिगमन (क्यूआर) विश्लेषण का उपयोग करके अपेक्षित गतिविधि [8] के लिए की जाती है, जो लागत पुश कोण से

सारणी 2: ओएलएस अनुमान: आउटपुट कीमतों के लिए इनपुट आश्रित चर: पीएमआई आउटपुट मूल्य

स्वतंत्र प्रभावित करने वाली वस्तुएँ	मॉडल 1	मॉडल 2
नियत	30.48*** (0.00)	18.26*** (0.00)
इनपुट कीमतें *(वैरिएबल की लैग्ड संख्या = 2)*	-	0.10** (0.03)
इनपुट कीमतें *(चरों की संख्या = 4)*	0.26** (0.03)	-
आउटपुट मूल्य *(चरों की संख्या = 1)*	-	0.48*** (0.00)
भविष्य का आउटपुट	0.11*** (0.000)	0.04 (0.01)
दम_अप्रैल_2020	-9.65*** (0.000)	-10.57*** (0.00)
समायोजित आर-चुकता	0.73	0.81

टिप्पणियाँ: 1. *** और ** 1 और 5 प्रतिशत के स्तर पर महत्व को दर्शाता है।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पी-मान हैं।
3. परिणाम अप्रैल 2012-जून 2022 की अवधि के लिए अनुमानित हैं।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

इनपुट कीमतों के साथ-साथ मांग-पक्ष से आउटपुट कीमतों को प्रभावित कर सकती है। ओएलएस प्रतिगमन परिणाम बताते हैं कि पीएमआई समग्र इनपुट कीमतों से संबंधित आउटपुट कीमतों के लिए पास थ्रू धीमा और अधूरा है, और लंबी अवधि का पास-थ्रू 0.26 - 0.27 (सारणी 2) की सीमा में है।

मात्रात्मक प्रतिगमन

आउटपुट कीमतों और इनपुट कीमतों के बीच गैर-रैखिक संबंध को डिकोड करने के उद्देश्य से, जो राज्य पर निर्भर हैं, मात्रात्मक प्रतिगमन को विभिन्न मात्रात्मक पर आउटपुट कीमतों पर इनपुट कीमतों के प्रभाव की जांच करने का प्रयास किया जाता है। पांच मात्रात्मक (0.2, 0.3, 0.5, 0.7, और 0.8) के लिए मात्रात्मक प्रतिगमन गुणांक का अनुमान सारणी 3 में दिया गया है । यह देखा गया है कि पीएमआई इनपुट मूल्य के अनुमानित गुणांक स्वतंत्र चर के रूप में अपेक्षित सकारात्मक संकेत हैं, 1 प्रतिशत के स्तर पर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण हैं, और धीरे-धीरे 0.24 से 0.32 के बीच निम्न से ऊपरी मात्रा तक बढ़ते हैं।

अनुमानित मॉडल के ढलान गुणांक की अशक्त परिकल्पना मात्रात्मक के बराबर होने के कारण खारिज कर दी जाती है (चार्ट 4ए और सारणी 4बी) [9]। पीएमआई इनपुट कीमतों के साथ काफी

[8] संमिश्र पीएमआई का फ्यूचर आउटपुट इंडेक्स जो सर्वेक्षण करता है कि अगले 12 महीनों में अपेक्षित व्यावसायिक गतिविधि का स्तर उच्च, निम्न या स्थिर रहेगा, अपेक्षित मांग के संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है।

[9] यह प्रासंगिक है क्योंकि यह दर्शाता है कि ऐसे मामलों में जब अनुसंधान का महत्व विशिष्ट मात्राओं पर होता है, रैखिक मॉडल अपर्याप्त निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्या व्याख्यात्मक और आश्रित चर के बीच एक लिंक है, और यदि कोई लिंक मौजूद है, तो की ताकत संपर्क।

सारणी 3: मात्रात्मक प्रतिगमन परिणाम निर्भर चर:
पीएमआई आउटपुट मूल्य

स्वतंत्र प्रभावित करने वाली वस्तुएँ	मात्रात्मक प्रतिगमन अनुमान				
	0.2	0.3	0.5	0.7	0.8
सी	34.48*** (0.00)	33.74*** (0.00)	29.23*** (0.00)	26.45*** (0.00)	26.32*** (0.00)
इनपुट कीमतें	0.24*** (0.00)	0.24*** (0.00)	0.30*** (0.00)	0.32*** (0.00)	0.32*** (0.00)
भविष्य का आउटपुट	0.07** (0.01)	0.08** (0.01)	0.10** (0.02)	0.14*** (0.00)	0.14*** (0.00)
दम_अप्रैल2020	-5.72*** (0.00)	-6.10*** (0.00)	-5.29*** (0.00)	-5.10*** (0.00)	-5.43*** (0.00)

टिप्पणियाँ: 1. *** और ** 1 और 5 प्रतिशत के स्तर पर महत्व को दर्शाता है।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पी-मान हैं।
3. मात्रात्मक प्रतिगमन कंपोनेंट: ह्यूबर सैंडविच स्टैंडर्ड एरर्स एंड कोवैरियंस; स्पार्सिटी विधि: अवशिष्ट का उपयोग करके कर्नेल (एपनेक्निकोव); अद्वितीय इष्टतम समाधान की पहचान की गई।
4. परिणाम अप्रैल 2012-जून 2022 की अवधि के लिए अनुमानित हैं।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

लंबी अवधि के लिए उच्चतम डेसाइल पर काम कर रहा है, आउटपुट कीमतों के लिए इसका पास-थ्रू अधिक मजबूत हो सकता है, क्योंकि भविष्य का आउटपुट विकास में सुधार के साथ अपने ऊपरी डेसाइल की ओर बढ़ रहा है।

इस लेख का दूसरा उद्देश्य मुख्य सीपीआई पर इनपुट कीमतों के प्रभाव का पता लगाना है जो कि दोनों के बीच संबंधों की पहचान करने के लिए हेडलाइन सीपीआई का एक घटक है। मात्रात्मक प्रतिगमन का उपयोग करते हुए, यह देखा गया है कि अप्रैल 2012-जून 2022 की अवधि के लिए कोर सीपीआई [10] पर

सारणी 4: मात्रात्मक प्रतिगमन
(आश्रित चर: पीएमआई आउटपुट मूल्य)

ए. मात्रात्मक प्रक्रिया अनुमान गुणांक

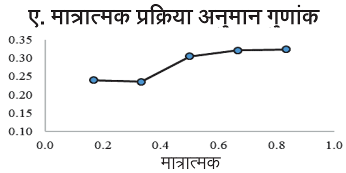

बी. मात्रात्मक ढलान इक्वेलिटी टेस्ट

टेस्ट सारांश	: वाइल्ड टेस्ट
ची- वर्ग आँकड़ा	: 28.05***
ची- वर्ग डी.एफ	: 12
पी -मूल्य	: 0.00

टिप्पणियाँ: 1. ***1 प्रतिशत स्तर पर महत्व दर्शाता है
2. अनुमानित समीकरण मात्रात्मक ताऊ = 0.5: टेस्ट मात्रात्मक = 0.9: 1 टेस्ट के आंकड़े सभी गुणांकों की तुलना करते हैं।
3. अनुलग्नक बी क्यूआर गुणांकों की तुलना में ओएलएस अनुमान से विश्वास बैंड की रिपोर्ट करता है।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[10] मौसमी रूप से समायोजित, एम-ओ-एम कोर सीपीआई का उपयोग विश्लेषण के लिए किया गया है।

सारणी 5: मात्रात्मक प्रतिगमन आश्रित चर :
कोर सीपीआई (एम-ओ-एम)

स्वतंत्र प्रभावित करने वाली वस्तुएँ	मात्रात्मक प्रतिगमन अनुमान				
	0.2	0.3	0.5	0.7	0.8
सी	-0.84 (0.14)	-1.01 (0.10)	-1.50** (0.02)	-1.68** (0.01)	-0.97 (0.28)
इनपुट कीमतें	0.02** (0.05)	0.02** (0.03)	0.04*** (0.00)	0.04*** (0.00)	0.03* (0.06)
दम_अप्रैल2020	0.81*** (0.00)	0.80*** (0.00)	0.88*** (0.00)	0.88** (0.00)	0.57* (0.06)

टिप्पणियाँ: 1. ***, ** और * क्रमशः 1, 5 और 10 प्रतिशत के स्तर पर महत्व को दर्शाता है।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पी-मान हैं।
3. मात्रात्मक प्रतिगमन कंपोनेंट: ह्यूबर सैंडविच स्टैंडर्ड एरर्स एंड कोवैरियंस; स्पार्सिटी विधि: अवशिष्ट का उपयोग करके कर्नेल (एपनेक्निकोव); अद्वितीय इष्टतम समाधान की पहचान की गई।
4. परिणाम अप्रैल 2012-जून 2022 की अवधि के लिए अनुमानित हैं।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

पीएमआई इनपुट कीमतों का प्रभाव इनपुट कीमतों की उच्च मात्रा में अधिक है, हालांकि समग्र प्रभाव 0.02- की सीमा में पास-थ्रू गुणांक के साथ मामूली है। 0.04 (सारणी 5 और 6)।

वेक्टर ऑटोप्रतिगमन (वीएआर) विश्लेषण

कोर सीपीआई और हेडलाइन सीपीआई दोनों के संबंध की गतिशीलता का पता लगाने के लिए, हमने (ए) पीएमआई इनपुट कीमतों के द्वि-भिन्न वीएआर मॉडल पर विचार किया, जो हेडलाइन मुद्रास्फीति के साथ और (बी) पीएमआई इनपुट मूल्य कोर सीपीआई मुद्रास्फीति के साथ थे। इस अनुभवजन्य अभ्यास का फोकस इनपुट कीमतों से सीपीआई हेडलाइन और कोर मुद्रास्फीति की प्रतिक्रिया की तुलना करना और प्रभाव की परिमाण और दृढ़ता की जांच करना है। इस उद्देश्य के लिए, हम वीएआर अनुमानों (चार्ट 6) से प्राप्त हेडलाइन और कोर सीपीआई मुद्रास्फीति की आवेग प्रतिक्रिया पर निर्भर करते हैं।

सारणी 6: मात्रात्मक प्रतिगमन
(आश्रित चर: प्रमुख सीपीआई एम-ओ-एम)

ए. मात्रात्मक प्रक्रिया अनुमान गुणांक इनपुट कीमत

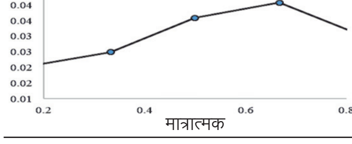

बी. मात्रात्मक ढलान इक्वेलिटी टेस्ट

टेस्ट सारांश	: वाइल्ड टेस्ट
ची- वर्ग आँकड़ा	: 13.66*
ची- वर्ग डी.एफ	: 8
पी -मूल्य	: 0.09

टिप्पणियाँ: 1. *10 प्रतिशत स्तर पर महत्व दर्शाता है
2. इन परिणामों का आंकलन अप्रैल 2012 से जून 2022 की अवधि के लिए किया गया है

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट 6: बाई- वेरिएट वीएआर परिणाम

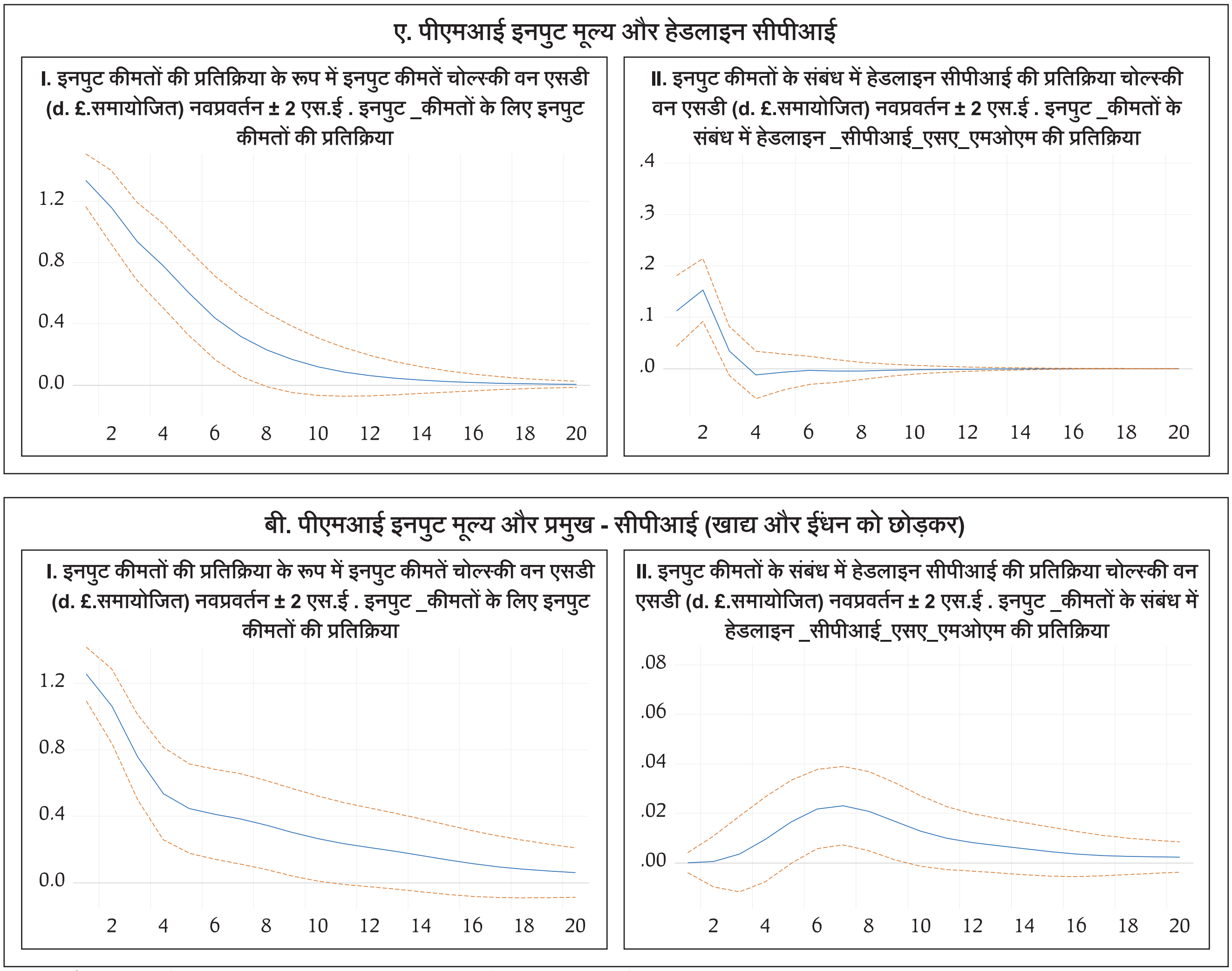

टिप्पणियाँ: 1. वीएआर के परिणाम मई 2011- जून 2022 की अवधि के लिए अनुमानित हैं।
2. एआईसी और एससी के साथ चयन ने मॉडल को चार अंतराल के साथ दिया। वीएआर अवशिष्ट सीरियल सहसंबंध एलएम परीक्षण के साथ मॉडल के अवशेषों को स्वत: सहसंबंध के लिए जांचा जाता है।
3. स्थिरता की स्थिति की जाँच इंगित करती है कि वीएआर की स्थिरता स्थिति की पुष्टि करने वाले यूनिट सर्कल के बाहर कोई जड़ नहीं है।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

मॉडल का अनुमान एआईसी मानदंड द्वारा सुझाए गए चार अंतरालों का उपयोग करके लगाया गया है। हेडलाइन सीपीआई के लिए, आवेग प्रतिक्रियाओं से संकेत मिलता है कि इनपुट कीमतों के लिए एक मानक विचलन झटका (जो कि 1.2 प्रतिशत की वृद्धि है) तीन महीने के अंतराल के साथ हेडलाइन मुद्रास्फीति पर लगभग 15 आधार अंकों (एमओएम) के चरम प्रभाव की ओर जाता है और प्रभाव घटता है। तुरंत। दूसरी ओर, इनपुट कीमतों के लिए व्यापक रूप से इसी तरह के झटके से कोर मुद्रास्फीति पर अधिक धीरे-धीरे प्रभाव पड़ता है। लगभग 2 बीपीएस का चरम प्रभाव 7 महीनों के बाद होता है। इस प्रकार विश्लेषण हेडलाइन मुद्रास्फीति पर इनपुट मूल्य झटके के अपेक्षाकृत तेज और मजबूत प्रभाव और कोर मुद्रास्फीति पर अधिक जड़त्वीय और कम प्रभाव का सुझाव देता है।

V. निष्कर्ष

यह लेख इनपुट कीमतों से आउटपुट कीमतों तक पास-थ्रू व्यवहार को डिकोड करता है, जो लागत-पुश दबावों के दूसरे क्रम के प्रभावों का आकलन करने में एक प्रमुख घटक है। उच्च ईंधन, कच्चे माल, परिवहन लागत और अन्य आपूर्ति श्रृंखला संबंधी बाधाओं से प्रेरित, इनपुट कीमतों में महामारी की बार-बार आने

वाली लहरों के साथ व्यापक-आधारित वृद्धि देखी गई है जो यूरोप में युद्ध से और बढ़ गई थी। 2020 और 2021 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार सुस्ती के कारण उत्पादन कीमतों में आनुपातिक रूप से वृद्धि नहीं होने के कारण, महामारी के दौरान, विशेष रूप से पहली कोविड-19 लहर के बाद, इनपुट और आउटपुट कीमतों के बीच का अंतर बढ़ गया। कागज के अनुभवजन्य परिणाम बताते हैं कि इनपुट से आउटपुट कीमतों में पास-थ्रू समय के साथ 0.26-0.27 की सीमा में दीर्घकालिक गुणांक के साथ बनता है। रिश्ते में गैर-रैखिकता भी इनपुट कीमतों की उच्च मात्रा में इनपुट कीमतों में वृद्धि के लिए आउटपुट कीमतों की संवेदनशीलता के साथ अनुभवजन्य रूप से सत्यापित है। इसके अलावा, उच्च इनपुट कीमतों का मुख्य मुद्रास्फीति के सापेक्ष हेडलाइन मुद्रास्फीति पर तेजी से संचरण और मजबूत प्रभाव पड़ता है।

फर्मों ने अपनी बढ़ती लागत का एक हिस्सा विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में कीमतों को बेचने के लिए पास करना शुरू कर दिया है, मांग की स्थिति में सुधार के बाद जो उन्हें ऐसा करने में सक्षम बनाता है। आगे बढ़ते हुए, अलग-अलग ताकतों के बीच चल रहे डायनामिक्स पर नजर रखने की जरूरत है - मांग उठना; हाल के महीनों में इनपुट मूल्य दबावों में कुछ नरमी आई है; और निरंतर वैश्विक अनिश्चितताएं - जो हेडलाइन मुद्रास्फीति पर प्रभाव को निर्धारित कर सकती हैं।

VI. संदर्भ

Ball, L. M. (1999). Policy rules for open economies. In Monetary policy rules (pp. 127-156). University of Chicago Press.

Ball, L., & Cecchetti, S. G. (1988). Imperfect Information and Staggered Price Setting. *The American Economic Review*, 999-1018.

Blanchard, O. J., & Kiyotaki, N. (1987). Monopolistic competition and the effects of aggregate demand. *The American Economic Review*, 647-666.

Hait, A., John, J., Das, A., & Mitra, A. (2013). Corporate Pricing Power, Inflation and IIP Growth: An Empirical Investigation. *Reserve Bank of India, WPS (DEPR), 09.*

Khundrakpam, J. K., & George, A. T., (2013). An empirical analysis of the Relationship between WPI and PMI-Manufacturing Price Indices in India. *Reserve Bank of India, WPS (DEPR), 06.*

Koenker, R., & Bassett Jr, G. (1982). Robust tests for heteroscedasticity based on regression quantiles. *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, 43-61.

Kundu, S. (2019). Rural wage dynamics in India: What role does inflation play. *RBI Occasional Paper, 40*, 51-84.

Nadhanael, G. V. (2012). Recent Trends in Rural Wages: An Analysis of Inflationary Implications. *Reserve Bank of India Occasional Papers*, *33*(1), 89-112.

Patra, M. D., Behera, H., & John, J. (2021). 'Is the Phillips Curve in India Dead, Inert and Stirring to Life or Alive and Well?. *RBI Bulletin, November.*

Raj, J., & Misra, S. (2011). Measures of core inflation in India–an empirical evaluation. *Reserve Bank of India, WPS (DEPR), 16.*

Schnabel, I. (2022). The globalization of inflation. In *Speech given at a conference organised by the Österreichische Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management, May* (Vol. 11).

Svensson, L. E. (1986). Sticky goods prices, flexible asset prices, monopolistic competition, and monetary policy. *The Review of Economic Studies*, *53*(3), 385-405.

Vijlder, W., (2022), "Companies' Pricing Power and the Inflation Outlook", BNP Paribas.

Yetman, J. (2020). *Pass-through from short-horizon to long-horizon inflation expectations, and the anchoring of inflation expectations.* Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department.

RBI (2022). Globalisation of Inflation and Conduct of Monetary Policy, Speech by Shri Shaktikanta Das, Governor, Reserve Bank of India - July 9, 2022 - Delivered at the Kautilya Economic Conclave, organised by Institute of Economic Growth in New Delhi.

RBI (2022). Annual Report for 2021-22.

RBI (2022). Monetary Policy Report, April.

RBI (2022). Resolution of the Monetary Policy Committee (MPC), February.

अनुबंध ए

I. वर्णनात्मक सांख्यिकी

सारणी 1: वर्णनात्मक सांख्यिकी

अवधि: अप्रैल 2012 - मई 2022

उपाय	पीएमआई-इनपुट कीमतें	पीएमआई-आउटपुट कीमतें	कोर सीपीआई (मौसमी रूप से समायोजित, माँ)
टिप्पणियों			136
अर्थ	53.77	51.43	0.49
मानक विचलन	3.27	1.87	0.26
न्यूनतम	37.82	40.50	-0.11
ज्यादा से ज्यादा	61.50	57.27	1.68
तिरछापन	-1.21	-0.83	0.78
कुकुदता	8.85	13.25	5.08

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

II. यूनिट रूट टेस्ट

सारणी 2: संवर्धित डिकी फुलर (एडीएफ़) परीक्षा परिणाम

चर	नियत	रुझान
पीएमआई इनपुट कीमतें	-3.14***	-3.08
पीएमआई आउटपुट मूल्य	-4.63***	-4.79***
कोर सीपीआई	2.01	0.81
कोर सीपीआई एम-ओ-एम (मौसमी रूप से समायोजित)	-9.25***	-9.86***
हेडलाइन सीपीआई एम-ओ-एम (मौसमी रूप से समायोजित)	-9.02***	-9.18***
भविष्य का आउटपुट	-2.59	-3.21
भविष्य आउटपुट (पहले अंतर पर)	-15.06***	-15.07***

टिप्पणियाँ: 1. *** 1 प्रतिशत के स्तर पर महत्व को दर्शाता है।

2. यूनिट रूट परीक्षण पीएमआई इनपुट और आउटपुट मूल्य श्रृंखला के लिए उन्हें I(0) चर बनाने के लिए अशक्त परिकल्पना की अस्वीकृति का संकेत देते हैं।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान

संलग्नक – बी

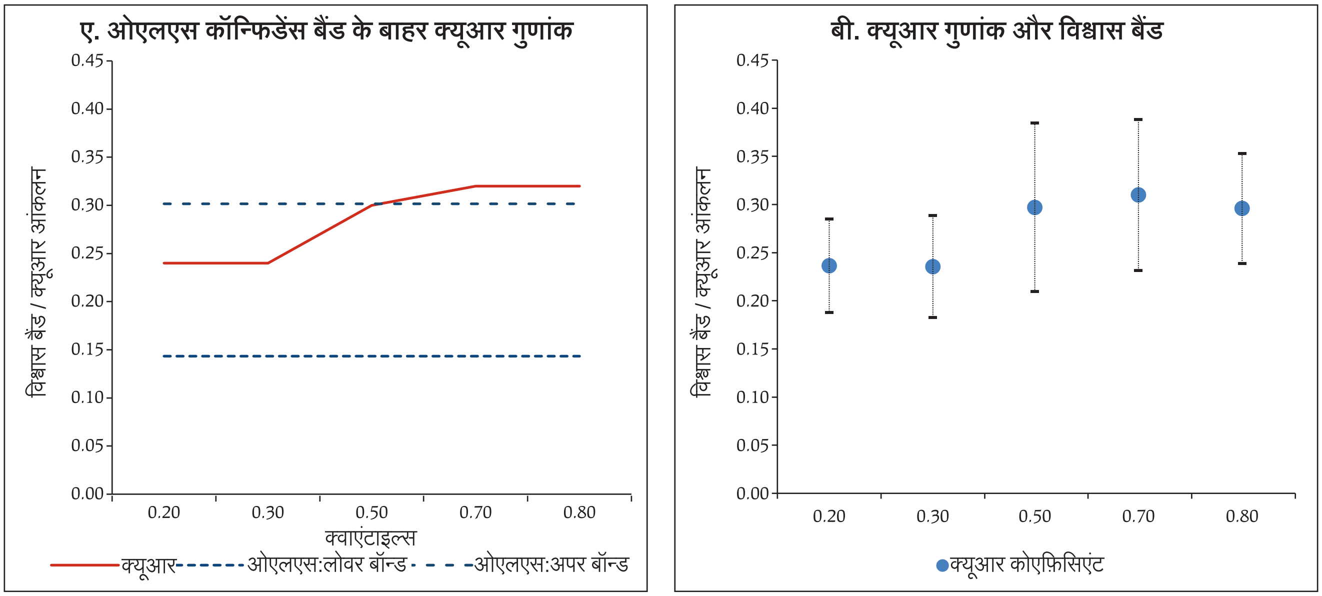

टिप्पणी: क्यूआर और ओएलएस मात्रात्मक प्रतिगमन और ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर को इंगित करते हैं।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ का आंकलन

*भारतीय राज्यों में आर्थिक गतिविधि पर कोविड-19 का प्रभाव**

सुधांशु गोयल ^, आकाश कोवुरी ^ और रमेश गोलायत ^

भारत ने आर्थिक गतिविधियों पर कोविड-19 महामारी के अंतर क्षेत्रीय प्रभाव को देखा। हम आर्थिक प्रभाव और बाद में सुधार प्रक्षेपवक्र में विषमता के चालकों को समझने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर एक आर्थिक गतिविधि सूचकांक का निर्माण करते हैं। हम पाते हैं कि आर्थिक संरचना में अंतर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने राज्य के योजित सकल मूल्य (जीएसवीए) में कृषि और खनन के उच्च हिस्से वाले राज्यों ने उद्योग और सेवाओं के उच्च हिस्से वाले राज्यों की तुलना में आर्थिक गतिविधियों में कम संकुचन देखा, महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए राष्ट्रीय नीति प्रतिक्रिया के पूरक राज्यों में अंतर नीति प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता है।

भूमिका

भारतीय अर्थव्यवस्था विषम क्षेत्रीय इकाइयों से बनी है जिनके अलग-अलग आर्थिक पथ हैं। प्रभावी नीति निर्माण और कार्यान्वयन के लिए नीति निर्माताओं के लिए आर्थिक गतिविधि के क्षेत्रीय और स्थानिक आयामों का संज्ञान लेना महत्वपूर्ण है। किसी देश का समग्र आर्थिक विकास महत्वपूर्ण रूप से उसके राज्यों/क्षेत्रों की समान प्रगति पर निर्भर करता है। इसके लिए, क्षेत्रों और उप-राष्ट्रीय इकाइयों की आर्थिक निगरानी महत्वपूर्ण हो जाती है।

वर्तमान में, राज्य स्तर पर समग्र आर्थिक गतिविधि को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) डेटा द्वारा मापा जा सकता है जो वार्षिक तौर पर उपलब्ध होता है। जैसा कि महामारी के दौरान स्पष्ट है, राज्य स्तर पर आर्थिक गतिविधि की लगभग वास्तविक समय की निगरानी क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुरूप त्वरित नीति प्रतिक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। राज्य स्तर पर उपलब्ध उच्च आवृत्ति संकेतक राज्य की समग्र के बजाय एक क्षेत्रीय आर्थिक तस्वीर प्रदान करते हैं। इस संदर्भ में, क्षेत्रीय स्तर पर समग्र आर्थिक परिदृश्य को दर्शाने वाला एक सूचकांक अनिवार्य है।

कोविड-19 महामारी के दौरान, लॉकडाउन ने आर्थिक गतिविधियों, आपूर्ति श्रृंखलाओं, कार्य की प्रकृति और प्रवासन प्रारूप में व्यवधान उत्पन्न किया। केंद्र सरकार द्वारा एक व्यापक दिशा और नीति समर्थन देने के साथ, राज्यों और स्थानीय सरकारों ने अपनी विशिष्ट स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नीतियों को अपनाने और लागू करने में नेतृत्व किया। परिणामस्वरूप, राज्यों में आर्थिक सुधार अलग-अलग होने की उम्मीद है। इस संदर्भ में, हम राज्यों में विविध आर्थिक प्रक्षेपवक्रों को मापने के लिए एक आर्थिक गतिविधि सूचकांक का निर्माण करते हैं। कोविड-19 लॉकडाउन और गतिशीलता प्रतिबंधों से प्रेरित असममित आर्थिक प्रभाव के लिए क्षेत्रों की आर्थिक संरचना एक संभावित व्याख्या हो सकती है।

शेष पेपर निम्नानुसार आयोजित किया गया है: खंड II दुनिया भर में क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधि सूचकांकों पर साहित्य के साथ-साथ भारत के लिए विशिष्ट साहित्य की समीक्षा प्रदान करता है। खंड III क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधि सूचकांक के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा और प्रमुख घटक विश्लेषण (पीसीए) कार्यपद्धति का संक्षेप में वर्णन करता है। खंड IV राज्य स्तर पर सूचकांक प्रस्तुत करता है। खंड V आर्थिक संरचना और आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव के बीच संबंध पर चर्चा करता है और खंड VI आलेख का समापन करता है।

II. साहित्य की समीक्षा

दुनिया भर के नीति निर्माताओं द्वारा आर्थिक प्रदर्शन के वास्तविक समय मापन की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। वैश्विक स्तर पर, उप-राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक गतिविधि को मापने के लिए कई सूचकांक हैं।

फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ फिलाडेल्फिया 50 राज्यों में से प्रत्येक के लिए एक मासिक संयोग सूचकांक तैयार करता है। एक गतिक एकल-कारक मॉडल का उपयोग चार चरों अर्थात गैर-कृषि

^ लेखक आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) से हैं।

* डॉ. देब प्रसाद रथ, प्रधान परामर्शदाता, डीईपीआर से प्राप्त सुझावों और निरंतर प्रोत्साहन से लेखक अत्यधिक लाभान्वित हुए। डॉ. राजीव जैन और डॉ. जी. वी. नथनएल से प्राप्त टिप्पणियों की सराहना की जाती है। इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों को नहीं दर्शाते हैं।

पेरोल रोजगार, उत्पादन श्रमिकों द्वारा विनिर्माण में काम किए गए औसत घंटे, बेरोजगारी दर, और मजदूरी और वेतन संवितरण का उपयोग करके राज्य सूचकांक बनाने के लिए किया जाता है। डलास फेड द्वारा टेक्सास लीडिंग सूचकांक का उपयोग राज्य में आर्थिक गतिविधि की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। समग्र सूचकांक पर पहुंचने के लिए यह आठ प्रमुख संकेतकों का उपयोग करता है, जैसे डॉलर का टेक्सास मूल्य, अमेरिकी प्रमुख सूचकांक, वास्तविक तेल की कीमत, अच्छी परमिट, बेरोजगारी बीमा के लिए प्रारंभिक दावे, टेक्सास स्टॉक सूचकांक, हेल्प-वांटेड सूचकांक और विनिर्माण क्षेत्र में काम के औसत साप्ताहिक घंटे।

हबली एवं अन्य (2020) ने पीसीए और अन्य तरीकों का उपयोग करते हुए कनाडा के संदर्भ में चार प्रायोगिक समग्र आर्थिक गतिविधि सूचकांकों का प्रस्ताव दिया। रिज़र्व बैंक ऑफ़ न्यूज़ीलैंड ने वास्तविक समय में क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए प्रायोगिक क्षेत्रीय गतिविधि सूचकांक (आरएआई) विकसित किया है। प्रत्येक क्षेत्रीय सूचकांक आर्थिक गतिविधि के 6 मासिक संकेतकों को सारांशित करता है, जिसमें उपभोक्ता खर्च, नौकरी खोजने वालों की संख्या, ऑनलाइन नौकरी की रिक्तियां, यातायात की मात्रा (हल्के और भारी वाहन), और विद्युत की मांग शामिल हैं। सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले भार पर पहुंचने के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ़ न्यूज़ीलैंड पीसीए कार्यपद्धति का उपयोग करता है।

शिकागो फेड राष्ट्रीय गतिविधि सूचकांक (सीएफ़एनएआई) राष्ट्रीय आर्थिक गतिविधि के 85 मासिक संकेतकों का भारित औसत है। यह पाया गया कि 85 आर्थिक गतिविधियों की श्रृंखला के पहले प्रमुख घटक से निर्मित एकल सूचकांक मुद्रास्फीति का प्रभावी ढंग से पूर्वानुमान लगा सकता है। सीएफ़एनएआई के लिए उपयोग किए जाने वाले आर्थिक संकेतक डेटा की चार व्यापक श्रेणियों से लिए गए हैं: i) उत्पादन और आय; ii) रोजगार, बेरोजगारी, और घंटे; iii) व्यक्तिगत उपभोग और आवास; और iv) बिक्री, ऑर्डर और इन्वेंट्री। सीएफ़एनएआई जैसे सूचकांक संयुक्त राज्य में आर्थिक गतिविधि और मुद्रास्फीति के वर्तमान और भविष्य के कार्य पर उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं।

भारत में, भादुरी एवं अन्य (2020) ने राष्ट्रीय स्तर पर 6, 9 और 12 उच्च-आवृत्ति संकेतकों का उपयोग करके एकल-सूचकांक गतिक कारकों का निर्माण किया। कुमार (2020) ने गतिक कारक मॉडल का उपयोग करते हुए 27 मासिक संकेतकों से भारत के लिए एक आर्थिक गतिविधि सूचकांक का निर्माण किया। यह अध्ययन अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित स्थिति का पता लगाने के लिए उद्योग, सेवाओं, वैश्विक और विविध गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करने वाले मासिक संकेतकों का उपयोग करता है। हालांकि, उप-राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर इस तरह के शोध भारतीय संदर्भ में अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं।

इस पृष्ठभूमि में, हम भारतीय उप-राष्ट्रीय इकाइयों के लिए क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों का एक समग्र सूचकांक बनाने का प्रयास करते हैं। सूचकांक छह उच्च आवृत्ति मासिक संकेतकों का एक संयोजन है जो पीसीए कार्यपद्धति का उपयोग करके क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक गतिविधि को दर्शाता है।

III. चरों और समग्र डेटा का विश्लेषण

राज्य स्तर पर आर्थिक गतिविधि सूचकांक बनाने के लिए चरों का चयन कार्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारा उद्देश्य उन संकेतकों को शामिल करना है जो आर्थिक गतिविधियों में स्पष्ट और लगातार होने वाले उतार-चढ़ाव को पकड़ते हैं। मासिक आधार पर राज्यों में आर्थिक गतिविधियों की प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए, चुनिंदा 18 राज्यों[1] के लिए पीसीए तकनीक का उपयोग कर एक समग्र सूचकांक तैयार किया गया है। इन राज्यों को डेटा उपलब्धता की सुसंगतता के आधार पर और चयनित समय अवधि के लिए लापता मूल्यों से बचने के लिए लिया गया था। इस पेपर में जिन चरों को लिया गया है वे हैं: i) माल और सेवा कर (जीएसटी) संग्रह; ii) विद्युत उत्पादन; iii) रोजगार दर; iv) निर्यात; v) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) काम की मांग और vi) प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत खातों में जमा। ये संकेतक अर्थव्यवस्था में कई क्षेत्रों को कवर करने वाली गतिविधियों को दर्शाते हैं। डेटा मार्च 2020 से फरवरी 2022 तक है।

चूंकि जीएसटी संग्रह में वृद्धि आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि को दर्शाती है, इसे राज्य स्तर पर आर्थिक गतिविधि के महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक के रूप में लिया जाता है। विद्युत उत्पादन को

[1] इन राज्यों का संयुक्त रूप से भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 93 प्रतिशत से अधिक का योगदान है।

अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र के प्रदर्शन के संकेतक के रूप में माना जा सकता है, जिससे यह आर्थिक गतिविधि का एक महत्वपूर्ण प्रतिबिंब है। रोजगार दर एक अन्य संकेतक है जिसका उत्पादन और आय पर सीधा असर पड़ता है। उच्च रोजगार दर उच्च आर्थिक वृद्धि के लिए अच्छा संकेत देती है और ऐसा ही इसके विपरीत भी। एक अन्य महत्वपूर्ण चर निर्यात है जो राज्य में उत्पादित कुल उत्पादन का एक हिस्सा है। निर्यात में वृद्धि मुख्य रूप से उच्च उत्पादन का परिणाम होगी और इस प्रकार यह उच्च आर्थिक गतिविधि को दर्शाती है। मनरेगा की कार्य मांग को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। मनरेगा के तहत काम की मांग में वृद्धि ग्रामीण स्तर पर आर्थिक गतिविधियों में मंदी को दर्शा सकती है क्योंकि मंदी की स्थिति में लोगों को वैकल्पिक आजीविका के अवसर नहीं मिलने पर मनरेगा के काम की मांग बढ़ जाती है। यह प्रवृत्ति विशेष रूप से अर्थव्यवस्था में कोविड-19 प्रेरित मंदी के दौरान स्पष्ट थी, जिससे राज्य स्तर पर आर्थिक गतिविधि को मापने में इस चर के महत्व का संकेत मिलता है। पीएमजेडीवाई खातों के तहत जमा मुख्य रूप से अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हैं। पीएमजेडीवाई खातों के तहत जमा राशि में वृद्धि अनौपचारिक श्रमिकों की आय में वृद्धि को दर्शा सकती है और इस प्रकार आर्थिक गतिविधियों में तेजी का संकेत दे सकती है।

एक संकेतक पर पहुंचने के लिए आर्थिक गतिविधि के कई आयामों को दर्शाने के लिए एक समग्र संकेतक का उपयोग किया जाता है। इस संकेतक का उपयोग आर्थिक गतिविधि की विभिन्न गतिकी का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। एक बहुभिन्नरूपी विश्लेषण का उपयोग डेटासेट की समग्र संरचना का अध्ययन करने, इसकी उपयुक्तता का आकलन करने और बाद के कार्यपद्धतिगत विकल्पों (जैसे, भार, एकत्रीकरण) को निर्देशित करने के लिए किया जाता है।

III.1: प्रमुख घटक विश्लेषण (पीसीए)

शोधकर्ता आमतौर पर डेटा विश्लेषण तकनीकों के एक सेट का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, क्रोनबैक गुणांक अल्फा तकनीक (अब से, सी-अल्फा) (क्रोनबैक, 1951) एक मॉडल या सर्वेक्षण में मदों की आंतरिक स्थिरता का सबसे आम अनुमान है। हालांकि, सी-अल्फा तकनीक की कमी यह है कि सहसंबंध आवश्यक रूप से समग्र संकेतक द्वारा व्यक्त की गई घटना पर अकेले संकेतकों के वास्तविक प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं। क्लस्टर विश्लेषण (सीएलए) तकनीक, जो हमेशा एक समूह का निर्माण करेगी, एक विशुद्ध रूप से वर्णनात्मक उपकरण है और यदि विश्लेषण के दौरान किए गए कार्यपद्धति संबंधी विकल्पों को स्पष्ट रूप से समझाया नहीं जाता है तो यह पारदर्शी नहीं हो सकता है। कैनोनिकल सहसंबंध विश्लेषण (सीसीए) एक अन्य तकनीक है जिसका उपयोग चर के दो समूहों के बीच संबंधों की जांच के लिए किया जा सकता है। सीसीए में, एक द्विभाजित निर्भर चर के मूल्यों में चर (या मामलों) को वर्गीकृत करने का एक तरीका विविक्तकर प्रकार्य विश्लेषण (डीएफए) द्वारा दिया जाता है। हालांकि, डीएफए कई मान्यताओं पर आधारित है, जैसे पूर्वानुमानों के कम सहसंबंध, रैखिकता और योगात्मकता, और पर्याप्त नमूना आकार जो इसके उपयोग को सीमित करता है (ओईसीडी, 2008)।

उच्च आवृत्ति संकेतकों और अनुभवजन्य अभ्यास का उपयोग करके भारतीय राज्यों के अंतर्निहित प्रदर्शन का आकलन करने में चुनौतियां हैं। उदाहरण के लिए, संभावित संकेतकों के एक बड़े सेट से उपयुक्त संकेतकों का चुनाव और चुने गए संकेतकों से एक ही निष्कर्षण के साथ, एक अंतर्निहित सामान्य प्रवृत्ति के बजाय अल्पकालिक स्वभाव को प्रतिबिंबित कर सकता है। दी गई अवधि के लिए जीएसवीए के लिए मासिक डेटा के अभाव में, अन्य अनुभवजन्य साधनों का उपयोग करना कठिन है। हम एक समग्र संकेतक विकसित करने के लिए पीसीए विधि का उपयोग करते हैं जो गतिविधि संकेतकों में मोड़ और प्रवृत्तियों का पता लगा सकता है।

यह आलेख विभिन्न विशेषता प्रतिनिधि चर पर पीसीए करके राज्य स्तर पर कुल आउटपुट डेटा में रुझानों का पता करने के लिए एक आर्थिक गतिविधि सूचकांक प्राप्त करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। पारंपरिक तरीकों की तुलना में इस कार्यपद्धति का मुख्य लाभ यह है कि यह अन्य तरीकों से जुड़ी कई माप समस्याओं से बचाती है, जैसे कि याद पूर्वाग्रह, मौसमी और डेटा संग्रह समय। अन्य सांख्यिकीय विकल्पों की तुलना में, पीसीए अभिकलात्मक रूप से आसान है, और डेटा के आयाम को कम करने में सभी चर का उपयोग करता है। पीसीए उच्च-आयामी डेटा को निम्न-आयामी डेटा में परिवर्तित करता है। इसके अलावा, यह सूचना हानि को कम करने के साथ-साथ संबंधित सुविधाओं को हटाकर एल्गोरिथम प्रदर्शन में सुधार करता है।

III.2 पीसीए कार्यप्रणाली

पीसीए डेटा सेट के विभिन्न आयामों में अधिकतम भिन्नता (सबसे बड़ी आईजेनवैल्यू) निकालकर काम करता है। इस संदर्भ में, हम विभिन्न उच्च-आवृत्ति चरों से मासिक आर्थिक गतिविधि सूचकांक का निर्माण करते हैं। उच्च-आवृत्ति चर का हमारा चयन मानदंडों पर आधारित है जैसे: i) राज्य-वार आर्थिक संकेतक अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं; और ii) चर समयबद्ध तरीके से और महत्वपूर्ण प्रकाशन अंतराल के बिना जारी किए जाते हैं।

पीसीए चरों के एक बड़े सेट को छोटे सेट में बदलकर काम करता है जिसमें अभी भी बड़े सेट में अधिकांश जानकारी होती है। प्रमुख घटक नए चर हैं जो प्रारंभिक चर के रैखिक संयोजन के रूप में निर्मित होते हैं जो चर के वास्तविक सेट से अधिकांश जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।

गणितीय शब्दों में, एन सहसंबद्ध चर के प्रारंभिक सेट से, पीसीए असंबद्ध सूचकांक या आयतीय घटक बनाता है, जहां प्रत्येक घटक प्रारंभिक चर का एक रैखिक भारित संयोजन होता है। उदाहरण के लिए, चर X_1 से Xn के सेट से, प्रमुख घटक हैं

$$PC_1 = a_{11}X_1 + a_{12}X_2 + \ldots + a_{1n}X_n$$

$$\vdots$$

$$PC_m = a_{m1}X_1 + a_{m2}X_2 + \ldots + a_{mn}X_n$$

जहाँ a_{mn} m^{th} प्रमुख घटक और n^{th} चर के लिए भार का प्रतिनिधित्व करता है। विभिन्न चरों की सीमा के बीच बड़े अंतर के कारण उत्पन्न सूचकांक में संभावित पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए, पीसीए तकनीक को लागू करने से पहले सभी चरों का मानकीकरण करना महत्वपूर्ण है। इसके बाद, सहप्रसरण मैट्रिक्स का निर्माण किया जाता है, जिससे आईजेनवेक्टर और आईजेनवैल्यू प्राप्त किए जाएंगे जो एक सूचकांक बनाने के लिए प्रमुख घटकों की गणना करने के लिए महत्वपूर्ण है।

सहप्रसरण मैट्रिक्स एक n × n सममित मैट्रिक्स है जिसमें प्रारंभिक चर के सभी संभावित युग्मों से जुड़े सहप्रसरण के रूप में प्रविष्टियाँ हैं। उदाहरण के लिए, 3 चर x, y, और z के साथ 3-आयामी डेटा सेट के लिए, सहप्रसरण मैट्रिक्स इस रूप का 3×3 मैट्रिक्स है:

$$\begin{bmatrix} Cov(x,x) & Cov(x,y) & Cov(x,z) \\ Cov(y,x) & Cov(y,y) & Cov(y,z) \\ Cov(z,x) & Cov(z,y) & Cov(z,z) \end{bmatrix}$$

डेटा के प्रमुख घटकों को निर्धारित करने के लिए, सहप्रसरण मैट्रिक्स से आईजेनवेक्टर और आईजेनवैल्यू की गणना की जाती है। प्रत्येक की एक आईजेनवैल्यू होती है और उनकी संख्या डेटा के आयामों की संख्या के बराबर होती है। प्रत्येक प्रमुख घटक के लिए प्रसरण (λ_i) संबंधित आईजेनवेक्टर के आईजेनवैल्यू द्वारा दिया जाता है। आईजेनवेक्टरों को उनके आईजेनवैल्यू के क्रम में रैंकिंग करके, उच्चतम से निम्नतम, हम महत्व के क्रम में प्रमुख घटक प्राप्त करते हैं।

इस बाधा के अधीन कि वर्गित भार का योग एक है, घटकों को डेटा सेट में उनके द्वारा बताई गई भिन्नता की मात्रा के आधार पर अवरोही क्रम में क्रमबद्ध किया जाता है। पहला घटक (पीसी$_1$) डेटासेट में भिन्नता की सबसे बड़ी संभावित मात्रा की व्याख्या करता है। प्रमुख घटक द्वारा मूल डेटा सेट में कुल भिन्नता का अनुपात λ_i /n द्वारा दिया जाता है, क्योंकि आईजेनवैल्यू का योग प्रारंभिक डेटा सेट में चर की संख्या के बराबर होता है (व्यास और कुमारनायके, 2006)।

उसी बाधा के अधीन, दूसरा घटक (पीसी$_2$) पहले घटक के साथ पूरी तरह से असंबद्ध है। दूसरा घटक पहले घटक की तुलना में कम भिन्नता की व्याख्या करता है। हालाँकि, प्रत्येक घटक डेटा में एक अतिरिक्त आयाम प्राप्त करता है क्योंकि बाद के घटक पिछले घटकों के साथ असंबद्ध होते हैं; लेकिन मूल डेटा सेट में भिन्नता के छोटे और छोटे अनुपात की व्याख्या करता है। वर्तमान अध्ययन में, हमने सूचकांक के निर्माण के लिए पहले प्रमुख घटक पर विचार किया है।

पीसीए में चर के स्तर के एक मानकीकृत मूल्य की गणना की जाती है। सूचकांक के एक सकारात्मक मूल्य का मतलब है कि गतिविधि औसत से ऊपर थी और एक नकारात्मक मूल्य के लिए इसके विपरीत। सूचकांक का उपयोग क्षेत्रीय आर्थिक गति के संकेतक के रूप में किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी विशेष राज्य के लिए लगातार कई महीनों के दौरान एक दिया गया सूचकांक मूल्य बढ़ता (घटता) है, तो इसे एक संकेत के रूप में लिया जा सकता है कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में स्थितियां सुधर रही हैं (खराब हो रही हैं)। इसी तरह, लगातार कई महीनों के सकारात्मक मूल्यों को एक संकेत के रूप में लिया जा सकता है कि उस क्षेत्र में गतिविधि औसत स्तर से ऊपर बढ़ रही है और इसके विपरीत।

IV. राज्य स्तर पर आर्थिक गतिविधि सूचकांक

कोविड-19 महामारी और परिणामी लॉकडाउन के कारण राज्यों में आर्थिक गतिविधियों में भारी गिरावट आई (सारणी 1)। यह अप्रैल और मई 2020 के महीनों में राज्यों में सूचकांक मूल्य में तेज गिरावट से परिलक्षित होता है। नतीजतन, जैसे-जैसे राज्यों में महामारी की गंभीरता कम होने लगी है, आने वाले महीनों में सूचकांक मूल्य में सापेक्ष सुधार स्पष्ट है। हालाँकि, दूसरी लहर के आगमन के साथ, आर्थिक गतिविधि फिर से बाधित हुई, हालाँकि पहली महामारी लहर की तुलना में कम गंभीर थी। यह पहली लहर की तुलना में राज्यों में सूचकांक के अपेक्षाकृत कम संकुचन में परिलक्षित हुआ। इसके बाद, अन्य कदमों में तेजी से टीकाकरण और स्वास्थ्य के मोर्चे पर बेहतर तैयारियों पर ध्यान देने के साथ, ओमिक्रॉन लहर का प्रभाव जीवन और आजीविका दोनों पर कम गंभीर था। ओमिक्रॉन लहर के बावजूद राज्यों में दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में सूचकांक सकारात्मक रहा।

अप्रैल 2020 के महीने के दौरान, चूंकि आर्थिक गतिविधि राज्यों में समग्र गिरावट के दौर से गुजर रही थी, राजस्थान और महाराष्ट्र में अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव देखा गया था। दूसरी लहर की वजह से आर्थिक आघात के समय, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में आर्थिक गतिविधियों में कम गिरावट देखी गई। जबकि तेलंगाना, असम और पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों पर अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव देखा गया। इसके बाद, जैसा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट देश में आया। कई राज्यों की अर्थव्यवस्थाएं इसके प्रभाव का सामना करने में सक्षम थीं जैसा कि राज्यों में सूचकांक के सकारात्मक मूल्यों से अनुमान लगाया जा सकता है। इस प्रकार, भारतीय राज्यों में आर्थिक गतिविधियों पर कोविड-19 के प्रभाव के लिए एक अलग स्थानिक स्वरूप था।

सारणी 1: राज्य-वार आर्थिक गतिविधि सूचकांक

क्षेत्र	मार्च-20	अप्रै-20	मई-20	जून-20	जुला-20	अग-20	सित-20	अक्टू-20	नव-20	दिस-20	जन-21	फर-21
आंध्र प्रदेश	-0.82	-2.03	-1.15	-0.04	-0.53	-0.44	-0.29	-0.40	-0.66	-0.25	0.71	0.26
असम	-0.09	-1.96	-1.13	-0.13	-0.18	-0.51	0.27	0.24	-0.11	0.08	0.29	-0.30
बिहार	-0.71	-1.92	-1.55	-0.48	-0.37	-0.82	-0.44	-0.27	-0.76	-0.23	0.16	0.09
छत्तीसगढ़	-1.40	-2.28	-0.65	-0.02	-0.26	-0.17	-0.54	-0.58	-0.61	-0.21	0.07	-0.16
गुजरात	-0.62	-1.83	-1.19	-0.46	-0.56	-0.66	-0.13	-0.10	-0.20	-0.17	-0.04	0.06
हरियाणा	-0.89	-2.36	-1.43	-0.77	-0.72	-0.84	-0.07	-0.25	-0.34	0.10	0.65	0.37
झारखंड	-0.33	-2.15	-1.46	-0.53	-0.35	-0.13	-0.22	-0.18	-0.12	-0.14	-0.06	0.16
कर्नाटक	-0.44	-1.76	-0.94	-0.53	-0.75	-0.68	-0.90	-0.70	-0.72	-0.22	-0.03	0.00
केरल	-0.29	-1.67	-0.51	-0.26	-0.24	-0.19	-0.11	-0.03	-0.52	0.01	0.03	0.02
मध्य प्रदेश	-0.97	-2.43	-1.51	-0.39	-0.20	-0.32	-0.13	0.04	0.07	0.40	0.37	-0.03
महाराष्ट्र	-0.74	-2.53	-1.54	-0.83	-0.81	-0.79	-0.45	-0.04	-0.12	0.25	0.41	0.29
ओडिशा	-1.16	-2.17	-1.02	-0.54	-0.57	-0.61	-0.66	-0.47	-0.75	-0.31	-0.28	-0.09
पंजाब	0.11	-2.49	-1.82	-0.44	-0.02	-0.29	-0.27	-0.34	-0.09	0.14	0.01	-0.02
राजस्थान	-1.00	-2.67	-1.33	-0.54	-0.37	-0.58	-0.38	-0.17	-0.14	0.18	0.28	0.14
तमिलनाडु	-0.14	-1.70	-1.21	-0.62	-0.45	-0.18	-0.19	-0.17	-0.12	0.19	0.22	0.09
तेलंगाना	-0.38	-2.12	-1.64	-0.91	-0.26	-0.24	-0.19	-0.04	-0.13	0.11	0.21	-0.18
उत्तर प्रदेश	-0.92	-1.96	-1.54	-1.02	-0.47	-0.42	-0.26	-0.25	-0.48	-0.13	0.05	-0.07
पश्चिम बंगाल	-0.36	-2.41	-1.81	-0.87	-0.23	-0.53	-0.13	-0.17	-0.48	0.11	0.40	0.38

क्षेत्र	मार्च-21	अप्रै-21	मई-21	जून-21	जुला-21	अग-21	सित-21	अक्टू-21	नव-21	दिस-21	जन-22	फर-22
आंध्र प्रदेश	1.29	0.79	-0.02	0.51	0.51	0.66	0.33	0.43	-0.09	0.17	0.51	0.55
असम	0.20	0.19	-0.39	-0.81	0.18	0.46	0.93	1.29	0.43	0.42	0.35	0.26
बिहार	0.78	0.82	0.05	0.04	0.54	0.23	0.07	0.49	0.47	1.14	1.38	1.29
छत्तीसगढ़	0.75	0.79	0.35	0.69	0.73	0.92	0.21	0.38	0.02	0.55	0.72	0.69
गुजरात	0.36	0.47	0.39	0.20	0.59	0.40	0.24	0.61	0.57	0.63	0.59	0.83
हरियाणा	0.86	0.62	-0.15	0.02	0.36	0.47	0.52	0.54	0.34	0.93	1.17	0.89
झारखंड	0.68	0.67	0.21	0.33	0.42	0.35	0.35	0.43	0.10	0.30	0.76	0.90
कर्नाटक	0.73	0.73	-0.10	-0.12	0.46	0.64	0.52	0.69	0.32	1.03	1.27	1.49
केरल	0.43	0.94	-0.04	-0.27	0.16	0.32	0.03	0.53	0.48	0.39	0.43	0.34
मध्य प्रदेश	0.86	0.61	-0.05	-0.20	0.42	0.02	0.15	0.25	0.46	1.07	0.81	0.70
महाराष्ट्र	1.01	0.73	0.27	0.07	0.56	0.47	0.26	0.62	0.44	0.90	0.84	0.75
ओडिशा	0.48	0.57	0.50	0.46	0.80	0.60	0.56	0.59	0.73	1.18	0.90	1.28
पंजाब	0.28	0.70	-0.02	-0.04	0.72	0.53	0.20	0.45	0.74	0.77	0.65	0.53
राजस्थान	0.58	0.48	-0.12	-0.08	0.51	0.61	0.13	0.70	0.59	0.77	1.24	1.16
तमिलनाडु	0.58	0.58	-0.07	-0.10	0.22	0.35	0.29	0.46	0.40	0.53	0.59	0.43
तेलंगाना	0.52	0.51	-0.25	-0.22	0.51	0.77	0.73	1.07	0.28	0.67	0.69	0.50
उत्तर प्रदेश	0.63	0.67	-0.11	0.12	0.64	0.57	0.56	0.70	0.45	0.90	1.28	1.09
पश्चिम बंगाल	0.99	0.90	-0.36	-0.33	0.30	0.33	0.44	0.69	0.58	0.86	0.92	0.77

स्रोत: लेखकों की अपनी गणना।

लॉकडाउन के चलते आवाजाही पर लगी पाबंदियों ने राज्यों को अलग-अलग तरह से प्रभावित किया है। निम्नलिखित खंड में, यह आलेख दिखाता है कि इस विशिष्ट आर्थिक प्रभाव के लिए एक संभावित व्याख्या इन राज्यों की विविध आर्थिक संरचना हो सकती है।

V. अनुभवजन्य विश्लेषण

कोविड-19 के दौरान सामाजिक दूरी और लॉकडाउन के परिणामस्वरूप, दैनिक आवाजाही और जीवनशैली से संबंधित आदतों में महत्वपूर्ण तरीके से बदलाव आया है। आईएमएफ़ (2021) कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान राज्य स्तर पर वायरस के प्रसार और अर्थव्यवस्था दोनों पर नियंत्रण उपायों और स्वैच्छिक सामाजिक दूरी के प्रभाव की मात्रा निर्धारित करता है। राज्य-स्तरीय अनुभवजन्य विश्लेषण से पता चलता है कि सामाजिक दूरी और रोकथाम के उपायों ने मामलों की संख्या को प्रभावी ढंग से कम कर दिया, लेकिन उच्च आर्थिक लागतों के साथ आया।

बेयर एवं अन्य (2021) ने भारत में आर्थिक गतिविधि को मापने के लिए दैनिक बिजली की खपत और मासिक रात के समय प्रकाश की तीव्रता के डेटा का उपयोग किया। वे दिखाते हैं कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश समान रूप से प्रभावित नहीं हुए हैं। विषमता को हिस्सों में कोविड-19 संक्रमणों की व्यापकता, विनिर्माण की हिस्सेदारी और वापसी प्रवासन द्वारा समझाया गया है। मीनन एवं अन्य (2021) कोविड-19 के श्रम बाजार प्रभाव के देश के भीतर क्षेत्रीय विषमता के निर्धारकों का पहले और बाद का विश्लेषण करते हैं। अध्ययन में पाया गया है कि क्षेत्रों में आर्थिक प्रभाव के प्रसार को केवल संक्रमण के प्रसार से नहीं समझाया जा सकता है। इसके बजाय, एक क्षेत्र की आर्थिक संरचना देखी गई विषमता का एक महत्वपूर्ण चालक है।

इस संदर्भ में, हम एक प्रासंगिक प्रश्न का विश्लेषण करते हैं; विभिन्न राज्यों की आर्थिक संरचना में अंतर को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तर पर कोविड-19 का प्रभाव कैसे प्रकट होता है।

महामारी के दौरान आर्थिक गतिविधियों पर लॉकडाउन का प्रभाव स्पष्ट था। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राज्यों में सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न नीतिगत उपायों ने लोगों की आवाजाही को कम कर दिया। आवाजाही प्रतिबंध उपायों की कठोरता, और इसका कार्यान्वयन गूगल मोबिलिटी डेटा में परिलक्षित होता है (सारणी 2)। इस डेटा का उपयोग लॉकडाउन उपायों की कठोरता को दर्शाने के लिए प्रॉक्सी के रूप में किया

सारणी 2: राज्य-वार गूगल मोबिलिटी डेटा

क्षेत्र	मार्च-20	अप्रै-20	मई-20	जून-20	जुला-20	अग-20	सित-20	अक्टू-20	नव-20	दिस-20	जन-21	फर-21	मार्च-21	अप्रै-21	मई-21	जून-21	जुला-21	अग-21	सित-21	अक्टू-21	नव-21	दिस-21	जन-22	फर-22
आंध्र प्रदेश	-16.4	-51.1	-33.6	-18.4	-23.7	-23.4	-17.0	-19.4	-16.8	-8.5	-10.2	-5.9	-5.3	-14.5	-36.3	-23.9	-14.6	-9.3	-5.5	-3.9	-0.1	8.3	2.9	14.9
असम	-12.5	-45.1	-24.0	-15.9	-27.2	-19.4	-10.6	-15.4	-12.7	-4.7	-8.3	-5.8	-5.7	-13.4	-32.5	-25.2	-20.5	-12.0	-4.9	-4.3	4.5	16.1	9.5	26.2
बिहार	-16.7	-38.1	-22.4	-12.0	-19.5	-7.6	-1.9	-9.4	-15.4	-3.7	-2.6	-4.6	-4.3	-16.7	-39.5	-16.6	-5.3	-0.5	5.6	1.4	-2.2	16.8	17.3	26.7
छत्तीसगढ़	-20.3	-43.8	-24.7	-17.2	-21.1	-19.0	-24.5	-19.6	-21.7	-13.1	-11.1	-12.7	-12.4	-46.5	-44.2	-20.9	-10.6	-4.1	0.3	2.9	-2.5	13.6	14.4	23.7
गुजरात	-24.3	-67.8	-49.4	-27.1	-26.3	-26.5	-20.0	-18.3	-26.6	-16.3	-15.9	-14.0	-13.5	-26.6	-33.5	-16.5	-11.6	-9.7	-4.3	0.6	-20.0	2.9	3.0	9.5
हरियाणा	-26.3	-66.0	-44.4	-32.1	-29.5	-27.6	-23.5	-21.5	-23.5	-18.6	-19.1	-16.1	-14.8	-21.5	-46.2	-24.2	-16.7	-13.2	-7.5	-5.2	-11.6	2.1	-4.1	7.3
झारखंड	-17.2	-43.8	-31.1	-19.5	-16.7	-14.2	-11.4	-16.4	-17.0	-8.8	-8.8	-9.1	-8.4	-24.3	-42.0	-25.9	-17.5	-9.2	-2.1	-2.9	-3.6	9.2	7.0	20.8
कर्नाटक	-25.0	-66.9	-44.8	-33.4	-42.7	-34.6	-32.9	-33.6	-31.2	-28.5	-25.9	-23.1	-21.7	-35.6	-61.1	-49.4	-35.2	-25.4	-21.9	-20.7	-20.5	-11.1	-16.7	-7.6
केरल	-20.5	-52.3	-30.2	-20.2	-25.4	-21.4	-19.6	-21.9	-18.6	-15.5	-10.8	-9.3	-6.4	-18.8	-52.1	-35.5	-23.2	-13.7	-6.6	-0.5	6.8	13.0	13.5	23.4
मध्य प्रदेश	-22.2	-57.1	-40.8	-27.0	-24.7	-22.4	-15.3	-17.8	-19.0	-12.4	-9.9	-10.4	-12.2	-42.6	-53.2	-29.0	-14.6	-8.8	-3.0	-1.6	-5.0	9.4	10.6	16.8
महाराष्ट्र	-29.0	-71.9	-60.3	-47.1	-47.1	-41.6	-37.6	-33.5	-32.1	-25.3	-23.2	-21.5	-22.5	-43.4	-45.8	-32.8	-26.4	-18.9	-16.3	-9.9	-16.6	-3.8	-3.4	2.9
ओडिशा	-18.6	-45.8	-26.6	-24.9	-28.4	-21.7	-15.2	-20.7	-17.0	-11.9	-9.5	-12.4	-9.7	-15.4	-44.1	-33.3	-21.8	-10.5	-4.8	-4.6	1.9	9.6	8.4	17.8
पंजाब	-22.2	-61.3	-38.1	-25.9	-24.8	-25.8	-23.7	-20.0	-20.1	-16.5	-17.3	-17.1	-16.8	-19.8	-35.3	-22.6	-14.2	-10.7	-7.1	-6.1	-8.7	-1.3	-3.9	3.4
राजस्थान	-23.0	-57.0	-36.5	-20.9	-16.4	-19.1	-16.5	-18.6	-23.5	-15.0	-12.5	-11.8	-10.4	-27.6	-52.5	-27.3	-13.3	-8.4	-4.9	-3.4	-8.0	7.6	8.5	19.2
तमिलनाडु	-18.7	-65.0	-41.9	-32.4	-34.4	-31.2	-23.3	-22.3	-23.4	-16.6	-19.6	-14.4	-11.3	-19.9	-50.1	-37.9	-18.7	-11.4	-8.2	-4.4	-11.6	2.4	-9.2	7.6
तेलंगाना	-25.0	-66.6	-49.9	-35.5	-38.8	-38.1	-33.3	-34.0	-29.9	-26.5	-25.4	-20.1	-20.0	-29.3	-46.0	-34.1	-26.5	-22.3	-18.0	-16.0	-12.3	-4.6	-13.6	-2.0
उत्तर प्रदेश	-20.7	-50.2	-28.1	-19.5	-18.5	-15.2	-12.6	-13.1	-14.9	-7.7	-6.2	-3.9	-2.8	-15.4	-43.4	-23.1	-10.8	-2.9	5.6	6.1	2.7	18.9	13.0	20.8
पश्चिम बंगाल	-20.2	-56.8	-46.5	-29.1	-30.7	-28.1	-21.1	-24.7	-20.3	-13.2	-13.7	-14.0	-11.9	-17.9	-42.0	-31.5	-20.9	-13.6	-8.6	-13.7	-7.6	3.3	1.7	12.3

स्रोत : गूगल मोबिलिटी रिपोर्ट डेटा।

जाता है। उच्च आवाजाही प्रतिबंध स्पष्ट रूप से महामारी की पहली लहर के दौरान आर्थिक गतिविधि सूचकांक में गिरावट से जुड़े थे। अप्रैल और मई 2020 के महीनों में सबसे कड़ा लॉकडाउन था और इन महीनों में आर्थिक गतिविधियों में भी तेज संकुचन देखा गया। दूसरी लहर के दौरान, आवाजाही प्रतिबंध अपेक्षाकृत हल्के थे, जिससे आर्थिक गतिविधियों पर कम गंभीर प्रभाव पड़ा। इसके अलावा, जब ओमिक्रॉन लहर ने देश को प्रभावित किया, तो लॉकडाउन केवल सीमांत थे, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधि एक सकारात्मक पथ पर चलती रही। लॉकडाउन का आर्थिक गतिविधि पर सीधा प्रभाव पड़ा, जिसके लिए यह आवश्यक हो गया कि इसे एक अंशांकित और सुविचारित तरीके से उपयोग किया जाए और अंतिम उपाय के रूप में उपयोग किया जाए ताकि उपयुक्त उपायों के माध्यम से आर्थिक गतिविधि को तेजी से बहाल किया जा सके।

हालाँकि, राज्यों में आर्थिक गतिविधियों पर आवाजाही प्रतिबंधों का अपेक्षाकृत भिन्न प्रभाव है। यह पाया गया कि कुछ राज्यों में लंबे समय तक आवाजाही प्रतिबंधों का आर्थिक गतिविधियों पर और अधिक प्रभाव पड़ा। इसके विपरीत, कुछ राज्यों ने अपेक्षाकृत जल्दी ही आर्थिक गतिविधियों में पुनरुत्थान देखा, जबकि उनमें लंबी अवधि के लिए आवाजाही प्रतिबंध जारी था। आवाजाही पर प्रतिबंधों ने अलग-अलग तीव्रता के साथ राज्यों में आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया (चार्ट 1)।

राज्यों की विविध आर्थिक संरचना और क्षेत्रीय संरचना आर्थिक गतिविधि पर अंतर प्रभाव का एक संभावित कारण था (चार्ट 2)। जो राज्य खनन और उत्खनन के साथ-साथ कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर अधिक निर्भर थे, उनमें महामारी के बीच अपेक्षाकृत बेहतर आर्थिक परिदृश्य देखा गया। कृषि क्षेत्र की वृद्धि में सबसे कम गिरावट उम्मीद की किरण बनी रही। सेवा क्षेत्र में, कंपनियों की घर से काम करने/ कहीं से भी काम करने की नीति और काम को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए इंटरनेट के मजबूत उपयोग के कारण कुछ सेवाओं पर अच्छा प्रभाव देखा गया। हालांकि, संपर्क गहन सेवाएं सबसे अधिक नकारात्मक रूप से प्रभावित हुईं, जबकि लोक प्रशासन जैसी सेवाओं ने सेवाओं में महत्वपूर्ण गिरावट में गुंजाइश प्रदान करने का प्रयास किया। विनिर्माण के दबदबे वाले आर्थिक ढांचे वाले राज्यों में भी लॉकडाउन का खामियाजा दूसरों के मुकाबले ज्यादा देखा गया।

चार्ट 1: भारतीय राज्यों में गतिशीलता और आर्थिक गतिविधि के बीच सहसंबंध

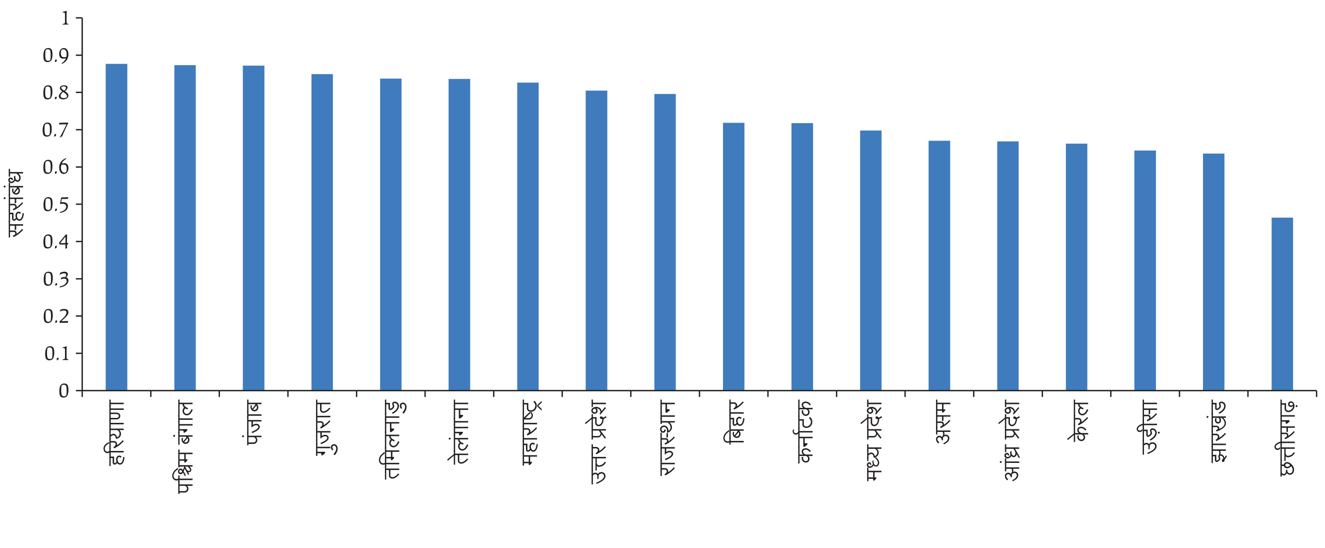

स्रोत: लेखकों की अपनी गणना।

चार्ट 2: जीएसवीए की राज्य-वार क्षेत्रीय संरचना

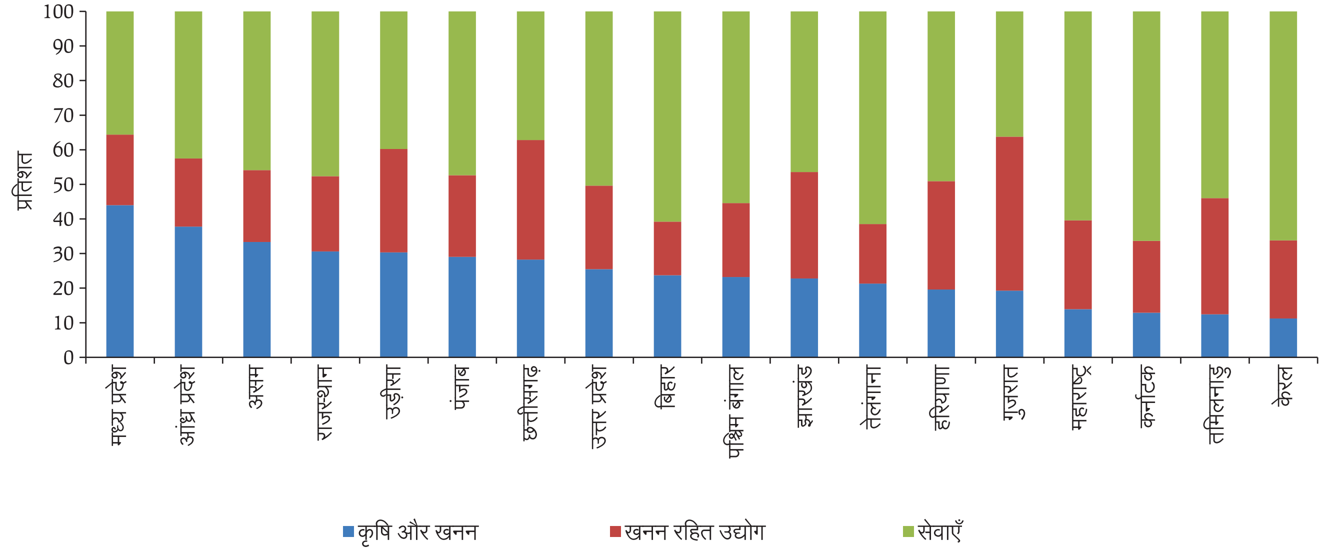

स्रोत: एमओएसपीआई, भारत सरकार।

बाद के खंड में प्रस्तुत चार्ट राज्य की आर्थिक संरचना और समग्र आर्थिक गतिविधि पर आवाजाही प्रतिबंधों के प्रभाव के बीच संबंध दिखाते हैं। वक्र की नीचे की ओर झुकी हुई प्रकृति का मतलब होगा कि जीएसवीए में उल्लिखित उप-क्षेत्र के उच्च हिस्से वाले राज्यों में (वाई अक्ष पर मान अधिक है) आर्थिक गतिविधि और गतिशीलता के बीच कम सहसंबंध है (एक्स अक्ष पर मान कम है) जिससे राज्य की समग्र आर्थिक गतिविधियों पर आवाजाही प्रतिबंधों का प्रभाव कम हुआ है। इसका मतलब यह है कि जिन राज्यों में उस क्षेत्र का हिस्सा अधिक था, वे अन्य राज्यों की तुलना में आवाजाही प्रतिबंधों के कारण अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुए। दूसरे शब्दों में, नीचे की ओर झुके हुए वक्र का अर्थ है कि आवाजाही प्रतिबंधों का समग्र आर्थिक गतिविधि पर अपेक्षाकृत कम प्रभाव पड़ा, जिससे यह संकेत मिलता है कि जीएसवीए में उस क्षेत्र की उच्च हिस्सेदारी ने अन्य राज्यों की तुलना में लॉकडाउन प्रेरित आवाजाही प्रतिबंधों के खिलाफ राज्य की आर्थिक आघात-सहनीयता को मजबूत किया।

V.1 कृषि

आवाजाही और आर्थिक गतिविधि सूचकांक के बीच सहसंबंध उन राज्यों के लिए कम पाया गया जिनके जीएसवीए में कृषि का हिस्सा अधिक है (चार्ट 3ए)। यह इंगित करता है कि कृषि के अपेक्षाकृत अधिक हिस्से वाले राज्यों ने आर्थिक गतिविधियों पर कम प्रभाव देखा है। कोविड-19 के कारण हुए आर्थिक आघात के बीच कृषि क्षेत्र आघात-सहनीय साबित हुआ है। कृषि क्षेत्र में, जो राज्य वानिकी और लॉगिंग पर अधिक निर्भर हैं, उन्होंने आर्थिक गतिविधि पर अपेक्षाकृत कम प्रभाव देखा, जैसा कि वानिकी और लॉगिंग में उच्च हिस्सेदारी वाले राज्यों के लिए आवाजाही और आर्थिक गतिविधि के बीच कम सहसंबंध में परिलक्षित होता है (चार्ट 3बी)।

V.2 उद्योग

आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, विपरीत प्रवासन के कारण प्रवासी श्रमिकों की कमी और कम मांग के कारण औद्योगिक क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ। विनिर्माण पर अधिक निर्भरता वाले

चार्ट 3: कृषि और वानिकी

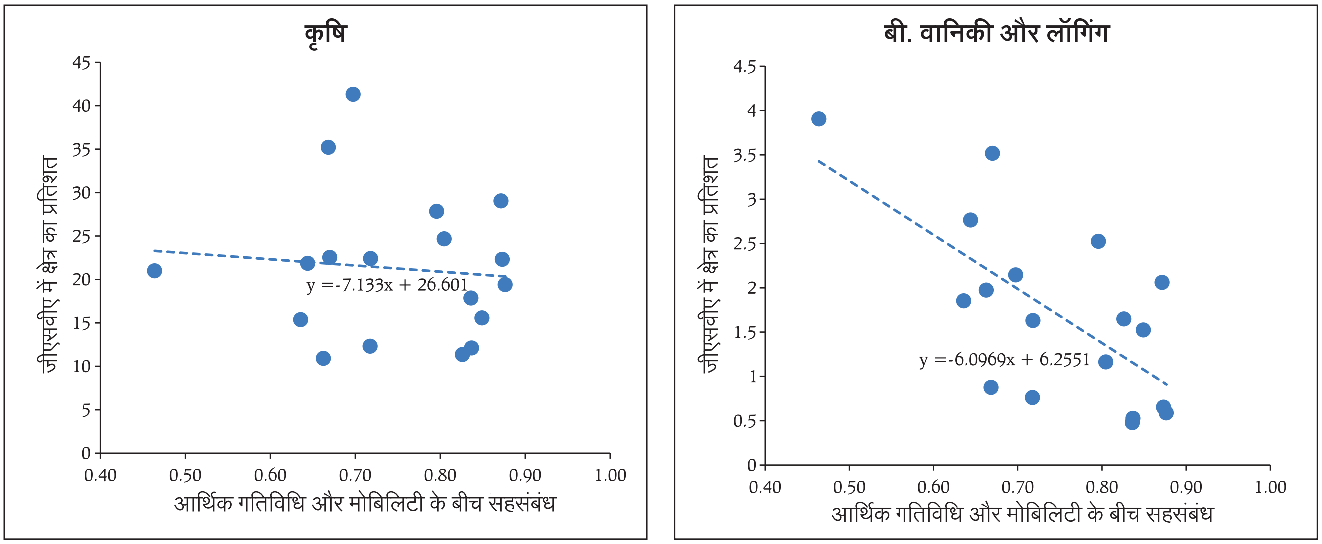

स्रोत: लेखकों की अपनी गणना।

राज्यों में आर्थिक गतिविधि और आवाजाही के बीच उच्च सहसंबंध पाया गया जिससे इन राज्यों पर आवाजाही प्रतिबंधों का अधिक प्रभाव पड़ा (चार्ट 4ए)। विनिर्माण के उच्च हिस्से और आवाजाही और आर्थिक गतिविधि के बीच उच्च सहसंबंध के साथ, आवाजाही प्रतिबंधों का समग्र आर्थिक गतिविधि पर अधिक गहरा प्रभाव पड़ा। उद्योग क्षेत्र के भीतर, हालांकि, खनन और उत्खनन के उच्च हिस्से वाले राज्यों में आवाजाही और आर्थिक गतिविधि के बीच कम सहसंबंध था, जो ऐसे राज्यों में आर्थिक गतिविधि पर आवाजाही प्रतिबंधों के कम प्रभाव को दर्शाता है (चार्ट 4बी)।

चार्ट 4: उद्योग

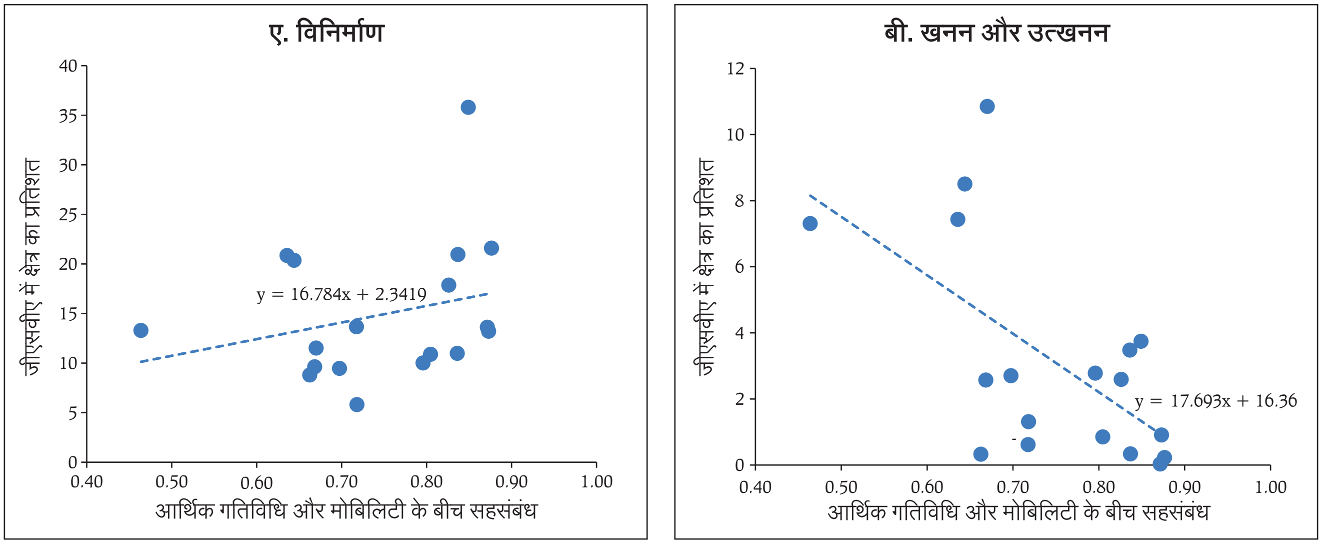

स्रोत: लेखकों की अपनी गणना।

चार्ट 5: सेवाएं

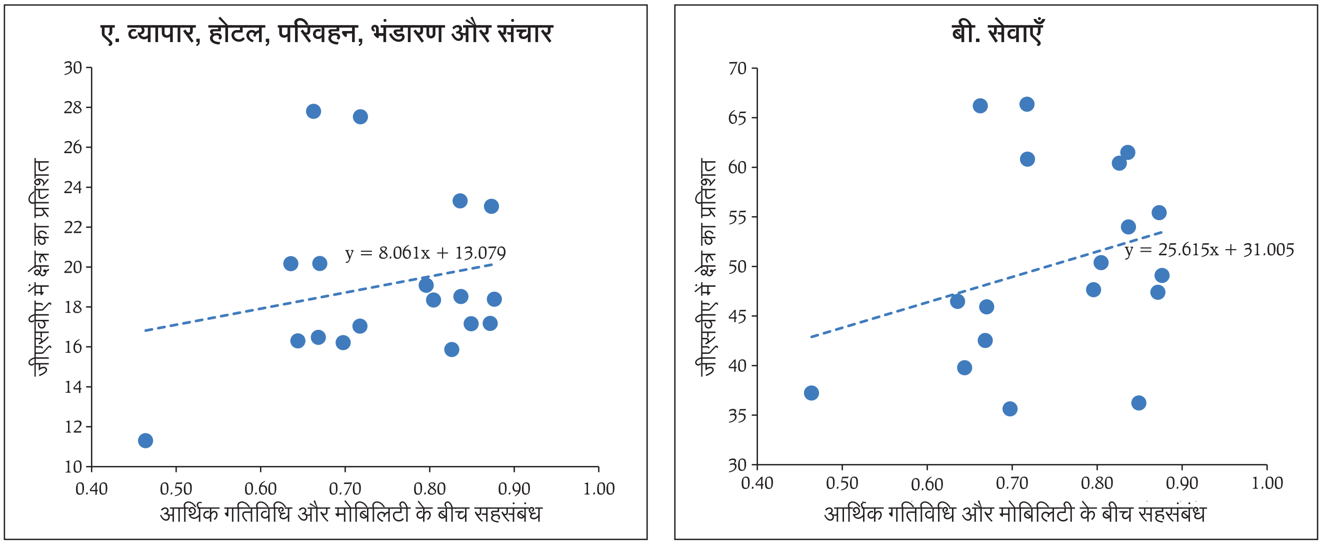

स्रोत: लेखकों की अपनी गणना।

V.3 सेवाएं

कोविड-19 के प्रकोप से सेवा क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए इनपुट प्रदान करने में क्षेत्र की भूमिका को देखते हुए, इसने एक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव देखा। सेवा क्षेत्र में, व्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण और संचार जैसी संपर्क गहन सेवाओं के उच्च हिस्से वाले राज्यों में आवाजाही और आर्थिक गतिविधि के बीच उच्च सहसंबंध पाया गया और इसके विपरीत भी । यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि संपर्क-गहन सेवाओं पर अधिक निर्भरता वाले राज्यों में आवाजाही प्रतिबंधों का आर्थिक गतिविधियों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा (चार्ट 5ए और 5बी)।

VI. निष्कर्ष

कोविड-19 ने राज्य की अर्थव्यवस्थाओं पर एक स्थायी छाप छोड़ी है, जिससे स्थायी परिवर्तन हुए हैं। राज्य-वार आर्थिक गतिविधि सूचकांक से पता चलता है कि राज्य की अर्थव्यवस्थाओं में कोविड-19 के कारण हुए व्यवधानों से बड़े पैमाने पर और अभूतपूर्व गिरावट आई है। संबंधित लॉकडाउन और आवाजाही प्रतिबंधों ने, हालांकि, राज्यों में अंतर प्रभाव लाया। संबंधित राज्यों की आर्थिक संरचना ने कोविड-19 प्रेरित प्रतिबंधों के बाद उनके आर्थिक प्रक्षेपवक्र को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह पाया गया कि अपने जीएसवीए में कृषि और खनन के उच्च हिस्से वाले राज्यों ने उद्योग और सेवाओं के उच्च हिस्से वाले राज्यों की तुलना में अधिक आघात-सहनीय आर्थिक मार्ग देखा। कृषि क्षेत्र में, जीएसवीए में वानिकी और लॉगिंग के उच्च हिस्से वाले राज्यों ने आर्थिक गतिविधियों पर अपेक्षाकृत कम प्रभाव देखा। यह भी स्पष्ट था कि अपने जीएसवीए में विनिर्माण और सेवाओं के उच्च हिस्से वाले राज्यों ने आर्थिक गतिविधियों पर अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव देखा।

हालांकि, आर्थिक संरचना के अलावा, यह संभव है कि आवाजाही और आर्थिक गतिविधि के बीच का संबंध अन्य कारकों से प्रभावित हो सकता है, जिसमें विभिन्न स्थानीयकृत आवाजाही प्रतिबंध और विभिन्न राज्यों में अनुकूल नीति प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। इन कारकों को जोड़ने से विश्लेषण और समृद्ध होगा, हालांकि, इस तरह के औपचारिक विश्लेषण के लिए डेटा की उपलब्धता और मात्रात्मकता की आवश्यकता होती है, जो इस समय दुर्लभ है।

उप-क्षेत्रीय स्तर पर और आर्थिक संरचना के इस तरह के विस्तृत विश्लेषण ने राष्ट्रीय नीति हस्तक्षेपों के पूरक के रूप में

उनकी संबंधित आर्थिक संरचना के आधार पर राज्यों द्वारा एक अलग नीति प्रतिक्रिया की आवश्यकता और महत्व पर बल दिया है। यह सुनिश्चित करेगा कि इस तरह के बड़े संकट के दौरान, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अच्छी तरह से सूचित और समन्वित नीतिगत निर्णयों से समग्र आर्थिक गतिविधियों में न्यूनतम नुकसान होगा और आर्थिक विकास के पहिए प्रमुख आर्थिक व्यवधानों के बाद तेजी से चलने लग जाएंगे।

संदर्भ

Bhadury, S., Ghosh, S., and Kumar, P. (2020), "Nowcasting Indian GDP Growth Using a Dynamic Factor Model", *RBI Working Paper Series No. 03.*

Beyer, R. C., Franco-Bedoya, S., and Galdo, V. (2021), "Examining the economic impact of COVID-19 in India through daily electricity consumption and nighttime light intensity", *World Development*, 140, 105287.

Cortina, J. M. (1993), "What is coefficient alpha? An examination of theory and applications", *Journal of applied psychology*, 78(1), 98.

Crone, T. M., and Clayton-Matthews, A. (2005), "Consistent economic indexes for the 50 states", *Review of Economics and Statistics*, 87(4), 593-603.

Cronbach L. J. (1951), "Coefficient alpha and the internal structure of tests", *Psychometrika*, 16: 297-334.

Deb P, Furceri D, David J, and Tawk N (2020), "The Effect of Containment Measures on the COVID-19 Pandemic", *IMF Working Paper*, August.

Habli N., Macdonald R. and Tweedle J. (2020), "Experimental Economic Activity Indexes for Canadian Provinces and Territories: Experimental Measures Based on Combinations of Monthly Time series", *Analytical Studies Branch Research Paper Series, Statistics Canada.*

IMF (2020), "The Great Lockdowns", *World Economic Outlook*, April.

Jobson, J. D. (1992), "Principal components, factors and correspondence analysis", Applied multivariate data analysis (pp. 345-482), *Springer, New York, NY.*

Joint Research Centre-European Commission. (2008), "Handbook on constructing composite indicators: methodology and user guide", *OECD publishing.*

Kumar P. (2020), "An Economic Activity Index for India", *RBI Bulletin*, November 2020.

McLachlan G., (2004), "Discriminant Analysis and Statistical Pattern Recognition", NY: Wiley-Interscience, Wiley Series in Probability and Statistics.

Meinen, P., Serafini, R., and Papagalli, O. (2021). Regional economic impact of Covid-19: the role of sectoral structure and trade linkages. *Working Paper Series 2528, European Central Bank.*

Kishore N., Kahn R. and others (2021), "Lockdowns result in changes in human mobility which may impact the epidemiologic dynamics of SARS-CoV-2", *Scientific Report.* (https://www.nature.com/articles/s41598-021-86297-w.pdf)

Regional Activity Indices (RAIs), Treasury of New Zealand. https://www.treasury.govt.nz/publications/research-and-commentary/regional-activity-indices.

Vyas S., and Kumaranayake L. (2006), "Constructing socio-economic status indices: how to use principal components analysis", *Health policy and planning*, 21(6), 459-468.

वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुद्रा और बैंकिंग

मूल्य और उत्पादन

सरकारी लेखा और खज़ाना बिल

वित्तीय बाजार

बाह्य क्षेत्र

भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

अवसरिक शृंखला

विषय-वस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिंदा आर्थिक संकेतक	91
	भारतीय रिज़र्व बैंक	
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	92
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	93
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डॉलर का क्रय/विक्रय	94
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	95
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं	95
	मुद्रा और बैंकिंग	
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	96
7	मुद्रा स्टॉक (एम$_3$) के स्रोत	97
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	98
9	कुल चलनिधि राशियां	98
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	99
11	आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत	99
12	वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण	100
13	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश	100
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	101
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन	102
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	103
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक	104
	कीमत और उत्पादन	
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधारः 2012=100)	105
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	105
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	105
21	थोक मूल्य सूचकांक	106
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधारः 2011-12=100)	110
	सरकारी खाते और खज़ाना बिल	
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	110
24	खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	111
25	खज़ाना बिलों की नीलामी	111
	वित्तीय बाजार	
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	112
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	113
28	वाणिज्यिक पत्र	113
29	चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	113
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	114

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
	बाह्य क्षेत्र	
31	विदेशी व्यापार	115
32	विदेशी मुद्रा भंडार	115
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां	115
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	116
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत जावक विप्रेषण	116
36	भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) सूचकांक	117
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)- पंजीकरण	118
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	119
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (करोड़ ₹)	120
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	121
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (करोड़ ₹)	122
42	अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	123
	भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	124
	अवसरिक श्रृंखला	
44	लघु बचत	126
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	127
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	128
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	129
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	130
49	राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां	131
50 (ए)	हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार	132
50 (बी)	हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक	135

टिप्पणियां : .. = उपलब्ध नहीं।
– = शून्य/नगण्य
प्रा/अ= प्रारंभिक/अनंतिम   आंसं = आंशिक रूप से संशोधित

सं. 1 : चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2021-22	2020-21	2021-22		2022-23
		ति4	ति1	ति4	ति1
	1	2	3	4	5
1 वास्तविक क्षेत्र (% परिवर्तन)					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	8.1	5.7	18.1	3.9	12.7
1.1.1 कृषि	3.0	2.8	2.2	4.1	4.5
1.1.2 उद्योग	9.8	11.6	40.4	1.0	6.0
1.1.3 सेवाएं	8.8	4.3	15.5	5.0	17.5
1.1ए अंतिम खपत व्यय	7.0	9.6	10.2	2.3	21.3
1.1बी सकल नियत पूंजी निर्माण	15.8	10.1	62.5	5.1	20.1

	2021-22	2021		2022	
		जून	जुला.	जून	जुला.
	1	2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	11.4	13.8	11.5	12.7	-
2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)					
2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक					
2.1.1 जमाराशियां	8.9	9.8	9.8	8.6	9.2
2.1.2 ऋण	9.6	6.1	6.1	13.4	14.5
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	9.7	6.1	6.2	13.9	15.1
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	6.0	10.4	8.2	6.2	8.0
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	13.0	16.9	16.8	10.9	11.3
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	8.8	10.7	9.9	7.8	8.6
3 अनुपात (%)					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	4.00	4.00	4.50	4.50
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
3.3 नकदी-जमा अनुपात	4.7	4.7	5.0	5.3	5.6
3.4 ऋण-जमा अनुपात	72.2	71.1	70.2	73.5	72.9
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात	77.2	-56.5	-8.9	235.9	94.3
3.6 निवेश-जमा अनुपात	28.7	30.1	29.9	29.5	29.5
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	19.7	87.1	41.6	124.8	56.3
4 ब्याज दरें (%)					
4.1 नीति रिपो दर	4.00	4.00	4.00	4.90	4.90
4.2 रिवर्स रिपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
4.3 स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ़) दर*	-	-	-	4.65	4.65
4.4 सीमांत स्थायी सुविधा दर	4.25	4.25	4.25	5.15	5.15
4.5 आधार दर	4.25	4.25	4.25	5.15	5.15
4.6 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	7.25/8.80	7.40/8.80	7.40/8.80	7.25/8.80	7.75/8.80
4.7 एक वर्ष से अधिक की मीयादी जमा दर	6.45/7.00	6.55/7.05	6.55/7.00	6.70/7.30	6.70/7.50
4.8 बचत जमा दर	5.00/5.60	4.90/5.50	4.90/5.50	5.00/5.75	5.30/5.75
4.9 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00
4.10 91-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) आय	3.34	3.15	3.21	4.61	5.04
4.11 182-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) आय	3.84	3.44	3.39	5.16	5.62
4.12 364-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) आय	4.27	3.72	3.53	5.79	5.98
4.13 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर आय (एफबीआईएल)	4.58	3.89	3.73	6.29	6.33
5 आरबीआई संदर्भ दर और फारवर्ड प्रीमिआ	6.86	6.36	6.22	7.50	7.32
5.1 भा.रु.-अमेरिकी डॉलर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	76.18	74.18	74.39	78.33	79.42
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	84.01	88.57	88.39	82.56	81.17
5.3 अमेरिकी डॉलर का वायदा प्रीमिआ 1-माह (%)	5.67	3.80	3.55	2.76	3.32
3-माह (%)	4.46	3.99	3.82	2.86	3.35
6-माह (%)	4.10	4.13	4.01	2.89	3.20
6 मुद्रास्फीति (%)					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.51	6.3	5.6	7.0	6.7
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.13	5.6	5.3	6.2	5.8
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	12.97	12.1	11.6	16.2	13.9
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	10.25	8.6	6.3	18.6	15.0
6.3.2 ईंधन और पावर	32.50	29.3	27.0	50.9	43.8
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	11.10	11.0	11.5	9.3	8.2
7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)					
7.1 आयात	55.43	97.5	62.0	58.2	43.6
7.2 निर्यात	44.62	47.9	49.7	30.4	2.1

टिप्पणी : फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) भारतीय रिज़र्व बैंक के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/ 2017-18 के अनुसार जी सेक बेंचमार्क का प्रकाशन शुरू किया है। एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से संदर्भ दरों का प्रसार शुरू किया है।

*: 8 अप्रैल 2022 दिनांकित प्रेस अधिसूचना सं.2022-2023/41के अनुसार।

#: 3 दिसंबर, 2021 से सभी पखवाड़ों के लिए बैंक ऋण वृद्धि और संबंधित अनुपात को चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा पिछली रिपोर्टिंग त्रुटियों के लिए समायोजित किया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 2 : भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(करोड़ ₹)

मद	अंतिम शुक्रवार/शुक्रवार की स्थिति						
	2021-22	2021	2022				
		अग.	जूला. 29	अग. 5	अग. 12	अग. 19	अग. 26
	1	2	3	4	5	6	7
1 निर्गम विभाग							
1.1 देयताएं							
1.1.1 संचलन में नोट	3107637	2916737	3156104	3166385	3185355	3168838	3154428
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	15	15	10	11	9	10	13
1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां	**3107652**	**2916752**	**3156114**	**3166396**	**3185364**	**3168849**	**3154440**
1.2 आस्तियां							
1.2.1 सोने के सिक्के और बुलियन	128208	111366	119129	121153	122636	120697	120011
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	2978927	2804667	3036520	3044812	3062327	3047770	3034085
1.2.3 रुपया सिक्का	518	719	465	430	401	382	345
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	–	–	–	–	–	–	–
2 बैंकिंग विभाग							
2.1 देयताएं							
2.1.1 जमाराशियां	1794574	2011955	1543010	1525598	1478677	1493989	1496095
2.1.1.1 केंद्र सरकार	101	101	101	101	100	101	101
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना							
2.1.1.3 राज्य सरकारें	42	42	42	42	42	42	42
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	683437	641437	834457	801142	809848	813943	764114
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	7123	6682	8140	7664	8134	7898	7734
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	4121	3546	4384	4471	4418	4330	4104
2.1.1.7 अन्य बैंक	37589	37424	45065	43126	44578	43048	43222
2.1.1.8 अन्य	988819	1292462	600009	618317	562464	578873	623501
2.1.1.9 भारत के बाहर वित्तीय संस्थान	73343	30259	50814	50735	49092	45754	53277
2.1.2 अन्य देयताएं	1359254	1318100	1336039	1339700	1357352	1316958	1313445
2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां	**3153828**	**3330055**	**2879049**	**2865298**	**2836029**	**2810948**	**2809540**
2.2 आस्तियां							
2.2.1 नोट और सिक्के	15	15	10	11	9	11	13
2.2.2 विदेश में रखे शेष	1243853	1435914	1042764	1021935	1002202	976910	974458
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.2 राज्य सरकारें	670	3080	6083	11292	6142	7689	4811
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	94299	91806	94387	95569	97060	95955	98308
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	–	35	–	–	–	–	–
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.6 नाबार्ड	24927	16772	9668	9707	9707	9707	9707
2.2.3.7 एक्जिम बैंक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.8 अन्य	8077	6634	32683	31598	23750	31150	30905
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	72741	28450	50932	50615	49006	45131	52039
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.4.2 सरकारी खज़ाना बिल	–	–	–	–	–	–	–
2.2.5 निवेश	1491042	1577196	1439687	1438280	1439160	1438491	1434212
2.2.6 अन्य आस्तियां	218203	170152	202834	206291	208991	205903	205088
2.2.6.1 स्वर्ण	201354	164566	195144	198460	200889	197713	196588

*: डेटा अनंतिम है।

सं. 3 : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(करोड़ ₹)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रिपो	रिवर्स रिपो	परिवर्तन-शील रिपो दर	परिवर्तन-शील रिवर्स रिपो दर	एमएसएफ	बाज़ार स्थिरीकरण योजना		विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जुला. 1, 2022	-	-	-	225495	504	149825	–	-	-	-374816
जुला. 2, 2022	-	-	-	-	25	44424	–	-	-	-44399
जुला. 3, 2022	-	-	-	-	4	4919	–	-	-	-4915
जुला. 4, 2022	-	-	-	-	202	161099	–	-	-	-160897
जुला. 5, 2022	-	-	-	-	327	196499	–	-	-	-196172
जुला. 6, 2022	-	-	-	-	322	159209	–	-	-	-158887
जुला. 7, 2022	-	-	-	-	352	125646	–	-	-	-125294
जुला. 8, 2022	-	-	-	-	370	115902	–	-	-	-115532
जुला. 9, 2022	-	-	-	-	26	5383	–	-	-	-5357
जुला. 10, 2022	-	-	-	-	10	7094	–	-	-	-7084
जुला. 11, 2022	-	-	-	-	1367	94077	–	-	-	-92710
जुला. 12, 2022	-	-	-	30884	277	116810	–	-	-	-147417
जुला. 13, 2022	-	-	-	-	298	135917	–	-	-	-135619
जुला. 14, 2022	-	-	-	-	120	122152	–	-	-	-122032
जुला. 15, 2022	-	-	-	183276	1089	100227	–	400	-	-282814
जुला. 16, 2022	-	-	-	-	37	27914	–	-	-	-27877
जुला. 17, 2022	-	-	-	-	2	4475	–	-	-	-4473
जुला. 18, 2022	-	-	-	-	83	88341	–	-	-	-88258
जुला. 19, 2022	-	-	-	-	1175	88597	–	80	-	-87502
जुला. 20, 2022	-	-	-	-	890	73537	–	825	-	-73472
जुला. 21, 2022	-	-	-	-	3661	50435	698	750	-	-46826
जुला. 22, 2022	-	-	-	-	15456	49796	95	-	-	-34245
जुला. 23, 2022	-	-	-	-	129	4592	–	-	-	-4463
जुला. 24, 2022	-	-	-	-	60	3960	–	-	-	-3900
जुला. 25, 2022	-	-	-	-	59312	51909	160	655	-	6908
जुला. 26, 2022	-	-	50006	-	29032	48205	434	65	-	31202
जुला. 27, 2022	-	-	-	-	33001	51810	267	220	-	-18762
जुला. 28, 2022	-	-	-	-	10161	50759	-5000	505	-	-46103
जुला. 29, 2022	-	-	-	12712	139	148888	–	640	-	-162101
जुला. 30, 2022	-	-	-	-	778	37268	–	-	-	-36490
जुला. 31, 2022	-	-	-	-	14	4964	–	-	-	-4950

एसडीएफ़: स्थायी जमा सुविधा, एमएसएफ़: सीमांत स्थायी सुविधा।

सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डॉलर का क्रय-विक्रय

i) ओटीसी सेगमेन्ट में ऑनशॉर / ऑफशॉर में परिचालन

मद	2021-22	2021	2022	
		जुला.	जून	जुला.
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डॉलर) (1.1-1.2)	17312	7205	-3719	-19049
1.1 क्रय (+)	113991	16160	18960	19721
1.2 विक्रय (-)	96679	8955	22679	38770
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (करोड़ ₹)	134629	54618	-29401	-152265
3 संचयी (मार्च के के अंत से) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	17312	35892	247	-18802
(करोड़ ₹)	134629	268570	-551	-152816
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	65791	49010	30856	22019

ii) मुद्रा वायदा भाग में परिचालन

मद	2021-22	2021	2022	
		जुला.	जून	जुला.
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डॉलर) (1.1-1.2)	0	0	0	0
1.1 क्रय (+)	2370	0	3570	1695
1.2 विक्रय (-)	2370	0	3570	1695
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	0	0	-2406	0

सं. 4ए भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	31 जुला. 2022 की स्थिति		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	5348	17293	-11945
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	13320	3040	10280
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	15082	1533	13549
4. 1 वर्ष से अधिक	10135	0	10135
कुल (1+2+3+4)	**43885**	**21866**	**22019**

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	2021-22	2021	2022					
		अग. 27	मार्च 25	अप्रै. 22	मई 20	जून 17	जुला. 29	अग. 26
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 सीमांत स्थायी सुविधा	11	2	11	140	1009	7	139	4034
2 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुर्नवित्त								
2.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
3 प्राथमिक व्यापारियों के लिए चलनिधि सुविधा								
3.1 सीमा	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900
3.2 बकाया	–	0	0	0	0	0	1655	0
4. अन्य								
4.1 सीमा	76000	76000	76000	76000	76000	76000	76000	76000
4.2 बकाया	32401	23296	32401	31021	35521	49364	40314	40159
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	32412	23298	32412	31161	36530	49371	42108	44193

टिप्पणीः 1. अन्य को विशेष पुर्नवित्त सुविधा अर्थात एक्ज़िम बैंक को 22 मई 2020 से पुनः शुरू कर दिया।

2. अन्य के लिए पुनर्वित सुविधा, अर्थात भारिबैंक अधिनियम 1934 के नाबार्ड/ सिडबी/एनएचबी यू /एस 17 (4 एच), 17 अप्रैल 2020 से।

मुद्रा और बैंकिंग

सं. 6: मुद्रा भंडार की मात्रा

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2021-22	**2021**	**2022**		
		जुला. 30	**जून 17**	**जुला. 15**	**जुला. 29**
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	3035689	2839134	3102251	3105134	3063746
1.1 संचलन में नोट	3105703	2919525	3198495	3187360	3156104
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	27270	26381	27550	27708	27868
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	743	743	743	743	743
1.4 बैंकों के पास नकदी	98028	107515	124537	110677	120968
2 जनता की जमाराशियां	2271436	2016798	2141695	2152268	2240452
2.1 बैंकों के पास मांग जमाराशियां	2212992	1970701	2087340	2095076	2183209
2.2 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियां	58444	46097	54355	57192	57244
3 एम$_1$ (1 + 2)	**5307125**	**4855932**	**5243946**	**5257402**	**5304199**
4 डाकघर बचत बैंक जमाराशियां	187061	174061	187061	187061	187061
5 एम$_2$ (3 + 4)	**5494186**	**5029993**	**5431007**	**5444463**	**5491260**
6 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियां	15186605	14516843	15417971	15653489	15728149
7 एम$_3$ (3 + 6)	**20493729**	**19372776**	**20661917**	**20910891**	**21032348**
8 कुल डाकघर जमाराशियां	1008539	910439	1008539	1008539	1008539
9 एम$_4$ (7 + 8)	**21502268**	**20283215**	**21670456**	**21919430**	**22040887**

सं. 7: मुद्रा भंडार (एम$_3$) का स्रोत

(करोड़ ₹)

स्रोत	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2021-22	2021	2022		
		जुला. 30	जून 17	जुला. 15	जुला. 29
	1	2	3	4	5
1 सरकार को निवल बैंक ऋण	**6477629**	**6055460**	**6261159**	**6420322**	**6408664**
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	1450596	1116973	1081805	1130936	1098524
1.1.1 सरकार पर दावे	1490991	1517584	1434456	1452911	1444172
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	1489324	1516748	1426587	1435151	1438088
1.1.1.2 राज्य सरकारें	1667	836	7869	17760	6083
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमाराशियां	40394	400612	352651	321975	345648
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	40352	400569	352608	321933	345606
1.1.2.2 राज्य सरकारें	42	42	42	42	42
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	5027033	4938487	5179354	5289386	5310141
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	**12616520**	**11624568**	**12901572**	**13028084**	**13116787**
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	16571	8573	29081	33079	34706
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	12599950	11615995	12872491	12995005	13082081
2.2.1 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक ऋण	11891314	10910567	12150353	12281271	12369350
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	690201	687606	695940	697171	695813
2.2.3 वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	18435	17823	26198	16563	16918
3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)	**4854063**	**4938902**	**4869550**	**4830738**	**4805020**
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	4442479	4595551	4457966	4419154	4393436
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	4442720	4595795	4458204	4419395	4393676
3.1.2 विदेशी देयताएं	241	244	238	240	240
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	411583	343350	411583	411583	411583
4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	**28013**	**27124**	**28293**	**28451**	**28611**
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	**3482496**	**3273278**	**3398657**	**3396705**	**3326734**
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	1308500	1382828	1212556	1282927	1332885
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	2173996	1890450	2186101	2113778	1993849
एम$_3$ (1+2+3+4-5)	**20493729**	**19372776**	**20661917**	**20910891**	**21032348**

सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2021-22	2021	2022		
		जुला. 30	जून 17	जुला. 15	जुला. 29
	1	2	3	4	5
मौद्रिक समुच्चय					
एन एम1 (1.1 + 1.2.1+1.3)	5307125	4855932	5243946	5257402	5304199
एन एम2 (एन एम1 + 1.2.2.1)	12081049	11320478	12124564	12242806	12322838
एन एम3 (एन एम2 + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4- 2.5)	20634885	19464641	20905548	21111856	21254775
1 घटक					
1.1 जनता के पास मुद्रा	3035689	2839134	3102251	3105134	3063746
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियां	17266157	16336358	17377601	17618194	17780184
1.2.1 मांग जमाराशियां	2212992	1970701	2087340	2095076	2183209
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	15053166	14365657	15290260	15523118	15596976
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	6773925	6464546	6880617	6985403	7018639
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	176718	64620	178170	227366	233740
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	8279241	7901111	8409643	8537715	8578337
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	58444	46097	54355	57192	57244
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग /सावधि निधीयन	274594	243052	371341	331335	353600
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	20080599	18659755	20253679	20533599	20603077
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	6477629	6055460	6261159	6420322	6408664
2.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	1450596	1116973	1081805	1130936	1098524
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	5027033	4938487	5179354	5289386	5310141
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	13602969	12604296	13992520	14113277	14194412
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैंक ऋण	39581	25304	52248	47937	44374
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	13563389	12578992	13940272	14065340	14150038
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)	952181	954632	1051364	1053851	1053136
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	28013	27124	28293	28451	28611
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4705191	4818369	4599366	4578159	4598202
2.3.1 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4442479	4595551	4457966	4419154	4393436
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	262711	222818	141399	159005	204766
2.4 पूंजी खाता	3021858	3025175	3256980	3288535	3291910
2.5 अन्य मदें (निवल)	1157060	1015432	718810	739819	683205

सं. 9: चलनिधि समुच्चय

(करोड़ ₹)

समुच्चय	2021-22	2021	2022		
		जुला.	मई	जून	जुला.
	1	2	3	4	5
1 एन एम$_3$	**20630753**	**19464641**	**20946605**	**20905548**	**21254775**
2 डाकघर जमाराशियां	594633	536387	594633	594633	594633
3 एल$_1$ (1 + 2)	**21225386**	**20001028**	**21541238**	**21500181**	**21849408**
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	49578	25815	30285	51696	52886
4.1 सावधि मुद्रा उधार	1824	4077	2044	2136	1924
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	39170	16525	28070	41045	43145
4.3 सावधि जमाराशियां	8584	5212	171	8514	7817
5 एल$_2$ (3 + 4)	**21274964**	**20026843**	**21571524**	**21551877**	**21902293**
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियां	66542	..	..	66542	..
7 एल$_3$ (5 + 6)	**21341506**	..	..	**21618419**	..

टिप्पणी : संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2021-22	2021	2022		
		जुला. 30	जून 17	जुला. 15	जुला. 29
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 संचलन में मुद्रा	3133716	2946649	3226788	3215811	3184715
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकरों की जमाराशियां	876726	723212	856083	851510	892045
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	823632	674997	800142	795474	834457
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	58444	46097	54355	57192	57244
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	4068887	3715957	4137226	4124513	4134003
2 स्रोत					
2.1 भा.रि.बैं.के देशी ऋण	906895	476111	863522	959835	1044841
2.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण	1450596	1116973	1081805	1130936	1098524
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	1448972	1116179	1073979	1113218	1092483
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	–	–	–	–	–
2.1.1.1.2 खज़ाना बिलों में निवेश	–	–	–	–	–
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1488816	1515963	1426161	1434627	1437624
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	1488816	1515963	1426161	1434627	1437624
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	508	786	426	524	465
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमाराशियां	40352	400569	352608	321933	345606
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल भा.रि.बैं. ऋण	1624	794	7826	17718	6041
2.1.2 बैंकों पर भा.रि.बैं. के दावे	-583282	-666167	-270530	-219038	-98057
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण और अग्रिम	-560272	-649436	-247364	-204181	-88389
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैं. के ऋण	39581	25304	52248	47937	44374
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	–	–	–	–	1655
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	23010	16731	23167	14857	9668
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	28013	27124	28293	28451	28611
2.3 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4442479	4595551	4457966	4419154	4393436
2.3.1 सोना	322213	280086	316922	306415	314274
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4120283	4315482	4141062	4112757	4079180
2.4 पूंजी खाता	1254092	1282350	1359593	1378470	1387980
2.5 अन्य मदें (निवल)	54408	100478	-147037	-95543	-55096

सं. 11: आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	2021-22	मार्च 31 /माह के अंतिम शुक्रवारों/शुक्रवारों की स्थिति के अनुसार बकाया					
		2021	2022				
		जुला. 30	जुला. 1	जुला. 8	जुला. 15	जुला. 22	जुला. 29
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	4068887	3715957	4111879	4094782	4124513	4069734	4134003
1 घटक							
1.1 संचलन में मुद्रा	3133716	2946649	3202121	3224973	3215811	3203720	3184715
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकरों की जमाराशियां	876726	723212	850691	813181	851510	809343	892045
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	58444	46097	59067	56628	57192	56671	57244
2 स्रोत							
2.1 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण	1450596	1116973	1142729	1126687	1130936	1052960	1098524
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	-560272	-649436	-299090	-265378	-204181	-139395	-88389
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	16571	8573	33091	33091	33079	33885	34706
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4442479	4595551	4487814	4444499	4419154	4411791	4393436
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	28013	27124	28451	28451	28451	28451	28611
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	1308500	1382828	1281116	1272569	1282927	1317959	1332885

सं. 12: वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवारों/ माह के रिपोर्टिंग शुक्रवारों की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2021-22	2021	2022		
		जुला. 30	जून 17	जुला. 15	जुला. 29
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियां	16331874	15397909	16441606	16679626	16841140
1.1.1 मांग जमाराशियां	2072747	1834965	1946297	1955843	2042035
1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	14259128	13562944	14495309	14723782	14799104
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	6416607	6103325	6522889	6625702	6659597
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	176718	64620	178170	227366	233740
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	7842520	7459619	7972420	8098080	8139507
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	274594	243052	371341	331335	353600
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	17575002	16509051	18098650	18333362	18442905
2.1.1 सरकार को ऋण	4728179	4642819	4878940	4989653	5013472
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	12846823	11866233	13219710	13343710	13429432
2.1.2.1 बैंक ऋण	11891314	10910567	12150353	12281271	12369350
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	11836304	10833089	12106795	12245342	12337006
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	11522	8628	16680	16748	15084
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	769	1369	10274	803	825
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	943218	945669	1042402	1044888	1044173
2.2 वाणिज्यिक बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	262711	222818	141399	159005	204766
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	465464	429173	337352	351058	395303
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियां	133439	151187	127711	130370	131174
2.2.3 समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधार	69314	55168	68242	61683	59364
2.3 निवल बैंक रिज़र्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	1268887	1420586	1159593	1098140	1031308
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	683437	674997	800142	795474	834457
2.3.2 उपलब्ध नकदी	85926	96153	112088	98485	108463
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	-499524	-649436	-247364	-204181	-88389
2.4 पूंजी खाता	1743595	1718654	1873217	1885894	1879759
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	756537	792840	713478	693652	604480
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	571535	518436	598531	573552	607998
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	26533	50080	14199	15996	4635

सं. 13: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

(करोड़ ₹)

मद	25 मार्च 2022 की स्थिति	2021	2022		
		जुला. 30	जून 17	जुला. 15	जुला. 29
	1	2	3	4	5
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	4728948	4644188	4881576	4990456	5014297
2 अन्य सरकारी प्रतिभूतियां (गैर-एसएलआर)	-	-	155014	155675	155767
3 वाणिज्यिक पत्र	55315	80502	61302	63059	66568
4 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
4.1 सरकारी उद्यम	7642	10674	10495	9634	9643
4.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	73814	70398	69429	69284	69317
4.3 अन्य	5152	5162	5052	5024	5039
5 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
5.1 सरकारी उद्यम	117860	113832	95982	101002	100216
5.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	326188	315601	304876	317146	321684
5.3 अन्य	148753	149065	94194	91171	92223
6 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
6.1 म्यूचुअल फंड	34404	47220	53426	54338	42228
6.2 वित्तीय संस्थाएं	174090	153215	187793	178555	181488

टिप्पणी : कॉलम संख्या (1), (2) और (3) के डेटा अंतिम हैं, और कॉलम (4) एवं (5) के डेटा अनंतिम हैं।

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(करोड़ ₹)

मद	अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार (मार्च के संबंध में) /अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			
	2021-22	2021	2022		2021-22	2021	2022	
		जुला.	जून	जुला.		जुला.	जून	जुला.
	1	2	3	4	5	6	7	8
सूचना देने वाले बेंकों की संख्या	212	210	212	213	136	134	136	137
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	**262674**	**244295**	**285295**	**277258**	**258649**	**239820**	**281448**	**273313**
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	194143	184989	192746	189750	190570	180794	189411	186516
1.2 बैंकों से उधार राशि	38369	40938	52754	44571	38317	40920	52745	44372
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	30162	18369	39794	42937	29762	18106	39291	42425
2 अन्य के प्रति देयताएं	**17832517**	**16802388**	**18047818**	**18437473**	**17380755**	**16365752**	**17603893**	**17993275**
2.1 कुल जमाराशियां	16899634	15968858	17018078	17398187	16465313	15549096	16592098	16972313
2.1.1 मांग	2117513	1875111	2000093	2088527	2072747	1834965	1953690	2042035
2.1.2 मीयादी	14782121	14093747	15017985	15309660	14392567	13714131	14638408	14930278
2.2 उधार	278985	248716	377078	358861	274594	243052	371389	353600
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	653898	584814	652663	680426	640848	573604	640406	667362
3 रिज़र्व बैंक से उधार	**94299**	**91796**	**94514**	**94387**	**94299**	**91796**	**94514**	**94387**
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	–	–	–	–	–	–	–	–
3.2 अन्य	94299	91796	94514	94387	94299	91796	94514	94387
4 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	788725	790639	900326	965461	769363	771150	878046	942919
4.1 उपलब्ध नकदी	88732	98123	105079	111672	85926	96153	101525	108463
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	699993	692516	795246	853789	683437	674997	776521	834457
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	**315282**	**251433**	**351706**	**342859**	**243637**	**198368**	**290692**	**283762**
5.1 अन्य बैंकों के पास शेष	199434	177673	227191	213644	164240	142739	192665	180250
5.1.1 चालू खाते में	19733	21223	16502	23550	16691	18316	13393	20748
5.1.2 अन्य खातों में	179701	156450	210689	190094	147549	124423	179272	159502
5.2 मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	36905	22888	39869	32149	6982	7856	18581	12456
5.3 बैंकों को अग्रिम	39340	23898	28852	39130	35802	23030	27413	37065
5.4 अन्य आस्तियां	39603	26974	55793	57937	36613	24743	52032	53991
6 निवेश	**4874070**	**4784348**	**5031395**	**5155661**	**4728948**	**4644188**	**4887253**	**5014297**
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	4867102	4776959	5025387	5149445	4728179	4642819	4886445	5013472
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	6968	7389	6008	6215	769	1369	807	825
7 बैंक ऋण	**12259048**	**11247903**	**12558493**	**12734992**	**11891314**	**10910567**	**12190429**	**12369350**
7क खाद्यान्न ऋण	90827	113296	86635	78064	55011	77478	40915	32345
7.1 ऋण नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	12016486	11040563	12324519	12489317	11651337	10705239	11959103	12126412
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	36070	30468	32204	34760	36055	30452	32188	34745
7.3 देशी बिल- भुनाए गए	155796	124749	151304	161899	154212	123424	149482	159962
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	19537	19261	19739	18685	19157	19080	19518	18453
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	31160	32862	30727	30331	30554	32371	30138	29778

टिप्पणी : कॉलम (4) एवं (8) के डेटा अनंतिम हैं।

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

क्षेत्र	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 25, 2022	2021	2022		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		जुला. 30	जून 17	जुला. 29	2022-23	2022
	1	2	3	4	%	%
I. सकल बैंक ऋण (II+III)	**11891314**	**10800511**	**12149034**	**12369224**	**4.0**	**14.5**
II. खाद्यान्न ऋण	**55011**	**77478**	**43559**	**32345**	**-41.2**	**-58.3**
III. गैर-खाद्यान्न ऋण	**11836304**	**10723034**	**12105475**	**12336880**	**4.2**	**15.1**
1. कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	**1461350**	**1351072**	**1500875**	**1529206**	**4.6**	**13.2**
2. उद्योग	**3152449**	**2880627**	**3168168**	**3182010**	**0.9**	**10.5**
2.1 सूक्ष्म और लघु[1]	532081	434388	554398	557251	4.7	28.3
2.2 मझौले	213996	160312	220669	219327	2.5	36.8
2.3 बड़े	2406372	2285927	2393101	2405433	0.0	5.2
3. सेवाएं	**3017116**	**2722774**	**3070538**	**3171546**	**5.1**	**16.5**
3.1 परिवहन परिचालक	155353	141665	152045	155202	-0.1	9.6
3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	20899	20457	19687	20925	0.1	2.3
3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	64369	59881	63973	65089	1.1	8.7
3.4 शिपिंग	8437	7558	7205	7306	-13.4	-3.3
3.5 नौवहन	23979	32301	21733	22498	-6.2	-30.3
3.6 पेशेवर सेवाएं	116743	109606	120107	118567	1.6	8.2
3.7 व्यापार	696349	630630	733416	720086	3.4	14.2
3.7.1 थोक व्यापार	351228	327579	384026	366135	4.2	11.8
3.7.2 खुदरा व्यापार	345121	303052	349390	353950	2.6	16.8
3.8 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	291168	284585	298732	294842	1.3	3.6
3.9 गैर -बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)[2] जिसमें से	1078447	913694	1101044	1163637	7.9	27.4
3.9.1 आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी)	278979	255481	283992	305509	9.5	19.6
3.9.2 सरकारी वित्तीय संस्थाएं (पीएफआई)	144121	83808	140173	157764	9.5	88.2
3.10 अन्य सेवाएं [3]	561373	522397	552596	603395	7.5	15.5
4 व्यक्तिगत ऋण	**3385827**	**3024152**	**3520062**	**3594016**	**6.1**	**18.8**
4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	27613	18945	30461	32175	16.5	69.8
4.2 आवास	1684424	1522703	1740921	1769249	5.0	16.2
4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	78734	64531	78429	87991	11.8	36.4
4.4 शेयरों और बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	6161	5557	6547	6473	5.1	16.5
4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	147789	126835	152931	162706	10.1	28.3
4.6 शिक्षा	82723	77773	84375	85098	2.9	9.4
4.7 वाहन ऋण	402667	368230	427654	438973	9.0	19.2
4.8 सोने के आभूषण पर ऋण	75311	73215	75024	77325	2.7	5.6
4.9 अन्य व्यक्तिगत ऋण	880406	766365	923719	934025	6.1	21.9
5. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र *(मेमो)*						
5.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां[4]	1485438	1356044	1450586	1535442	3.4	13.2
5.2 सूक्ष्म और लघु उद्यम[5]	1377138	1209760	1429973	1441472	4.7	19.2
5.3 मध्यम उद्यम [6]	351900	246461	363489	367377	4.4	49.1
5.4 आवास	614487	592064	616839	606970	-1.2	2.5
5.5 शिक्षा ऋण	58118	64601	57931	57499	-1.1	-11.0
5.6 नवीकरणीय ऊर्जा	3538	2245	3868	4239	19.8	88.8
5.7 सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर	2483	3012	2586	2535	2.1	-15.8
5.8 निर्यात ऋण [7]	23330	25734	18582	17637	-24.4	-31.5
5.9 अन्य	37159	34032	46243	47359	27.4	39.2
5.10 नेट पीएसएलसी- एसएफ /एमएफ सहित कमजोर वर्ग	1180928	985765	1190612	1244034	5.3	26.2

टिप्पणी : 1. डेटा अनंतिम हैं। सकल बैंक ऋण और गैर -खाद्य ऋण का डाटा धारा -42 रिटर्न पर आधारित है, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को (एससीबी) शामिल किया गया है, जब कि क्षेत्रवार गैर-खाद्य ऋण डेटा क्षेत्र-वार पर और उद्योग-वार बैंक ऋण(एसआईबीसी) रिटर्न, के आधार पर है। जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कुल गैर खादय ऋण के लगभग 93 प्रतिशत के चुनिंदा बैंकों को समाविष्ट किया गया है। टिप्पणी 2: जनवरी 2021 से, क्षेत्रीय ऋण डेटा संशोधित प्रारूप पर आधारित हैं, जिसके कारण पहले प्रकाशित कुछ मौजूदा घटकों के मान और वृद्धि दर में कुछ बदलाव हुए हैं। टिप्पणी 3: चुनिंदा एससीबी द्वारा पिछली रिपोर्टिंग त्रुटियों के लिए बैंकों की ऋण वृद्धि को समायोजित किया जाता है।

1. सूक्ष्म और लघु में विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्योगों को ऋण शामिल है।
2. एनबीएफसी के अंतर्गत एचएफसी, पीएफआई, माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं (एमएफआई), स्वर्ण ऋण से जुड़ी एनबीएफसी और अन्य शामिल हैं।
3. अन्य सेवाओं के अंतर्गत म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी और एमएफ के अलावा बैंकिंग व वित्त तथा अन्य सेवाएं जो सेवाओं के अंतर्गत अन्यत्र नहीं दर्शाए गए हैं।
4. कृषि और उससे सम्बद्ध कार्यकलापों के अंतर्गत प्राथमिकता- प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) भी शामिल है।
5. सूक्ष्म और लघु उद्यमों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋणऔर पीएसएलसी भी शामिल हैं।
6. मध्यम उद्यमों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत मध्यम उद्यमों को ऋण शामिल हैं।

सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 25, 2022	2021	2022		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		जुला. 30	जून 17	जुला. 29	2022-23	2022
	1	2	3	4	%	%
2 उद्योग (2.1 से 2.19)	3152449	2880627	3168168	3182010	0.9	10.5
2.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	49038	45736	48459	50525	3.0	10.5
2.2 खाद्य प्रसंस्करण	173243	153923	175631	169002	–2.4	9.8
2.2.1 चीनी	26307	21953	24107	21764	–17.3	–0.9
2.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	18246	16399	18322	16393	–10.2	0.0
2.2.3 चाय	5728	5266	6382	5810	1.4	10.3
2.2.4 अन्य	122962	110305	126820	125034	1.7	13.4
2.3 पेय पदार्थ और तंबाकू	18176	16558	17471	17098	–5.9	3.3
2.4 वस्त्र	223508	206106	218393	213990	–4.3	3.8
2.4.1 सूती वस्त्र	90189	81791	86492	83098	–7.9	1.6
2.4.2 जूट से बने वस्त्र	3509	2593	3582	3631	3.5	40.0
2.4.3 मानव-निर्मित वस्त्र	38354	37299	38363	38354	0.0	2.8
2.4.4 अन्य वस्त्र	91456	84423	89955	88907	–2.8	5.3
2.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद	11481	10862	11349	11428	–0.5	5.2
2.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद	16248	15270	16658	16951	4.3	11.0
2.7 काग़ज़ और काग़ज़ से बने उत्पाद	40073	38499	40885	41083	2.5	6.7
2.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आण्विक इंधन	107242	87087	102685	113550	5.9	30.4
2.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद	196179	174987	207155	210273	7.2	20.2
2.9.1 उवर्रक	33160	26911	34780	35530	7.1	32.0
2.9.2 औषधि और दवाइयां	61093	52662	63009	62263	1.9	18.2
2.9.3 पेट्रो केमिकल्स	19622	24459	20896	21485	9.5	–12.2
2.9.4 अन्य	82303	70955	88470	90995	10.6	28.2
2.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	71915	60067	72228	72485	0.8	20.7
2.11 कांच और कांच के सामान	5948	6163	5916	6088	2.3	–1.2
2.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद	47912	48434	48310	49356	3.0	1.9
2.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	288395	283855	292613	299621	3.9	5.6
2.13.1 लोहा और स्टील	187443	193359	187121	196997	5.1	1.9
2.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	100952	90497	105492	102624	1.7	13.4
2.14 सभी अभियांत्रिकी	167680	148758	166937	165512	–1.3	11.3
2.14.1 इलेक्ट्रानिक्स	38180	34001	39191	39505	3.5	16.2
2.14.2 अन्य	129500	114757	127746	126007	–2.7	9.8
2.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपस्कर	89688	88437	91996	91404	1.9	3.4
2.16 रत्न और आभूषण	80411	71901	73082	73652	–8.4	2.4
2.17 निर्माण	117625	120777	117986	116875	–0.6	–3.2
2.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	1193965	1093502	1211341	1214513	1.7	11.1
2.18.1 पावर	610815	571749	620478	627053	2.7	9.7
2.18.2 दूरसंचार	130349	115859	131922	129063	–1.0	11.4
2.18.3 सड़क	269896	240119	278364	279600	3.6	16.4
2.18.4 हवाई अड्डा	6646	7420	6794	8673	30.5	16.9
2.18.5 बंदरगाह	8886	11430	7954	8028	–9.6	–29.8
2.18.6 रेलवे	10512	12916	11494	11561	10.0	–10.5
2.18.7 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	156861	134010	154335	150534	–4.0	12.3
2.19 अन्य उद्योग	253724	209703	249073	248604	–2.0	18.6

टिप्पणी : जनवरी 2021 से, क्षेत्रीय ऋण डेटा संशोधित प्रारूप पर आधारित हैं, जिसके कारण पहले प्रकाशित कुछ मौजूदा घटकों के मान और विकास दर में कुछ बदलाव हुए हैं।

सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति								
	2020-21	2021	2022						
		जून 25	अप्रै. 29	मई 06	मई 20	मई 27	जून 03	जून 17	जून 24
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	32	33	33	31	31	32	31	32	31
1 कुल जमाराशियां (2.1.1.2+2.2.1.2)	**125859.6**	**126578.8**	**130356.1**	**126088.5**	**125524.8**	**126958.1**	**125966.0**	**126781.0**	**126907.3**
2 मांग और मीयादी देयताएं									
2.1 मांग देयताएं	**23736.9**	**26326.8**	**26799.3**	**24951.1**	**23918.5**	**24062.9**	**24419.3**	**25476.7**	**25634.1**
2.1.1 जमाराशियां									
2.1.1.1 अंतर-बैंक	4896.9	4843.0	5097.7	5178.3	5609.3	5845.9	6064.0	6339.0	5795.6
2.1.1.2 अन्य	13,899.4	16531.2	14888.6	12730.8	12344.8	12752.4	12737.0	13391.9	14144.1
2.1.2 बैंकों से उधार	0.0	819.8	579.8	664.8	444.9	619.8	724.4	824.7	869.7
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	4940.6	4132.8	6233.2	6377.3	5519.6	4844.8	4893.9	4921.2	4824.7
2.2 मीयादी देयताएं	**179957.5**	**169926.4**	**188046.3**	**185154.8**	**183304.2**	**183687.5**	**179240.0**	**178448.5**	**171256.4**
2.2.1 जमाराशियां									
2.2.1.1 अंतर-बैंक	65333.7	56574.5	69276.0	68469.7	66818.1	66131.9	62589.3	61653.1	55387.0
2.2.1.2 अन्य	111960.2	110047.6	115467.5	113357.8	113180.0	114205.7	113228.9	113389.1	112763.2
2.2.2 बैंकों से उधार	630.0	909.2	1000.0	999.7	998.7	1024.3	998.3	994.8	994.8
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	2033.7	2395.1	2302.9	2327.5	2307.4	2325.6	2423.3	2411.5	2111.4
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 अधिसूचित बैंक/राज्य सरकार से उधार	63559.8	53948.1	63081.2	62142.7	61405.1	61247.8	57891.0	59306.8	59486.6
4.1 मांग	15691.8	10771.0	13292.8	13229.4	13178.1	13228.8	13304.8	13449.4	13779.8
4.2 मीयादी	47868.0	43177.2	49788.3	48913.3	48227.0	48019.0	44586.3	45857.5	45706.8
5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	**8151.1**	**8751.1**	**10297.1**	**10261.9**	**11345.9**	**10695.3**	**11134.4**	**11382.2**	**10732.4**
5.1 उपलब्ध नकदी	570.3	669.6	886.4	802.6	973.4	798.5	905.4	982.8	1229.4
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	7580.8	8081.5	9410.7	9459.3	10372.5	9896.9	10229.0	10399.4	9503.0
6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेष	**1148.1**	**1222.8**	**1398.7**	**1098.2**	**1162.1**	**1227.5**	**1184.0**	**1372.1**	**1274.2**
7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	**64455.2**	**67450.1**	**72964.6**	**71668.6**	**70980.1**	**71631.0**	**70529.4**	**70958.1**	**69014.4**
8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	**28835.7**	**20792.7**	**28772.6**	**27555.1**	**25709.0**	**26130.0**	**23984.4**	**23731.8**	**20955.4**
9 बैंक ऋण (10.1+11)	**114631.6**	**106675.1**	**120025.5**	**118961.7**	**118897.7**	**119819.7**	**117024.7**	**118113.1**	**117728.1**
10 अग्रिम									
10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	**114612.1**	**106671.0**	**120004.5**	**118940.8**	**118876.8**	**119798.9**	**117003.8**	**118092.2**	**117707.2**
10.2 बैंकों से प्राप्य राशि	89429.1	86149.5	108476.3	106788.7	106283.7	105636.7	104787.9	105785.2	83603.8
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	19.5	4.1	21.0	20.9	20.9	20.9	20.9	20.8	20.8

कीमत और उत्पादन

सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधारः 2012=100)

समूह/उप समूह	2021-22			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	जुला. '21	जून'22	जुला.'22(अ)	जुला.'21	जून'22	जुला.'22(अ)	जुला.'21	जून'22	जुला.'22(अ)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 खाद्य और पेय पदार्थ	**162.8**	**168.7**	**165.0**	**161.7**	**172.4**	**172.5**	**167.9**	**179.3**	**179.4**	**164.0**	**174.9**	**175.0**
1.1 अनाज और उत्पाद	146.4	150.4	147.6	145.1	153.8	155.2	149.1	157.5	159.3	146.4	155.0	156.5
1.2 मांस और मछली	200.4	206.5	202.6	204.5	217.2	210.8	210.9	223.4	217.1	206.8	219.4	213.0
1.3 अंडा	173.3	176.0	174.4	180.4	169.6	174.3	185.0	172.8	176.7	182.2	170.8	175.2
1.4 दूध और उत्पाद	158.3	159.0	158.6	157.1	165.4	166.4	158.2	166.4	167.1	157.5	165.8	166.7
1.5 तेल और चर्बी	192.2	172.4	184.9	188.7	208.1	202.2	170.6	188.6	184.8	182.1	200.9	195.8
1.6 फल	155.3	163.5	159.2	157.7	165.8	169.9	170.9	174.1	179.6	163.9	169.7	174.4
1.7 सब्जी	156.1	192.8	168.5	152.8	167.3	168.6	186.4	211.5	208.5	164.2	182.3	182.1
1.8 दाल और उत्पाद	164.1	164.4	164.2	163.6	164.6	164.4	164.7	163.6	164.0	164.0	164.3	164.3
1.9 चीनी और उत्पाद	117.4	119.1	118.0	113.9	119.1	119.2	115.7	121.4	121.5	114.5	119.9	120.0
1.10 मसाले	171.2	167.5	170.0	169.7	188.9	191.8	165.5	183.5	186.3	168.3	187.1	190.0
1.11 गैर नशीले पेय पदार्थ	167.8	154.7	162.3	166.2	174.2	174.5	153.4	159.1	159.8	160.9	167.9	168.4
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	173.0	175.8	174.3	171.0	181.9	183.1	173.5	186.3	187.7	172.2	183.9	185.2
2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ	**190.3**	**196.5**	**191.9**	**189.7**	**192.9**	**193.2**	**195.5**	**198.3**	**198.6**	**191.2**	**194.3**	**194.6**
3 कपड़ा और जूते	**168.2**	**158.4**	**164.3**	**165.3**	**180.4**	**181.8**	**155.5**	**169.4**	**170.6**	**161.4**	**176.0**	**177.4**
3.1 कपड़ा	168.8	160.9	165.7	166.0	180.7	182.0	157.9	171.6	172.7	162.8	177.1	178.3
3.2 जूते	164.5	144.7	156.3	161.1	178.7	180.3	141.9	157.4	158.7	153.1	169.9	171.3
4 आवास	**--**	**163.0**	**163.0**	**--**	**--**	**--**	**161.5**	**166.8**	**167.8**	**161.5**	**166.8**	**167.8**
5 ईंधन और लाइट	**164.0**	**159.8**	**162.4**	**162.5**	**176.7**	**179.6**	**157.7**	**174.9**	**179.6**	**160.7**	**176.0**	**179.6**
6 विविध	**164.1**	**156.1**	**160.2**	**162.8**	**171.0**	**171.8**	**155.0**	**163.8**	**164.7**	**159.0**	**167.5**	**168.4**
6.1 घरेलू सामान और सेवा	161.8	153.5	157.9	160.3	170.3	171.3	150.7	162.1	163.0	155.8	166.4	167.4
6.2 स्वास्थ्य	172.0	163.3	168.6	170.4	178.2	178.8	161.5	170.9	171.7	167.0	175.4	176.1
6.3 परिवहन और संचार	157.9	150.0	153.7	157.1	165.5	166.3	149.5	157.2	157.4	153.1	161.1	161.6
6.4 मनोरंजन	162.7	154.8	158.2	160.7	168.0	168.6	151.2	164.1	164.6	155.3	165.8	166.3
6.5 शिक्षा	168.4	160.1	163.5	167.2	172.6	174.6	160.3	166.5	169.2	163.2	169.0	171.4
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव	161.3	160.8	161.1	160.4	169.5	169.7	159.6	169.2	169.8	160.1	169.4	169.7
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	**164.5**	**163.1**	**163.8**	**163.2**	**173.6**	**174.3**	**161.8**	**171.4**	**172.3**	**162.5**	**172.6**	**173.4**

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

अ: अनंतिम

सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2021-22	2021	2022	
				जुला.	जून	जुला.
	1	2	3	4	5	6
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2016	2.88	123.6	122.8	129.2	129.9
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	5.89	1075	1061	1125	1131
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	–	1084	1070	1137	1143

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 20: मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2021-22	2021	2022	
		जुला.	जून	जुला.
	1	2	3	4
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)	47999	47764	50804	50784
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)	65426	68338	60936	55994

स्रोत: मुंबई में सोने और चांदी के मूल्य के लिए भारत बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लि., मुंबई।।

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक

(आधार: 2011-12=100)

कमोडिटी	भारांक	2020-21	2021	2022		
			जुला.	मई	जून (अ)	जुला. (अ)
	1	2	3	4	5	6
1 सभी पण्य वस्तुएँ	**100.000**	**139.4**	**135.0**	**155.0**	**154.0**	**153.8**
1.1 प्राथमिक वस्तुएं	**22.618**	**160.7**	**154.3**	**178.5**	**182.4**	**177.5**
1.1.1 खाद्य वस्तुएं	**15.256**	**167.3**	**161.5**	**178.4**	**183.6**	**178.9**
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+ दाल)	3.462	163.5	159.7	171.7	170.7	172.6
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	187.6	170.1	208.4	229.1	208.7
1.1.1.3 दूध	4.440	156.9	155.9	163.9	164.2	164.4
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	164.0	164.0	173.6	177.8	173.1
1.1.1.5 मसाले	0.529	159.8	150.1	177.9	177.9	182.9
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	168.3	162.8	173.5	172.1	172.3
1.1.2 खाद्येतर वस्तुएं	**4.119**	**158.1**	**152.2**	**179.9**	**176.3**	**171.7**
1.1.2.1 फाइबर	0.839	158.4	146.3	234.6	228.1	208.6
1.1.2.2 तिलहन	1.115	214.4	216.9	223.7	217.5	208.1
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं	1.960	119.9	116.3	127.7	128.6	129.5
1.1.2.4 फूल	0.204	217.0	168.2	217.1	196.3	225.5
1.1.3 खनिज	**0.833**	**197.2**	**187.4**	**210.2**	**208.2**	**210.2**
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	193.3	182.0	206.0	204.0	206.0
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	211.0	206.5	224.7	223.2	225.1
1.1.4 कच्चा तेल और नैसर्गिक गैस	**2.410**	**110.3**	**101.0**	**165.5**	**176.4**	**167.5**
1.2 ईंधन और बिजली	**13.152**	**124.6**	**115.2**	**163.6**	**155.4**	**165.6**
1.2.1 कोल	**2.138**	**129.0**	**127.5**	**130.9**	**130.9**	**130.9**
1.2.1.1 कुकिंग कोल	0.647	143.0	142.5	143.4	143.4	143.4
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोल	1.401	119.8	119.8	119.8	119.8	119.8
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	170.5	138.1	212.6	212.6	212.6
1.2.2 खनिज तेल	**7.950**	**126.2**	**118.5**	**186.7**	**174.8**	**188.7**
1.2.3 बिजली	**3.064**	**117.4**	**98.2**	**126.4**	**122.2**	**130.0**
1.3 विनिर्मित उत्पाद	**64.231**	**135.0**	**132.3**	**145.0**	**143.7**	**143.1**
1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	**9.122**	**157.9**	**155.8**	**170.8**	**169.6**	**167.0**
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	142.8	142.2	145.9	147.1	147.3
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियस,मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	144.1	142.2	145.6	144.0	148.6
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	122.3	123.3	122.8	123.9	125.1
1.3.1.4 सब्जियां और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	187.2	185.6	213.6	207.3	193.4
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	149.4	148.0	160.7	160.5	161.9
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	145.6	142.9	151.7	152.2	156.5
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	133.3	125.9	159.5	155.1	155.2
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	146.2	142.6	156.3	159.4	162.7
1.3.1.9 चीनी,गुड़ और शहद	1.163	122.9	118.0	126.3	125.9	125.9
1.3.1.10 कोक, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	130.5	127.0	134.3	134.6	134.4
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स, कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	136.7	131.9	158.0	156.5	160.7
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	171.1	172.5	178.0	187.4	190.1
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	157.5	153.6	170.3	169.6	171.6
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	137.0	136.6	140.8	140.9	141.7
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	153.5	151.5	170.4	177.1	178.2
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	200.9	202.1	207.0	209.2	206.5
1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण	**0.909**	**126.8**	**126.5**	**128.4**	**128.5**	**128.4**
1.3.2.1 शराब और स्पिरीट	0.408	123.6	123.0	127.6	127.6	127.9
1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट	0.225	130.5	129.6	135.0	135.5	135.6
1.3.2.3 शीतल पेय,मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी के अन्य उत्पाद	0.275	128.6	129.3	124.1	124.0	123.2
1.3.3 विनिर्मित तंबाकू उत्पाद	**0.514**	**160.2**	**161.1**	**164.3**	**164.0**	**164.8**
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	160.2	161.1	164.3	164.0	164.8

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक *(जारी)*

(आधारः 2011-12=100)

कमोडिटी	भारांक	2020-21	2021	2022		
			जुला.	मई	जून (अ)	जुला. (अ)
1.3.4 वस्त्र विनिर्माण	**4.881**	**135.2**	**130.8**	**148.5**	**148.6**	**147.2**
1.3.4.1 धागों की कताई और वस्त्र तैयार करना	2.582	128.2	121.3	143.5	143.3	140.1
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	146.8	145.5	158.9	159.6	160.1
1.3.4.3 बुने हुए और क्रॉचिडेट फेब्रिक्स	0.193	125.5	123.4	133.4	133.3	133.5
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	138.7	135.7	151.7	154.4	154.6
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	168.5	168.6	167.4	163.0	161.8
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	126.2	123.6	135.1	135.1	135.8
1.3.5 विनिर्मित तैयार वस्त्र	**0.814**	**143.1**	**141.8**	**146.7**	**146.7**	**147.3**
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर वुलन के तैयार वस्त्र	0.593	142.0	140.9	145.4	145.2	146.1
1.3.5.2 बुने हुए क्रॉस्चिटेड वस्त्र	0.221	145.8	144.0	150.3	150.5	150.5
1.3.6 चमड़ा और उससे बने हुए उत्पाद का विनिर्माण	**0.535**	**119.2**	**117.3**	**121.4**	**122.5**	**122.9**
1.3.6.1 चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिंग और फर की रंगायी	0.142	103.4	102.6	106.9	107.5	107.5
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और दोहन	0.075	141.5	140.1	142.1	141.7	141.5
1.3.6.3 जूते-चप्पल	0.318	121.0	118.5	123.0	124.7	125.3
1.3.7 लकड़ी के विनिर्माण और लकड़ी और कॉर्क के उत्पाद	**0.772**	**141.0**	**140.2**	**141.7**	**148.3**	**143.0**
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	128.8	126.5	136.3	136.9	136.3
1.3.7.2 विनियर शीट,प्लायवुड का विनिर्माण,लॅमिन बोर्ड,पार्टिकल बोर्डऔर अन्य पॅनल और बोर्ड	0.493	141.9	141.1	140.1	150.0	142.3
1.3.7.3 बिल्डरों की बढ़ईगीरी	0.036	193.9	194.2	201.5	203.0	202.3
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	134.1	134.8	136.2	136.8	135.5
1.3.8 कागज़ और कागज़ के उत्पाद का विनिर्माण	**1.113**	**137.5**	**133.5**	**156.3**	**155.8**	**153.9**
1.3.8.1 लुगदी, कागज़ और कागज़ बोर्ड	0.493	141.4	135.6	157.9	158.4	157.6
1.3.8.2 लहरदार कागज़ और पेपर बोर्ड और कागज़ के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	137.8	135.9	153.6	152.6	150.4
1.3.8.3 कागज़ की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	131.0	127.8	156.5	154.9	151.6
1.3.9 मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनरुत्पादन	**0.676**	**157.8**	**156.1**	**167.7**	**167.3**	**167.0**
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	157.8	156.1	167.7	167.3	167.0
1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पाद का विनिर्माण	**6.465**	**133.5**	**129.3**	**147.0**	**147.5**	**147.2**
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	143.8	137.5	166.6	166.3	166.0
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	129.6	127.3	139.2	141.3	141.9
1.3.10.3 प्लास्टिक और सिथेंटिक रबड़ प्राथमिक रूप में	1.001	140.3	135.1	152.0	150.5	146.6
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एग्रोकेमिकल उत्पाद	0.454	132.1	128.9	142.1	143.7	144.0
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	130.4	124.6	143.1	142.3	143.3
1.3.10.6 साबुन और डिटर्जेंट,सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	128.1	126.8	138.1	139.0	140.6
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	130.3	125.6	143.8	144.7	145.0
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	106.6	102.7	115.2	116.0	115.6
1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण	**1.993**	**135.9**	**134.3**	**139.1**	**139.9**	**139.9**
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	135.9	134.3	139.1	139.9	139.9
1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद का विनिर्माण	**2.299**	**124.8**	**121.4**	**132.0**	**131.6**	**130.5**
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब,रबड़ टायर की रीट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	104.3	102.9	108.0	109.2	111.1
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	101.9	100.7	106.6	106.3	106.8
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	138.0	133.2	147.2	146.0	143.4
1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	**3.202**	**123.7**	**122.6**	**131.9**	**132.6**	**132.0**
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	139.1	137.9	148.5	155.9	155.8
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	115.6	114.2	118.3	118.9	118.9
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	119.3	109.0	136.0	140.1	138.6
1.3.13.4 चीनी मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी	0.222	112.9	112.1	117.4	117.2	117.8
1.3.13.5 सीमेन्ट,चूना और प्लास्टर	1.645	126.4	126.2	136.1	135.9	134.3

सं. 21ः थोक मूल्य सूचकांक *(जारी)*

(आधारः 2011-12=100)

कमोडिटी	भारांक	2020-21	2021	2022		
			जुला.	मई	जून (अ)	जुला. (अ)
1.3.13.6 कंक्रीट,सीमेन्ट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं	0.292	129.2	127.8	134.1	133.2	134.4
1.3.13.7 पत्थरों को काटना,आकार देना और संवारना	0.234	122.2	123.9	123.4	123.8	124.6
1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद	0.169	90.6	85.5	104.3	103.9	104.5
1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण	**9.646**	**140.1**	**134.0**	**158.2**	**150.2**	**148.9**
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	150.8	137.8	176.1	159.3	163.0
1.3.14.2 मेटेलिक आयरन	0.653	147.7	140.9	174.8	161.2	156.9
1.3.14.3 नरम इस्पात-अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	119.1	115.2	133.3	129.0	128.0
1.3.14.4 नरम इस्पात- लंबे उत्पाद	1.081	137.4	131.4	156.7	152.7	149.9
1.3.14.5 नरम इस्पात- चपटे उत्पाद	1.144	157.5	156.3	174.1	162.6	157.2
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	133.7	127.0	149.2	147.0	147.5
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील अर्ध निर्मित	0.924	141.7	134.1	167.4	148.1	156.7
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	155.9	148.5	177.0	169.2	174.0
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	139.7	133.4	153.3	152.0	145.2
1.3.14.10 कास्टिंग	0.925	118.9	117.1	128.3	128.0	127.0
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं	0.271	159.0	154.7	172.1	169.9	168.5
1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण	**3.155**	**130.5**	**129.3**	**140.6**	**139.3**	**140.3**
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	123.9	123.2	133.7	133.1	133.7
1.3.15.2 धातु से बने टैंक,जलाशय और डिब्बे	0.660	156.2	156.2	170.3	165.7	164.5
1.3.15.3 बाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलरर्स को छोड़कर	0.145	96.1	96.8	99.7	97.5	100.0
1.3.15.4 धातु की फोर्जिंग, दबाना, स्टैपिंग और रोल फॉर्मिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	117.5	115.3	132.3	133.6	139.2
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	108.2	106.5	112.2	112.5	112.3
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	136.5	134.1	143.9	143.2	144.3
1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण	**2.009**	**113.7**	**113.1**	**115.9**	**116.1**	**116.2**
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे	0.402	106.0	104.1	114.8	115.0	117.2
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	134.7	134.6	135.0	134.9	134.9
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	121.7	119.7	128.2	128.0	128.6
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स	0.641	102.1	102.8	98.7	98.6	97.7
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	108.4	107.7	112.7	112.7	112.9
1.3.16.6 हाथ घडी और दीवार घडी	0.076	145.6	144.9	149.6	152.6	149.6
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	106.1	105.2	106.1	108.3	107.0
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	98.3	98.5	99.6	98.3	98.3
1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण	**2.930**	**122.3**	**121.1**	**127.2**	**128.3**	**127.5**
1.3.17.1विद्युतमोटर्स,जनरेटर,ट्रांसफार्मरऔरबिजलीवितरणऔरनियंत्रणसंबंधीउपकरण	1.298	119.7	118.8	122.6	124.2	124.3
1.3.17.2 बैटरी और एक्युम्युलेटर	0.236	121.8	120.0	129.7	131.7	132.1
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	103.1	99.6	108.6	112.4	112.9
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रानिक और बिज़ली के वायर और केबल	0.428	140.7	138.9	152.0	151.6	145.7
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	114.5	114.1	117.0	116.8	117.0
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	128.4	126.3	134.0	134.1	134.6
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	113.2	113.1	114.7	116.4	115.6
1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण	**4.789**	**120.0**	**119.2**	**124.9**	**124.7**	**125.5**
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन,एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	119.2	119.4	127.7	125.7	125.8
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	122.1	120.4	126.5	127.1	127.6
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	115.1	114.0	117.6	117.5	117.7
1.3.18.4 बेयरिंग, गियर्स, गेयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	118.1	120.6	120.5	120.9	123.7
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर	0.008	74.2	74.2	78.1	78.5	78.2
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने –उतारने वाले उपकरण	0.285	120.0	117.0	125.3	124.6	126.4

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक *(समाप्त)*

(आधारः 2011-12=100)

कमोडिटी	भारांक	2020-21	2021	2022		
			जुला.	मई	जून (अ)	जुला. (अ)
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	133.4	135.0	144.9	142.6	143.5
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	128.4	126.4	133.8	134.3	136.5
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	114.2	114.8	118.6	118.3	119.6
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	78.2	76.6	83.6	84.2	83.8
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	130.1	128.6	129.6	129.4	128.0
1.3.18.13 कपड़ा,परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	125.3	121.4	125.8	126.9	126.7
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	134.7	133.1	137.2	137.9	138.9
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	66.6	66.2	68.3	68.3	68.2
1.3.19 मोटर वाहन, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण	**4.969**	**122.7**	**121.3**	**127.5**	**127.7**	**127.5**
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	122.6	121.5	126.2	126.2	126.3
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	122.7	121.1	129.1	129.4	128.9
1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण	**1.648**	**131.7**	**130.6**	**135.3**	**135.5**	**136.2**
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली –वस्तुओं का निर्माण	0.117	158.9	158.9	159.1	159.1	163.5
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टाक	0.110	104.4	104.5	103.8	104.0	103.9
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	131.0	129.7	135.3	135.6	136.0
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाडी	0.117	137.2	136.4	139.9	139.9	140.8
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	135.9	132.3	146.5	147.7	149.2
1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण	**0.727**	**150.1**	**146.2**	**155.9**	**155.8**	**157.7**
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	150.1	146.2	155.9	155.8	157.7
1.3.22 अन्य विनिर्माण	**1.064**	**137.9**	**137.0**	**144.1**	**139.6**	**144.3**
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	136.0	135.1	142.3	137.7	142.7
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	192.3	203.3	186.8	192.1	175.4
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	140.4	138.3	147.5	148.2	148.9
1.3.22.4 खेल और खिलौने	0.005	150.9	150.1	156.7	160.6	160.9
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और सामग्री	0.049	171.8	171.3	175.7	173.5	171.3
2 खाद्य सूचकांक	**24.378**	**163.8**	**159.4**	**175.6**	**178.4**	**174.4**

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 22: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधारः 2011-12=100)

उद्योग	भारांक	2020-21	2021-22	अप्रैल-जून		जून	
				2021-22	2022-23	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
सामान्य सूचकांक	100.00	118.1	131.6	121.3	136.7	122.8	137.9
1 क्षेत्रवार वर्गीकरण							
1.1 खनन	14.37	101.0	113.3	107.1	116.7	105.5	113.4
1.2 विनिर्माण	77.63	117.2	131.0	119.1	134.2	121.2	136.3
1.3 बिजली	7.99	157.6	170.1	168.3	197.1	169.1	196.9
2 उपयोग आधारित वर्गीकरण							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	118.1	129.5	123.9	141.1	122.4	139.2
2.2 पूंजीगत माल	8.22	75.9	88.7	74.0	95.8	81.2	102.4
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	124.7	143.9	133.8	149.5	132.7	147.3
2.4 बुनियादी/निर्माण वस्तुएं	12.34	124.7	148.2	137.1	150.6	137.9	148.9
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	101.2	113.8	91.7	116.1	100.1	123.9
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	142.1	146.7	139.1	140.7	141.8	145.9

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सरकारी लेखा और खज़ाना बिल

सं. 23: केन्द्र सरकार का लेखा - एक नज़र में

(करोड़ ₹)

मद	वित्तीय वर्ष	अप्रैल-जुलाई			
	2022-23 (बजट आकलन)	2022-23 (वास्तविक)	2021-22 (वास्तविक)	बजट आकलन के लिए प्रतिशत	
				2022-23	2021-22
	1	2	3	4	5
1 राजस्व प्राप्तियां	**2204422**	**755795**	**669149**	**34.3**	**37.4**
1.1 कर राजस्व (निवल)	1934771	666212	529189	34.4	34.2
1.2 करेतर राजस्व	269651	89583	139960	33.2	57.6
2 गैरेतर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	**79291**	**30119**	**14148**	**38.0**	**7.5**
2.1 ऋण की वसूली	14291	5559	5777	38.9	44.4
2.2 अन्य प्राप्तियां	65000	24560	8371	37.8	4.8
3 कुल प्राप्तियां (उधारियों को छोड़कर) (1+2)	**2283713**	**785914**	**683297**	**34.4**	**34.6**
जिसमें से:	3194663	918075	876012	28.7	29.9
4 राजस्व व्यय					
4.1 ब्याज भुगतान	940651	283870	225817	30.2	27.9
5 पूंजी व्यय	750246	208670	128428	27.8	23.2
6 कुल व्यय (4+5)	**3944909**	**1126745**	**1004440**	**28.6**	**28.8**
7 राजस्व घाटा (4-1)	**990241**	**162280**	**206863**	**16.4**	**18.1**
8 राजकोषीय घाटा (6-3)	**1661196**	**340831**	**321143**	**20.5**	**21.3**
9 सकल प्राथमिक घाटा (8-4.1)	**720545**	**56961**	**95326**	**7.9**	**13.7**

स्रोत : महालेखानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और केंद्रीय बजट 2022-23।

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(करोड़ ₹)

मद	2021-22	2021	2022					
		जुला. 30	जून 24	जुला. 1	जुला. 8	जुला. 15	जुला. 22	जुला. 29
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	5310	9355	9455	9969	11681	12099	10785	11428
1.2 प्राथमिक व्यापारी	16705	23157	34041	29426	26678	28800	29993	35008
1.3 राज्य सरकारें	31320	47982	70800	56300	70000	68800	59800	58800
1.4 अन्य	72109	159946	128325	138186	135518	129105	127831	121432
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	70130	119323	102032	105571	102273	102307	102435	103721
2.2 प्राथमिक व्यापारी	63669	54786	111392	109413	102865	101420	99496	99464
2.3 राज्य सरकारें	15763	15355	28246	28218	38718	38887	38887	38187
2.4 अन्य	69259	113457	110496	116191	122509	119605	117743	113193
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	112386	120838	113968	116249	113296	109776	118731	113731
3.2 प्राथमिक व्यापारी	160461	123281	181683	174254	174070	175478	179050	178252
3.3 राज्य सरकारें	22836	19825	26686	27825	27825	27825	27925	26571
3.4 अन्य	118392	94163	125126	132315	135458	138639	127465	132209
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	289362	159116	155906	156291	85925	114790	123995	129551
4.4 अन्य	659	314	934	854	743	984	1189	638
कुल खज़ाना बिल (14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)#	758339	901468	1042250	1043917	1060892	1052742	1040141	1031995

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं है। यह बिल स्वरूप के अनुसार मध्यवर्ती हैं क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए परिसमाप्त किए जाते हैं।

सं. 25: खज़ाना बिलों की नीलामी

(राशि करोड़ ₹ में)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियाँ			स्वीकृत बोलियां			कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)
		संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या	कुल अंकित मूल्य				
			प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी		प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91-दिवसीय खज़ाना बिल										
2022-23										
जून 29	13000	87	33195	7011	47	12989	7011	20000	98.73	5.1595
जुला. 6	9000	100	28436	13720	52	8980	13720	22700	98.74	5.1389
जुला. 13	9000	115	38019	1690	55	8960	1690	10650	98.71	5.2401
जुला. 20	9000	97	28467	3220	50	8980	3220	12200	98.67	5.3987
जुला. 27	9000	140	44475	1527	40	8983	1527	10510	98.62	5.6229
182-दिवसीय खज़ाना बिल										
2022-23										
जून 29	12000	185	33092	1015	75	11985	1015	13000	97.19	5.7899
जुला. 6	7000	164	38850	10513	40	6987	10513	17500	97.25	5.6651
जुला. 13	7000	135	23911	183	54	6986	183	7169	97.22	5.7453
जुला. 20	7000	111	21688	11	37	6989	11	7000	97.17	5.8515
जुला. 27	7000	109	23147	13	33	6987	13	7000	97.11	5.9788
364-दिवसीय खज़ाना बिल										
2022-23										
जून 29	8000	206	24833	1167	50	7973	1167	9139	94.10	6.2870
जुला. 6	5000	200	19532	30	78	4970	30	5000	94.23	6.1390
जुला. 13	5000	172	19962	43	62	4957	43	5000	94.20	6.1750
जुला. 20	5000	161	13106	1363	91	4937	1363	6300	94.14	6.2441
जुला. 27	5000	156	22243	271	57	4975	271	5246	94.06	6.3300

वित्तीय बाजार

सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार		दरों का दायरा	भारित औसत दरें
		उधार लेना/उधार देना	उधार लेना/उधार देना
		1	2
जुला.	1, 2022	3.30-5.20	4.72
जुला.	2, 2022	3.70-4.90	4.28
जुला.	4, 2022	3.00-4.95	4.72
जुला.	5, 2022	3.30-4.90	4.71
जुला.	6, 2022	3.00-4.85	4.68
जुला.	7, 2022	3.30-5.00	4.67
जुला.	8, 2022	3.30-4.95	4.69
जुला.	11, 2022	3.30-4.95	4.69
जुला.	12, 2022	3.30-4.90	4.66
जुला.	13, 2022	3.30-4.85	4.66
जुला.	14, 2022	3.30-4.85	4.67
जुला.	15, 2022	3.25-5.25	4.74
जुला.	16, 2022	3.80-4.95	4.30
जुला.	18, 2022	2.50-4.90	4.69
जुला.	19, 2022	2.50-4.92	4.73
जुला.	20, 2022	3.30-4.90	4.75
जुला.	21, 2022	3.30-5.25	4.82
जुला.	22, 2022	3.30-5.30	4.98
जुला.	25, 2022	3.30-5.40	5.04
जुला.	26, 2022	3.30-5.50	5.09
जुला.	27, 2022	3.30-5.45	5.06
जुला.	28, 2022	3.30-5.40	5.06
जुला.	29, 2022	3.25-5.30	4.92
जुला.	30, 2022	3.80-4.51	4.22
अग.	1, 2022	3.35-4.95	4.73
अग.	2, 2022	3.25-4.85	4.66
अग.	3, 2022	3.25-4.85	4.65
अग.	4, 2022	3.25-4.80	4.59
अग.	5, 2022	3.30-5.35	5.00
अग.	6, 2022	4.00-5.40	4.44
अग.	8, 2022	3.50-5.65	5.10
अग.	10, 2022	3.50-5.30	5.08
अग.	11, 2022	3.25-5.25	5.05
अग.	12, 2022	3.50-5.50	5.17

टिप्पणी: नोटिस मुद्रा सहित

सं. 27: जमा प्रमाण-पत्र

मद	2021	2022			
	जुला. 30	जून 17	जुला. 1	जुला. 15	जुला. 29
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	64304.10	194418.87	223791.41	235248.52	249062.16
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (करोड़ ₹)	950.89	25090.17	50542.41	20150.94	29372.29
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	4.05-4.85	4.86-6.58	4.93-6.39	5.38-6.19	5.33-6.38

सं. 28: वाणिज्यिक पत्र

मद	2021	2022			
	जुला. 31	जून 15	जून 30	जुला. 15	जुला. 31
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	414981.65	389282.00	372542.35	381468.70	374226.45
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (करोड़ ₹)	149052.15	55172.75	67595.30	46218.50	48380.15
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	3.38-12.94	4.69-13.52	4.88-12.38	4.95-12.13	5.05-12.40

सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक कारोबार

(करोड़ ₹)

मद	2021-22	2021	2022					
		जुला. 30	जून 24	जुला. 1	जुला. 8	जुला. 15	जुला. 22	जुला. 29
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	14515	13281	21624	25106	25664	22265	25768	21115
2 नोटिस मुद्रा	2122	3801	689	5655	767	6353	518	4246
3 मीयादी मुद्रा	515	575	238	577	426	653	351	318
4 त्रिपक्षीय रिपो	618526	652552	710395	779612	611867	716782	589701	724049
5 बाजार रिपो	383844	337951	482415	588716	490392	538102	449231	515023
6 कार्पोरेट बांड में रिपो	4373	7200	116	100	308	5129	2947	183
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	67793	77056	84579	105754	73721	85366	91965	98204
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	51300	40423	70092	49175	68638	66162	59173	70519
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	5570	5104	5016	5785	5517	3863	4603	5865
10 खज़ाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	4690	3883	6131	8629	5577	3000	3823	2921
10.2 182-दिवसीय	3440	3251	4424	5815	6677	4434	4651	5438
10.3 364-दिवसीय	3530	5958	2916	4023	2168	2664	2107	1597
10.4 नकदी प्रबंधन बिल								
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	68530	58619	88578	73427	88577	80123	74357	86341
11.1 भारतीय रिज़र्व बैंक	–	224	133	24	80	386	336	442

सं. 30: गैर-सरकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(राशि करोड़ ₹ में)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2021-22		2021-22 (अप्रै-जुला.)		2022-23 (अप्रै-जुला.)*		जुला. 2021		जुला. 2022*	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 इक्विटी शेयर	**164**	**138894**	**32**	**26117**	**59**	**18579**	**10**	**13252**	**14**	**281**
1ए प्रीमियम	154	136893	30	25523	54	17699	9	13073	12	206
1.1 पब्लिक	121	112567	24	25354	42	17324	8	13198	11	222
1.1.1 प्रीमियम	119	111314	24	24881	40	16739	8	13061	10	188
1.2 राइट्स	43	26327	8	763	17	1254	2	54	3	59
1.2.1 प्रीमियम	35	25580	6	641	14	960	1	13	2	18
2 अधिमान शेयर	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
2.1 पब्लिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3 बांड और डिबेंचर	**28**	**11589**	**10**	**5389**	**12**	**2823**	**4**	**1808**	**1**	**298**
3.1 परिवर्तनीय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.1.1 पब्लिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.1.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.2 अपरिवर्तनीय	28	11589	10	5389	12	2823	4	1808	1	298
3.1.1 पब्लिक	28	11589	10	5389	12	2823	4	1808	1	298
3.1.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4 कुल (1+2+3)	**192**	**150484**	**42**	**31506**	**71**	**21401**	**14**	**15061**	**15**	**579**
4.1 पब्लिक	149	124157	34	30743	54	20147	12	15007	12	520
4.2 राइट्स	43	26327	8	763	17	1254	2	54	3	59

टिप्पणी: 1. अप्रैल 2020 से इक्विटी निर्गमों का मासिक डेटा उनकी लिस्टिंग की तारीख के आधार पर संकलित किया गया है।
2. संख्याओं के पूर्णांकन के कारण कालम के आंकडे कुल में नहीं जुड़ सकते।

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)।

* : आंकड़े अनंतिम है।

बाह्य क्षेत्र

सं. 31: विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2021-22	2021	2022				
			जुला.	मार्च	अप्रै.	मई	जून	जुला.
		1	2	3	4	5	6	7
1 निर्यात	करोड ₹	3147021	264666	339850	302579	302079	330827	288748
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	422004	35513	44574	39725	39069	42373	36274
1.1 तेल	करोड ₹	503850	43524	74769	60009	66033	83255	50756
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	67472	5840	9806	7878	8540	10664	6376
1.2 तेल से इतर	करोड ₹	2643171	221142	265081	242570	236046	247572	237992
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	354533	29673	34767	31847	30529	31710	29898
2 आयात	करोड ₹	4572775	343920	481031	459226	489335	519834	527542
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	613052	46147	63091	60291	63288	66582	66273
2.1 तेल	करोड ₹	1207803	92429	161219	153257	148600	168311	168227
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	161810	12402	21145	20121	19219	21558	21134
2.2 तेल से इतर	करोड ₹	3364972	251491	319812	305969	340736	351524	359315
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	451242	33745	41946	40170	44069	45024	45139
3 व्यापार शेष	करोड ₹	-1425753	-79253	-141181	-156647	-187257	-189008	-238794
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	-191048	-10634	-18517	-20566	-24219	-24209	-29999
3.1 तेल	करोड ₹	-703953	-48905	-86450	-93248	-82567	-85056	-117471
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	-94339	-6562	-11339	-12242	-10679	-10894	-14757
3.2 तेल से इतर	करोड ₹	-721800	-30348	-54730	-63399	-104690	-103952	-121323
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	-96709	-4072	-7178	-8324	-13540	-13314	-15241

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय।

सं. 32: विदेशी मुद्रा भंडार

मद	इकाई	2021	2022					
		अग. 27	जुला. 22	जुला. 29	अग. 5	अग. 12	अग. 19	अग. 26
		1	2	3	4	5	6	7
1 कुल भंडार	**करोड ₹**	**4669426**	**4568803**	**4549652**	**4542615**	**4545959**	**4499645**	**4480681**
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	**633558**	**571560**	**573875**	**572978**	**570740**	**564053**	**561046**
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	करोड ₹	4212584	4077817	4053160	4040594	4038200	3998377	3982307
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	571600	510136	511257	509646	506994	501216	498645
1.2 स्वर्ण	करोड ₹	275932	307766	314274	319613	323525	318410	316599
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	37441	38502	39642	40313	40618	39914	39643
	मात्रा (मैट्रिक टन)	724.24	780.36	781.29	781.29	781.29	781.29	781.29
1.3 एसडीआर	एसडीआरएस मिलियन	13657	13657	13657	13657	13657	13658	13658
	करोड ₹	143028	143587	142583	142952	144431	143493	142411
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	19407	17963	17985	18031	18133	17987	17832
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	करोड ₹	37883	39632	39635	39456	39803	39364	39363
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	5110	4960	4991	4987	4994	4936	4926

* अंतर यदि कोई हो, तो पूर्णांकन के वजह से हैं।

सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2021-22	2021	2022		2021-22	2022-23
		जुला.	जून	जुला.	अप्रै.-जुला.	अप्रै.-जुला.
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियां	**139022**	**141791**	**135977**	**135407**	**3127**	**1428**
1.1 एफसीएनआर (बी)	16918	19599	15681	15878	-875	-1040
1.2 एनआर (ई) आरए	100801	102989	98982	97937	3138	1293
1.3 एनआरओ	21303	19203	21314	21592	863	1175

सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	2021-22	2021-22	2022-23	2021	2022	
		अप्रै.-जुला.	अप्रै.-जुला.	जुला.	जून	जुला.
	1	2	3	4	5	6
1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)	**38587**	**13106**	**18879**	**1552**	**3772**	**5213**
1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1. 1.1.2)	**56231**	**19857**	**22025**	**2620**	**4773**	**5834**
1.1.1.1 सकल अंतर्वाह/सकल निवेश	**84835**	**27925**	**29207**	**4778**	**5951**	**6791**
1.1.1.1.1 इक्विटी	59684	20695	21839	2922	4047	5044
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	1698	112	439	2	113	60
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक	42932	12983	16561	2373	2285	4155
1.1.1.1.1.3 शेयरों की अधिप्राप्ति	14143	7320	4561	473	1580	756
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की ईक्विटी पूंजी	910	279	279	73	69	73
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	19347	5934	5934	1556	1459	1556
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	5805	1297	1434	300	445	191
1.1.1.2 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	**28605**	**8068**	**7183**	**2158**	**1178**	**957**
1.1.1.2.1 इक्विटी	27189	7904	6707	2086	1074	895
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	1416	164	475	72	103	62
1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)	**17644**	**6751**	**3146**	**1068**	**1001**	**622**
1.1.2.1 इक्विटी पूंजी	10061	3350	1546	818	421	483
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	3379	1126	1126	282	282	282
1.1.2.3 अन्य पूंजी	7604	3206	1343	357	487	174
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	3400	931	869	389	189	317
1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)	**-16777**	**-1216**	**-14701**	**-1618**	**-6694**	**362**
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	–	–	–	–	–	–
1.2.2 एफआईआई	-14071	-1018	-14657	-1396	-6586	458
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	–	–	–	–	–	–
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	2706	198	44	222	108	96
1 विदेशी निवेश अंतर्वाह	**21809**	**11890**	**4178**	**-66**	**-2922**	**5574**

सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	2021-22	2021	2022		
		जुला.	मई	जून	जुला.
	1	2	3	4	5
1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण	**19610.77**	**1308.47**	**2039.26**	**1984.68**	**1982.44**
1.1 जमाराशियां	830.05	46.93	79.46	72.49	79.96
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	112.90	6.89	11.76	14.54	11.65
1.3 इक्विटी / डेट में निवेश	746.57	50.21	82.47	65.03	59.71
1.4 उपहार	2336.29	175.22	248.69	222.77	216.33
1.5 दान	16.55	0.78	1.01	1.12	1.18
1.6 यात्रा	6909.04	346.91	994.82	1043.08	1015.27
1.7 निकट संबंधियों का रखरखाव	3302.37	243.23	336.96	304.85	292.72
1.8 चिकित्सा उपचार	37.79	2.88	4.43	4.39	4.29
1.9 विदेश में शिक्षा	5165.33	423.35	264.61	240.86	276.03
1.10 अन्य	153.88	12.07	15.04	15.55	25.30

सं. 36: भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (रीर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (नीर)

मद	2020-21	2021-22	2021	2022	
			अगस्त	जुलाई	अगस्त
	1	2	3	4	5
40- मुद्रा बास्केट (आधार: 2015-16=100)					
1 व्यापार आधारित भारांक					
1.1 नीर	93.92	93.13	93.19	92.08	92.26
1.2 रीर	103.46	104.66	105.23	103.56	103.86
2 निर्यात आधारित भारांक					
2.1 नीर	93.59	93.55	93.36	93.50	93.65
2.2 रीर	102.96	103.48	103.95	102.31	102.58
6- मुद्रा बास्केट (व्यापार-भारित)					
1 आधार : 2015-16=100					
1.1 नीर	88.45	87.03	87.16	86.88	87.24
1.2 रीर	101.84	102.27	102.72	102.96	103.77
2 आधार : 2018-19 =100					
2.1 नीर	100.00	98.39	98.54	98.23	98.63
2.2 रीर	100.00	100.42	100.86	101.11	101.90

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार - पंजीकरण

(राशि अमेरिकी मिलियन डॉलर में)

मद	2021-22	2021	2022	
		जुला.	जून	जुला.
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	1086	80	109	96
1.2 राशि	28851	3034	1789	2316
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	18	1	1	1
2.2 राशि	11035	400	100	300
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	1104	81	110	97
3.2 राशि	39886	3434	1889	2616
4 भारित औसत परिपक्वता (वर्षों में)	8.00	9.23	5.50	4.64
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 6 महीने के लिबॉर पर भारित औसत मार्जिन या अस्थिर दर के ऋणों के लिए संदर्भ दर	1.71	2.44	1.77	1.28
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-10.50	0.00-10.50	0.00-10.37	0.00-11.15
उधारकर्ता श्रेणियाँ				
I. कॉर्पोरेट विनिर्माण	12244	1001	389	296
II. कॉर्पोरेट -बुनियादी संरचना	17023	1699	131	288
ए) परिवहन	1597	0	0	36
बी) ऊर्जा	8215	442	125	60
सी) पानी और सफ़ाई व्यवस्था	10	1	0	0
डी) संचार	1258	0	0	0
ई) सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी संरचना	0	0	0	0
एफ)अन्वेषण खनन और रिफाइनरी	4691	500	5	164
जी) अन्य उप -क्षेत्र	1252	756	1	28
III. कॉर्पोरेट सेवा क्षेत्र	1570	32	661	118
IV. अन्य संस्थाएं	609	0	300	303
ए) एसई जेड़ में इकाई	9	0	0	3
बी) सिडबी				
सी) एक्जिम बैंक	600	0	300	300
V. बैंक	100	0	0	0
VI. वित्तीय संस्थान (एनबी एफ सी के अलावा)	4	0	0	0
VII. एनबीएफसी	7995	679	406	1611
ए) एनबीएफसी -आई एफ सी/ए एफ सी	5621	414	0	340
बी) एनबी एफ सी -एमएफआई	93	15	6	51
सी) एनबीफसी - अन्य	2282	250	400	1220
VIII. गैर -सरकारी संगठन	0	0	0	0
IX. सूक्ष्म वित्त संस्था	0	0	0	0
X. अन्य	341	23	2	0

सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	जन.-मार्च 2021			जन.-मार्च 2022 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	**336072**	**332683**	**3389**	**384903**	**400927**	**-16024**
1 चालू खाता (1.1+1.2)	**173382**	**181543**	**-8161**	**218823**	**232247**	**-13424**
1.1 पण्य	**91281**	**133025**	**-41745**	**118020**	**172503**	**-54483**
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	**82101**	**48518**	**33583**	**100803**	**59744**	**41059**
1.2.1 सेवाएं	56004	32520	23485	69876	41557	28319
1.2.1.1 यात्रा	2308	3141	-834	2757	5133	-2376
1.2.1.2 परिवहन	6080	5633	446	9398	11002	-1604
1.2.1.3 बीमा	647	566	82	904	428	476
1.2.1.4 जीएनआईई	159	241	-82	160	271	-111
1.2.1.5 विविध	46811	22938	23873	56657	24723	31934
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	26802	3327	23475	32786	3520	29266
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	13324	12847	478	16835	13867	2968
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	1258	1402	-145	1615	1504	111
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	696	399	297	763	269	494
1.2.2 अंतरण	20927	2085	18842	23723	2591	21132
1.2.2.1 आधिकारिक	18	285	-267	21	239	-218
1.2.2.2 निजी	20909	1801	19108	23702	2353	21350
1.2.3 आय	5170	13913	-8743	7204	15596	-8392
1.2.3.1 निवेश आय	3517	13192	-9675	5589	14792	-9202
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1653	721	932	1614	804	810
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**162690**	**150429**	**12261**	**166081**	**167787**	**-1707**
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	**108195**	**98236**	**9959**	**95111**	**96550**	**-1439**
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	15393	12714	2679	24396	10620	13777
2.1.1.1 भारत में	13679	7928	5750	23281	6028	17253
2.1.1.1.1 इक्विटी	8553	7894	659	15845	5177	10669
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	4519		4519	5229		5229
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	607	34	573	2207	851	1356
2.1.1.2 विदेश में	1714	4786	-3072	1115	4592	-3477
2.1.1.2.1 इक्विटी	1714	1197	517	1115	2132	-1017
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	753	-753	0	845	-845
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	2835	-2835	0	1615	-1615
2.1.2 संविभाग निवेश	92802	85522	7280	70715	85930	-15215
2.1.2.1 भारत में	92500	84310	8190	70254	84543	-14289
2.1.2.1.1 एफआईआई	92500	84310	8190	70254	84543	-14289
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	81440	73679	7761	62553	75636	-13083
2.1.2.1.1.2 ऋण	11059	10631	428	7701	8907	-1206
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0		0
2.1.2.2 विदेश में	303	1212	-909	461	1387	-926
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	**26446**	**18725**	**7721**	**33737**	**20826**	**12911**
2.2.1 बाह्य सहायता	5380	1387	3993	3988	1331	2657
2.2.1.1 भारत द्वारा	10	21	-11	13	16	-3
2.2.1.2 भारत को	5370	1366	4004	3976	1315	2661
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	11834	5759	6075	11346	7913	3433
2.2.2.1 भारत द्वारा	683	745	-63	514	373	141
2.2.2.2 भारत को	11152	5014	6138	10832	7540	3292
2.2.3 भारत को अल्पावधि	9232	11578	-2346	18403	11582	6821
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	8067	11578	-3511	14571	11582	2988
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	1165	0	1165	3833	0	3833
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	**16733**	**21158**	**-4425**	**27241**	**33202**	**-5961**
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	16518	21158	-4640	27195	32602	-5407
2.3.1.1 आस्तियां	4141	7973	-3832	13120	17970	-4850
2.3.1.2 देयताएं	12377	13185	-808	14075	14632	-557
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	11350	11889	-539	13468	13309	159
2.3.2 अन्य	215	0	215	46	600	-554
2.4 रुपया ऋण चुकौती		7	-7	0	12	-12
2.5 अन्य पूंजी	11315	12302	-987	9991	17196	-7205
3 भूल-चूक		**711**	**-711**	0	**893**	**-893**
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	**3389**	**-3389**	**16024**	0	**16024**
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	0	3389	-3389	16024	0	16024

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(करोड़ ₹)

मद	जन.-मार्च 2021			जन.-मार्च 2022 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	**2449502**	**2424800**	**24702**	**2895618**	**3016163**	**-120545**
1 चालू खाता (1.1+1.2)	**1263718**	**1323202**	**-59484**	**1646199**	**1747190**	**-100991**
1.1 पण्य	**665312**	**969572**	**-304260**	**887863**	**1297738**	**-409875**
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	**598406**	**353629**	**244776**	**758336**	**449452**	**308883**
1.2.1 सेवाएं	408194	237025	171170	525672	312631	213042
1.2.1.1 यात्रा	16819	22896	-6077	20740	38617	-17877
1.2.1.2 परिवहन	44312	41058	3254	70702	82770	-12068
1.2.1.3 बीमा	4719	4125	594	6801	3218	3583
1.2.1.4 जीएनआईई	1158	1759	-601	1201	2035	-834
1.2.1.5 विविध	341186	167187	173999	426228	185990	240238
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	195350	24250	171099	246649	26481	220167
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	97117	93634	3484	126651	104321	22330
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	9166	10220	-1054	12147	11313	834
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	5073	2905	2168	5742	2024	3718
1.2.2 अंतरण	152529	15199	137330	178471	19496	158975
1.2.2.1 आधिकारिक	129	2074	-1945	158	1796	-1638
1.2.2.2 निजी	152400	13125	139275	178313	17700	160613
1.2.3 आय	37682	101406	-63724	54193	117326	-63133
1.2.3.1 निवेश आय	25637	96153	-70517	42047	111277	-69230
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	12045	5252	6793	12145	6049	6096
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**1185784**	**1096418**	**89366**	**1249419**	**1262257**	**-12838**
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	**788594**	**716008**	**72586**	**715520**	**726343**	**-10823**
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	112193	92670	19523	183534	79893	103640
2.1.1.1 भारत में	99699	57788	41911	175144	45346	129797
2.1.1.1.1 इक्विटी	62338	57537	4801	119205	38945	80260
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	32935	0	32935	39334	0	39334
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	4427	251	4176	16605	6401	10203
2.1.1.2 विदेश में	12493	34882	-22389	8390	34547	-26157
2.1.1.2.1 इक्विटी	12493	8726	3767	8390	16040	-7650
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	5490	-5490	0	6355	-6355
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	20666	-20666	0	12153	-12153
2.1.2 संविभाग निवेश	676402	623338	53063	531986	646450	-114463
2.1.2.1 भारत में	674196	614505	59691	528521	636017	-107496
2.1.2.1.1 एफआईआई	674196	614505	59691	528521	636017	-107496
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	593588	537019	56569	470586	569008	-98422
2.1.2.1.1.2 ऋण	80608	77487	3122	57935	67009	-9074
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	2206	8833	-6628	3465	10433	-6968
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	**192758**	**136479**	**56279**	**253804**	**156675**	**97128**
2.2.1 बाह्य सहायता	39212	10111	29101	30003	10013	19989
2.2.1.1 भारत द्वारा	71	153	-82	95	120	-26
2.2.1.2 भारत को	39141	9958	29183	29908	9893	20015
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	86255	41978	44276	85354	59528	25826
2.2.2.1 भारत द्वारा	4975	5433	-459	3867	2804	1062
2.2.2.2 भारत को	81280	36545	44735	81487	56723	24764
2.2.3 भारत को अल्पावधि	67291	84390	-17099	138447	87134	51313
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	58799	84390	-25591	109614	87134	22479
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	8492	0	8492	28833	0	28833
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	**121962**	**154215**	**-32253**	**204931**	**249778**	**-44847**
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	120397	154215	-33818	204584	245264	-40680
2.3.1.1 आस्तियां	30186	58112	-27927	98701	135191	-36490
2.3.1.2 देयताएं	90211	96103	-5892	105884	110073	-4190
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	82726	86651	-3925	101318	100121	1197
2.3.2 अन्य	1565	0	1565	347	4514	-4167
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	50	-50	0	93	-93
2.5 अन्य पूंजी	82471	89666	-7196	75165	129368	-54203
3 भूल-चूक	0	**5180**	**-5180**	0	**6716**	**-6716**
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	**24702**	**-24702**	**120545**	0	**120545**
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	0	24702	-24702	120545	0	120545

टिप्पणी: पीः प्रारंभिक

सं. 40: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	जन.-मार्च 2021			जन.-मार्च 2022 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	**173382**	**181517**	**-8135**	**218822**	**232225**	**-13404**
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	**147285**	**165545**	**-18260**	**187896**	**214060**	**-26164**
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	**91281**	**133025**	**-41745**	**118020**	**172503**	**-54483**
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	89691	115206	-25515	118046	164299	-46253
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	1590	0	1590	-26	0	-26
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण		17819	-17819		8204	-8204
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	**56004**	**32520**	**23485**	**69876**	**41557**	**28319**
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	102	6	96	214	24	190
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	54	211	-157	44	440	-397
1.अ.ख.3 परिवहन	6080	5633	446	9398	11002	-1604
1.अ.ख.4 यात्रा	2308	3141	-834	2757	5133	-2376
1.अ.ख.5 निर्माण	752	713	39	596	720	-124
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	647	566	82	904	428	476
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	1258	1402	-145	1615	1504	111
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	238	2107	-1868	193	2518	-2325
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	27574	3909	23665	33629	4009	29620
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	13324	12847	478	16835	13867	2968
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	727	878	-150	970	1224	-253
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	159	241	-82	160	271	-111
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं है	2781	865	1916	2560	416	2145
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	**5170**	**13913**	**-8743**	**7204**	**15596**	**-8392**
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1653	721	932	1614	804	810
1.आ.2 निवेश आय	2621	12952	-10331	4303	13417	-9113
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	1363	7837	-6474	3206	8193	-4987
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	28	1633	-1605	80	1591	-1511
1.आ.2.3 अन्य निवेश	122	3481	-3359	96	3629	-3533
1.आ.2.4 रिज़र्व आस्तियां	1109	1	1107	922	4	918
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	896	240	656	1286	1375	-89
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	**20927**	**2058**	**18868**	**23722**	**2570**	**21153**
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	20909	1801	19108	23702	2353	21350
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	20224	1303	18920	22943	1677	21267
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	686	497	188	759	676	83
1.इ.2 सामान्य सरकार	17	258	-240	20	217	-197
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	**191**	**230**	**-38**	**244**	**173**	**71**
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	87	38	49	117	29	88
2.2 पूँजी अंतरण	104	191	-88	127	144	-17
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	**162499**	**153615**	**8884**	**181861**	**167636**	**14226**
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	**15393**	**12714**	**2679**	**24396**	**10620**	**13777**
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	13679	7928	5750	23281	6028	17253
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	13071	7894	5177	21074	5177	15897
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	8553	7894	659	15845	5177	10669
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	4519		4519	5229		5229
3.1.अ.2 ऋण लिखत	607	34	573	2207	851	1356
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	607	34	573	2207	851	1356
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	1714	4786	-3072	1115	4592	-3477
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	1714	1950	-236	1115	2977	-1862
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	1714	1197	517	1115	2132	-1017
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश		753	-753		845	-845
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	2835	-2835	0	1615	-1615
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक		2835	-2835		1615	-1615
3.2 संविभाग निवेश	**92802**	**85522**	**7280**	**70715**	**85930**	**-15215**
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	92500	84310	8190	70254	84543	-14289
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	81440	73679	7761	62553	75636	-13083
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	11059	10631	428	7701	8907	-1206
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	303	1212	-909	461	1387	-926
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिज़र्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	**2662**	**4929**	**-2267**	**4629**	**7403**	**-2774**
3.4 अन्य निवेश	**51642**	**47061**	**4581**	**66098**	**63683**	**2415**
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	11565	11889	-324	13514	13909	-395
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	215	0	215	46	600	-554
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	11350	11889	-539	13468	13309	159
3.4.2.3 सामान्य सरकार			0			0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र			0			0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	22382	16416	5966	29061	28537	524
3.4.3अ भारत को ऋण	21690	15650	6040	28534	28148	386
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	692	766	-74	527	389	138
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	27	43	-16	40	17	22
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	9232	11578	-2346	18403	11582	6821
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	8435	7134	1301	5080	9637	-4557
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार			0			0
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	**3389**	**-3389**	**16024**	0	**16024**
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण			0			0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए			0			0
3.5.3 आईएमएफ में रिज़र्व निधियों की स्थिति एन.ए			0			0
3.5.4 अन्य रिज़र्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	3389	-3389	16024	0	16024
4. कुल आस्तियां / देयताएं	**162499**	**153615**	**8884**	**181861**	**167636**	**14226**
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	99217	89707	9510	89872	92596	-2725
4.2 ऋण लिखत	54846	53384	1462	70886	65402	5484
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	8435	10524	-2088	21104	9637	11466
5. निवल भूल-चूक		**711**	**-711**		**893**	**-893**

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(करोड़ ₹)

मद	जन.-मार्च 2021			जन.-मार्च 2022 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	**1263714**	**1323006**	**-59291**	**1646190**	**1747025**	**-100835**
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	**1073506**	**1206597**	**-133090**	**1413535**	**1610368**	**-196833**
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	**665312**	**969572**	**-304260**	**887863**	**1297738**	**-409875**
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	653724	839694	-185970	888059	1236020	-347961
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	11588	0	11588	-196	0	-196
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	129878	-129878	0	61718	-61718
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	**408194**	**237025**	**171170**	**525672**	**312631**	**213042**
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	741	44	697	1613	184	1429
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	393	1536	-1143	329	3313	-2984
1.अ.ख.3 परिवहन	44312	41058	3254	70702	82770	-12068
1.अ.ख.4 यात्रा	16819	22896	-6077	20740	38617	-17877
1.अ.ख.5 निर्माण	5482	5199	283	4482	5418	-937
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	4719	4125	594	6801	3218	3583
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	9166	10220	-1054	12147	11313	834
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	1737	15356	-13619	1454	18944	-17489
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	200979	28494	172485	252989	30162	222827
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	97117	93634	3484	126651	104321	22330
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	5300	6397	-1096	7300	9206	-1906
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	1158	1759	-601	1201	2035	-834
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं है	20269	6308	13962	19262	3129	16133
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	**37682**	**101406**	**-63724**	**54193**	**117326**	**-63133**
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	12045	5252	6793	12145	6049	6096
1.आ.2 निवेश आय	19106	94405	-75299	32373	100933	-68559
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	9937	57123	-47186	24116	61632	-37516
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	203	11901	-11699	602	11973	-11371
1.आ.2.3 अन्य निवेश	886	25372	-24486	721	27299	-26578
1.आ.2.4 रिज़र्व आस्तियां	8080	10	8071	6935	29	6906
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	6530	1748	4782	9674	10344	-670
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	**152526**	**15003**	**137523**	**178462**	**19331**	**159131**
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	152400	13125	139275	178313	17700	160613
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	147403	9500	137903	172602	12613	159989
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	4997	3625	1372	5711	5086	624
1.इ.2 सामान्य सरकार	126	1878	-1752	149	1631	-1482
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	**1393**	**1673**	**-280**	**1836**	**1303**	**533**
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	636	278	358	879	220	660
2.2 पूँजी अंतरण	757	1395	-638	957	1084	-127
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	**1184395**	**1119643**	**64752**	**1368137**	**1261119**	**107018**
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	**112193**	**92670**	**19523**	**183534**	**79893**	**103640**
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	99699	57788	41911	175144	45346	129797
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	95272	57537	37735	158539	38945	119594
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	62338	57537	4801	119205	38945	80260
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	32935	0	32935	39334	0	39334
3.1.अ.2 ऋण लिखत	4427	251	4176	16605	6401	10203
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	4427	251	4176	16605	6401	10203
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	12493	34882	-22389	8390	34547	-26157
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	12493	14216	-1723	8390	22395	-14005
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	12493	8726	3767	8390	16040	-7650
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	5490	-5490	0	6355	-6355
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	20666	-20666	0	12153	-12153
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	20666	-20666	0	12153	-12153
3.2 संविभाग निवेश	**676402**	**623338**	**53063**	**531986**	**646450**	**-114463**
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	674196	614505	59691	528521	636017	-107496
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	593588	537019	56569	470586	569008	-98422
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	80608	77487	3122	57935	67009	-9074
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	2206	8833	-6628	3465	10433	-6968
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिज़र्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	**19402**	**35925**	**-16523**	**34822**	**55690**	**-20868**
3.4 अन्य निवेश	**376398**	**343008**	**33391**	**497250**	**479086**	**18164**
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	84291	86651	-2360	101664	104634	-2970
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	1565	0	1565	347	4514	-4167
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	82726	86651	-3925	101318	100121	1197
3.4.2.3 सामान्य सरकार			0	0	0	0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र			0	0	0	0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	163138	119653	43484	218623	214684	3939
3.4.3अ भारत को ऋण	158092	114067	44025	214662	211760	2902
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	5045	5586	-540	3961	2925	1037
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	198	313	-116	300	131	169
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	67291	84390	-17099	138447	87134	51313
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	61481	52000	9481	38216	72502	-34286
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	0	0	0	0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	**0**	**24702**	**-24702**	**120545**	**0**	**120545**
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण			0	0	0	
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए			0	0	0	
3.5.3 आईएमएफ में रिज़र्व निधियों की स्थिति एन.ए			0	0	0	
3.5.4 अन्य रिज़र्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	24702	-24702	120545	0	120545
4. कुल आस्तियां / देयताएं	**1184395**	**1119643**	**64752**	**1368137**	**1261119**	**107018**
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	723159	653844	69315	676102	696601	-20499
4.2 ऋण लिखत	399754	389097	10657	533274	492016	41258
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	61481	76702	-15221	158761	72502	86259
5. निवल भूल-चूक	**0**	**5180**	**-5180**	**0**	**6716**	**-6716**

टिप्पणी: पीः प्रारंभिक

सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	वित्तीय वर्ष/समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2021-22		2021				2022	
			मार्च		दिसं.		मार्च	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.1 इक्विटी पूंजी और पुनर्निवेशित अर्जन	132765	493987	122726	456947	130904	487895	132765	493987
1.2 अन्य पूंजी	78807	27694	71203	25177	77192	26301	78807	27694
1 विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	211573	521681	193929	482125	208096	514196	211573	521681
2.1 इक्विटी	1110	156381	2340	177278	6113	172794	1110	156381
2.2 ऋण	9533	105994	5596	101232	3603	104286	9533	105994
2 संविभाग निवेश	10642	262375	7936	278510	9716	277080	10642	262375
3.1 व्यापार ऋण	18603	118156	5644	100329	12891	113450	18603	118156
3.2 ऋण	10474	205023	13335	197527	8856	204063	10474	205023
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	42081	140994	42436	143760	34796	143502	42081	140994
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	19918	32203	19191	12384	19946	29833	19918	32203
3 अन्य निवेश	91075	496377	80606	454000	76489	490849	91075	496377
4 रिज़र्व्स	607309		576984		633614		607309	
5 कुल आस्तियां/देयताएं	920599	1280433	859454	1214634	927915	1282125	920599	1280433
6 आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)	-359834		-355180		-354210		-359834	

नोट: * इक्विटी पूंजी में निवेश निधि का हिस्सा और पुनर्निवेशित आय शामिल है।

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक – भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि. व 2020-21	2021	2022		वि.व 2020-21	2021	2022	
		जुला.	जून	जुला.		जुला.	जून	जुला.
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. निपटान प्रणाली								
वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 सीसीआईएल प्रचलित प्रणाली (1.1 से 1.3)	33.01	2.68	3.42	3.39	206873112	16798812	22912930	21126044
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.1.1 से 1.1.3)	12.22	0.98	1.32	1.33	142072939	11096031	15445511	14218681
1.1.1 आउटराईट	6.22	0.50	0.68	0.71	8793301	744621	844409	851204
1.1.2 रेपो	3.08	0.25	0.34	0.34	51015712	3802644	5627915	5764070
1.1.3 त्रि-पक्षीय रिपो	2.92	0.24	0.30	0.28	82263926	6548766	8973188	7603407
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	19.91	1.64	1.97	1.93	59775826	5290626	6778125	6272728
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @	0.88	0.07	0.13	0.13	5024347	412155	689294	634635
बी. भुगतान प्रणाली								
I वित्तीय बाजार आधार-संरचना (एफएमआई)	–	–	–	–	–	–	–	–
1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)	2078.39	167.65	194.42	189.26	128657516	10741314	12356054	11551440
1.1 ग्राहक लेनदेन	2063.73	166.43	193.18	188.06	113319292	9288984	10840909	9927091
1.2 इंटरबैंक लेनदेन	14.66	1.22	1.24	1.20	15338225	1452331	1515145	1624349
II खुदरा								
2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.6)	577934.74	41372.72	69921.27	74673.64	42728006	3215234	4298158	4267239
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण) @	9.76	1.03	0.62	0.68	575	61	37	40
2.2 एपीबीएस $	12573.33	1047.34	1222.24	1259.99	133345	7981	23010	12511
2.3 आईएमपीएस	46625.25	3524.64	4557.01	4608.30	4171037	311310	443776	444541
2.4 एनएसीएच जमा $	18757.82	1174.68	1489.99	1892.88	1281685	85697	100909	119677
2.5 एनईएफटी	40407.29	3170.00	4022.33	4018.39	28725463	2204303	2716013	2627354
2.6 यूपीआई @	459561.30	32455.02	58629.08	62893.40	8415900	605883	1014413	1063117
2.6.1 जिसमें से यूएसएसडी@	11.99	1.08	0.99	1.62	177	16	12	18
3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.3)	12189.49	986.32	1225.96	1217.97	1034444	86503	100325	100581
3.1 भीम आधार पे @	227.73	17.49	39.82	21.26	6113	414	1049	621
3.2 एनएसीएच नामे $	10754.74	877.08	1048.14	1067.05	1026641	85980	99060	99754
3.3 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @	1207.02	91.75	138.00	129.66	1689	109	216	207
4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)	61782.93	5225.86	5376.24	5481.80	1701851	135972	169669	180371
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)	22398.82	1820.49	2279.46	2348.34	971638	74885	108752	115856
4.1.1 पीओएस आधारित $	11124.59	900.27	1210.51	1220.69	380643	30498	40466	41767
4.1.2 अन्य $	11274.23	920.21	1068.95	1127.64	590994	44387	68286	74089
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)	39384.11	3405.37	3096.79	3133.47	730213	61087	60917	64515
4.2.1 पीओएस आधारित $	22967.10	1901.64	2012.90	2053.40	451550	36764	39877	41211
4.2.2 अन्य $	16417.00	1503.73	1083.89	1080.07	278663	24324	21040	23304
5 प्रीपेड भुगतान लिखत (5.1 से 5.2)	65782.75	4958.99	6258.03	6195.34	279416	20587	24738	25309
5.1 वालेट	53013.86	4068.85	4979.19	4855.87	220183	16624	18488	18775
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)	12768.89	890.14	1278.83	1339.48	59233	3963	6250	6534
5.2.1 पीओएस आधारित $	1116.16	73.49	87.22	85.43	19546	893	1301	1285
5.2.2 अन्य $	11652.73	816.64	1191.62	1254.05	39687	3070	4949	5250
6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)	6999.12	596.11	593.72	588.67	6650333	553256	599196	579727
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	6999.12	596.11	593.72	588.67	6650333	553256	599196	579727
6.2 अन्य	0.00	–	–	–	–	–	–	–
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	724689.03	53139.99	83375.21	88157.42	52394049	4011553	5192086	5153226
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	726767.42	53307.64	83569.63	88346.69	181051565	14752867	17548140	16704666
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	719768.30	52711.53	82975.91	87758.02	174401233	14199611	16948944	16124940

भाग II - भुगतान के प्रकार तथा चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि. व. 2021-22	2021	2022		वि. व. 2021-22	2021	2022	
		जुला.	जून	जुला.		जुला.	जून	जुला.
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. अन्य भुगतान चैनल								
1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)	507531.37	36837.05	62581.28	68450.73	14973395	1137233	1715115	1786611
1.1 इंट्रा-बैंक $	40805.69	3133.94	4309.58	4902.42	2726360	210685	305131	323926
1.2 इंटर-बैंक $	466725.68	33703.12	58271.69	63548.30	12247035	926547	1409985	1462684
2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)	40726.59	3474.33	3551.14	3734.46	83159996	6812775	8205044	7325646
2.1 इंट्रा-बैंक @	9583.32	828.56	866.17	930.32	52142582	4294238	5134748	4438066
2.2 इंटर-बैंक @	31143.27	2645.77	2684.67	2804.13	31017413	2518538	3070297	2887580
बी. एटीएम								
3 एटीएम से नकद निकासी (3.1 से 3.3)	65287.63	5378.82	5734.36	5777.88	3111948	254886	271368	272103
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना $	62.37	4.74	6.79	6.95	3130	235	336	342
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना $	64898.80	5348.70	5694.37	5735.52	3097741	253780	269936	270609
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना $	326.45	25.38	33.20	35.42	11076	871	1096	1152
4 पीओएस पर नकद निकासी $ (4.1 से 4.2)	91.17	7.45	2.30	2.26	728	62	22	22
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना $	79.42	6.15	2.27	2.25	557	43	22	22
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना $	11.75	1.30	0.03	0.01	171	19	0	0
5 माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @	11126.04	869.89	1167.16	1082.22	299776	22973	31318	29517
5.1 एईपीएस @	11126.04	869.89	1167.16	1082.22	299776	22973	31318	29517

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	मई 2022 तक	2021	2022	
		जुला.	जून	जुला.
	1	2	3	4
भुगतान प्रणाली अवसंरचना				
1 कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)	9912.93	9690.43	10004.74	10083.90
1.1 क्रेडिट कार्ड	736.27	634.14	787.23	802.56
1.2 डेबिट कार्ड	9176.66	9056.29	9217.52	9281.34
2 पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)	15553.69	13176.84	15589.89	15604.53
2.1 वालेट @	12787.93	11032.89	12932.46	12922.65
2.2 कार्ड @	2765.76	2143.95	2657.43	2681.89
3 एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)	2.52	2.40	2.53	2.54
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम $	2.20	2.13	2.20	2.20
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम $	0.31	0.27	0.33	0.34
4 माइक्रो एटीएम की संख्या @	7.81	4.75	9.40	9.64
5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या	60.70	46.08	65.91	68.19
6 भारत क्यूआर @	49.72	42.51	42.80	45.21
7 यूपीआई क्यूआर *	1727.34	1078.80	1951.71	2013.02

@: नवंबर 2019 से नया समावेश

$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा।

* सितंबर 2020 से नया समावेश; केवल स्थिर यूपीआई क्यूआर कोड़ शामिल है।

नोट: 1. डेटा अनंतिम है।

2. 31 जनवरी 2020 से ईसीस (डेबिट और क्रेडिट) एनएसीएच के साथ मिल दिया गया है।

3. कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा के परिभाषाओं में संशोधन के साथ अधिक ग्रेन्युलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।

4. केवल घरेलू वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन लिया जाता है; फास्ट टैग लेनदेन; डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि। इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सपायर्ड कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।

अवसरिक श्रृंखला

सं. 44: लघु बचत

(करोड़ ₹)

योजना		2020-21	2021		2022	
			फर.	दिसं.	जन.	फर.
		1	2	3	4	5
1. लघु बचत	**प्राप्तियां**	**181237**	**14405**	**18175**	**14893**	**13932**
	बकाया	**1259585**	**1224772**	**1397878**	**1412766**	**1426737**
1.1 कुल जमाराशियां	**प्राप्तियां**	**132687**	**10143**	**13855**	**10676**	**9753**
	बकाया	**867494**	**847119**	**969847**	**980523**	**990274**
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	39748	2252	4475	3018	3568
	बकाया	205888	194738	226701	229719	233287
1.1.2 एमजीएनआरईजी	प्राप्तियां					
	बकाया					
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	276	-23	-366	-15	-20
	बकाया	3419	3037	3200	3185	3165
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	166	57	2	-1	-777
	बकाया	175	40	150	149	-628
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	12211	1135	1228	1146	933
	बकाया	221379	220277	232747	233892	234825
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004	प्राप्तियां	21009	1950	1929	1615	1490
	बकाया	97051	94750	114134	115749	117239
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	41470	3798	3926	3438	3217
	बकाया	207557	203597	241034	244474	247690
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	108205	107099	116043	116819	117578
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	7473	7418	7931	7967	7996
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	7227	7267	6983	6964	6944
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	84652	81813	110077	112724	115172
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	17807	974	2662	1475	1338
	बकाया	132029	130683	151885	153359	154697
1.1.9 डाक घर सावधि मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	0	0	-1	0	4
	बकाया	-25	-24	-25	-25	-22
1.1.10 अन्य जमाराशियां	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	21	21	21	21	21
1.2 बचत प्रमाणपत्र	**प्राप्तियां**	**34860**	**3647**	**3978**	**3691**	**3583**
	बकाया	**286863**	**282483**	**321027**	**324713**	**328337**
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	17361	1843	1860	1626	1585
	बकाया	135348	133016	150513	152139	153724
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	-3	0	0	0	0
	बकाया	159	157	158	158	158
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	-7911	-470	-426	-193	940
	बकाया	-6776	-6194	-8455	-8648	-7708
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	25340	2274	2544	2258	1019
	बकाया	147942	145422	168720	170978	171996
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	प्राप्तियां	41	0	0	0	23
	बकाया	-114	-147	-114	-114	-90
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	प्राप्तियां	32	0	0	0	16
	बकाया	-74	-103	-74	-74	-58
1.2.7 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	10378	10332	10279	10274	10315
1.3 लोक भविष्य निधि	**प्राप्तियां**	**13690**	**615**	**342**	**526**	**596**
	बकाया	**105228**	**95170**	**107004**	**107530**	**108126**

स्रोत : महालेखाकार, पोस्ट और टेलीग्राफ।

टिप्पणी : अप्रैल 2017 से प्राप्तियों का डाटा निवल प्राप्तियाँ हैं। अर्थात सकल प्राप्तियाँ माइनस सकल भुगतान

सं. 45: केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2021			2022	
	जून	सितं	दिसं.	मार्च	जून
	1	2	3	4	5
(क) कुल (₹ करोड़ में)	**7882533**	**8235318**	**8439811**	**8529036**	**8784931**
1. वाणिज्यिक बैंक	35.99	37.82	35.40	37.75	38.04
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.34	0.35	0.27	0.29	0.33
3. बीमाकृत कंपनियां	25.83	24.18	25.74	25.89	26.34
4. म्यूच्युअल फंड	2.82	2.91	3.08	2.91	2.32
5. सहकारी बैंक	1.82	1.50	1.82	1.81	1.84
6. वित्तीय संस्थाएं	1.43	1.17	1.69	0.94	1.09
7. कॉरपोरेट	1.39	0.72	1.37	1.47	1.52
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	1.79	1.81	1.66	1.56	1.43
9. भविष्य निधियां	4.04	3.77	4.33	4.60	4.77
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	17.11	16.98	16.92	16.62	16.06
11. अन्य	7.43	8.79	7.73	6.15	6.30
11.1 राज्य सरकार	1.67	1.67	1.69	1.82	1.84

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2021			2022	
	जून	सितं	दिसं.	मार्च	जून
	1	2	3	4	5
(ख) कुल (₹ करोड़ में)	**4028849**	**4153508**	**4257578**	**4410250**	**4472011**
1. वाणिज्यिक बैंक	33.75	35.94	34.41	34.39	34.22
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.39	0.44	0.40	0.38	0.41
3. बीमाकृत कंपनियां	29.67	27.50	28.85	28.42	28.39
4. म्यूच्युअल फंड	1.74	1.97	1.91	1.82	1.89
5. सहकारी बैंक	4.12	3.60	4.07	4.04	4.06
6. वित्तीय संस्थाएं	1.79	1.72	1.73	1.72	1.73
7. कॉरपोरेट	1.45	1.32	1.70	1.82	1.98
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02
9. भविष्य निधियां	21.09	18.27	20.66	20.79	20.52
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.88	0.85	0.83	0.80	0.79
11. अन्य	5.10	8.38	5.40	5.81	5.99
11.1 राज्य सरकार	0.18	0.18	0.19	0.20	0.21

खज़ाना बिल					
श्रेणी	2021			2022	
	जून	सितं	दिसं.	मार्च	जून
	1	2	3	4	5
(ग) कुल (₹ करोड़ में)	**901327**	**763582**	**692869**	**757198**	**1022053**
1. वाणिज्यिक बैंक	52.25	50.22	47.01	51.14	53.14
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	1.82	1.33	1.53	4.20	2.49
3. बीमाकृत कंपनियां	4.75	4.12	6.29	6.58	5.34
4. म्यूच्युअल फंड	19.93	17.72	13.72	14.01	14.86
5. सहकारी बैंक	1.60	1.32	1.49	1.79	1.34
6. वित्तीय संस्थाएं	2.56	2.12	2.36	3.53	3.73
7. कॉरपोरेट	3.00	2.40	3.13	3.47	4.27
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.00	0.15	0.72	0.49	0.40
9. भविष्य निधियां	0.10	0.37	0.85	0.21	1.70
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	2.58	2.63	0.00	0.00	0.00
11. अन्य	11.42	17.62	22.89	14.59	12.72
11.1 राज्य सरकार	7.97	12.64	18.92	11.54	10.99

सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(करोड़ ₹)

मद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (सं.अ.)	2021-22 (ब.अ.)
	1	2	3	4	5	6
1. कुल वितरण	**4265969**	**4515946**	**5040747**	**5410887**	**6523916**	**7160694**
1.1 गतिविधियां	2537905	2635110	2882758	3074492	3906147	4254004
1.1.1 राजस्व	1878417	2029044	2224367	2446605	3259401	3242247
1.1.2 पूंजी	501213	519356	596774	588233	636062	922982
1.1.3 ऋण	158275	86710	61617	39654	10684	88775
1.2 गैर गतिविधियां	1672646	1812455	2078276	2253027	2526514	2810847
1.2.1 राजस्व	1555239	1741432	1965907	2109629	2334608	2602289
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	724448	814757	894520	955801	1082302	1244457
1.2.2 पूंजी	115775	69370	111029	141457	189487	177328
1.2.3 ऋण	1632	1654	1340	1941	2419	31230
1.3 अन्य	55417	68381	79713	83368	91255	95843
2. कुल प्राप्तियां	**4288432**	**4528422**	**5023352**	**5734166**	**6489736**	**7039032**
2.1 राजस्व प्राप्तियां	3132201	3376416	3797731	3851563	3834126	4682025
2.1.1 कर प्राप्तियां	2622145	2978134	3278947	3231582	3175594	3829889
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	1652377	1853859	2030050	2012578	2100982	2514708
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	965622	1121189	1246083	1216203	1071552	1311449
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	4146	3086	2814	2800	3060	3732
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	510056	398282	518783	619981	658532	852135
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	33220	34224	36273	31137	39830	33198
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	69063	142433	140287	110094	54861	201138
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	20942	42213	44667	59515	21151	19581
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	48122	100219	95621	50578	33710	181557
3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	**1064704**	**997097**	**1102729**	**1449230**	**2634928**	**2277532**
3 क वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	1046708	989167	1097210	1440548	2580406	2276017
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	617123	144792	387091	571872	890012	-----
3क.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	195816	-144847	325987	190241	107494	-----
3क.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	429585	844375	710119	868676	1690394	-----
3क.2 बाह्य वित्तपोषण	17997	7931	5519	8682	54522	1514
3ख. वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	1046708	989167	1097210	1440548	2580406	2276017
3ख.1.1 बाज़ार उधार (निवल)	689821	794856	795845	971378	1778062	1620936
3ख.1.2 लघु बचत (निवल)	35038	71222	88961	209232	455724	367863
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	45688	42351	51004	38280	47300	45504
3ख.1.4 आरक्षित निधियां	-6436	18423	-18298	10411	-3450	5051
3ख.1.5 जमाराशियां और अग्रिम	17792	25138	66289	-14227	29050	28868
3ख.1.6 नकद शेष	-22463	-12476	17395	-323279	34179	121663
3ख.1.7 अन्य	287268	49653	96014	548753	239540	86132
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	17997	7931	5519	8682	54522	1514
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल वितरण	*27.7*	*26.4*	*26.7*	*26.6*	*33.0*	*32.1*
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल प्राप्तियां	*27.9*	*26.5*	*26.6*	*28.2*	*32.9*	*31.6*
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर राजस्व प्राप्तियां	*20.3*	*19.8*	*20.1*	*18.9*	*19.4*	*21.0*
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कर प्राप्तियां	*17.0*	*17.4*	*17.4*	*15.9*	*16.1*	*17.2*
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर सकल वित्तीय घाटा	*6.9*	*5.8*	*5.8*	*7.1*	*13.3*	*10.2*

…: उपलब्ध नहीं। सं.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बज़ट अनुमान

स्रोत : केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज

सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जुला. 2022 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
	1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	745.17	31	1842.24	29	2179.68	16
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	-	-	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-
6	गोवा	-	-	-	-	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	-	-	-	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	414.62	17	357.80	3
10	जम्मू और कश्मीर	-	-	914.12	22	559.26	11
11	झारखंड	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	-	-	-	-	-	-
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-
16	मणिपुर	12.29	27	181.79	27	512.95	12
17	मेघालय	111.14	20	89.07	13	-	-
18	मिज़ोरम	68.09	23	145.85	17	181.54	11
19	नगालैंड	120.32	27	186.51	25	157.92	16
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	714.60	30	-	-	-	-
23	राजस्थान	4859.53	31	-	-	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	717.36	31	1369.32	30	988.22	18
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
27	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-
28	उत्तरप्रदेश	-	-	-	-	-	-
29	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

सं. 48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य /संघ शासित प्रदेश	जुला. 2022 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलामी ख़ज़ाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	9556	945	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	2081	3	0	0
3	असम	3512	72	0	0
4	बिहार	6477	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	5703	0	1	4308
6	गोवा	788	380	0	0
7	गुजरात	8368	554	0	1000
8	हरियाणा	1404	1405	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0
11	झारखंड	997	0	0	0
12	कर्नाटक	10656	0	0	38746
13	केरल	2476	0	0	0
14	मध्य प्रदेश	0	1059	0	0
15	महाराष्ट्र	53921	1169	0	18000
16	मणिपुर	177	116	0	0
17	मेघालय	904	63	9	0
18	मिज़ोरम	449	55	0	0
19	नगालैंड	1899	38	0	0
20	उड़ीसा	15069	1697	98	43400
21	पुदुचेरी	389	0	0	923
22	पंजाब	4192	0	0	0
23	राजस्थान	0	0	129	6400
24	तमिलनाडु	7725	0	28	9182
25	तेलंगाना	6527	1427	0	0
26	त्रिपुरा	702	15	0	1600
27	उत्तराखंड	3087	0	116	0
28	उत्तरप्रदेश	3968	156	0	0
29	पश्चिम बंगाल	10387	721	235	0
	कुल	**161413**	**9874**	**614**	**123559**

सं. 49: राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां

(करोड़ ₹)

क्र. सं.	राज्य	2020-21		2021-22		2022-23						2022-23 में अब तक कुल राशि उठाई गई है	
						मई		जून		जुलाई			
		सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल	निवल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आंध्र प्रदेश	50896	41915	46443	36692	7390	6810	10500	9630	8000	7130	29890	26265
2	अरुणाचल प्रदेश	767	767	563	530	-	-	-	-	-	-20	-	-20
3	असम	15030	14230	12753	10753	-	-	2000	2000	2000	2000	4000	4000
4	बिहार	27285	24685	28489	24334	-	-750	-	-	-	-	-	-750
5	छत्तीसगढ़	13000	10500	4000	913	-	-	-	-	-	-	-	-
6	गोवा	3354	3054	2000	1450	-	-	100	100	-	-	100	100
7	गुजरात	44780	33280	31054	13554	-	-3000	4000	2500	4500	3300	8500	2800
8	हरियाणा	30000	25550	30500	20683	3000	1000	8000	5625	4000	2745	15000	8720
9	हिमाचल प्रदेश	6000	3755	4000	1875	-	-	-	-430	1000	570	1000	140
10	जम्मू और कश्मीर	9328	6020	8562	5373	1000	1000	-	-	1250	750	2250	1750
11	झारखंड	9400	8900	5000	3191	-	-	-	-200	-	-	-	-200
12	कर्नाटक	69000	61900	59000	49000	-	-	-	-	-	-	-	-
13	केरल	28566	23066	27000	18120	-	-1000	1500	1500	-	-1000	1500	-1500
14	मध्य प्रदेश	45573	38773	22000	13900	-	-	2000	2000	-	-	2000	2000
15	महाराष्ट्र	69000	50022	68750	40790	16000	13500	10000	3500	-	-1800	30000	19200
16	मणिपुर	1302	1044	1476	1326	250	250	150	150	250	190	650	515
17	मेघालय	1777	1587	1608	1298	-	-	200	200	200	150	400	350
18	मिज़ोरम	944	677	747	447	150	150	100	100	90	90	340	275
19	नगालैंड	1721	1366	1727	1222	-	-	400	400	250	250	650	650
20	उड़ीसा	3000	500	0	-6473	-	-	-	-1000	-	-	-	-2500
21	पुदुचेरी	1390	790	1374	841	-	-	-	-	200	200	200	200
22	पंजाब	32995	23467	25814	12428	1500	800	-	-1742	5100	4100	8100	3558
23	राजस्थान	57359	44273	51149	38243	3500	3000	6500	3688	5000	4000	15000	10688
24	सिक्किम	1292	1292	1511	1471	-	-	-	-	150	150	150	150
25	तमिलनाडु	87977	76796	87000	72500	-	-622	8000	6150	8000	6500	16000	12028
26	तेलंगाना	43784	37365	45716	38667	-	-420	7000	6370	5000	4370	12000	9375
27	त्रिपुरा	1916	1631	300	0	-	-	-	-125	-	-	-	-125
28	उत्तराखंड	75500	59185	62500	42355	-	-1500	-	-2733	-	-1000	-	-5233
29	उत्तरप्रदेश	6200	5208	3200	1800	-	-	-	-	-	-	-	-
30	पश्चिम बंगाल	59680	50180	67390	45199	2500	-	5000	4500	8000	6500	15500	8500
	कुल	798816	651777	701626	492483	35290	19218	65450	42183	52990	39175	163230	100936

- : शून्य

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

सं. 50 (ए): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार

(राशि करोड़ में)

मद	2019-20				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	**238613.6**	**476724.8**	**386450.4**	**530769.8**	**1632558.5**
जीडीपी का प्रतिशत	*4.8*	*9.8*	*7.5*	*10.3*	*8.1*
I. वित्तीय आस्तियां	**398076.7**	**567753.2**	**517351.0**	**924069.3**	**2407250.2**
जीडीपी का प्रतिशत	*8.1*	*11.7*	*10.1*	*18.0*	*12.0*
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	12239.0	296625.6	124015.7	451698.3	884578.5
(ए) बैंक जमाराशि	-10550.9	278124.4	116211.9	444044.6	827830.0
i. वाणिज्यिक बैंक	-13293.8	269475.4	66666.7	446006.7	768855.0
ii. सहकारी बैंक	2742.9	8649.0	49545.2	-1962.1	58975.0
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	22789.9	18501.2	7803.7	7653.7	56748.5
2. जीवन बीमा निधियाँ	117873.1	108209.1	110373.8	37714.2	374170.2
3. भविष्य और पेंशन फंड (पीपीएफ़ सहित)	104681.1	98426.3	103356.1	193739.0	500202.5
4. मुद्रा	61244.1	-26104.8	86832.6	160690.2	282662.1
5. निवेश	43936.8	43018.8	22655.1	-11953.8	97656.9
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	23303.5	38382.2	19191.1	-19191.1	61685.7
(बी) इक्विटि	18648.2	2172.4	936.2	4981.0	26737.8
6. छोटी बचत (पीपीएफ़ छोड़ कर)	57038.5	46514.1	69053.6	91117.2	263723.4
II. वित्तीय देयताएँ	**159463.1**	**91028.5**	**130900.6**	**393299.5**	**774691.7**
जीडीपी का प्रतिशत	*3.2*	*1.9*	*2.6*	*7.7*	*3.9*
ऋण (उधार)					
1. वित्तीय कार्पोरेशन (ए+बी)	159429.6	90994.9	130867.1	393266.0	774557.6
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	140261.4	58074.4	114905.9	196581.1	509822.8
जिसमें :					
वाणिज्यिक बैंक	135754.1	57135.0	87377.4	202214.2	482480.6
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	19168.2	32920.5	15961.2	196684.8	264734.8
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	-519.7	22976.7	29930.7	198264.3	250652.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	17033.0	8093.1	-15710.4	-3093.1	6322.6
iii. बीमा कंपनियाँ	2655.0	1850.8	1740.9	1513.6	7760.2
2. गैर-वित्तीय कार्पोरेशन (निजी कॉर्पोरेट व्यापार)	33.8	33.8	33.8	33.8	135.1
3. सामान्य सरकार	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-1.0

सं. 50 (ए): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार *(जारी..)*

(राशि करोड़ में)

मद	2020-21				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	**600422.5**	**573643.2**	**481433.5**	**719844.5**	**2375343.7**
जीडीपी का प्रतिशत	*15.5*	*12.1*	*8.8*	*12.5*	*12.0*
I. वित्तीय आस्तियां	**805869.5**	**612224.3**	**651241.3**	**1092617.4**	**3161952.5**
जीडीपी का प्रतिशत	*20.8*	*13.0*	*12.0*	*19.0*	*16.0*
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	297412.4	278631.7	158172.2	525550.7	1259767.1
(ए) बैंक जमाराशि	281191.3	264565.3	147096.0	527056.7	1219909.2
i. वाणिज्यिक बैंक	279010.5	262033.7	143558.6	471730.9	1156333.7
ii. सहकारी बैंक	2180.8	2531.6	3537.3	55325.8	63575.6
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	16221.1	14066.4	11076.3	-1506.0	39857.9
2. जीवन बीमा निधियाँ	123291.4	142365.7	156438.6	141120.0	563215.8
3. भविष्य और पेंशन फंड (पीपीएफ़ सहित)	119666.9	110916.6	108512.2	207604.5	546700.1
4. मुद्रा	202432.7	21286.9	91456.0	66800.5	381976.1
5. निवेश	6249.8	-12956.4	67659.3	63624.0	124576.7
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	-16021.0	-28837.7	57675.4	51267.0	64083.8
(बी) इक्विटि	18599.4	8291.5	5307.1	6333.3	38531.2
6. छोटी बचत (पीपीएफ़ छोड़ कर)	55760.7	70924.2	67947.4	86862.2	281494.6
II. वित्तीय देयताएँ	**205447.0**	**38581.1**	**169807.8**	**372772.9**	**786608.8**
जीडीपी का प्रतिशत	*5.3*	*0.8*	*3.1*	*6.5*	*4.0*
ऋण (उधार)					
1. वित्तीय कार्पोरेशन (ए+बी)	205490.3	38624.3	169851.0	372816.9	786782.5
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	211058.8	13213.0	139622.0	284732.6	648626.4
जिसमें :					
वाणिज्यिक बैंक	211259.3	13213.8	140514.3	242476.0	607463.5
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	-5568.6	25411.3	30229.0	88084.4	138156.1
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	-15450.4	21627.1	15921.2	61326.1	83424.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	10516.6	2875.1	13048.5	25336.1	51776.2
iii. बीमा कंपनियाँ	-634.8	909.2	1259.3	1422.2	2955.9
2. गैर-वित्तीय कार्पोरेशन (निजी कॉर्पोरेट व्यापार)	33.8	33.8	33.8	33.0	134.4
3. सामान्य सरकार	-77.0	-77.0	-77.0	-77.0	-308.0

सं. 50(ए): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार *(समाप्त)*

(राशि करोड़ में)

मद	2021-22				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	**519781.2**	**358325.2**	**453302.7**	**636259.8**	**1967668.9**
जीडीपी का प्रतिशत	*10.1*	*6.4*	*7.2*	*9.6*	*8.3*
I. वित्तीय आस्तियां	**382780.7**	**547346.2**	**834009.6**	**796341.7**	**2560478.2**
जीडीपी का प्रतिशत	*7.5*	*9.7*	*13.2*	*12.0*	*10.8*
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	-84377.1	202652.1	425821.4	151374.9	695471.4
(ए) बैंक जमाराशि	-106507.3	197301.2	422819.5	140297.2	653910.7
i. वाणिज्यिक बैंक	-108037.7	195617.4	418642.9	145510.5	651733.1
ii. सहकारी बैंक	1530.4	1683.8	4176.7	-5213.3	2177.6
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	22130.2	5350.9	3001.9	11077.7	41560.7
2. जीवन बीमा निधियाँ	114617.8	127356.0	103154.9	95681.7	440810.4
3. भविष्य और पेंशन फंड (पीपीएफ़ सहित)	126469.7	108777.0	91543.9	254877.2	581667.9
4. मुद्रा	128660.2	-68631.2	62793.3	146845.0	269667.4
5. निवेश	24929.6	82305.4	69760.9	50980.8	227976.7
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	14573.0	63151.3	37912.2	44963.7	160600.1
(बी) इक्विटि	4502.5	13218.5	27808.2	3084.1	48613.3
6. छोटी बचत (पीपीएफ़ छोड़ कर)	71423.1	93829.6	79877.9	95524.7	340655.3
II. वित्तीय देयताएँ	**-137000.5**	**189021.0**	**380706.9**	**160081.8**	**592809.2**
जीडीपी का प्रतिशत	*-2.7*	*3.4*	*6.0*	*2.4*	*2.5*
ऋण (उधार)					
1. वित्तीय कार्पोरेशन (ए+बी)	-137021.8	188999.7	380685.6	160060.6	592724.1
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	-113662.5	134166.1	320160.2	153323.3	493987.0
जिसमें :					
वाणिज्यिक बैंक	-108061.2	135728.8	317452.5	152364.2	497484.4
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	-23359.3	54833.7	60525.5	6737.3	98737.1
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	-31118.4	28880.1	29479.8	-31016.3	-3774.8
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	7132.0	24403.8	29494.8	37436.2	98466.8
iii. बीमा कंपनियाँ	627.1	1549.8	1550.9	317.4	4045.2
2. गैर-वित्तीय कार्पोरेशन (निजी कॉर्पोरेट व्यापार)	33.8	33.8	33.8	33.8	135.1
3. सामान्य सरकार	-12.5	-12.5	-12.5	-12.5	-50.0

टिप्पणियां: 1. हाउसहोल्ड की निवल वित्तीय बचत निवल वित्तीय आस्तियों के प्रवाह को संदर्भित करती है, जो हाउसहोल्ड द्वारा धारित वित्तीय आस्तियों में परिवर्तन को घटाकर उनकी वित्तीय देयताओं में परिवर्तन को दर्शाती है।
2. छोटी बचत और पीपीएफ में संशोधन मुख्य रूप से लेखा महानियंत्रक, भारत सरकार के मासिक डेटा से प्राप्त तिमाही आंकड़ों के कारण होता है।
3. 2021-22 के लिए बैंक जमा में संशोधन का श्रेय बीएसआर-2 के अनुसार कुल जमा में हाउसहोल्ड की कम हिस्सेदारी को दिया जाता है।
4. जीडीपी के अनुपात के रूप में डेटा की गणना 31 मई, 2022 को जारी राष्ट्रीय आय 2021-22 के अनंतिम अनुमानों के आधार पर की गई है।
5. पूर्णांकन के कारण कॉलम में दिए गए आंकड़े कुल योग के बराबर नहीं हो सकते हैं।

सं. 50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक

(राशि करोड़ में)

मद	जून-2019	सितं-2019	दिसं-2019	मार्च-2020
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी)	**16315506.3**	**16632816.5**	**17010694.5**	**17180616.2**
जीडीपी का प्रतिशत	*84.7*	*85.4*	*86.2*	*85.6*
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	8858293.4	9136417.9	9252629.8	9696674.3
i. वाणिज्यिक बैंक	8131543.2	8401018.6	8467685.3	8913692.0
ii. सहकारी बैंक	726750.2	735399.2	784944.4	782982.3
(बी) जीवन बीमा निधि	3883609.7	3930727.6	4049902.5	3884771.5
(सी) मुद्रा	2010842.9	1984738.1	2071570.7	2232261.0
(डी) म्यूचुअल फंड	1404631.5	1412654.1	1468727.6	1197092.9
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	**6370092.6**	**6461087.5**	**6591954.6**	**6985220.6**
जीडीपी का प्रतिशत	*33.1*	*33.2*	*33.4*	*34.8*
ऋण (उधार)				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	5148115.0	5206189.4	5321095.3	5517676.4
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	4668496.4	4725631.3	4813008.7	5015222.9
ii. सहकारी बैंक	478956.2	479656.9	506946.6	501074.8
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	1221977.5	1254898.1	1270859.3	1467544.1
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	451922.3	474899.0	504829.7	703094.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	673312.1	681405.2	665694.8	662601.7

50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक *(जारी.)*

(राशि करोड़ में)

मद	जून-2020	सितं-2020	दिसं-2020	मार्च-2021
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी)	**18039169.4**	**18606364.4**	**19333484.1**	**20168953.3**
जीडीपी का प्रतिशत	*94.9*	*98.6*	*100.8*	*101.9*
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	9977865.6	10242430.9	10389526.9	10916583.6
i. वाणिज्यिक बैंक	9192702.5	9454736.2	9598294.8	10070025.7
ii. सहकारी बैंक	785163.1	787694.7	791232.1	846557.9
(बी) जीवन बीमा निधि	4102000.7	4274424.9	4551882.0	4718718.2
(सी) मुद्रा	2434693.7	2455980.6	2547436.6	2614237.0
(डी) म्यूचुअल फंड	1343752.0	1443784.4	1648999.0	1730461.0
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	**7190710.8**	**7229335.1**	**7399186.1**	**7772003.0**
जीडीपी का प्रतिशत	*37.8*	*38.3*	*38.6*	*39.3*
ऋण (उधार)				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	5728735.3	5741948.3	5881570.2	6166302.8
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	5226482.2	5239696.0	5380210.4	5622686.4
ii. सहकारी बैंक	500870.2	500865.3	499968.8	542221.2
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	1461975.5	1487386.9	1517615.9	1605700.3
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	687643.6	709270.7	725191.9	786518.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	673118.3	675993.4	689041.8	714377.9

50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक *(समाप्त)*

(राशि करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

मद	जून-2021	सितं-2021	दिसं-2021	मार्च-2022
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी)	**20508115.7**	**21057343.4**	**21673261.7**	**22104312.7**
जीडीपी का प्रतिशत	*97.4*	*95.9*	*95.0*	*93.4*
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	10810076.3	11007377.6	11430197.1	11570494.3
i. वाणिज्यिक बैंक	9961988.0	10157605.4	10576248.3	10721758.8
ii. सहकारी बैंक	848088.3	849772.1	853948.8	848735.5
(बी) जीवन बीमा निधि	4894238.5	5105262.1	5175997.5	5287980.3
(सी) मुद्रा	2742897.3	2674266.1	2737059.4	2883904.4
(डी) म्यूचुअल फंड	1855000.1	2064363.5	2126112.0	2152140.5
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	**7634981.2**	**7823980.9**	**8204666.6**	**8364727.1**
जीडीपी का प्रतिशत	*36.3*	*35.6*	*36.0*	*35.3*
ऋण (उधार)				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	6052640.2	6186806.3	6506966.5	6660289.7
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	5514625.2	5650354.1	5967806.6	6120170.8
ii. सहकारी बैंक	536604.9	535027.3	537720.1	538664.3
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	1582341.0	1637174.6	1697700.1	1704437.4
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	755399.6	784279.7	813759.5	782743.2
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	721510.0	745913.7	775408.5	812844.7

टिप्पणी: 1. डेटा को केवल चुनिंदा वित्तीय लिखतों के लिए संकलित किया गया है(बैंकिंग क्षेत्र, एनबीएफ़सी और एचएफ़सी से ऋण) जिसके लिए डेटा उपलब्ध है।
2. जीडीपी अनुपात के रूप में डेटा की गणना 28 फरवरी 2022 को जारी राष्ट्रीय आय 2021-22 के दूसरे अग्रिम अनुमान पर आधारित है।
3. हो सकता है कि कॉलम में दिए गए अंकों को पूर्णांकन के कारण कुल योग में न जोड़ा जाए।

वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1

1.2 और 6: वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।
3.5 और 3.7: वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।
4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।
4.5, 4.6 और 4.7 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।
4.10 से 4.12 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम निलामी दिन से संबंधित है।
4.13 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।
7.1 और 7.2: विदेशी व्यापार यूएस डॉलर से संबंधित है।

सारणी सं. 2

2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।
2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियों और अल्पावधि प्रतिभूतियों/बांडों सहित जैसे - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी।

सारणी सं. 4

http://nsdp.rbi.org.in के 'रिज़र्व टैम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉर्वर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5

अन्य को विशेष पुर्नवित्त सुविधा, अर्थात् एक्ज़िम बैंक को 31 मार्च 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6

अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकडे सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।

2.2 : आईएमएफ खाता सं.1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4: आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांड शामिल हैं।

सारणी सं. 8

एनएम$_2$ और एनएम$_3$ में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।
2.4: चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।
2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

सारणी सं. 9

वित्तीय सस्थांओं में एक्जिम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।
एल$_1$ और एल$_2$ मासिक आधार पर और एल$_3$ तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।
जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

सारणी सं. 13

कालम सं. (1) (2) और (3) में दर्शाये गए आंकडें अंतिम (आरआरबीसहित) और कालम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकडें अनंतिम (आरआरबी को छोड़कर) हैं।

सारणी सं. 14

कालम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकडें अनंतिम हैं।

सारणी सं. 17

2.1.1: राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।

2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।

4. : आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं. 24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं. 30

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।

1: बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।

2: संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

सारणी सं. 32

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांडों में निवेश तथा सार्क स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा और भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक को अतंरित एसडीआर शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिज़र्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास को शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रूपी-अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं. 34

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.1.4 : अनुमान

1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान

'अन्य पूंजी' एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी सस्थांओं/शाखाओं के बीच के ऋण सबंधी लेनदेन से संबंधित है।

हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय-अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान-संतुलन के आंकड़ो से मेल न खाएं।

सारणी सं. 35

1.10 : जर्नलों के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

सारणी सं. 36

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि या मूल्यह्रास का सकेंतक। 6-मुद्राओंवाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2018-19 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। इससे संबंधित कार्यपद्धति का विवरण बुलेटिन के दिसंबर 2005, अप्रैल 2014 और जनवरी 2021 के अंक में दिया गया है।

सारणी सं. 37

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

सारणी सं. 38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

सारणी सं. 43

भाग I- ए. भुगतान प्रणाली

1.1.3: प्रतिभूति खंड के अंतर्गत त्रिपक्षीय रेपो का परिचालन 05 नवंबर, 2018 से किया गया है।

भाग I-बी भुगतान प्रणाली

4.1.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

4.2.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड अंतरण और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध है।

5.1: माल और सेवाओं की खरीद और वॉलेट के माध्यम से निधि अंतरण शामिल है।

5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।

6.1: तीन ग्रिडों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।

6.2: अन्य 'में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल है जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन केंद्र से संबंधित है।

भाग II- ए अन्य भुगतान चैनल

1: मोबाइल भुगतान -
- बैंकों और यूपीआई ऐप के मोबाइल ऐप के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल है।
- जुलाई 2017 के डेटा में केवल व्यक्तिगत भुगतान और मोबाइल के माध्यम से पहल किए गए, संसाधित और अधिकृत किए गए कॉर्पोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल के माध्यम से शुरू नहीं किए गए है, संसाधित और अधिकृत नहीं हैं, को शामिल नहीं किया गया है।

2: इंटरनेट भुगतान --नेटबैंकिंग 'के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट से किया गया वित्तीय लेनदेन शामिल है।

भाग II-बी एटीएम

3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई से किए गए लेनदेन से संबंधित है।

भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना

3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) के एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलएओ को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया हैं।

सारणी सं. 45

(-): नगण्य को दर्शाता है।

जून 2016 से टेबल फार्मेट संशोधित किया है, जिसमें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों सहित राज्य सरकारों की स्वामित्ववाली प्रतिभूतियाँ और खज़ाना बिलों सहित शामिल है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्वल डिस्कॉ म एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बान्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इसका हिस्सा बहुत कम है।

"अन्य" श्रेणी में राज्य सरकारों, पेंशन निधियां न्यास, संस्थाएं, हिंदू अविभक्त परिवार / वैयक्तिक आदि. शामिल है।

सारणी सं. 46

वर्ष 2011-12 के आधार पर जीडीपी डेटा है। वर्ष 2019-20 का जीडीपी डेटा केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा 29 मई 2020 को जारी राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान से संबंधित है। वर्ष 2020-21 का जीडीपी डेटा केंद्रीय बज़ट 2020-21 से लिया गया है।
राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि व्यय को छोड़कर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय।
1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुन:चुकौती सहित) और राज्य सरकार के निवल चुकौती से संबंधित है।
1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।
2: यह डाटा केंद्र और राज्य सरकारों को दिये गये उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते है।
3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार है।
3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधारियां शामिल हैं।
3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष प्रतिभूतियों में किये गये निवल निवेश को दर्शाते है।
यह डेटा नए डेटा की उपलब्धता के साथ घटकों में समायोजन के कारण पिछले प्रकाशनों से भिन्न हो सकता है।
3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।
3बी.1.7: वित्तीय संस्थानों, बीमा और पेंशन निधि, प्रेषण, नकदी शेष निवेश लेखा से लिये गये ऋण, खज़ाना बिलों सहित।

सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और निलामी खज़ाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपाश्विक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू एमए) दिया जाता है।
राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।
प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।
-: नगण्य

सारणी सं. 48

समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।
नीलामी खज़ाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारो में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों की खज़ाना बिल शामिल हैं।
--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी संबंधी अवधारणाएं एवं कार्यप्रणालियां भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन के वर्तमान सांख्यिकी संबंधी व्यापक मार्गदर्शिका (**https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=17618**) में उपलब्ध हैं।

'वर्तमान सांख्यिकी' का टाइम सीरिज डाटा https://dbie.rbi.org.in पर उपलब्ध है।
विस्तृत टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों (जैसे **भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक**) में उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2022	₹350 एक प्रति (कांउटर पर) ₹400 एक प्रति (डाक प्रभार सहित) ₹4,800 (डाक प्रभार सहित एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) ₹3,600 (एक वर्ष रियायती दर*) ₹3,840 (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क - डाक प्रभार सहित@) ₹2,880 (एक वर्ष रियायती दर@)	15 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (डाक प्रभार सहित) 180 अमरीकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकीय हैंडबुक 2020-21	₹550 (सामान्य) ₹600 (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक 2020-21	₹600 (सामान्य) ₹650 (डाक प्रभार सहित) ₹450 (रियायती) ₹500 (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्त: 2021-22 के बजटों का अध्ययन	₹600 एक प्रति (कांउटर पर) ₹650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट 2021-22	₹575 एक प्रति (कांउटर पर) ₹625 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	22 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. रिपोर्ट ऑफ दि कमिटी ऑन फुलर कैपिटल अकांउट कन्वर्टिबिलिटी (तारापोर समिति की रिपोर्ट II)	₹140 एक प्रति (कांउटर पर) ₹170 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	25 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
7. बैंकिंग शब्दावली (2012)	₹80 एक प्रति (कांउटर पर) ₹120 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
8 अनुवाद के विविध आयाम (हिंदी)	₹165 एक प्रति (कांउटर पर) ₹205 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
9. बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयनः दशा और दिशा (हिंदी)	₹150 एक प्रति (कांउटर पर) ₹200 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
10. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 41, सं. 2, 2020	₹200 एक प्रति (कांउटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
11. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 42, सं. 1, 2021	₹200 एक प्रति (कांउटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
12. पर्सपेक्टिव्स ऑन सेंट्रल बैंकिंग गवर्नर्स; स्पीक (1935-2010) प्लैटिनम जुबिली	₹1400 एक प्रति (कांउटर पर)	50 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)

टिप्पणियां:

1. उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।
2. टाइम सीरीज़ डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (http://dbie.rbi.org.in)।
3. भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-1997 (4 खंड), वित्तीय संकट के संदर्भ में केन्द्रीय बैंकिंग की चुनौतियां और भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि और वित्त भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।

* भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

@ इलेक्ट्रानिक भुगतान को बढ़ावा देने हेतु, घरेलू ग्राहक जो एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना चाहते है, उन्हें 20 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

सामान्य अनुदेशः

1. बिकी हुई प्रतियां वापस नहीं ली जाएंगी।
2. प्रकाशन कन्साइनमेंट वीपीपी आधार पर नहीं भेजा जाएगा।
3. जहां कहीं रियायती मूल्य का उल्लेख नहीं है, वहां भारत में छात्रों, अध्यापकों/व्याख्याताओं, अकादमि क और शैक्षिक सस्थांओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी, बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रकाशन के पिछले अकं उपलब्ध नहीं है।
4. प्रकाशनों की बिक्री तथा वितरण (सोमवार से शुक्रवार) तक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, आरबीआई, अमर बिल्डिंग, तल मंज़िल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मंबुई - 400 001 में किया जाएगा। बिक्री अनुभाग का सपर्क नं. 022-2260 3000, विस्तार 4002, ई-मेलः spsdepr@rbi.org.in है।
5. सदस्यता शुल्क मुख्यतः एनईएफटी द्वारा किया जाना चाहिए और अग्रेषणपत्र, जिसके साथ एनईएफटी विवरण संलग्न हो, निदेशक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, आरबीआई, अमर बिल्डिंग, तल मंज़िल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मंबुई - 400 001।

   एनईएफटी फार्म में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित है :

लाभार्थी का नाम	आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारिबैंक
बैंक का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक
शाखा तथा पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBIS0MBPA04
खाते का प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8024129-19
प्रेषक से प्राप्तकर्ता की जानकारी	अभिदाता का नाम.......... अभिदाता सं...........

6. प्रकाशनों को शीघ्रातिशीघ्र भेजने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तथापि मांग अधिक होने पर 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर प्रकाशनों की आपूर्ति की जाएगी। औपचारिकताएं पूरा करने और उसके बाद उपलब्ध प्रकाशनों को भेजने में न्यूनतम एक महीने का समय लगेगा। 'प्रकाशन प्राप्त न होने की शिकायत' **2 महीने के अंदर भेजी जाए।**
7. **कृपया अपनी अंशदान संख्या, नाम, पता तथा ई-मेल आईडी spsdepr@rbi.org.in पर मेल करें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें।**